राष्ट्रीय संस्करण
CopyRight - Jagran.com

सनी बोले, हमने तब जीतना शुरू किया था जब विराट पैदा भी नहीं हुए थे

>> 14

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 167

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, सोमवार, 25 नवंबर 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 16

BYJU'S The Learning App

IAS 2020

प्रारंभिक परीक्षा टेस्ट सीरिज-2020

1ST DECEMBER 2019 (रविवार) से प्रारंभ

TOTAL 30 TESTS @5,000/-

PRELIMS MASTER 2020

प्रिलिम्स पाठ्यक्रम का सम्पूर्ण कवरेज

(GS + CSAT) @7,500/-

STARTS 9TH DECEMBER 2019

कार्यालय का पता : Shop No. 15, Ground Floor, Vardhman Central Mall, Nehru Vihar, Mukherjee Nagar, Delhi-54

अधिक जानकारी के लिए CALL, SMS/WHATSAPP करें- 9205881869

सरोकार

12 हजार महिलाओं को दिखाई सशक्तीकरण की राह

पलामू : झारखंड के गढ़वा जिले की सुमन अखौरी तीन दशक से ग्रामीण व आदिवासी महिलाओं को सशक्त बनाने में जुटी हैं जागृति महिला मंडल नामक संस्था के बैनर तले सुमन अब तक 12 हजार महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई व हस्तशिल्प का प्रशिक्षण देकर स्वावलंबन की राह दिखा चुकी हैं। (पेज-11)

जागरण विशेष

'ग्रीन कुंभ' की थीम पर होगा 2021 का हरिद्वार कुंभ

हरिद्वार : हरिद्वार कुंभ-2021 को भव्य, यादगार और अनूठा बनाने के लिए कुंभ मेला अधिष्ठान बड़े पैमाने पर तैयारी कर रहा है। विशेष यह कि इस बार हरिद्वार कुंभ का आयोजन 'ग्रीन कुंभ' की थीम पर होगा। इसमें गंगा की शुद्धता और पर्यावरण की रक्षा पर विशेष फोकस रहेगा। (पेज-11)

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▶ पृष्ठ 3

सांगली का शाही घराना स्विस बैंक खातों की जांच के दायरे में

नई दिल्ली : स्विस बैंकों में खाता रखने वाले भारतीयों की जांच के घेरे में एक शाही घराना भी आ चुका है। भारतीय जांच अधिकारी ने महाराष्ट्र में सांगली के पूर्व राजघराने के दो लोगों की जानकारी स्विट्जरलैंड के कर विभाग से मंगाई है। इस जांच में आधिकारिक सहयोग के लिए भारतीय अधिकारियों ने स्विट्जरलैंड सरकार से अनुरोध कर रखा है।

नेशनल न्यूज ▶ पृष्ठ 7

परनीत कौर ने हेलीकाप्टर में सुनीं खफा विधायकों की शिकायत

पटियाला : पंजाब में अफसरशाही के हावी होने और फोन टैपिंग से खफा पटियाला जिले के विधायकों को मनाने की कमान मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी और सांसद परनीत कौर ने संभाल ली है। परनीत रविवार को नाराज विधायकों को अपने साथ हेलीकॉप्टर में लेकर गईं और उनकी शिकायतें सुनीं।

बिजनेस ▶ पृष्ठ 12

आरकॉम ने अनिल अंबानी का इस्तीफा नामंजूर किया

नई दिल्ली : रिलायंस कम्यूनिकेशंस (आरकॉम) ने कहा है कि कर्जदाताओं ने चेयरमैन अनिल अंबानी समेत चार अन्य निदेशकों का इस्तीफा नामंजूर कर दिया है। इन्हें कॉरपोरेट इन्सॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रक्रिया में सहयोग करने को कहा गया है। अंबानी व चार अन्य निदेशकों ने इस महीने की शुरुआत में कंपनी से इस्तीफा दे दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने तलब की न्योते और दावे की चिट्ठी

टिप्पणी ▶ बिना पत्र देखे महाराष्ट्र में सरकार गठन की प्रक्रिया पर कैसे दे सकते हैं फैसला

कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से सोमवार सुबह 10:30 बजे दोनों पत्र के साथ पेश होने को कहा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

महाराष्ट्र में सरकार गठन की प्रक्रिया को असंवैधानिक ठहराने की शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को तत्काल फैसला देने से इन्कार कर दिया। मामले को समझने और कानूनी बारीकियां परखने के लिए अदालत ने केंद्र सरकार से कहा है कि राज्यपाल का भाजपा को सरकार बनाने का न्योता देने का और देवेंद्र फड़नवीस की ओर से सरकार बनाने का दावा करने वाले दोनों पत्र पेश करे। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को सोमवार सुबह 10:30 बजे तक पत्र पेश करने को कहा है। केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को नोटिस भी जारी किया है।

शनिवार को नाटकीय घटनाक्रम में अलसुबह महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने भाजपा नेता देवेंद्र फड़नवीस को मुख्यमंत्री और राकांपा के अजीत पवार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। अजीत का दावा है कि उनके साथ राकांपा के विधायक भाजपा को समर्थन देने के लिए तैयार हैं। राज्यपाल ने भाजपा को 30 नवंबर तक बहुमत साबित करने को कहा है। फिर दिनभर चले घटनाक्रम में राकांपा अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि यह अजीत का निजी फैसला है और पार्टी विधायक भाजपा के साथ सरकार बनाने के पक्ष में नहीं है। उन्होंने अजीत पवार को विधायक दल के नेता पद से हटाते हुए व्हिप जारी करने का अधिकार भी छीन लिया। इसके बाद सरकार गठन की पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस, शिवसेना और राकांपा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की।

इस राजनीतिक घमासान पर सुप्रीम कोर्ट ने छुट्टी वाले दिन रविवार को विशेष सुनवाई की। जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने मामले पर करीब एक घंटा सुनवाई की। कोर्ट ने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने याचिका में प्रतिपक्षी बनाए गए सभी पक्षकारों को ईमेल के जरिये याचिका की प्रतियां दी हैं। हालांकि याचिका में प्रतिपक्षी बनाई गई महाराष्ट्र सरकार, देवेंद्र फड़नवीस और अजीत पवार की ओर से कोर्ट में कोई प्रतिनिधि नहीं पेश हुआ। कोर्ट ने कहा, राज्यपाल का आदेश और देवेंद्र फड़नवीस का राज्यपाल को दिया गया पत्र देखे बगैर कैसे आदेश दिया जा सकता है। कोर्ट ने जब पूछा कि महाराष्ट्र सरकार की ओर से कोई है, तो पता चला कि सरकार या मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री की ओर से कोई भी वकील मौजूद नहीं था। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अगर कोर्ट उनसे कहता है तो वह राज्यपाल से जरूरी रिकॉर्ड मंगाकर कोर्ट में पेश कर सकते हैं। कोर्ट ने उनसे सोमवार को दोनों पत्र पेश करने को कहा। पत्र देखकर ही उचित आदेश पारित करना संभव होगा।

विपक्ष के वकीलों ने कहा, कुछ नहीं पता : कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की ओर से बहस कर रहे कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा कि देवेंद्र फड़नवीस का सरकार बनाने का दावा करने वाला और राज्यपाल की ओर से उन्हें न्योता देने वाला पत्र कहां है? इस पर दोनों वकीलों ने कहा कि उनके पास कोई पत्र या आदेश नहीं है। यह किसी को नहीं मालूम कि कब राज्यपाल ने उन्हें न्योता दिया और कब उन्होंने सरकार बनाने का दावा किया। यह भी नहीं मालूम कि राज्यपाल ने दावे की जांच परख कब की।

महा उलटफेर (विशेष) पेज>>4

सरकार गठन की प्रक्रिया को असंवैधानिक ठहराने की मांग के साथ कोर्ट पहुंची हैं कांग्रेस, राकांपा और शिवसेना

महाराष्ट्र मामले पर सुनवाई के लिए रविवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंचे बाएं से महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चव्हाण, कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला, अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और अन्य। प्रेट्र

क्या हैं याचिका की मांगें?

- शीर्ष अदालत देवेंद्र फड़नवीस को सरकार बनाने का न्योता देने का राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का आदेश असंवैधानिक घोषित कर रद करे।
- राज्यपाल को निर्देश दिया जाए कि वह शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस के गठबंधन को सरकार बनाने का निमंत्रण दें। उद्धव के नेतृत्व में इस गठबंधन में 144 से ज्यादा विधायकों के होने का दावा किया गया है।
- सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल याचिका में अंतरिम मांग की गई है कि महाराष्ट्र में 24 घंटे के अंदर सदन में बहुमत साबित करने का आदेश दिया जाए।

पवार बनाम पवार से गहराया सस्पेंस

ओमप्रकाश तिवारी, मुंबई

- शपथ के बाद से चुप्पी साधे अजीत ने ट्वीट कर शरद को बताया अपना नेता
- शरद पवार ने भतीजे के बयानों को झूठा और भ्रामक बताकर किया खारिज

महाराष्ट्र में रविवार को भी सियासी हलचल बनी रही। उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद से चुप्पी साधे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता अजीत पवार ने एक के बाद एक ट्वीट कर हलचल और बढ़ा दी। वहीं राकांपा अध्यक्ष शरद पवार ने अजीत की बातों और दावों को झूठा ठहरा दिया। शरद पवार ने शनिवार को ही स्पष्ट कर दिया था कि भाजपा को समर्थन अजीत का निजी फैसला है।

अजीत ने रविवार को एक के बाद एक ट्वीट कर कहा, 'मैं राकांपा में हूं और हमेशा राकांपा में ही रहूंगा। पवार साहब हमारे नेता हैं। हमारा भाजपा-राकांपा गठबंधन महाराष्ट्र में अगले पांच साल स्थिर सरकार देगा। चिंता की कोई बात नहीं है। सब ठीक है। बस थोड़े धैर्य की जरूरत है।' अजीत ने प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा नेताओं का धन्यवाद भी किया।

रुख पर कायम शरद पवार : कुछ देर बाद शरद पवार ने ट्वीट किया, 'भाजपा से गठबंधन का सवाल ही नहीं है। राकांपा ने सरकार बनाने के लिए एकमत से शिवसेना व कांग्रेस से गठबंधन का फैसला किया है।''अजीत पवार का बयान झूठा व भ्रामक है। उन्होंने लोगों में संशय बढ़ाने और गलत धारणा पैदा करने के लिए यह सब कहा है।'

निर्दलीयों और छोटे दलों पर नजर : सभी की निगाहें 13 निर्दलीयों और छोटे दलों के 16 विधायकों पर लगी हैं। किसी भी खेमे के लिए इनका साथ अहम हो सकता है। शिवसेना का दावा है कि उसे सात निर्दलीयों का समर्थन हासिल है। वहीं भाजपा 14 विधायकों के साथ होने का दावा कर रही है। ज्ञात हो, 288 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा को 105, शिवसेना को 56, राकांपा को 54 व कांग्रेस को 44 सीटें मिली हैं। बहुमत के लिए 145 का आंकड़ा छूना होगा।

रविवार की हलचल

- उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे ने होटल ललित में ठहरे शिवसेना विधायकों से मुलाकात की।
- शरद पवार होटल रेनेसां में राकांपा विधायकों से मिले। बाद में उद्धव और आदित्य भी वहां पहुंच गए।
- राकांपा नेता जयंत पाटिल ने अजीत पवार से मुलाकात कर उन्हें मनाने की कोशिश की। अजीत के नहीं मानने के बाद पाटिल भी होटल रेनेसां पहुंच गए।
- शाम को होटल में ही शरद पवार ने राकांपा विधायकों के साथ बैठक की।
- दादर कार्यालय में भाजपा विधायक दल की बैठक हुई। इसमें देवेंद्र फड़नवीस, भूपेंद्र यादव, चंद्रकांत पाटिल व केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल उपस्थित रहे।
- भाजपा ने कहा कि बहुमत साबित करने की रणनीति तैयार है। रात को अजीत भी फड़नवीस से मिलने पहुंचे।

न्यायपालिका के लिए मील का पत्थर साबित होगा अयोध्या का फैसला : मोदी

'मन की बात' ▶ फैसले पर लोगों का धैर्य, संयम व परिपक्वता सराहनीय

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- कहा, भारतीयों ने साबित किया, देशहित से बड़ा उनके लिए कुछ भी नहीं

अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को शांति और सद्भाव के साथ स्वीकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को धन्यवाद दिया है। 'मन की बात' कार्यक्रम के 59वें एपिसोड में प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरे देश ने फैसले पर जिस प्रकार के धैर्य, संयम और परिपक्वता का परिचय दिया है उससे साबित हो गया है कि भारतीयों के लिए राष्ट्रहित से बढ़कर कुछ भी नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला न्यायपालिका के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इस ऐतिहासिक फैसले के बाद देश अब नई उम्मीदों, नई आकांक्षाओं और नए इरादे के साथ नए रास्ते पर चल पड़ा है।

प्रधानमंत्री ने अयोध्या पर अदालत के फैसले के पहले पिछले महीने की 'मन की बात' की भी याद दिलाई। जिसमें उन्होंने देशवासियों से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उसी तरह स्वीकार करने की अपील की थी, जिस तरह 2010 में इसी मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को शांति और भाई-चारे के साथ स्वीकार किया था।

रेडियो पर 'मन की बात' कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जागरण आर्काइव

उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 130 करोड़ भारतीयों ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि उनके लिए देशहित से बढ़कर कुछ नहीं है। देश में शांति, एकता और सद्भावना के मूल्य सर्वोपरि हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जहां एक ओर लंबे समय के बाद कानूनी लड़ाई समाप्त हुई है, वहीं, देश में न्यायपालिका के प्रति सम्मान और बढ़ गया है।

'फिट इंडिया स्कूल रैंकिंग' शुरू करने की घोषणा : प्रधानमंत्री मोदी ने देश में 'फिट इंडिया स्कूल ग्रेडिंग सिस्टम' शुरू करने की घोषणा की। इसे तीन वर्गों में विभाजित किया गया है- फिट इंडिया स्कूल, फिट इंडिया स्कूल (3 स्टार) और फिट इंडिया स्कूल (5 स्टार)। रैंकिंग का निर्धारण इस पर होगा कि स्कूल फिटनेस को कितना महत्व देते हैं। उन्होंने स्कूलों से दिसंबर में 'फिट इंडिया' सप्ताह मनाने की अपील भी की।

जनवरी में हो सकती है परीक्षा पर चर्चा : रेडियो कार्यक्रम में मध्य प्रदेश की श्वेता के सुझाव का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार जनवरी में परीक्षा पर चर्चा का आयोजन करने की कोशिश होगी। पिछले साल यह कार्यक्रम फरवरी में हुआ था।

राजनीति में आने की इच्छा नहीं थी पेज>>3

टीम इंडिया ने पारी से जीत का रचा कीर्तिमान

बीसीसीआइ प्रेसीडेंट सौरव गांगुली ने जीत के बाद विराट कोहली को ट्राफी प्रदान की। (एएनआइ)

अभिषेक त्रिपाठी, कोलकाता

- बांग्लादेश को पारी और 46 रनों से पराजित किया, सीरीज 2-0 से जीती

कप्तान विराट कोहली (136) के शतक के साथ मैन ऑफ द मैच व मैन ऑफ द सीरीज इशांत शर्मा और उमेश यादव के अद्भुत प्रदर्शन की बदौलत भारत ने कोलकाता के ईडन गार्डेंस स्टेडियम में मेहमान बांग्लादेश को गुलाबी गेंद से हुए अपने पहले डे-नाइट टेस्ट में पारी और 46 रन से पराजित किया।

भारत ने दो मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में इंदौर में मेहमानों को पारी और 130 रनों से पराजित किया था। इस आधार पर भारत ने 2-0 से सीरीज तो जीती ही साथ ही 360 अंकों के साथ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में अपना पहला पायदान बरकरार रखा।

इस टेस्ट मैच में भारत को तीसरे दिन जीत के लिए चार विकेट की दरकार थी। मेजबान टीम ने तीसरे दिन के शुरुआती घंटे में ही मैच जीत लिया। इस जीत के साथ उसने टेस्ट चैंपियनशिप में अपना अजेय रिकॉर्ड कायम रखा। इस मैच में इशांत ने नौ विकेट झटके जबकि उनका अच्छा साथ उमेश यादव ने आठ विकेट लेकर दिया। महमूदुल्लाह रिटायर्ड हर्ट होने के चलते मैदान पर नहीं लौटे। इस तरह बांग्लादेश की दूसरी पारी 41.1 ओवर में 195 रन पर सिमट गई। भारत ने बांग्लादेश की पहली पारी 106 रन पर समेटने के बाद दूसरे दिन नौ विकेट पर 347 रन बनाकर अपनी पहली पारी घोषित की थी। (पेज-14 भी देखें)

142 साल के टेस्ट इतिहास में लगातार चार टेस्ट पारी और रनों के अंतर से जीतने वाला पहला देश बना भारत। इससे पहले दुनिया की कोई भी टीम ऐसा नहीं कर पाई थी। भारत ने इस क्रम में दो मैच दक्षिण अफ्रीका और दो मैच बांग्लादेश को हराए

12 वीं लगातार सीरीज भारतीय टीम ने घर में जीती। यह अब तक का इस टीम का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है

01 टेस्ट है जो भारत में टीम इंडिया ने बिना स्पिनर के विकेट के जीता है

07 लगातार टेस्ट भारत ने पहली बार जीते हैं। इस दौरान उसने वेस्टइंडीज को दो, दक्षिण अफ्रीका को तीन और बांग्लादेश को दो मैच हराए। इससे पहले उसने 2013 में लगातार छह टेस्ट जीते थे

नई रणनीति

जम्मू कश्मीर में आतंकियों के सफाए के लिए सरकार ने नई रणनीति तैयार की है, इसके लिए तीनों सेनाओं को मैदान में उतारा गया है

जल, थल व नभ से एक साथ आतंकियों पर वार

- कश्मीर में तीनों सेनाओं की कमान करेगी आतंकियों का सफाया
- सशस्त्र बल विशेष परिचालन विभाग के तहत की जा रही तैनाती

नई दिल्ली, एएनआइ : कश्मीर में आतंकियों के सफाए के लिए मोदी सरकार ने नई रणनीति तैयार की है। दहशतगर्दों पर अब जल, थल और नभ (आकाश) तीनों तरफ से प्रहार किया जाएगा। इसी के तहत कश्मीर घाटी में पहली बार सेना, नौसेना और वायुसेना की संयुक्त कमान तैनात की जा रही है। वरिष्ठ रक्षा सूत्रों ने बताया कि सेना के विशेष बल, नौसेना के मरीन कमांडो और वायुसेना के गरुड़ विशेष बल को हाल ही में गठित सशस्त्र बल विशेष परिचालन विभाग के तहत कश्मीर में तैनात किया गया है।

नई रणनीति के तहत श्रीनगर के नजदीक संयुक्त विशेष बल की टुकड़ी की तैनाती शुरू कर दी गई है। इस इलाके को परंपरागत रूप से दहशतगर्दों का गढ़ माना जाता है। हालांकि, नौसेना और वायुसेना के विशेष बल पहले भी कश्मीर घाटी में आतंकियों के खिलाफ अभियान चलाते रहे हैं, लेकिन पहली बार तीनों को संयुक्त कमान के तहत लाया जा रहा है। सशस्त्र बल विशेष परिचालन विभाग का पहला प्रमुख मेजर जनरल अशोक धींगरा को बनाया गया है।

नौसेना के उच्च प्रशिक्षण प्राप्त मार्कोस कमांडो को वुलर झील इलाके में तैनात किया गया है, जबकि वायुसेना की गरुड़ टीम को लोलब और हजिन इलाके में आतंकियों के सफाए की जिम्मेदारी दी गई है। वायुसेना का विशेष बल पहले भी कश्मीर घाटी में आतंकियों के खिलाफ सफल ऑपरेशन कर चुका है। गौरतलब है कि हजिन इलाके में छह आतंकियों को मार गिराने के लिए जेपी निराला को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। सशस्त्र बल विशेष परिचालन विभाग ने अलग-अलग इलाकों में दो सैन्य अभ्यास भी किया है, जिसमें सैनिकों को दुश्मनों पर हमला करने और उसके कब्जे वाले इलाके को अपने कब्जे में लेने का प्रशिक्षण दिया गया। इनमें पहला अभ्यास कच्छ इलाके में और दूसरा अभ्यास अंडमान और निकोबार द्वीप पर किया गया। कच्छ इलाके में हुए अभ्यास का कोडनेम एक्स स्मेलिंग फील्ड और अंडमान में हुए अभ्यास का कोडनेम डीएएनएक्स-2019 रखा गया था।

रिहा हो सकते हैं कुछ और कश्मीरी नेता

जम्मू : जम्मू-कश्मीर में सौ दिन से अधिक समय से हिरासत में चल रहे कुछ नेताओं को जल्द रिहा किया जा सकता है। इन नेताओं पर लगाए गए प्रतिबंधों में भी ढील दी जा रही है। कुछ राजनीतिक नेताओं को स्वास्थ्य कारणों से घाटी के बाहर जाने की इजाजत भी मिल सकती है। जम्मू-कश्मीर सरकार के कुछ अधिकारियों ने इसके संकेत भी दिए हैं, लेकिन केंद्र सरकार के साथ विचार-विमर्श के बाद ही इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। सूत्रों के अनुसार, राज्य प्रशासन ने गत शनिवार को चार से पांच नेताओं को उनके अनुरोध पर कुछ देर के लिए घर जाने की इजाजत भी दी थी। उल्लेखनीय है कि हाल ही में डल झील के किनारे बने सेंटूर होटल (सब जेल) से विभिन्न दलों के नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं को ठंड के कारण एमएलए हॉस्टल में शिफ्ट किया गया था। (पेज-6)

वरिष्ठ आइएएस राजीव कुमार को जबरन रिटायर करने की तैयारी

लखनऊ : भ्रष्टाचार पर जीरो टालरेंस की नीति के तहत योगी सरकार अब 1983 बैच के वरिष्ठ आइएएस अधिकारी राजीव कुमार द्वितीय को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने की तैयारी में है। इसके लिए प्रक्रिय शुरू कर दी गई है। नोएडा प्लाट आवंटन घोटाले में पूर्व मुख्य सचिव नीरा यादव के साथ जेल की सजा काट चुके राजीव कुमार द्वितीय 2016 से निलंबित हैं। यदि राजीव कुमार को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई तो यह प्रदेश में किसी आइएएस अफसर को जबरन रिटायर करने का पहला मामला होगा। (पेज-3)

ब्रिटिश पीएम जॉनसन के चुनाव घोषणा पत्र में ब्रेक्जिट पर जोर

लंदन : ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने रविवार को कंजरवेटिव पार्टी का चुनाव घोषणापत्र जारी किया। इसमें उन्होंने आम चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए ब्रेक्जिट और मितव्ययिता जैसे मुद्दों पर आगे बढ़ने का संकल्प दोहराया है। जॉनसन ने जुलाई में अल्पमत सरकार का कामकाज संभाला था, लेकिन ब्रिटेन को यूरोपीय संघ से अलग करने के समझौते (ब्रेक्जिट) को गति नहीं दे सके थे। (पेज-13)

सड़क पर गिरे जहरीले केमिकल ने ली दो युवकों की जान

राकेश कुमार सिंह, नई दिल्ली

- दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में केमिकल के कारण फिसली बाइक
- लोकनायक अस्पताल में भर्ती तीसरे दोस्त की हालत नाजुक

दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में शनिवार सुबह सड़क पर ग्रीस जैसा केमिकल गिरा होने के कारण बाइक सवार तीन युवक फिसल कर नीचे गिर गए। तीनों के शरीर में केमिकल लग गया। केमिकल इतना जहरीला था कि युवकों के शरीर पर तुरंत ही घाव जैसे दाने निकलने शुरू हो गए। साथ ही जहां-जहां केमिकल लगा वह हिस्सा नीला पड़ गया। तीनों को लोक नायक अस्पताल पहुंचाया गया, जहां 24 घंटे के अंदर दो युवकों महेश व शिवम ने दम तोड़ दिया। तीसरे युवक मोनू की हालत गंभीर बनी हुई है।

कश्मीरी गेट थाना पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। रविवार को दोनों के शवों का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने घटनास्थल से केमिकल का नमूना जांच के लिए फॉरेंसिक साइंस लैब में भेजा है। जांच से ही पता चलेगा कि बेहद खतरनाक जहरीले केमिकल का नाम क्या है।

पुलिस के मुताबिक, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर संविदा पद पर काम करने वाले करावल नगर निवासी महेश, मोनू और रोहिणी निवासी शिवम दोस्त की शादी में शरीक होकर नांगलोई से एक ही बाइक से लौट रहे थे। शनिवार सुबह करीब पौने छह बजे मोरी गेट से आगे पुल डफरिन के पास पहुंचने पर सड़क पर गिरे केमिकल की वजह से बाइक फिसल गई। इससे तीनों गिर गए और उनके शरीर में केमिकल लग गया। इसके बाद तीनों को पिकेट पर तैनात पुलिसकर्मियों ने अस्पताल पहुंचाया। माना जा रहा है कि पुरानी दिल्ली के केमिकल मार्केट में किसी टैंकर में रिसाव से सड़क पर केमिकल गिर गया होगा। पुलिस सीसीटीवी फुटेज से टैंकर के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही है।

49 लाख रुपये का एनवायरमेंटल कंपनसेशन (ईसी) वसूला है दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने पिछले आठ दिनों में। राजधानी में प्रदूषण फैला रहे छोटे-बड़े 63 वाहनों से यह वूसली की गई।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
सोमवार 25 नवंबर 2019

पुरी ने मनोज तिवारी को सीएम पद का चेहरा बताया, फिर पलटे

सियासी सरगर्मी ▶ मामला तूल पकड़ा तो केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट कर दी सफाई, कहा- भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में आगामी चुनाव जीतेगी पार्टी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा औपचारिक तौर पर भले ही मुख्यमंत्री प्रत्याशी का कोई चेहरा पेश नहीं कर रही है, लेकिन केंद्रीय शहरी विकास और उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने रविवार को प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी का नाम आगे कर दिया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र के शहरी केंद्र प्रमुखों के सम्मेलन में हरदीप पुरी ने स्पष्ट तौर पर कहा, 'हम लोग मनोज तिवारी के नेतृत्व में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं और उन्हें मुख्यमंत्री बनाकर ही छोड़ेंगे'। इसके बाद कार्यकर्ताओं में जोश भर गया और कार्यक्रम स्थल पर जय श्रीराम के साथ अबकी बारी, मनोज तिवारी के नारे लगने लगे। हालांकि बाद में हरदीप पुरी ने ट्वीट कर बताया कि उनका आशय मनोज तिवारी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का था।

शास्त्री पार्क में आयोजित सम्मेलन में हरदीप पुरी करीब 25 मिनट तक बोले। इस दौरान बीच-बीच में भारत माता की जय के नारे लग रहे थे। लेकिन जैसे ही भाषण खत्म करते समय 24वें मिनट में उन्होंने मनोज तिवारी को मुख्यमंत्री बनाने की बात कही, तो कार्यकर्ताओं में उल्लास फैल गया। मनोज तिवारी के समर्थन में नारे लगने लगे। हालांकि मनोज तिवारी ने सभी को शांत करते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री की इस बात को भूल जाएं और बाकी सब याद रखें। उनका आशय यह था कि केंद्रीय मंत्री ने चुनावी तैयारियों को लेकर जो बोला है, उन पर ध्यान दें। लेकिन हरदीप पुरी के बयान ने तूल पकड़ लिया। मीडिया में खबर फैल गई। करीब तीन घंटे के बाद हरदीप पुरी ने ट्वीट कर बयान पर स्पष्टीकरण दिया।

उन्होंने कहा, 'दिल्ली में भाजपा विजय की ओर अग्रसर है। पार्टी ने अब तक मुख्यमंत्री पद के लिए किसी को नामित नहीं किया है। मनोज तिवारी प्रदेश अध्यक्ष हैं। पार्टी उनके नेतृत्व में पूरे जोश से काम कर रही है। मेरे बयान का मतलब यह था कि भाजपा उनके नेतृत्व में आगामी विधानसभा चुनाव जीतेगी'। हालांकि स्पष्टीकरण के बाद भी मनोज तिवारी के समर्थकों का जोश कम नहीं हुआ है।

उधर, मनोज तिवारी का कहना है कि प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते दिल्ली में सरकार बनाने की मेरी जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री कौन होगा, यह मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि आप नेताओं की नींद उड़ गई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री उम्मीदवार का फैसला संसदीय बोर्ड द्वारा किया जाता है।

शास्त्री पार्क में आयोजित भाजपा के शहरी केंद्र प्रमुख सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का स्वागत करते दिल्ली भाजपा अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी। जागरण

भाजपा के लिए आसान नहीं सीएम पद का प्रत्याशी घोषित करना

निहाल सिंह, नई दिल्ली

दिल्ली विधानसभा के चुनावी मैदान में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के साथ उतरना भाजपा के लिए आसान नहीं होगा। पार्टी इस समय कई गुटों में दिखाई देती है। ऐसे में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने से पार्टी के भीतर गुटबाजी मुखर रूप से सामने आ सकती है। यही कारण है कि केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी को प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने के बयान पर कुछ ही घंटे में सफाई देनी पड़ गई। हालांकि, इसके साथ ही पार्टी में एक बार फिर मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर चर्चा तेज हो गई है। साथ ही उम्मीदवार घोषित करने और न करने को लेकर नफा-नुकसान भी टटोला जाने लगा है।

पार्टी के कई नेता प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष तरीके से मुख्यमंत्री बनने की चाहत रखते हैं। इसे लेकर एक-दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ के साथ दिल्ली का लोकप्रिय नेता दिखाने की कोशिशें भी दिखाई देती हैं। पार्टी के आंतरिक मंचों पर इसे लेकर दावेदारी पेश की जाती है। एक-दूसरे का पत्ता काटने का भी प्रयास होता है। वैसे पूर्व के अधिकतर चुनावों में पार्टी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के साथ ही चुनाव में कूदती रही है। इसके नुकसान ही सामने आए हैं। वर्ष 2015 में जब भाजपा पूरे देश में चरम पर थी, तब भी दिल्ली का किला फतह करने का अरमान पूरा नहीं हो सका था। जबकि भाजपा ने चर्चित आइपीएस व अन्ना आंदोलन की उपज किरण बेदी पर दांव लगाया था। वर्ष 2013 में डॉ. हर्षवर्धन के नेतृत्व में कड़ी टक्कर देने के बाद भी भाजपा बहुमत से चूक गई और सरकार नहीं बना पाई।

पार्टी में मुख्य रूप से तीन से चार नामों की चर्चा मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए हैं। इसमें मनोज तिवारी के अलावा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विजय गोयल, केंद्रीय मंत्री डॉ. हर्षवर्धन व नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता का नाम लिया जा रहा है। पूर्वांचल का चेहरा होने व प्रदेश अध्यक्ष के रहते दो चुनावों (नगर निगम व लोकसभा) में जीत दिलाने से मनोज तिवारी की दावेदारी अधिक है। विजय गोयल भले ही राजस्थान से राज्यसभा सदस्य हैं, लेकिन उनकी सीएम बनने की महत्वाकांक्षा छुपी नहीं है। केंद्रीय मंत्री डॉ. हर्षवर्धन खुले तौर पर तो कोई गतिविधि अपनी उम्मीदवारी को लेकर नहीं करते, लेकिन उनके समर्थक उनके लिए अंदरखाने अभियान चलाते रहते हैं। विजेंद्र गुप्ता चूंकि नेता प्रतिपक्ष हैं तो उनके समर्थक भी उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की मांग करते रहते हैं।

आप ने पुरी के बयान वापसी पर बोला हमला

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

▶ संजय सिंह ने किया ट्वीट-इसका मतलब केजरीवाल जी के खिलाफ आपके पास कोई नहीं?

▶ राघव चड्ढा बोले, तिवारी का नाम वापस लेना क्या यह भाजपा की पूर्वांचल विरोधी मानसिकता नहीं हैं?

आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री पद के लिए मनोज तिवारी को चेहरा बताने के बाद अपना बयान वापस लेने पर आम आदमी पार्टी (आप) ने केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी पर हमला बोला है।

आप से राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने ट्वीट कर कहा कि तो इसका मतलब केजरीवाल जी के खिलाफ आपके पास कोई नहीं? बिना दूल्हे की बारात? आपका मुख्यमंत्री उम्मीदवार दो घंटे में ही मैदान छोड़कर भाग गया या भाजपा को उनकी प्रतिभा पर भरोसा नहीं है?

उन्होंने कहा कि पुरी जी दिल्ली की जनता जानना चाहती कि केजरीवाल जी के सामने आपका चेहरा कौन है? आपने तिवारी जी का नाम बताया भी और तीन घंटे में मैदान छोड़ कर भाग गए, क्या चुनाव से भाजपा ने केजरीवाल को वॉकओवर दे दिया है?

आप के राष्ट्रीय प्रवक्ता राघव चड्ढा ने ट्वीट कर कहा कि क्यों दो घंटे के भीतर ही भाजपा ने मनोज तिवारी का नाम वापस ले लिया। क्या यह भाजपा की पूर्वांचल विरोधी मानसिकता नहीं हैं?

इससे पहले पुरी के बयान पर आप ने पार्टी मुख्यालय में प्रेसवार्ता की थी। इसमें पुरी द्वारा भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी को आगामी विधानसभा चुनाव में सीएम का चेहरा बताने के बयान का पार्टी ने स्वागत किया था। इसके साथ ही तंज कसा था कि अब पार्टी 2015 के विधानसभा चुनाव में सीटें जीतने का रिकॉर्ड तोड़ेगी और प्रचंड बहुमत से 2020 में दिल्ली में सरकार बनाएगी। संजय सिंह ने केंद्रीय मंत्री पुरी के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि काफी समय से इस प्रश्न का उत्तर दिल्ली की जनता जानना चाह रही थी। इस प्रश्न का जवाब मिल गया है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता हरदीप पुरी ने स्पष्ट कर दिया है कि मनोज तिवारी भाजपा के मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं। अब तस्वीर बिल्कुल साफ है। दिल्ली में एक तरफ अरविंद केजरीवाल हैं, जिन्होंने दिल्ली की जनता की सुविधाएं और विकास के लिए काम किया है। दूसरी तरफ मनोज तिवारी का चेहरा है, जिन्होंने कहा है कि दिल्ली में दो सौ यूनिट बिजली की योजना खत्म होगी। जिन्होंने कहा कि जनता की सारी छूट खत्म करेंगे। बसों में महिलाओं की मुफ्त यात्रा खत्म करेंगे।

आतिशी बोलीं, भाजपा का सीएम उम्मीदवार तीन घंटे में ही मैदान छोड़कर भागा

राज्य ब्यूरो,नई दिल्ली : आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता एवं प्रवक्ता आतिशी ने कहा कि हरदीप पुरी न केवल भाजपा की सरकार में कैबिनेट मंत्री के पद पर आसीन हैं, बल्कि दिल्ली के चुनाव में सह प्रभारी भी हैं। एक सह प्रभारी द्वारा दिए गए बयान का एक महत्व होता है। उन्होंने यह बयान एक सार्वजनिक मंच से दिया है। भाजपा से प्रश्न पूछते हुए आतिशी ने कहा कि दो ही घंटे में मनोज तिवारी के सीएम पद की उम्मीदवारी को वापस ले लिया गया, क्या भाजपा को मनोज तिवारी की प्रतिभा पर विश्वास नहीं है? क्या भाजपा को लगता है कि तिवारी अरविंद केजरीवाल के सामने टिक नहीं पाएंगे?

कांग्रेस का तंज, शुरू हुई मुख्यमंत्री पद की लड़ाई

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी द्वारा एक कार्यक्रम में की गई घोषणा अब भाजपा के लिए गले की हड्डी बन गई है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता व पूर्व विधायक मुकेश शर्मा ने ट्वीट कर भाजपा पर तंज कसा है कि पुरी ने प्रदेश अध्यक्ष व सांसद मनोज तिवारी को मुख्यमंत्री पद से नवाज दिया है, लेकिन अब भाजपा के अन्य नेताओं का क्या होगा? उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे विजेंद्र गुप्ता, विजय गोयल, डॉ. हर्षवर्धन, प्रवेश वर्मा, सतीश उपाध्याय का क्या होगा? हरदीप पुरी के बयान ने भाजपा के भीतर की लड़ाई सड़क पर ला दी है। वास्तव में भाजपा का यही असली चेहरा है।

छात्रावास शुल्क मामले में जेएनयू ने भी बनाई समिति

जासं, नई दिल्ली: जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में छात्रावास शुल्क बढ़ोतरी और नई नियमावली मामले को सुलझाने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने सात सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठित की है। समिति की अध्यक्षता रेक्टर तृतीय प्रोफेसर राना प्रताप सिंह करेंगे। समिति ने रविवार शाम साढ़े पांच बजे तक ई-मेल के जरिये विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों से सुझाव मांगे थे। दूसरी तरफ विद्यार्थियों ने समिति के गठन पर सवाल उठाए हैं। इन्हीं मामलों को सुलझाने के लिए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से भी एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति बनाई गई है जो संभवतः सोमवार को सुझाव सौंपेगी। जेएनयू के रजिस्ट्रार प्रोफेसर प्रमोद कुमार की ओर से जारी सर्कुलर के मुताबिक छात्रावास के मुद्दों के समाधान के लिए सक्षम प्राधिकारी ने उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है। विद्यार्थी प्रतिनिधियों को अपने सुझाव रविवार शाम साढ़े पांच बजे तक इस समिति को ई-मेल के माध्यम से भेजने के लिए कहा गया था। छात्र संघ का कहना है कि इस समिति में कुलपति ने सिर्फ अपने साथियों को ही जगह दी है। दूसरी बात, सुझाव देने के लिए रविवार शाम साढ़े पांच बजे तक का ही समय दिया गया है। तीसरी बात जब एचआरडी की समिति छात्र संघ से बात कर सकती है तो विश्वविद्यालय की समिति को बात करने में क्या परेशानी है। हमारी मांग है कि छात्रावास शुल्क बढ़ोतरी पूरी तरह से वापस ली जाए। छात्रावास नियमावली को रद किया जाए।

समिति में अध्यक्ष राना प्रताप सिंह के अलावा स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के डीन प्रोफेसर अश्विनी महापात्रा, स्कूल ऑफ संस्कृत एंड इंडिक स्टडीज के डीन प्रोफेसर गिरीश नाथ झा, स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के डीन प्रोफेसर पवन कुमार धर, छात्र कल्याण डीन प्रोफेसर उमेश अशोक कदम, छात्र कल्याण एसोसिएट डीन प्रोफेसर वंदना मिश्रा और प्रोवोस्ट नीरज समजदार शामिल हैं।

केजरीवाल का आरोप, कच्ची कॉलोनियों में रजिस्ट्री पर केंद्र की नीयत खराब

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

▶ बुराड़ी के वेस्ट कमल विहार में 33 कॉलोनियों में सीवर लाइन डालने की योजना का किया शुभारंभ

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को बुराड़ी के वेस्ट कमल विहार में 33 कॉलोनियों में सीवर लाइन डालने की योजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव नजदीक है तो पिछले दो माह से केंद्र सरकार को कच्ची कॉलोनियों को पक्का करने की याद आ रही है। कच्ची कॉलोनियों में रजिस्ट्री के मामले पर केंद्र सरकार चुप है। केजरीवाल ने कहा, मैं इन कॉलोनियों में रजिस्ट्री कराकर ही दम लूंगा। इस मौके पर विधायक संजीव झा भी मौजूद थे।

केजरीवाल ने कहा कि कच्ची कॉलोनियों में रजिस्ट्री को लेकर केंद्र सरकार की नीयत खराब है। पिछले पांच साल से केंद्र सरकार कहां थी, जब इस दौरान वह दिन-रात खड़े होकर इन कॉलोनियों में विकास कार्य करवा रहे थे। यही कारण है कि आज 1800 में 1300 कच्ची कॉलोनियों में सड़क और नालियों के काम चल रहे हैं तो 900 कॉलोनियों में नई सीवर व 500 कॉलोनियों में पानी की पाइप लाइन बिछाई गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्ना आंदोलन के बाद जब हमने नई पार्टी बनाई तो कच्ची कॉलोनियों में जाकर वहां के हालात देखे थे। उसी समय इन कॉलोनियों का उद्धार करने का फैसला कर लिया था। हमारी सरकार बनी तो नियम को बदलकर कच्ची कॉलोनियों में काम शुरू कराया, लेकिन अब केंद्र सरकार को इन कॉलोनियों की याद आने लगी है।

उन्होंने कहा कि दिल्ली में 70 साल में पहली ऐसी सरकार आई है, जो बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करा रही है। पहले ऐसा किसी सरकार ने नहीं किया। उन्होंने कहा कि अभी मंच पर कुछ बुजुर्ग महिलाएं आईं, जो उज्जैन की तीर्थ यात्रा कर लौटी हैं। उन्होंने मुझे श्रवण कुमार का चित्र भेंट किया। इससे बेहद खुशी होती है कि वह एक आम आदमी के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि आम आदमी की समस्याओं को वह अच्छी तरह से जानते हैं।

उन्होंने कहा कि पहले की सरकारें वोट जनता का लेती थीं, लेकिन काम अडानी और अंबानी का करती थीं, लेकिन हमारी सरकार में ऐसा नहीं है। यही कारण है कि हमने लोगों के घरों के सेप्टिक टैंक की मुफ्त में सफाई की योजना शुरू की है। अगले एक माह में एक नंबर जारी कर दिया जाएगा, जिस पर कॉल करने के बाद दिल्ली सरकार की गाड़ी आएगी और सेप्टिक टैंक की सफाई मुफ्त कर जाएगी।

महिलाओं के मुफ्त बस में सफर पर बड़े मंत्री को कष्ट : मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा, मैंने अखबार में केंद्र सरकार के एक बड़े मंत्री का बयान पढ़ा, जिन्हें महिलाओं के बस में मुफ्त सफर करने पर तकलीफ हो रही है। उस मंत्री को हर माह चार हजार यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है। 200 यूनिट बिजली मुफ्त करने का विरोध किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने पूछा, मैंने ऐसे लोगों के ड्राइवरों के लिए बिजली को मुफ्त किया है तो इसमें हर्ज क्या है? मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने पांच सालों में खूब काम किया है। अब चुनाव आ गया है लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए चुनाव आप सब को लड़ना है। अगर हमारी सरकार नहीं बनी तो विकास पर ब्रेक लग जाएगा।

दिल्ली में सौ पार्किंग बनाएगा डीडीए

जासं, नई दिल्ली : दिल्ली सरकार और नगर निगम के बीच उलझती रही पार्किंग समस्या का समाधान अब दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) निकालेगा। इसके लिए राजधानी में एक सौ पार्किंग बनाई जाएंगी, जिसके लिए जगह चिह्नित की जा रही है। जल्द ही इस दिशा में टेंडर जारी होने की संभावना है।

गौरतलब है कि पार्किंग की समस्या दिल्ली के लिए नासूर बनती जा रही हैं। वैध पार्किंग न होने से एक ओर जहां अवैध पार्किंग का धंधा जोरों पर चल रहा है, वहीं सड़कों पर भी वाहन खड़े रहते हैं। इससे जगह-जगह जाम की समस्या गहराती जा रही है व सड़कों पर वाहनों की रफ्तार भी प्रभावित हो रही है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट और पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण एवं संरक्षण प्राधिकरण (ईपीसीए) के निर्देश पर पार्किंग नीति का ड्राफ्ट नोटिफिकेशन तैयार हो चुका है लेकिन दरों और मुफ्त पार्किंग के मसले पर इसका क्रियान्वयन लटका हुआ है।

इसके मद्देनजर अब डीडीए ने अपनी जमीन पर दिल्ली भर में पार्किंग बनाने का निर्णय लिया है। पहले चरण में दिल्ली के सभी हिस्सों में एक सौ पार्किंग बनाई जाएंगी। इनमें व्यावसायिक और रिहायशी दोनों क्षेत्र शामिल होंगे। सभी पार्किंग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल के तहत तैयार होंगी।

एम्स में किडनी प्रत्यारोपण एक महीने से बंद, 575 मरीज कर रहे इंतजार

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

एम्स में 575 मरीज किडनी प्रत्यारोपण के इंतजार में हैं, लेकिन नेफ्रोलॉजी विभाग में बेड की कमी के चलते करीब एक माह से यह सुविधा बंद है। इस वजह से किडनी की बीमारी से पीड़ित आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस माह अभी तक एक भी व्यस्क का प्रत्यारोपण नहीं हुआ है।

संस्थान के नेफ्रोलॉजी विभाग के डॉक्टर ने कहा कि समान्य तौर पर हर सप्ताह दो से तीन मरीजों का किडनी प्रत्यारोपण किया जाता है। हर माह 10 से से 12 मरीजों की सर्जरी होती है। जनरल सर्जरी विभाग के डॉक्टर किडनी प्रत्यारोपण करते हैं लेकिन प्रत्यारोपण से पहले और बाद में मरीज की देखभाल नेफ्रोलॉजी विभाग के डॉक्टर करते हैं।

इस वजह से नेफ्रोलॉजी विभाग की भूमिका अहम होती है। विभाग में लाइव डोनर किडनी प्रत्यारोपण के लिए 125 मरीज व कैडेवर डोनर प्रत्यारोपण के लिए 450 मरीज इंतजार में हैं। इन मरीजों को नियमित डायलिसिस करना पड़ता है। इस वजह से कई मरीजों की हालत गंभीर है। 10 मरीजों की जिंदगी तो खतरे में बताई जा रही है। इस वजह से उन मरीजों के तीमारदारों ने एम्स प्रशासन से बेड उपलब्ध कराने की मांग की है।

फॉलोअप में हैं दो हजार मरीज : एम्स में वर्ष 1972 से लेकर अब तक 2,900 मरीजों का किडनी प्रत्यारोपण हो चुका है। नेफ्रोलॉजी विभाग के लगभग दो हजार मरीज फॉलोअप में हैं। विभाग के वरिष्ठ डॉक्टर ने कहा कि कई बार बेड बढ़ाने की मांग की गई, लेकिन बेड नहीं बढ़ाए जा रहे हैं। करीब 30 साल से नेफ्रोलॉजी व यूरोलॉजी के लिए अलग ब्लॉक के प्रस्ताव को एम्स प्रशासन ने ठंडे बस्ते में डाल रखा है, जबकि मरीजों का दबाव बढ़ गया है। विभाग के पास कुल 24 बेड हैं, जिनमें से सिर्फ चार बेड प्रत्यारोपण वाले मरीजों के लिए सुनिश्चित हैं। हर साल करीब 150 मरीजों का प्रत्यारोपण होता है। इनमें से 10 से 15 फीसद मरीजों में संक्रमण की आशंका रहती है। इस वजह से उन्हें भर्ती करने की जरूरत होती है। दिक्कत यह है कि दूसरे अस्पताल किडनी की बीमारी से पीड़ित मरीजों को अंतिम स्टेज में एम्स स्थानांतरित करते हैं। ऐसे मरीजों को भी इमरजेंसी में भर्ती करना पड़ता है। अस्पताल की नीति है कि इमरजेंसी में भर्ती किडनी के मरीजों को 24 घंटे में वार्ड में भर्ती करना अनिवार्य है।

इमरजेंसी में अक्सर सात-आठ मरीज वेटिंग में होते हैं। इस वजह से प्रत्यारोपण के लिए पंजीकृत मरीजों को भर्ती करने का अवसर नहीं मिल पा रहा है। मरीजों के दबाव के अनुसार, किडनी प्रत्यारोपण के मरीजों के लिए करीब 20 बेड की जरूरत है। यही नहीं संस्थान में 13 डायलिसिस मशीन हैं। दूसरे अस्पताल से स्थानांतरित कर इमरजेंसी में पहुंचे मरीजों की डायलिसिस में ही ज्यादातर मशीनें व्यस्त रहती हैं।

सिर्फ चार सरकारी अस्पतालों में प्रत्यारोपण की सुविधा

दिल्ली में सरकारी क्षेत्र के सिर्फ चार अस्पतालों में ही किडनी प्रत्यारोपण की सुविधा है। इनमें एम्स, सफदरजंग, आरएमएल और यकृत व पित्त विज्ञान संस्थान (आइएलबीएस) शामिल हैं। आइएलबीएस में किडनी प्रत्यारोपण के लिए ढाई से चार लाख खर्च आता है। सफदरजंग व आरएमएल में अभी बहुत कम प्रत्यारोपण होता है। वहीं निजी अस्पतालों में किडनी प्रत्यारोपण के लिए छह से आठ लाख रुपये खर्च करने पड़ते हैं। ऐसे में आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों के लिए एम्स ही सबसे बड़ा सहारा है। इस बारे में एम्स प्रशासन ने कुछ भी बयान देने से इन्कार कर दिया।

फीस निर्धारण को लेकर हाई कोर्ट में याचिका

नई दिल्ली, जासं : निजी स्कूलों में फीस निर्धारण और फीस कम करने की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इस पर न्यायमूर्ति राजीव शकधर की पीठ ने दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इसके साथ ही पीठ ने निजी स्कूलों के प्रबंधन को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

याचिका में अभिभावकों ने कानून के उन प्रावधानों को लागू किए जाने की मांग की है, जिनमें फीस न बढ़ाए जाने के साथ ही स्कूल के पास पर्याप्त धनराशि होने की स्थिति में शिक्षा निदेशक के पास फीस निर्धारित करने या कम करने का अधिकार निहित है। याचिका के अनुसार शिक्षा निदेशालय ने 2012 से 2019 की जांच में पाया कि एपीजे स्कूल शेखसराय के पास 30 करोड़ से अधिक का अतिरिक्त कोष है और स्कूल ने कई दस्तावेजों को छुपाया था।

दिल्ली नागरिक सरकारी बैंक में हुए घोटाले पर आरबीआइ से मांगी रिपोर्ट

विनीत त्रिपाठी, नई दिल्ली

दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक में फर्जी दस्तावेजों व इनकम टैक्स रिटर्न (आइटीआर) के आधार पर करोड़ों के लोन बांटने वालों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लोन बांटने के नाम पर हुए करोड़ों के घोटाले के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआइ) को दोबारा जांच के आदेश दिए हैं। न्यायमूर्ति राजीव शकधर की पीठ ने जब आरबीआइ की सीलबंद रिपोर्ट को खोला तो पाया कि मामले की जांच शिकायतकर्ता की शिकायत के हिसाब से नहीं की गई। पीठ ने पहली जांच से असंतुष्टि जाहिर की और निर्देश दिया कि मामले की जांच पूरी कर एक्शन टेकन रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में 25 मई 2020 तक पेश की जाए।

दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक के सदस्य व याचिकाकर्ता अनिल कुमार गौर ने 2016 में अधिवक्ता राजेश श्रीवास्तव के माध्यम से याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता का आरोप है कि सहकारी बैंक में लोन देने के नाम पर 2011 से 2014 के बीच करीब 50 करोड़ का घोटाला हुआ। उन्होंने इस संबंध में आरबीआइ से शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई न होने पर उन्होंने याचिका दायर की। दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक द्वारा वर्ष 2011 से 2014 के बीच फर्जी दस्तावेज और आइटीआर के आधार पर लोन जारी किया गया। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि सरकारी नौकरी के फर्जी दस्तावेज के आधार पर भी लोन दिए गए। कुछ लोगों ने शिक्षक होने का दावा करके लोन लिया, लेकिन बाद में जांच में पता चला कि वे सरकारी शिक्षक नहीं हैं। मामले से जुड़ी 96 फाइल बैंक से गायब होने की जानकारी मिलने पर हाई कोर्ट के निर्देश पर वर्ष 2011 से 2014 तक सभी रिकॉर्ड सीज करा दिए गए।

अनिल कुमार गौर ने बताया कि 30 अक्टूबर 2019 को रजिस्ट्रार ऑफ कॉपरेटिव सोसायटी ने आरबीआइ को दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक में हुई वित्तीय अनियमितता को लेकर पत्र लिखा है। एडिशनल रजिस्ट्रार रंजीत सिंह ने गंभीर आरोपों को देखते हुए वर्तमान सीईओ को हटाकर किसी अन्य उपयुक्त को नियुक्त करने को कहा है।

व्यापार मेला

हर परिस्थिति में दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम सीआरपीएफ के कमांडो से लोगों को मिल रहा रूबरू होने का मौका

दुश्मन के लिए कोबरा हैं सीआरपीएफ के कमांडो

किशन कुमार, नई दिल्ली

23 किलो वजन, कई दिन तक बिना कपड़े बदले व बिना खाना-पानी, बिना किसी मदद के न सिर्फ जंगल में रहना, बल्कि दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने की क्षमता रखने वाले केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के जवानों से रूबरू होने का मौका लोगों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में मिल रहा है। सीआरपीएफ के इन जवानों को कोबरा कमांडो के नाम से जाना जाता है। पहली बार इन कोबरा कमांडो को किसी सार्वजनिक स्थल पर लोगों के सामने अपने हथियार व उपकरणों के साथ आने का मौका मिला है। आइए जानते हैं क्या है कोबरा कमांडो की खासियत और किस तरह से करते हैं काम व कैसे रखते हैं हथियार।

कड़ा प्रशिक्षण प्राप्त करके बनते हैं कमांडो : जंगली क्षेत्रों व दुर्गम स्थितियों में रहकर देश की हिफाजत करने वाले ये कमांडो जब इस प्रकार सीधे रूप से लोगों से मुखातिब हो रहे हैं तो इन कमांडों का भी सीना अपने प्रति मिलने वाले प्रेम व लोगों में देशभक्ति की भावना को देखकर गर्व से चौड़ा हो रहा है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कमांडो सहायक कमांडेट राज ने बताया कि एक कमांडो यूं ही नहीं कमांडो बन जाता है। कड़े परीक्षण, धैर्य व मौत से जूझने का दम रखने वाला ही कमांडो बनकर निकलता है। उन्होंने बताया कि जब यहां से कमांडो वापस अपने अन्य कमांडो के बीच पहुंचता है तो यहां से सकारात्मक ऊर्जा लेकर पहुंचता है। उन्होंने बताया कि तीन से पांच कमांडो को यहां पर तैनात किया गया है। इसका उद्देश्य है कि एक कमांडो जब जंगली क्षेत्र में दुश्मन से निपटने के लिए जाता है तो वह किन-किन हथियारों व उपकरणों के साथ जंग के मैदान में उतरता है।

अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में सीआरपीएफ के मंडप में कोबरा कमांडो के साथ फोटो खिंचवाने के लिए लगी लोगों की भीड़। जागरण

वर्ष 2015 में आए थे देश के सामने

कोबरा कमांडो को वर्ष-2015 की गणतंत्र दिवस की परेड के मौके पर पहली बार राष्ट्र ने देखा था। इसका गठन करने से पहले यूएस मेरिन कमांडो की कार्यप्रणाली, ट्रेनिंग, व सर्जिकल स्ट्राइक समेत कई अन्य ऑपरेशन की जानकारी ली गई थी। तब से अब तक ये कमांडो अपने बल व साहस के लिए प्रख्यात हैं।

कमांडों की वर्दी, हथियारों व उपकरणों की बात करें तो इनका वजन ही करीब 23 किलो होता है, जिसमें एक्स 95 राइफल, चाकू, पानी की बोतल, खाद्य सामग्री, नाइट विजन चश्मा, जर्मन आर्मी का स्टेहेलम के नाम से मशहूर हेलमेट व जीपीएस शामिल है। उन्होंने बताया कि कोबरा कमांडो 23 किलो वजन के साथ 11 रातें जंगल में गुजारने का सामर्थ्य रखते हैं। यही कारण है कि इस बल को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बलों की सूची में शामिल किया गया है।

जंगली क्षेत्रों में एक मिनट के लिए भी जूते व कपड़े नहीं उतारते हैं कमांडो : सहायक कमांडेंट ने बताया कि चूंकि कमांडों को कुछ ऑपरेशन में कई दिनों तक जंगली क्षेत्र में रहना होता है। ऐसे में कमांडो को इस तरह से प्रशिक्षण दिया जाता है कि वे बिना किसी मदद व खाने के गुजारा कर लें। कमांडो पानी के लिए नदी व झरने का इस्तेमाल करता है तो वहीं खाने के लिए उन्हें जंगल में पाई जाने वाली कई वनस्पतियों की जानकारी दी जाती है। जंगल में रहने के दौरान कमांडो एक मिनट के लिए भी अपने जूते व वर्दी नहीं उतारता है।

लंबे समय से बनकर तैयार सर्जरी ब्लॉक नहीं हो पा रहा शुरू

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : एम्स में एक तरफ बेड की कमी से किडनी प्रत्यारोपण इन दिनों बंद है। वहीं दूसरी ओर सर्जरी ब्लॉक का भवन पिछले कई सालों से बनकर तैयार है, लेकिन एम्स प्रशासन इसे अब तक शुरू करने में नाकाम रहा है। यदि यह सर्जरी ब्लॉक में इलाज की सुविधा शुरू होती तो किडनी प्रत्यारोपण बंद करने की नौबत नहीं आती। अब पूरे मामले पर एम्स प्रशासन ने चुप्पी साध रखी है।

मरीजों की सुविधा के लिए फरवरी 2014 में एम्स में सर्जरी ब्लॉक, मातृ व शिशु ब्लॉक का निर्माण शुरू हुआ था। उसी दौरान सफदरजंग अस्पताल में इमरजेंसी ब्लॉक व सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक का निर्माण शुरू हुआ था। सफदरजंग अस्पताल में दोनों ब्लॉकों में पिछले साल इलाज की सुविधा शुरू हो चुकी है। एम्स के सर्जरी ब्लॉक वर्ष 2015 में ही बनकर तैयार होना था। इसमें 200 बेड का प्रावधान है। जिस वक्त इसका निर्माण शुरू हुआ था तब कहा गया था कि इसमें किडनी प्रत्यारोपण के लिए अलग से सुविधा होगी, लेकिन करीब दो साल से यह भवन बनकर तैयार है। फिर भी इसमें इलाज शुरू नहीं हुआ। इसके दो बड़े कारण बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि पहले इस ब्लॉक में मॉड्यूलर ऑपरेशन थियेटर नहीं बनाया गया था। इसलिए मॉड्यूलर ऑपरेशन थियेटर बनने

42.9 फीसद ग्रामीण घरों में लोग आज भी हैंडपंप का पानी पीते हैं, जबकि 40.9 फीसद शहरी घरों में पाइपलाइन का पानी पीने में इस्तेमाल होता है। सरकार देश में पेयजल व्यवस्था में सुधार की दिशा में काम कर रही है।

आंगनबाड़ियों के लिए स्मार्टफोन खरीदने में तत्परता दिखाएं राज्य

नई दिल्ली, प्रेट्र : नीति आयोग ने राज्य सरकारों से राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम के तहत आंगनबाड़ियों के लिए स्मार्टफोन और विकास मापने के उपकरणों की खरीद में तत्परता दिखाने को कहा है। इस समय आंगनबाड़ियों के पास 6.28 लाख स्मार्टफोन और 6.37 लाख विकास मापक उपकरण हैं। पोषण चुनौती संबंधी राष्ट्रीय परिषद की बैठक में नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा कि पांच राज्यों ने स्मार्टफोन की खरीद नहीं की है और 14 राज्यों को विकास मापक उपकरण खरीदना है।

कुमार ने कहा कि जब तक हम यह काम नहीं करते हैं तब तक हमें आंगनबाड़ी से जरूरी आंकड़े नहीं मिल सकते हैं। इतना ही नहीं खुद आंगबाड़ियों के लिए गंभीर कुपोषित बच्चों का पता लगाना मुश्किल होगा। स्मार्टफोन और विकास मापक उपकरण की खरीद राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम या पोषण अभियान के तहत की जा रही है। इसका मकसद बच्चों में अल्पपोषण, एनीमिया और जन्म के समय कम वजन में कमी लाना है।

अब नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों पर होगा जनजागरण

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- 26 नवंबर को संविधान दिवस के मौके पर संसद के केंद्रीय कक्ष से होगा कार्यक्रमों का आगाज
- मौलिक अधिकारों के बाद भारतीयों के दायित्वों के प्रचार-प्रसार पर सरकार देगी जोर
- संविधान को अंगीकार करने के 70साल पूरे होने पर देश के विभिन्न राज्यों में चलेंगे कार्यक्रम

भारतीय संविधान के 70 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सरकार अगले एक साल तक देश भर में कार्यक्रम आयोजित करेगी। 26 नवंबर को संविधान दिवस के मौके पर इन कार्यक्रमों की शुरुआत होगी जो अगले साल इसी तारीख तक चलेंगे। इस पूरे वर्ष में सरकार आम जनता के बीच उनके मौलिक कर्तव्यों के प्रति जागरूकता फैलाने पर जोर देगी। पूरे देश में लोगों को संविधान की प्रस्तावना की शपथ दिलाई जाएगी।

देश भर में पूरे साल चलने वाले कार्यक्रमों की शुरुआत संसद के केंद्रीय कक्ष से होगी। बताया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। साल भर चलने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा काफी विस्तृत रखी गई है। इसमें आम जनता से लेकर विभिन्न वर्गों के लोगों को जोड़ने का प्रस्ताव है।

रविवार को 'मन की बात' रेडियो कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान दिवस के अवसर पर साल भर चलने वाले कार्यक्रमों की चर्चा की। मोदी ने कहा, 'इस बार संविधान को अपनाने के 70 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस बार पार्लियामेंट में विशेष आयोजन होगा और फिर साल भर पूरे देश में अलग-अलग कार्यक्रम होंगे।' सूत्र बताते हैं कि संविधान दिवस के मौके पर साल भर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में सरकार का मुख्य जोर संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों के प्रति आम जनता में जागरूकता पैदा करने पर होगा। इस विषय पर कई तरह के कार्यक्रम आयोजित करने की योजना है। केंद्र और राज्यों के सभी विभागों से किसी एक मौलिक कर्तव्य की पहचान कर उसके इर्द-गिर्द कार्ययोजना तैयार करने को कहा है।

आम जनता के संदर्भ में संविधान की चर्चा अब तक नागरिकों के मौलिक अधिकारों तक ही सीमित रही है। लेकिन संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों की भी चर्चा है। सरकार मानती है कि इनका प्रसार भी आम जनता के बीच होना चाहिए। ताकि भारतीय नागरिक होने के नाते लोग अपने दायित्वों का निर्वाह बेहतर तरीके से कर सकें। देश भर में कार्यक्रमों के आयोजन को लेकर केंद्र ने सभी राज्यों को इस महीने की शुरुआत में ही सूचित कर दिया था। केंद्रीय विधि व न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सभी राज्यों के राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर इस संबंध में सूचित किया था।

प्रत्येक भारतीय के मूल कर्तव्य

भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को वर्ष 1976 में स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता वाली समिति की ओर से तैयार की गई रिपोर्ट के आधार पर 42वें संशोधन के जरिये संविधान में जोड़ा गया। कुल 11 मौलिक कर्तव्य इस प्रकार हैं

- संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें
- स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें।
- भारत की संप्रभुता, एकता व अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें।
- देश की रक्षा करें और बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें।
- भारत के सभी भागों में समरसता व समान भ्रातृत्व की भावना का विकास करें जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हो और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं।
- समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और संरक्षण करें।
- वन, झील, नदी, आदि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें। प्राणियों के प्रति दयाभाव रखें।
- वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवता, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें।
- सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें व हिंसा से दूर रहें।
- व्यक्तिगत व सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों के उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत् प्रयास करें। ताकि राष्ट्र निरंतर प्रगति व उपलब्धि की नवीन ऊंचाइयां छू सके।
- प्रत्येक अभिभावक का कर्तव्य है कि वे अपने छह से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा के लिए उपयुक्त माहौल तैयार करें।

संविधान दिवस पर हरियाणा व पंजाब में भी विशेष सत्र

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ : 26 नवंबर को संविधान दिवस पर हरियाणा और पंजाब ने विधानसभा का विशेष सत्र आहूत किया है। हरियाणा में इसके लिए खास तैयारी है। राज्य में पहला मौका होगा, जब विधानसभा को अंदर-बाहर से पूरी तरह सजाया जाएगा। विधायकों के लिए स्वागत द्वार बनेंगे। रात में विधानसभा रंगबिरंगी रोशनी से नहाई नजर आएगी। हरियाणा के सभी दलों के विधायक सदन में मौलिक अधिकारों व कर्तव्यों पर चर्चा करेंगे और बाहर आकर लोगों को इस बारे में जागरूक करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता के अनुसार विशेष सत्र में प्रश्नकाल, काम रोको प्रस्ताव और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नहीं आएंगे। वहीं, पंजाब में विधानसभा अध्यक्ष राणा केपी सिंह ने संविधान दिवस मनाने के लिए विशेष सत्र 26 नवंबर को दो बजे बुलाया है। एक माह में यह दूसरा मौका है जब पंजाब में विशेष सत्र बुलाया गया है। 6 नवंबर को श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व को समर्पित विशेष सत्र बुलाया गया था।

सांगली का शाही घराना स्विस बैंक खातों की जांच के दायरे में

आग्रह ▶ भारत ने स्विट्जरलैंड के कर विभाग से मंगाई शाही दंपती की जानकारी

अभिनेत्री भाग्यश्री के माता-पिता हैं राजा विजयसिंह पटवर्धन व महारानी रोहिणी

सांगली के शाही दंपती विजय सिंह पटवर्धन और महारानी रोहिणी। साथ में हैं उनकी पुत्री और भारतीय सिनेमा की अभिनेत्री भाग्यश्री (मध्य में)। साभार : स्टारसनफोल्डेड

नई दिल्ली, प्रेट्र : स्विस बैंकों में खाता रखने वाले भारतीयों की जांच के घेरे में एक शाही घराना भी आ चुका है। भारतीय जांच अधिकारी ने महाराष्ट्र में सांगली के पूर्व राजघराने के दो लोगों की जानकारी स्विट्जरलैंड के कर विभाग से मंगाई है। इस जांच में आधिकारिक सहयोग के लिए भारतीय अधिकारियों ने स्विट्जरलैंड सरकार से अनुरोध कर रखा है।

इस पर स्विट्जरलैंड के अधिकारी सार्वजनिक नोटिस जारी कर सांगली के पूर्व शाही घराने के राजा विजयसिंह माधवराव पटवर्धन और उनकी पत्नी व महारानी रोहिणी विजयसिंह पटवर्धन से इस मामले को देखने के लिए अपना प्रतिनिधि नियुक्त करने को कहा है। स्विट्जरलैंड के अधिकारियों ने दोनों से यह भी कहा है कि यदि उन्हें अपने खातों से संबंधित सूचना भारत को दिए जाने को लेकर कोई आपत्ति है तो वे उसे बकायदा दर्ज कराएं। शाही पटवर्धन दंपती की बड़ी बेटी भाग्यश्री फिल्मों में बतौर अभिनेत्री काम कर चुकी हैं। वर्ष 1989 में रिलीज उनकी पहली फिल्म 'मैंने प्यार किया' सुपरहिट रही थी। उनकी दो अन्य बेटियां मधुवंती और पूर्णिमा पटवर्धन भी एक समय में छोटे पर्दे और मिस इंडिया कांटेस्ट से जुड़ी रही हैं।

स्विट्जरलैंड सरकार ऐसे मामलों में विदेशी सरकारों को सूचनाएं देने से पहले खातेदारों को अपना पक्ष रखने का मौका देने के लिए राजपत्र में सार्वजनिक नोटिस जारी करती है। स्विट्जरलैंड के हालिया संघीय राजपत्र में प्रकाशित दो अलग अधिसूचनाओं में पटवर्धन दंपती को 10 दिनों के भीतर अपना पक्ष रखने वाले व्यक्ति को नामित करने को कहा गया है। हालांकि इन अधिसूचनाओं में दंपती के नाम तथा उनकी जन्मतिथियां (विजय पटवर्धन की 24 अगस्त, 1942 और पत्नी रोहिणी की 27 अक्टूबर, 1950) छोड़ कोई अन्य जानकारी नहीं दी गई है।

इस मामले में पक्ष जानने के लिए पटवर्धन परिवार से बार-बार संपर्क किए जाने के बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। शाही दंपती मंगलमूर्ति इनवेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में निदेशक हैं। इस कंपनी का पता मुंबई रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी) में मुंबई स्थित 'सांगली विला' के नाम से दर्ज है। इसमें इनके आधिकारिक ईमेल पर भेजे गए सवालों का भी अब तक कोई जवाब नहीं मिला है। कंपनी की आखिरी बैलेंस शीट 31 मार्च, 2019 को जारी की गई थी।

30 साल पहले पीएम को भी भाया था 'रं' समाज का आतिथ्य

वर्ष 1990 में कैलास मानसरोवर यात्रा के दौरान पिथौरागढ़ जिले के धारचूला में प्रवास के समय काली नदी के तट पर नरेंद्र मोदी। साभार : राज्य सूचना आयुक्त सीएस नपलच्याल

गणेश जोशी, हल्द्वानी

▶ कैलास मानसरोवर की यात्रा के दौरान 1990 में नरेंद्र मोदी पहुंचे थे धारचूला

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 'रं' समाज की याद यूं ही नहीं आ गई। उन्होंने 1990 में धारचूला में प्रवास किया था। उस दौरान उन्हें रं समाज के लोगों के आतिथ्य ने काफी प्रभावित किया था। वह मातृभाषा के प्रति उनके लगाव से बेहद प्रभावित हुए थे। रविवार को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में रं समाज की बोली, उसके संरक्षण के प्रयास और उनकी संस्कृति का जिक्र किया तो समाज में खुशी की लहर दौड़ गई। समाज के सरोकारों से जुड़े राज्य सूचना आयुक्त सीएस नपलच्याल ने उस दौरे की यादें साझा की।

सीएस नपलच्याल बताते हैं कि तीन महीने पहले देहरादून में रं समाज का भव्य आयोजन हुआ था। इस आयोजन के दौरान तमाम आलेख भी प्रकाशित हुए थे, जिसमें हमारे समाज का विस्तृत वर्णन था। लगता है कि प्रधानमंत्री को इस लेख पर ही वर्ष 1990 में अपनी यात्रा का संस्मरण हो गया। जैसा कि वह मन की बात में भी जिक्र करते हैं। तब वह कैलास मानसरोवर की यात्रा पर थे। नेपाल से लौटते समय धारचूला में ठहरे थे। उन्होंने स्थानीय लोगों से खूब बातें की। तस्वीरें भी खिंचवाई थी। तब भी उन्होंने समुदाय की संस्कृति, मातृभाषा और परंपराओं की तारीफ की थी। रविवार को जब पीएम ने विलुप्ति होने को पहुंची रंग्लो बोली पर मन की बात में चर्चा की तो हमारे समुदाय के लोगों को बहुत खुशी हुई। इससे युवा पीढ़ी को भी अपनी संस्कृति को सहेजने के लिए प्रेरणा मिलेगी। हमारी बोली की कोई लिपि नहीं है। फिर भी हम वाट्सएप ग्रुप के जरिये देवनागिरी में ही संवाद करते हैं। अल्मोड़ा के जिला आयुर्वेदिक अधिकारी डॉ. केएस नपलच्याल का कहना है, हमने अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हर स्तर पर प्रयास करते हैं। बच्चे भी अपनी बोली का इस्तेमाल करें। इस तरह का माहौल बनाते हैं।

राजनीति में आने की कभी इच्छा नहीं थी : मोदी

प्रथम पृष्ठ से आगे

प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी राजनीति में आने की कभी इच्छा नहीं थी। वह तो इसके बारे में कभी सोचते तक नहीं थे। लेकिन अब जब वो इसका हिस्सा बन गए हैं तो लोगों के लिए बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री से उनके रेडियो कार्यक्रम में नेशनल कैडेट कोर (एनसीसी) के एक कैडेट ने पूछा कि अगर वह नेता नहीं होते क्या होते। मोदी ने कहा, 'अब यह बहुत जटिल सवाल है, क्योंकि हर बच्चा अपने जीवन में विभिन्न चरणों से गुजरता है। कभी वह कुछ बनना चाहता है तो कभी कुछ। लेकिन यह सच है कि मेरी कभी राजनीति में आने की इच्छा नहीं थी और न ही कभी मैंने इसके बारे में सोचा था।'

प्रधानमंत्री ने कहा, 'अब, मैं जहां भी हूं, मुझे पूरी तरह से जीवन जीना चाहिए और मुझे पूरे दिल से अपने देश के लिए काम करना चाहिए ... मैंने अब केवल इस उद्देश्य के लिए खुद को समर्पित किया है।'

प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि स्कूल के दिनों में वह भी एनसीसी के कैडेट रह चुके थे। वह आज भी खुद को एक कैडेट समझते हैं। वह अनुशासित कैडेट थे और उन्हें कभी दंड नहीं मिला था।

गूगल के चलते पढ़ने की आदत कम हुई : हरियाणा के रोहतक के छात्र अखिल ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि क्या व्यस्तता के बावजूद उन्हें किताबें पढ़ने और टीवी देखने का मौका मिल जाता है? प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्हें पढ़ना हमेशा से अच्छा लगता था। वह बहुत पुस्तकें पढ़ते थे। लेकिन गूगल ने उनकी पढ़ने की आदत को बहुत नुकसान पहुंचाया है। गूगल संदर्भ तलाशने का शॉर्टकट रास्ता बन गया है। लोग समझते हैं कि गूगल पर सबकुछ उपलब्ध है। किसी भी विषय में संदर्भ ढूंढना हो तो लोग तुरंत गूगल का सहारा लेते हैं। बहुत हद तक वह भी ऐसा ही करते हैं। उन्होंने कहा कि फिल्मों में उनकी कभी भी रुचि नहीं थी। पहले वह टेलीविजन खासकर डिस्कवरी चैनल कभी-कभी देख लेते थे।

यह भी कहा प्रधानमंत्री ने

- सात दिसंबर को सशस्त्र बल झंडा दिवस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। साथ ही सशस्त्र बलों के जवानों के कल्याण के लिए योगदान करें
- समुद्र तल से प्लास्टिक कचरा निकालने वाले स्कूबा डाइवरों का काम प्रशंसनीय। आम लोगों की मदद से ही प्लास्टिक मुक्त भारत का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है
- 26 नवंबर संविधान दिवस है और यह हर देशवासी के लिए विशेष होना चाहिए। इससे हम सभी में संविधान के आदर्शों और मूल्यों के सम्मान की भावना मजबूत होती है
- हर व्यक्ति को कम से कम अपनी मातृ भाषा की जानकारी होनी चाहिए। मातृ भाषा की जानकारी के बिना प्रगति संभव नहीं है

स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास वन्यजीवों की मौत की जांच कराने के निर्देश

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण (सीजेडए) ने गुजरात सरकार से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी (सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा) के पास वन्यजीव मानकों के उल्लंघन के चलते जंगल सफारी प्रोजेक्ट के लिए लाए गए जानवरों की मौत की जांच कराकर विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है। अधिकारिक दस्तावेजों में यह जानकारी दी गई है।

सामाजिक कार्यकर्ता अजय दूबे की शिकायत पर केंद्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण ने यह निर्देश जारी किया है। दूबे ने कहा है कि कई वन्यजीवों की मौत हो गई है। उनका यह भी दावा है कि इन जानवरों को अवैध तरीके से दूसरे देशों से लाया गया था।

दूबे की शिकायत पर सीजेडए ने गुजरात के मुख्य वन्यजीव वार्डेन को मामले की जांच कराने और विस्तृत रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण एक संवैधानिक संस्था है जो पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत आती है। इसका उद्देश्य देश में जैव विविधता को मजबूत करना है। इसके लिए सरकार की ओर से संस्था को वित्त मुहैया कराया जाता है।

आइएएस अफसर राजीव कुमार को जबरन रिटायर करने की तैयारी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

▶ नोएडा प्लॉट आवंटन घोटाले में काट चुके हैं जेल की सजा

भ्रष्टाचार पर जीरो टालरेंस नीति के तहत योगी सरकार 1983 बैच के आइएएस अधिकारी राजीव कुमार (द्वितीय) को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने की तैयारी में है। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नोएडा प्लाट आवंटन घोटाले में पूर्व मुख्य सचिव नीरा यादव के साथ जेल की सजा काट चुके राजीव कुमार 2016 से निलंबित हैं। उनका सेवाकाल 30 जून 2021 तक है। केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर तैनात 1982 बैंच के अविनाश कुमार श्रीवास्ताव के बाद वह उप्र के दूसरे सबसे वरिष्ठ आइएएस अधिकारी हैं। यदि उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई तो यह प्रदेश में किसी आइएएस अफसर को जबरन रिटायर करने का पहला मामला होगा।

राजीव कुमार को सरकार ने 31 अक्टूबर को नोटिस देकर 15 दिनों में जवाब मांगा था। कुमार ने नोटिस का जवाब दे दिया है जिसका परीक्षण किया जा रहा है। यदि सरकार जवाब से संतुष्ट नहीं हुई तो वह केंद्र सरकार के कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग को उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने का प्रस्ताव भेजेगी। राज्य सरकार के प्रस्ताव से संतुष्ट होने पर केंद्र सरकार संघ लोक सेवा आयोग से इस आशय की सहमति लेगी। इसके बाद केंद्र उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने के फैसले के बारे में राज्य सरकार को सूचित करेगा।

यह है मामला : राजीव कुमार 1994-95 के दौरान नोएडा अथारिटी में उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी थे। उन पर आरोप था कि तैनाती के दौरान उन्हें सेक्टर-51 में प्लॉट आवंटित हुआ। बाद में उन्हें सेक्टर 44 में प्लॉट दिया गया। फिर इसे भी बदलकर उन्हें सेक्टर 14ए में प्लॉट आवंटित किया गया, जबकि नोएडा अथारिटी के नियमों के तहत, प्लॉट की अदला-बदली सिर्फ एक बार की जा सकती थी। पूर्व मुख्य सचिव और नोएडा अथारिटी की तत्कालीन अध्यक्ष व मुख्य कार्यपालक अधिकारी नीरा यादव भी प्लॉट आवंटन घोटाले में भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी थीं और उन्हें भी जेल की सजा काटनी पड़ी थी। हालांकि वह सेवा से रिटायर हो चुकी हैं।

सीबीआइ कोर्ट ने सुनाई थी तीन साल की सजा : सीबीआइ कोर्ट ने नोएडा प्लॉट आवंटन घोटाले में राजीव कुमार को दोषी मानते हुए 20 नवंबर 2012 को तीन साल की सजा सुनाई थी। सीबीआइ कोर्ट के आदेश के खिलाफ वह इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचे। हाई कोर्ट ने 24 फरवरी 2016 को अपील खारिज करते हुए राजीव को सरेंडर करने का आदेश दिया। सरेंडर न करने पर कोर्ट को मार्च 2016 में उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करना पड़ा। अप्रैल 2016 में राजीव ने गाजियाबाद की सीबीआइ कोर्ट में सरेंडर किया था, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था।

सपा सरकार में था खासा रसूख : अखिलेश सरकार में राजीव कुमार प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक के पद पर तैनात रहे। उनके रसूख का अंदाज इसी से लगाया जा सकता है कि नवंबर 2012 में सीबीआइ कोर्ट की ओर से सजा सुनाए जाने के बाद भी सरकार ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। जेल जाने के बाद भी उन्हें निलंबित नहीं किया गया था।

बोडो उग्रवादी संगठन एनडीएफबी पर पाबंदी पांच साल के लिए बढ़ी

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्र ने असम के बोडो उग्रवादी संगठन एनडीएफबी पर लगे प्रतिबंध को पांच वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। केंद्र का कहना है कि संगठन लगातार हिंसक गतिविधियों के साथ-साथ रंगदारी मांगने जैसी आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहा है। यही नहीं, वह भारत विरोधी ताकतों के साथ मिलकर देश की संप्रभुता के लिए खतरा भी पैदा कर रहा है।

गृह मंत्रालय ने जारी अधिसूचना में कहा है कि 'नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एनडीएफबी) अलग बोडोलैंड बनाने की मंशा से भारत की संप्रभुता व क्षेत्रीय अखंडता को बाधित करने के लिए अवैध व हिंसक गतिविधियों में लिप्त रहा है।' 'गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम-1967 की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार केंद्र सरकार एनडीएफबी को उसके सभी समूहों, गुटों और अग्रिम संगठनों के साथ गैरकानूनी संगठन घोषित करती है।' गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और यह पांच साल तक जारी रहेगा।

प्रियंका के फैसलों से असहमति जताने पर दस कांग्रेसी निष्कासित

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

▶ निकाले गए कांग्रेसियों में पूर्व मंत्री, सांसद और विधायक भी
▶ प्राथमिक सदस्यता से छह वर्ष के लिए किए गए बाहर

पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के फैसलों पर असंतोष जताना उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेसियों को महंगा पड़ गया। हाईकमान के निर्देश पर नोटिस देने के बाद अनुशासन समिति ने ग्यारह में से दस कांग्रेसियों को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से छह वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया है।

संगठन में युवाओं को तरजीह दिए जाने से वरिष्ठ कांग्रेसियों में असंतोष है। इनमें से करीब डेढ़ दर्जन पार्टीजनों ने पिछले दिनों पूर्व सांसद संतोष सिंह के आवास पर बैठक कर अपनी उपेक्षा पर नाराजगी जताई। साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलकर सुझाव देने का निर्णय लिया। इसके बाद प्रियंका वाड्रा के निर्देश पर 21 नवंबर को अनुशासन समिति ने बैठक में शामिल ग्यारह सदस्यों को नोटिस देकर चौबीस घंटे में स्पष्टीकरण मांगा था।

रविवार को अनुशासन समिति ने इनमें से दस वरिष्ठ कांग्रेसियों को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से छह वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया। इनमें सिर्फ पूर्व विधायक हाफिज मोहम्मद उमर पर कार्रवाई नहीं की गई है। आदेश में कहा गया है कि आप लोगों द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्णयों पर अनवरत, अनावश्यक रूप से सार्वजनिक तौर पर बैठक कर विरोध किया जा रहा है। इससे पार्टी की छवि धूमिल हुई है। आपका कृत्य घोर अनुशासनहीनता की परिधि में आता है। साथ ही कहा गया है कि अनुशासन समिति आप के जवाब से संतुष्ट नहीं है।

पार्टी से निकाले गए दिग्गज: पार्टी के पूर्व सांसद संतोष सिंह, पूर्व एमएलसी सिराज मेंहदी, पूर्व गृह मंत्री रामकृष्ण द्विवेदी, पूर्व मंत्री सत्यदेव त्रिपाठी, पूर्व विधायक भूधर नारायण मिश्र, नेकचंद पांडेय, विनोद चौधरी, युवक कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वयंप्रकाश गोस्वामी, एआइसीसी सदस्य राजेंद्र सिंह सोलंकी और गोरखपुर के पूर्व जिलाध्यक्ष संजीव सिंह।

योजना कामयाब

देश के छह जिलों में चलाए जा रहे पायलट प्रोजेक्ट को विस्तार देने पर विचार कर रही सरकार, जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम में कारगर साबित हो रही हैं आयुर्वेदिक दवाएं

सफल हो रहा आयुर्वेद और एलोपैथी का समेकित इलाज

नीलू रंजन, नई दिल्ली

डायबिटीज, कैंसर, पक्षाघात, हृदय व सांस से संबंधित बीमारियों के इलाज में एलोपैथी और आयुर्वेदिक दवाओं के एक साथ प्रयोग का पायलट प्रोजेक्ट सफल हुआ है। सरकार अब इसके विस्तार पर विचार कर रही है। वर्ष 2017 में व्यापक रूप से शुरू की गई इस योजना के तहत अब तक लगभग 10 लाख मरीजों की जांच की चुकी है। इनमें लगभग 93 हजार मरीजों को लंबे समय तक उपचार के लिए चुना गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि देश में होने वाली कुल मौतों में से 60 फीसद के लिए यही बीमारियां जिम्मेदार होती हैं।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कैंसर, डायबिटीज, हृदय व सांस से संबंधित बीमारियों व पक्षाघात (स्ट्रॉक) पर नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम एनपीसीडीसीएस की औपचारिक शुरुआत वर्ष 2010 में की गई थी और इसे पूरे देश में चलाया भी जा रहा है, लेकिन वर्ष 2017 में पहली बार स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय और आयुष मंत्रालय के बीच इस योजना में आयुर्वेद को शामिल करने पर समझौता हुआ। इसके बाद बिहार के गया, राजस्थान के भीलवाड़ा, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी समेत छह जिलों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए गए। जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों के समग्र इलाज में आयुर्वेद को शामिल किए जाने को लोगों ने काफी पसंद किया। गंभीर मरीजों को इसका फायदा भी मिला। अब सरकार ने इस योजना के पायलट प्रोजेक्ट के विस्तार का फैसला किया है।

पिछले हफ्ते आयुष मंत्री श्रीपद नाइक ने राज्यसभा में बताया था कि डायबिटीज, कैंसर, किडनी व दिल की बीमारियों के लिए प्रामाणिक आयुर्वेदिक दवाएं विकसित की गई हैं, जो काफी प्रभावी साबित हो रही हैं। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआइआर) के तहत आने वाले एनबीआरआइ और सीआइएएमपी ने बीजीआर-34 नाम की आयुर्वेदिक दवा विकसित की है। यह डायबिटीज के इलाज में कारगर साबित हो रही है। इसे टाइप-2 डायबिटीज के इलाज में वैज्ञानिक रूप से प्रामाणिक पाया गया है। वहीं, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस (सीसीआरएएस) ने आयुर्वेदिक फार्मूले से आयुष-क्यूओएल-2सी नामक दवा बनाई है। एलोपैथी के साथ इस आयुर्वेदिक दवा का इस्तेमाल एम्स, दिल्ली और जॉन्स मेडिकल कॉलेज, बेंगलुरु में स्तन व सर्वाइकल कैंसर के मरीजों के जीवन को बेहतर बनाने में किया जा रहा है।

पुरातन चिकित्सा पद्धति सोवा रिग्पा पर भारत और चीन में ठनी

नई दिल्ली, प्रेट्र : पुरातन व पारंपरिक चिकित्सा पद्धति सोवा रिग्पा की विरासत पर भारत व चीन में ठन गई है। भारत ने वैश्विक पटल पर जब इस चिकित्सा पद्धति को अपनी 'अमूर्त सांस्कृतिक विरासत' बताया तो चीन ने आपत्ति दर्ज करा दी।

एक अधिकारी ने कहा, भारत ने यूनेस्को से सोवा रिग्पा को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में दर्ज करने का आग्रह किया है। चीन ने इस पर खुद का अधिकार बताते हुए आपत्ति दर्ज करा दी है।' उन्होंने कहा, भारतीय प्रतिनिधि मंडल पूरी मजबूती के साथ देश के आवेदन को आयुष मंत्रालय की तरफ से प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर आगे बढ़ा रहा है। आयुष मंत्रालय इस मुद्दे पर विदेश मंत्रालय के साथ बेहतर सामंजस्य बैठाते हुए काम कर रहा है। ज्ञात हो, मोदी सरकार पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए प्रयत्नशील है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 20 नवंबर को स्वायत्तशासी संगठन के तौर पर राष्ट्रीय सोवा रिग्पा संस्थान (एनआइएसआर) की स्थापना को मंजूरी दी है। इसके लिए 47.25 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। लद्दाख को जम्मू कश्मीर से हटाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद शायद उसके हित में यह पहला फैसला लिया गया है। एनआइएसआर में न सिर्फ भारत, बल्कि विदेश के छात्र भी सोवा रिग्पा की पढ़ाई कर सकेंगे।

आयुर्वेद के करीब व हिमालयी प्रदेशों में लोकप्रिय है यह पद्धति : सोवा रिग्पा एक पुरातन पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है, जो आयुर्वेद के काफी करीब है। माना जाता है कि सोवा रिग्पा की मूल पाठ्य पुस्तक रग्युड बजी है, जिसे खुद महात्मा बुद्ध ने पढ़ाया था। यह बुद्ध दर्शन से काफी गहराई से जुड़ी हुई है। भारत के सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में यह काफी लोकप्रिय है।

कह के रहेंगे — माधव जोशी

बहुमत सिद्ध करने के लिए हर मोर्चे पर तैयार भाजपा

अन्य दलों के विधायकों को अनुपस्थित रहने के लिए राजी कर बहुमत का आंकड़ा नीचे लाने का हो सकता है प्रयास

ओमप्रकाश तिवारी, मुंबई

अपने मुख्यमंत्री एवं 'सहयोगी दल' के उप मुख्यमंत्री को शपथ दिलवा चुकी भाजपा की ओर से दावा किया गया है कि सदन में बहुमत सिद्ध करने के लिए उसकी रणनीति तैयार है। करीब एक माह तक चुप बैठी भाजपा ने अब इस मोर्चे पर अपने सारे प्रयास एक साथ शुरू कर दिए हैं। वहीं, कांग्रेस-राकांपा-शिवसेना की तरफ से मोर्चा संभाल रहे महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे अनुभवी खिलाड़ी शरद पवार लगातार सदन में भाजपा के बहुमत न सिद्ध कर पाने और अपनी सरकार बनने का दावा कर रहे हैं।

महाराष्ट्र विधानसभा के 288 सदस्यों वाले सदन में बहुमत सिद्ध करने के लिए भाजपा को 145 सदस्यों की जरूरत है। भाजपा के दावे के अनुसार उसके पास निर्दलीय एवं छोटे सहयोगी दलों को मिलाकर कुल संख्या 119 है। शेष 26 विधायक जुटाने के लिए या तो उसे किसी बड़े समूह का समर्थन लेना होगा अथवा सदन से कुछ विधायकों को अनुपस्थित करवाकर बहुमत सिद्ध करने के लिए आवश्यक विधायकों की संख्या को नीचे लाना होगा। ऐसे में फिलहाल भाजपा को बहुमत सिद्ध करने के लिए तीन तस्वीरें बनती दिख रही हैं।

मुंबई में रविवार को भाजपा विधायक दल की बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस, पार्टी के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल व अन्य। एएनआइ

पहली तस्वीर : दो तिहाई विधायक पक्ष में ला पाते हैं या नहीं

भाजपा के साथ सरकार बनाते समय अजीत ने राज्यपाल को अपनी पार्टी के सभी 54 विधायकों द्वारा समर्थन का पत्र राज्यपाल को दे रखा है, लेकिन इसके बाद के घटनाक्रम को देखते हुए यह कहना मुश्किल है कि राकांपा के कितने विधायक उनके खेमे में हैं और कितने शरद पवार के। शरद पवार के सीधा मोर्चा संभाल लेने के बाद देखना होगा कि बहुमत के समय अजीत राकांपा की कुल विधायक संख्या 54 की दो तिहाई संख्या यानी 36 विधायकों को भाजपा के पक्ष में ला पाते हैं या नहीं। अजीत पवार के पास दूसरा रास्ता अपने समर्थक 12-15 विधायकों को सदन में अनुपस्थित रहने के लिए राजी करना हो सकता है।

दूसरी तस्वीर : अन्य दलों के विधायकों पर भाजपा की रहेगी नजर

माना जा रहा है कि भाजपा ने अब अचानक देवेंद्र फड़नवीस को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने का फैसला अकेले अजीत पवार के दम पर तो नहीं लिया होगा। भाजपा के पास दूसरा रास्ता अन्य दलों से ऐसे विधायकों को राजी करना होगा, जो सदन में बहुमत सिद्ध करने के समय अपने दल के व्हिप का उल्लंघन कर सदन से बाहर चले जाएं। चार प्रमुख दलों के अलावा चुनकर आए 29 अन्य विधायकों में से 14 के समर्थन का दावा भाजपा पहले से करती आ रही है। सरकार बनने की सुनिश्चितता पर इसमें पांच-छह की संख्या और बढ़ सकती है। माना जा रहा है कि बहुमत का आंकड़ा नीचे लाने के लिए भाजपा ने अपने चार नेताओं को सक्रिय कर दिया है। इनमें कांग्रेस छोड़ भाजपा में आए राधाकृष्ण विखे पाटिल एवं नारायण राणे और राकांपा से आए बबनराव पाचपुते एवं गणेश नाइक शामिल हैं। हालांकि, इस स्थिति में पार्टी के व्हिप के उल्लंघन के कारण सदस्यता गंवाने वाले विधायकों को जिताना भाजपा के लिए चुनौती बन सकती है। शरद पवार शनिवार को ही कह चुके हैं कि बगावत करने वाले विधायकों के विरुद्ध कांग्रेस, राकांपा और शिवसेना मिलकर प्रत्याशी खड़ा करेंगी।

तीसरी तस्वीर : कांग्रेस भी हो सकती है सॉफ्ट टारगेट

भाजपा के लिए एक 'सॉफ्ट टारगेट' कांग्रेस भी हो सकती है। इस समय 44 सदस्यों के साथ वह सबसे छोटा दल है। आश्चर्य की बात यह भी है कि कांग्रेस के विधायक अभी तक अपना कोई नेता भी नहीं चुन पाए हैं (या किसी रणनीति के तहत नहीं चुना है)। कांग्रेस विधायकों से समूह के रूप में या अलग-अलग संपर्क किया जा सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने माना है कि भाजपा ने उन सभी होटलों में कमरे बुक कर रखे हैं जहां कांग्रेस, राकांपा और शिवसेना के विधायक ठहरे हैं। इंटरकॉम पर उनसे संपर्क की कोशिश भी की जा रही है।

दिखेगा असर : संसद में बढ़ सकती है सियासी तल्खी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▸ हाथ आए नए मुद्दे पर सरकार को घेरने का मौका नहीं छोड़ेंगी कांग्रेस, राकांपा और शिवसेना

महाराष्ट्र के राजनीतिक घटनाक्रम का असर सोमवार को संसद के चल रहे मौजूदा सत्र में भी दिख सकता है। जहां एक-आध मामलों को छोड़ दें तो लगभग शांत चल रहे संसद के दोनों सदन फिर से गर्मा सकते हैं। इसके आसार इसलिए भी हैं, क्योंकि इस मामले में कांग्रेस, राकांपा और शिवसेना एक साथ खड़ी हैं। वैसे भी महाराष्ट्र में जिस तरह से देवेंद्र फड़नवीस सरकार बनी है, उस पूरे घटनाक्रम से तीनों ही पार्टियां को भारी झटका लगा है। ऐसे में वह सरकार को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ेंगी। फिलहाल वे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुकी हैं। ऐसे में वे केंद्र सरकार को घेरने के लिए संसद में भी इस मामले को तूल दे सकती हैं।

कांग्रेस, राकांपा और शिवसेना जिस तरह से महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर केंद्र सरकार और राज्यपाल की भूमिका पर सवाल खड़े कर रही हैं उसे देखते हुए उन्हें इस मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस का भी साथ मिल सकता है। बता दें कि तृणमूल कांग्रेस पहले से ही पश्चिम बंगाल में राज्यपाल की भूमिका को लेकर केंद्र का घेराव करने में जुटी है। हालांकि, ऐसा नहीं है कि राज्यपालों की भूमिका पर कोई पहली बार सवाल उठ रहे हैं। केंद्र की सरकारों पर शुरू से ही इस पद के दुरुपयोग का मुद्दा उठता रहा है। यही वजह थी कि केंद्र और राज्य संबंधों को लेकर जस्टिस आरएस सरकारिया की अगुआई में 1983 में गठित किए गए आयोग ने राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र के बजाय राज्यों की सलाह पर करने की बात कही थी। इसका मकसद साफ था कि राज्य और केंद्र के बीच पैदा होने वाले टकराव को कम किया जाए। यह बात अलग है कि इस अधिकार से केंद्र की सरकारें खुद को अलग नहीं कर पाईं। ऐसे में यदि विपक्ष राज्यपालों की भूमिका को मुद्दा बनाती है, तो एक बार फिर से उनकी भूमिका लेकर नए सिरे से बहस शुरु हो सकती है। सूत्रों की मानें तो कांग्रेस या दूसरे विपक्षी दलों के पास वैसे भी इस बार संसद सत्र के दौरान सरकार को घेरने के लिए कोई बड़ा राजनीतिक मुद्दा नहीं था। ऐसे में वे महाराष्ट्र को लेकर केंद्र सरकार और राज्यपाल, दोनों पर निशाना साध सकेंगी। हालांकि, संसद में विपक्ष का पैनापन सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी निर्भर करेगा।

अहम होगा विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव

राज्य ब्यूरो, मुंबई: मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके देवेंद्र फड़नवीस के लिए जितना जरूरी सदन में अपनी सरकार का बहुमत सिद्ध करना है, उससे ज्यादा जरूरी विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव में पार पाना है। चूंकि बहुमत की बानगी तो अध्यक्ष पद के चुनाव के समय ही मिल जाएगी।

सदन में नवनिर्वाचित विधायकों के जाने के बाद उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। यह शपथ उन्हें अस्थाई विधानसभा अध्यक्ष (प्रोटेम स्पीकर) दिलवाता है। इसका चयन सदन में वरिष्ठता क्रम के अनुसार किया जाता है। यह किसी भी दल का हो सकता है, लेकिन मान्यता यह है कि वह किसी ऐसे दल का हो, जिसकी तरफ से पक्षपात की उम्मीद न की जा सके क्योंकि पूर्णकालिक अध्यक्ष का चुनाव भी उसकी अध्यक्षता में ही होता है। यह जिम्मेदारी 2014 में सिर्फ एक सदस्यीय दल माकपा के विधायक जीवा पांडु गावित ने निभाई थी।

इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव की बारी आती है। सदन में सत्ताधारी दल की पहली परीक्षा इसी चुनाव में हो जाती है। इस बार भी ऐसा ही होगा। यदि भाजपा अपने विधानसभा अध्यक्ष को चुनवा कर लाने में सफल होती है, तो उसके बहुमत पाने के संकेत उसी समय मिल जाएंगे। अन्यथा संभव है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस बहुमत सिद्ध करने की नौबत आने से पहले ही कुर्सी छोड़ दें।

अदालत में भी महाराष्ट्र पर घमासान

सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी ▸ यहां मांग की कोई सीमा नहीं, कोई भी कुछ भी मांग सकता है

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

महाराष्ट्र में दो दिन से चल रहे राजनीतिक घमासान की धमक रविवार को सुप्रीम कोर्ट में भी सुनाई दी। राज्यपाल के फैसले के खिलाफ विपक्षी दलों की संयुक्त याचिका पर सुनवाई के दौरान दोनों तरफ के वकीलों में गरमागरम बहस हुई। याचिकाकर्ताओं की तरफ से राज्यपाल की कार्यवाही पर सवाल उठाए गए। वहीं, सरकार की तरफ से कहा गया कि राज्यपाल की कार्यवाही की चुनौती नहीं दी जा सकती। गरमागरम बहस के बीच कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की कि यहां मांग की कोई सीमा नहीं है। यहां कोई भी कुछ भी मांग कर सकता है।

शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने महाराष्ट्र के राज्यपाल की कार्यवाही पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ये सही है कि सरकार गठन के लिए आमंत्रित करने में राज्यपाल का विवेकाधिकार रहता है, लेकिन सवाल यह उठता है कि किस वक्त राज्यपाल ने संस्तुति की और किस समय कैबिनेट ने उस पर विचार किया और कैसे राष्ट्रपति शासन हटा। राज्यपाल ने फड़नवीस को सरकार बनाने का कब न्योता दिया और फड़नवीस ने सरकार बनाने का जो दावा किया उसकी राज्यपाल ने कब जांच की। ये सारी चीजें पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाती हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है जैसे कि राज्यपाल किसी के निर्देश पर चल रहे हों।

राज्यपाल की कार्रवाई लोकतंत्र की हत्या के समान: सिंघवी ने कहा कि जो हुआ वह एक तरह से लोकतंत्र की हत्या करने के समान है। राकांपा के 54 में से 41 विधायकों ने हस्ताक्षर करके कहा है कि वे पार्टी के साथ हैं। उन्होंने सदन में बहुमत साबित करने के बारे में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्व में झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक के मामलों का हवाला देते हुए कहा कि इस मामले में भी कोर्ट 24 घंटे के अंदर बहुमत साबित करने का आदेश दे।

राज्यपाल की कार्रवाई को चुनौती नहीं: कुछ भाजपा विधायकों और दो निर्दलीय विधायकों की ओर से पेश अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि अनुच्छेद 361 के तहत राज्यपाल और राष्ट्रपति किसी के प्रति जवाबदेह नहीं हैं। यह भी कानून का तय सिद्धांत है कि प्रधानमंत्री नियुक्त करने में राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री नियुक्त करने में राज्यपाल अपने विवेकाधिकार से काम करते हैं। उस समय मंत्रिपरिषद नहीं होती और वे किसी की सलाह से बंधे नहीं होते। उन्होंने कहा कि याचिका में देवेंद्र फड़नवीस को सरकार बनाने के निमंत्रण देने के राज्यपाल के आदेश को रद करने और राज्यपाल को गठबंधन को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने की मांग की गई है, जो सुनवाई करने लायक नहीं है।

कल कोई पीएम बनाने की मांग कर सकता है: मुकुल रोहतगी ने राज्यपाल को निर्देश देने की मांग पर आपत्ति उठाई और कहा कि यह मांग कैसे की जा सकती है। कोर्ट राज्यपाल को किसी दल को सरकार बनाने के लिए निमंत्रण देने का आदेश कैसे दे सकता है। इस पर पीठ के न्यायाधीश एनवी रमना ने कहा कि स्काई इज द लिमिट, पर यहां मांग की कोई सीमा नहीं है। कल को कोई याचिका दाखिल कर यह भी कह सकता है कि उसे प्रधानमंत्री नियुक्त करने का आदेश दे दो।

▸ सिब्बल और सिंघवी ने राज्यपाल के फैसले पर उठाए सवाल

▸ रोहतगी ने कहा, राज्यपाल की कार्यवाही को नहीं दी जा सकती चुनौती

महाराष्ट्र में राज्यपाल के फैसले के खिलाफ विपक्षी दलों की संयुक्त याचिका पर रविवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हुई। फाइल फोटो

दो साल में सारे मुकदमे निपटाने का आदेश हो सकता है?

मुकुल रोहतगी ने कोर्ट द्वारा विधानसभा को आदेश देने की मांग का विरोध करते हुए कहा कि संविधान में सबके काम बंटे हुए हैं। कोई किसी दूसरे के काम में दखल नहीं देता। कोर्ट को भी विधानसभा को निर्देश नहीं देना चाहिए। क्या विधानसभा आदेश दे सकती है कि सुप्रीम कोर्ट दो साल में सारे मुकदमे निपटा दे। इस पर पीठ ने कहा कि ऐसी भी दलीलें हम सुनते हैं।

राजनीतिक दल नहीं दाखिल कर सकते जनहित याचिका

मुकुल रोहतगी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अनुच्छेद 32 के तहत दाखिल की गई याचिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि राजनीतिक दल जनहित याचिका कैसे दाखिल कर सकते हैं। इस याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकती है।

रविवार को सुनवाई पर भी सवाल

मुकुल रोहतगी ने रविवार को मामले पर सुनवाई किए जाने पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार बन चुकी है। इन लोगों के पास कोई दस्तावेज भी नहीं हैं ऐसे में याचिका पर तत्काल सुनवाई की इतनी जल्दी क्या थी। इस पर पीठ ने कहा कि प्रधान न्यायाधीश ने पीठ गठित की है उनके आगे केस लगा है इसलिए वे सुन रहे हैं। रोहतगी ने कहा कि याचिका पर जवाब देने के लिए दो से तीन दिन का समय दिया जाए और चार पांच दिन बाद मामले पर सुनवाई हो। इससे पहले, सुनवाई शुरू होने पर ही कपिल सिब्बल ने कोर्ट से छुट्टी वाले दिन सुनवाई के लिए परेशान करने पर माफी मांगी थी।

सुनवाई देखने के लिए कई बड़े नेता भी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, प्रेट्र : महाराष्ट्र में देवेंद्र फड़नवीस को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने के राज्यपाल के फैसले के खिलाफ रविवार को छुट्टी के दिन सुप्रीम कोर्ट में अभूतपूर्व सुनवाई हुई। इस सुनवाई को लेकर पत्रकारों में तो उत्सुकता थी ही, नेताओं में भी दिलचस्पी कम नहीं थी। वैसे इस पर नजर तो पूरे देश की लगी थी। हाल ये था कि कोर्ट रूम खुलने से पहले ही कई दिग्गज नेता वहां इंतजार करते नजर आए।

राज्यपाल के फैसले के खिलाफ शिवसेना-राकांपा-कांग्रेस की तरफ से शनिवार की रात संयुक्त याचिका दायर की गई थी। दरअसल, इन तीनों दलों ने गठबंधन सरकार बनाने की औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए शुक्रवार की शाम बैठक की थी। आखिरी बातचीत शनिवार को करना तय हुआ था, लेकिन शनिवार को जब तक इनकी आंख खुलती, देवेंद्र फड़नवीस मुख्यमंत्री और राकांपा नेता अजीत पवार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके थे। तेजी से बदले घटनाक्रम के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले इन दलों के बड़े-बड़े नेता रविवार को सुप्रीम कोर्ट में अदालती कार्यवाही शुरू होने का इंतजार करते देखे गए। इनमें कांग्रेस की तरफ से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला, शिवसेना के सांसद गजानन किर्तिकर और राकांपा नेता व राज्यसभा सदस्य माजिद मेनन शामिल थे। ये सभी सुबह 11.30 बजे से पहले ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे।

रविवार होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट में भीड़ लगी रही। कोर्ट रूम के अंदर वकीलों के जिरह को सुनने के लिए पत्रकारों को मशक्कत करनी पड़ी। राजनीतिक दलों के नेता भी जिरह सुनने को उत्सुक दिखे। जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने 24 घंटे के भीतर बहुमत साबित करने का आदेश देने की बात तो नहीं मानी, लेकिन केंद्र सरकार से राज्यपाल द्वारा फड़नवीस को सरकार बनाने के लिए बुलाने और फड़नवीस द्वारा सरकार बनाने का दावा पेश करने संबंधी पत्र सोमवार को कोर्ट में पेश करने को कहा। तीन जजों की पीठ ने कहा कि तत्काल बहुमत साबित करने के मसले पर वह सोमवार को ही कोई आदेश दे सकती है।

इस साल तीसरी बार छुट्टी के दिन खुला सर्वोच्च न्यायालय

नई दिल्ली, प्रेट्र : रविवार को सुनवाई के साथ इस साल तीसरी बार सुप्रीम कोर्ट में छुट्टी के दिन सुनवाई हुई। सबसे पहले 20 अप्रैल को शनिवार के दिन तब सुनवाई हुई थी, जब सुप्रीम कोर्ट की पूर्व कर्मचारी ने तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश (सीजेआइ) रंजन गोगोई पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। इसके बाद शनिवार, नौ नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। 2018 में ऐसा एक बार हुआ था। उस समय 15 और 16 मई की दरम्यानी रात को डेढ़ बजे सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी। यह सुनवाई कांग्रेस की याचिका पर हुई थी, जिसमें विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद कर्नाटक में भाजपा को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने के राज्यपाल के फैसले को चुनौती दी गई थी। इसी तरह 29 जुलाई, 2015 को मुंबई बम धमाकों (1993) के दोषी याकूब मेमन की फांसी को रोकने के लिए दी गई याचिका पर भी आधी रात को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी।

कोर्ट ने पहले भी दिए हैं सदन में बहुमत साबित करने के आदेश

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▸ बोम्मई मामले में कहा था, सदन में बहुमत साबित होना ही अल्टीमेट टेस्ट

▸ हरीश रावत और येदियुरप्पा मामले में तो विधानसभा की एक-एक कार्यवाही पर दिया था आदेश

यह पहला मौका नहीं है जब राजनीतिक घमासान का मुद्दा शीर्ष अदालत में पहुंचा है। महाराष्ट्र के मामले से पहले भी कई मामले सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं और कोर्ट सदन में बहुमत साबित करने का आदेश भी दे चुका है।

सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सबसे पहले एसआर बोम्मई मामले में कहा था कि सदन में बहुमत साबित होना ही अल्टीमेट टेस्ट है। इसके बाद कोर्ट ने रामेश्वर दयाल के केस में इस बात को और स्पष्ट कर दिया। बाद में झारखंड में सरकार गठन का मामला, जिसे अनिल झा केस के नाम से जाना गया, कोर्ट पहुंचा। उत्तर प्रदेश के जगदंबिका पाल मामले में भी कोर्ट के आदेश पर फ्लोर टेस्ट हुआ था। 2016 में हरीश रावत सरकार के मामले में भी कोर्ट ने सदन में बहुमत साबित करने का न सिर्फ आदेश दिया था बल्कि यह भी बताया था कि कैसे फ्लोर टेस्ट होगा और अभी पिछले साल का ताजा मामला कर्नाटक का है, जब कोर्ट ने येदियुरप्पा सरकार को बहुमत साबित करने का आदेश दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने छह मई, 2016 को कोर्ट ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को सदन में बहुमत साबित करने का आदेश दिया था। उस समय राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा था। बहुमत पर मतदान के लिए कोर्ट के आदेश पर ही कुछ समय के लिए राष्ट्रपति शासन हटाया गया था। कोर्ट ने कहा था कि 10 मई को सुबह 11 बजे उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने और उसमें सिर्फ हरीश रावत के विश्वास मत पर मतदान कराने का आदेश दिया था। कोर्ट ने उत्तराखंड के डीजीपी और मुख्य सचिव को भी शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने का आदेश दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा की कार्यवाही को लेकर भी आदेश दिया था। यहां तक कहा था कि कब मतदान शुरू होगा और कब खत्म। किस दल के सदस्य कहां बैठेंगे। मतदान कैसे होगा और मत विभाजन किस तरह। सारी प्रक्रिया की वीडियो रिकार्डिंग कराने का भी आदेश दिया था और उसे अदालत में पेश करने को भी कहा था।

कर्नाटक मामले में तय तिथि से पहले फ्लोर टेस्ट कराया गया

पिछले साल कर्नाटक में हुए राजनैतिक घमासान के समय कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट की तय तिथि को पहले कर दिया था। कोर्ट ने राज्यपाल की ओर से बहुमत साबित करने के लिए दिए गए 15 दिन के समय में कटौती करके 30 घंटे कर दिया था। कोर्ट ने 18 मई को आदेश दिया था कि अगले दिन 19 मई को मुख्यमंत्री सदन में बहुमत साबित करें। कोर्ट ने बहुमत साबित होने तक मुख्यमंत्री के नीतिगत फैसले लेने और एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत करने की सिफारिश करने पर भी रोक लगा दी थी। यही नहीं, अदालत ने प्रोटेम स्पीकर नियुक्ति करने, विधायकों को शपथ दिलाने और तत्काल विश्वास मत प्रस्ताव पर मतदान कराने का भी आदेश दिया था। साथ ही कोर्ट ने राज्य के डीजीपी को इस दौरान सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम करने के आदेश दिये थे ताकि कोई गड़बड़ी न हो।

राकांपा के कई नेता हैं ईडी के निशाने पर

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

भाजपा के साथ सरकार बनाने के अजीत पवार के फैसले के बाद भले ही उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के केस की चर्चा शुरू हो गई हो, लेकिन सच्चाई यह भी है कि खुद शरद पवार समेत राकांपा के कई वरिष्ठ नेता केंद्रीय जांच एजेंसी के निशाने पर हैं। अजीत पवार के साथ ही शरद पवार के खिलाफ दो महीने पहले ही महाराष्ट्र स्टेट कोआपरेटिव बैंक घोटाले में ईडी ने मनी लांड्रिंग का केस दर्ज किया था। वहीं राकांपा के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल विमानन क्षेत्र के कई घोटाले में फंसे हुए हैं।

2007 से 2011 के बीच हुए 25 हजार करोड़ रुपये के महाराष्ट्र स्टेट कोआपरेटिव बैंक घोटाले में बांबे हाई कोर्ट के आदेश पर मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने एफआइआर दर्ज की थी। इनमें शरद पवार और अजीत पवार समेत 70 नामजद आरोपित हैं। इसी आधार पर ईडी ने सितंबर में मनी लांड्रिंग का केस दर्ज किया था। विधानसभा चुनाव के पहले शरद पवार ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया था और ईडी को पूछताछ की चुनौती दी थी। वैसे इस मामले में शरद पवार या अजीत पवार को ईडी ने एक बार भी पूछताछ के लिए नहीं बुलाया है। वहीं, सीबीआइ और ईडी प्रफुल्ल पटेल के नागरिक उड्डयन मंत्री रहने के दौरान हुए कई घोटाले की जांच कर रहा है। इनमें एयरबस खरीद और लाभ कमाने वाले रूटों को निजी विमानन कंपनियों को आवंटित करना शामिल है। वैसे इनमें से किसी भी केस में प्रफुल्ल पटेल को सीधे तौर पर आरोपित नहीं बनाया है, लेकिन कई मामलों में उनसे पूछताछ हो चुकी है। इसके साथ ही पिछले महीने ड्रग तस्कर सरगना और दाऊद इब्राहिम के करीबी इकबाल मिर्ची की बेनामी संपत्तियों की जांच के दौरान भी प्रफुल्ल पटेल का नाम सामने आया था। ईडी का आरोप है कि प्रफुल्ल पटेल के परिवार की कंपनी का बनाया सीजे हाउस इकबाल मिर्ची की बेनामी संपत्ति पर बना है और इसके एवज में मिर्ची की पत्नी को दो फ्लोर भी दिए गए थे। इसके लिए इकबाल मिर्ची की पत्नी के साथ समझौते पर खुद प्रफुल्ल पटेल के हस्ताक्षर हैं। ईडी इस मामले में उनसे पूछताछ कर चुका है। इसके अलावा पीएमसी बैंक घोटाले से प्रफुल्ल पटेल का नाम जुड़ चुका है। पीएमसी बैंक से लिए लोन से डीएचएफएल कंपनी ने दो निजी विमान खरीदे थे। आरोप है कि इनमें से एक का इस्तेमाल प्रफुल्ल पटेल करते थे।

इसके साथ ही राकांपा के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल और उनके भतीजे समीर भुजबल के खिलाफ भी ईडी का शिकंजा कस चुका है। भुजबल पर दिल्ली स्थित महाराष्ट्र सदन समेत कई निर्माण के ठेके में भ्रष्टाचार का आरोप है। इस मामले में वे जेल में रह चुके हैं और ईडी अब तक उनकी और उनके परिवार के सदस्यों की 178 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर चुका है।

फाइल फोटो

असुरक्षा

शरद पवार के कुनबे में सेंध लगने के बाद विपक्षी दलों में असुरक्षा, भाजपा पर मुंबई के सभी होटलों में पहले से कमरे बुक कर रखने का आरोप

भाजपा के 'ऑपरेशन लोटस' से चौकन्ना हुआ विपक्ष

ओमप्रकाश तिवारी, मुंबई

सदन में बहुमत सिद्ध करने की जिम्मेदारी भाजपा की है, लेकिन चिंतित कांग्रेस-राकांपा-शिवसेना दिखाई दे रही हैं। मराठा क्षत्रप शरद पवार के कुनबे में एक बड़ी सेंध लगने के बाद सभी को अपने राजनीतिक कुनबे असुरक्षित दिखाई देने लगे हैं। घटनाक्रम पर नजर दौड़ाएं तो मुंबई के पांचसितारा होटल भी अब इन्हें सुरक्षित नहीं लग रहे हैं।

कांग्रेस और राकांपा दोनों का मानना है कि भाजपा आवश्यक विधायकों की संख्या पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। भाजपा पर महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस शुरू करने का आरोप भी लगाया जा रहा है। कुछ दिनों पहले भाजपा नेता नारायण राणे ने सरकार बनाने का प्रयास शुरू करने की बात कही थी, तो उसे गंभीरता से नहीं लिया गया था। लेकिन, अब भाजपा द्वारा अधिकृत तौर पर नारायण राणे, राधाकृष्ण विखे पाटिल, गणेश नाईक और बबनराव पाचपुते को अन्य दलों के विधायकों से संपर्क की जिम्मेदारी दिए जाने से कांग्रेस-राकांपा-शिवसेना की चिंता और बढ़ गई है। शनिवार रात हवाई अड्डे के पास स्थित एक होटल में चलनेवाली शिवसेना की यूनियन के एक सदस्य ने फोन करके पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को बताया कि भाजपा के एक विधायक प्रसाद लाड के साथ राकांपा के कुछ विधायक रुके हुए हैं। शिवसेना ने यह खबर राकांपा अध्यक्ष शरद पवार को दी। पवार ने तुरंत अपने तीन सिपहसालार भेज वहां कमरे खुलवाकर दोनों विधायकों को अपने पास बुला लिया। होटल रेनेसां में रविवार शाम तब हंगामा हो गया, जब विधायकों के रुकने की जगह के आसपास एक सुरक्षा एजेंसी के कर्मचारी पाए गए। इस बात को लेकर शरद पवार के भरोसेमंद राकांपा विधायक जीतेंद्र आह्वाड ने खूब हंगामा किया।

महाराष्ट्र की राजनीति में पल-पल बदलते घटनाक्रमों के बीच मुंबई के एक होटल में रविवार को राकांपा विधायकों की बैठक को संबोधित करते शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे। बैठक में एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी मौजूद रहे। इस समय सभी दलों को अपने कुनबे में सेंध का डर सता रहा है। इसलिए विधायकों में भरोसा बनाए रखने के प्रयास किए जा रहे हैं। एएनआइ

विपक्षी दलों ने अपने विधायकों को होटल भेजा

- राकांपा के सारे विधायकों को पवई स्थित होटल रेनेसां में रखा गया है।
- शिवसेना के सारे विधायक होटल ललित में हैं।
- कांग्रेस ने जुहू स्थित जेडब्ल्यू मैरियट में अपने विधायकों को ठहरा रखा है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चह्वाण ने आरोप लगाया है कि मुंबई के सभी होटलों में भाजपा ने पहले से कमरे बुक कर रखे हैं। जहां-जहां कांग्रेस, राकांपा और शिवसेना विधायकों को रखा जा रहा है, वहां-वहां विधायकों से इंटरकॉम के जरिये संपर्क की कोशिश हो रही है।

अपने सदस्यों पर ही नहीं है विपक्षी दलों को भरोसा: अजीत पवार जैसे मजबूत सूबेदार के भाजपा से मिल जाने के बाद कोई दल अपने किसी सदस्य पर भरोसा नहीं कर पा रहा है। पांच साल नेता विरोधी दल की जिम्मेदारी निभानेवाले कांग्रेस के राधाकृष्ण विखे पाटिल अपने पुत्र के सुरक्षित भविष्य के लिए ऐन लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा में आ गए थे। विधायकों को केंद्र एवं राज्य में स्थिर सरकार के साथ रहने में ही भलाई और सुरक्षा का अहसास होता है। उन्हें पता है कि स्थिर सरकार किसी बड़े दल के साथ बननेवाली सरकार में ही आ सकती है, न कि खिचड़ी सरकार में। जल्दी होनेवाला चुनाव हर विधायक को डरा रहा है। कांग्रेस, राकांपा और शिवसेना नेताओं को नहीं पता कि आज पांच सितारा होटलों में उनके साथ रह रहे विधायक सदन में किसके साथ जाएंगे?

शक्ति परीक्षण से भाग रही है भाजपा : कांग्रेस

नई दिल्ली, प्रेट्र : महाराष्ट्र में बिना किसी देरी के विधानसभा में शक्ति परीक्षण की मांग करते हुए कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भाजपा बहुमत साबित करने से भाग रही है, क्योंकि उसके पास जरूरी संख्या बल नहीं है।

कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, भाजपा और एनसीपी के अजीत पवार ने संवैधानिक मूल्यों को नुकसान पहुंचाया है। राज्य में देवेंद्र फड़नवीस की सरकार गैरकानूनी है। सारे सवालों का एक ही जवाब है-शक्ति परीक्षण। उन्होंने कहा कि हमारी मांग बहुत साधारण है। सदन में बहुमत का इम्तिहान होना चाहिए। पता चल जाएगा कि किसके पास संख्या बल है।

सुरजेवाला के साथ ही एक अन्य कांग्रेसी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चह्वाण ने कहा कि शक्ति परीक्षण में देरी विधायकों की खरीद-फरोख्त को बढ़ावा देगी। इस सवाल पर कि क्या कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के पास जरूरी संख्या है, चह्वाण ने कहा कि हम लगातार शक्ति परीक्षण की मांग कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास संख्या बल है। भाजपा शक्ति परीक्षण से बच रही है।

17 सीटों पर नामांकन के लिए आज है अंतिम दिन। तीसरे चरण में झारखंड की इन सीटों पर 12 दिसंबर को मतदान होना है। नामांकन पत्रों की 26 नवंबर को जांच होगी, जबकि 28 नवंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे।

अयोध्या पर फैसला मानने के लिए राजनाथ सिंह ने अल्पसंख्यकों को कहा–शुक्रिया

चुनावी सभा ▶ रक्षा मंत्री ने झारखंड में कहा–अयोध्या में बनेगा दुनिया का भव्य राममंदिर

जेएनएन, पलामू

'विरोधी कहते थे भाजपा राम जन्मभूमि का समाधान नहीं चाहती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। पूरे देश विशेष कर अल्पसंख्यक समुदाय ने फैसले को सम्मान दिया। मैं मुस्लिम नेताओं और भाइयों का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला माना। अब वहां विश्वस्तरीय भव्य राममंदिर बनेगा।' यह बातें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को झारखंड के गढ़वा में चुनावी सभा के दौरान कहीं। वह यहां स्थानीय भाजपा प्रत्याशी भानु प्रताप शाही के पक्ष में प्रचार कर रहे थे। रक्षा मंत्री ने कहा, भारतीय जनता पार्टी को देश की चिंता है, वोट की चिंता नहीं। देश को परम वैभव पर पहुंचाना हम सभी का संकल्प है। उन्होंने कहा कि यह हमारे संकल्प की ही शक्ति है कि तीन तलाक से अल्पसंख्यक महिलाओं को मुक्ति दिलाई जा सकी। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर श्याम प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा करते हुए एक देश में दो निशान, दो विधान व दो प्रधान समाप्त करते हुए भाजपा की मजबूत सरकार ने एक भारत, श्रेष्ठ भारत बनाया।

2022 तक सभी को पक्का मकान : रक्षामंत्री ने कहा कि 2022 तक देश में सभी को पक्का मकान देने का काम पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही सभी घरों में नल से शुद्ध पेयजल भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। कहा, किसी को विश्वास नहीं था कि मोदी सरकार घर-घर शौचालय बनाएगी। पूरे भवनाथपुर विधानसभा में ही 70 हजार शौचालय का निर्माण कराकर हमारी सरकार ने महिलाओं को इज्जत देने का काम किया। हमने कभी झूठ बोलकर वोट नहीं मांगा, विकास गिनाकर वोट मांगा हूं। हिसाब पक्का है, इसलिए विश्वास है कि आप भवनाथपुर में निश्चित तौर पर कमल खिलाएंगे।

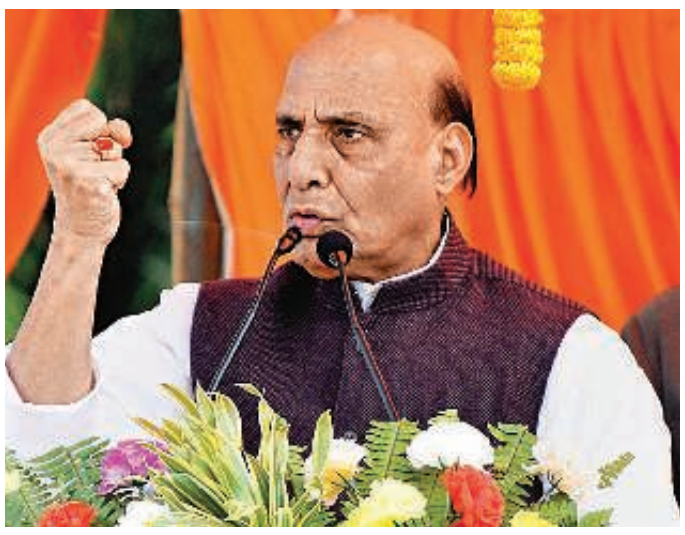

पलामू जिले के विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के पांडू में रविवार को आयोजित चुनावी सभा में बोलते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। जागरण

राष्ट्र विरोधी ताकतों को बल देती रहीं पिछली सरकारें : स्मृति ईरानी

जासं, गढ़वा : गढ़वा में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने रविवार को भाजपा प्रत्याशी सत्येंद्र नाथ तिवारी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने विपक्ष पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि देश की आजादी के बाद भाजपा व नरेंद्र मोदी की सरकार ने राष्ट्र निर्माण व सभी वर्गों के सम्मान देने तथा साथ लेकर चलने की योजना पर कार्य कर रही है। पिछली सरकारें राष्ट्र विरोधी ताकतों को बल देने वाला कार्य करती रही हैं। इसी कारण देश का विकास नहीं हो सका। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विरोधियों के झांसे में नहीं आएं। वह सभी अपने घर में तिजोरी भरने के लिए आप सभी को भ्रम में डालकर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार सभी वर्ग का उत्थान चाहती है।

बंगाल में तीन विधानसभा सीटों पर मतदान आज

जासं, कोलकाता : बंगाल में विधानसभा की तीन सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव को सोमवार को मतदान है। 28 नवंबर को मतगणना होगी। इन तीनों ही सीटों पर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधी टक्कर है, लेकिन कांग्रेस व माकपा गठबंधन तृणमूल और भाजपा के लिए चुनौती पेश कर सकते हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव के बाद यह पहला मौका है जब एक बार फिर से सत्तारूढ़ तृणमूल और भाजपा एक-दूसरे के आमने-सामने होंगे। जिन तीन सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं उनमें से एक-एक पर तृणमूल, भाजपा और कांग्रेस का कब्जा है। जिन सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें पश्चिम मेदिनीपुर जिले की खड़गपुर सदर, नदिया जिले की करीमपुर व उत्तर दिनाजपुर की कालियागंज सीटें शामिल हैं। कालियगंज सीट कांग्रेस विधायक प्रमथनाथ राय के निधन से खाली हुई है। खड़गपुर सीट से पिछली बार विधायक चुने गए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने लोकसभा चुनाव जीतने के बाद इस्तीफा दे दिया था। करीमपुर की तृणमूल विधायक महुआ मैइत्रा ने भी कृष्णनगर संसदीय सीट से जीतने के बाद इस्तीफा दे दिया था।

अग्निपरीक्षा से कम नहीं : उपचुनाव में भाजपा की जीत किसी चुनौती से कम नहीं होगी। क्योंकि इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों में मुस्लिम व दलितों की आबादी बहुलता में है। इन क्षेत्रों के ज्यादातर दलित शरणार्थी हैं, जिनके पूर्वज 1971 में मुक्ति युद्ध के दौरान तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश से भाग कर भारत आए थे। दूसरी ओर भाजपा शीर्ष नेतृत्व ने साफ कर दिया है कि वे राज्य में एनआरसी लागू करने को प्रतिबद्ध हैं।

बाबुल और मुकुल ने तृणमूल से मुक्त कराया भाजपा कार्यालय

जागरण संवाददाता, आसनसोल

केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो व भाजपा के केंद्रीय सचिव मुकुल राय ने रविवार को आसनसोल के गौरांडी हाटतल्ला कार्यालय को कब्जा मुक्त कराया और भाजपा का झंडा भी फहराया। इस दौरान आसनसोल से लेकर गौरांडी व कांटापहाड़ी तक चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात थी। सप्ताह भर पूर्व ही बाराबनी के गौरांडी हाटतल्ला, कांटापहाड़ी और जामग्राम स्थित भाजपा के तीन कार्यालयों को कथित रुप से तृकां कार्यकर्ताओं द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। बाद में उक्त कार्यालयों पर कथित रूप से तृणमूल कांग्रेस ने कब्जा भी जमा लिया। इसके बाद से ही भाजपा कार्यकर्ताओं में दहशत व्याप्त था। सभी को केंद्रीय मंत्री सह स्थानीय सांसद बाबुल सुप्रियो के आने का इंतजार था।

रविवार को यहां भाजपा कार्यालय में सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता सुबह से ही जमे हुए थे। दोपहर करीब एक बजे केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो, भाजपा नेता मुकुल राय और युवा नेता शंखदेव पांडा के पहुंचने के बाद विशाल वाहन जुलूस लेकर सभी गौरांडी हाटतल्ला पहुंचे। मंत्री का काफिला सीधे हाटतल्ला स्थित भाजपा कार्यालय पहुंचा। वहां क्षतिग्रस्त कार्यालय का हाल देखने के बाद उपस्थित कार्यकर्ताओं से विस्तृत जानकारी ली। इसके बाद केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो व मुकुल राय ने भाजपा का झंडा फहराकर कार्यालय को पुनर्स्थापित किया। मुकुल राय ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा - 'मैंने तृणमूल कांग्रेस में ममता के साथ रहकर जो गलती की है, आज उसका प्रायश्चित करने आया हूं।'

मुकुल राय ने कहा, ममता को चक्करघिन्नी की तरह घूम रही हैं। एक जगह बैठ नहीं पा रही है, उन्हें लगता है कि कोई उनकी कुर्सी उठा ले जा रहा। कहा कि अब वैसे भी सिर्फ एक ही वर्ष ममता सरकार बची है। मुकुल ने भाजपा कार्यालय तोड़े जाने को लेकर बाराबनी थाना प्रभारी को भी लपेटे में लेते हुए कहा कि एक वर्ष बाद जब भाजपा राज्य में सत्ता में आएगी तो थाना प्रभारी के रुपयों से ही पुनः कार्यालय निर्माण कराया जाएगा।

जोतो भांगबे तोतो हारबी

केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने हाटतल्ला में उपस्थित लोगों को संबोधित करने के दौरान तृणमूल कांग्रेस को चेतावनी देते हुए कहा कि जोतो भांगबी तोतो हारबी यानी जितना कार्यालय तोड़फोड़ करोगे उतना ही हारोगे। बाबुल सुप्रियो ने कहा कि पुलिस के दम पर तृकां के गुंडा वाहिनी अत्याचार चला रही है। लेकिन जिस दिन सत्ता से बाहर हुए पुलिस नहीं रहेगी तब पता चलेगा। पहले भी आसनसोल में भाजपा के कार्यालय तोड़े गये और झंडा जलाये गये लेकिन वहां उलटा हुआ और भाजपा का ही वोट बढ़ा।

शिवसेना के नेता नरेंद्र पाटिल ने की अजीत पवार से मुलाकात

मुंबई, एजेंसियां : शिवसेना नेता नरेंद्र पाटिल ने रविवार को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार से मुलाकात की। मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताते हुए पाटिल ने कहा कि हर कोई स्थिर सरकार चाहता है। वहीं, शिवसेना प्रमुख ठाकरे और राकांपा अध्यक्ष शरद पवार की एक होटल में मुलाकात हुई। उसी होटल में राकांपा के विधायक रखे गए हैं।

नरेंद्र पाटिल ने यहां पत्रकारों से कहा, 'अजीत पवार ने अपना मत स्पष्ट कर दिया है। मैं और भाजपा एमएलसी निरंजन दवखरे ने उनसे मुलाकात की, क्योंकि चुनाव के बाद उनसे भेंट नहीं हुई थी...जो भी सही निर्णय होगा वह लेंगे...मैं बस यह कह सकता हूं कि हर कोई स्थिर सरकार चाहता है ताकि किसानों की सस्याओं और अन्य मुद्दों का समाधान हो।'

वहीं, शरद पवार और उद्धव ठाकरे की रेनेसां होटल में मुलाकात हुई। टूट-फूट से बचाने के लिए इसी होटल में राकांपा के 46 विधायकों को रखा गया था। दोनों नेताओं ने विधायकों से अब तक के हालात पर चर्चा भी की। बैठक में आदित्य ठाकरे भी मौजूद थे। बाद में आदित्य ठाकरे ने बैठक से संबंधित कुछ फोटो भी ट्वीट किए। देर शाम सुरक्षा कारणों से सभी 46 विधायकों को छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के पास स्थित हयात होटल में शिफ्ट कर दिया गया।

राकांपा के विधायकों को जिस होटल में रखा गया है, वहां सादी वर्दी में दो पुलिसकर्मियों को देखकर पार्टी के नेता और विधायक भड़क गए। विधायक जितेंद्र अवाद और कुछ नेताओं की पुलिसकर्मियों से बहस भी हुई। नेताओं ने उनके होटल आने का कारण पूछा और उनसे पहचान पत्र भी मांगे।

'महाराष्ट्र में एनसीपी सरकार बनवाए तो केंद्र में भी पद'

जासं, कानपुर: महाराष्ट्र में जारी सत्ता की खींचतान के बीच एनडीए के घटक दल रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री रामदास आठवले ने अब एनसीपी के लिए केंद्र सरकार में भागीदारी की पेशकश की है। कानपुर में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अगर एनसीपी भाजपा को महाराष्ट्र में सरकार बनाने में मदद करती है तो उसके दो सांसदों को केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है। वह पार्टी की जनाधिकार रैली को संबोधित करने आए थे।

घोषणापत्र में कांग्रेस, राजद ने किसानों और पिछड़ों को साधा

राज्य ब्यूरो, रांची : झारखंड विस चुनाव के लिए कांग्रेस और राजद दोनों ने रविवार को अपना घोषणापत्र जारी कर दिया। कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में तमाम उन सफल फॉर्मूलों को शामिल किया है, जिसकी बदौलत पार्टी को पंजाब से लेकर छत्तीसगढ़ तक में सफलता मिली। किसानों की ऋण माफी, पारा शिक्षकों और आंगनबाड़ी कर्मियों का मानदेय बढ़ाना, बेरोजगारी दूर करने, बेरोजगारी भत्ता देने के साथ-साथ बिजली-पानी पर महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। किसानों को दो लाख रुपये तक के ऋण माफ किए जाएंगे और किसानों को उत्पादों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा। घोषणापत्र के माध्यम से पार्टी ने आदिवासियों, किसानों और महिलाओं को साधने का प्रयास किया है तो अल्पसंख्यकों पर खास नजर है।

गरीबी उन्मूलन राजद की प्राथमिकता : राष्ट्रीय जनता दल घोषणापत्र के अनुसार राजद पिछड़ों को जहां 27 फीसद आरक्षण देगा, वहीं अल्पसंख्यकों की सामाजिक-आर्थिक उन्नति के लिए जस्टिस रंगनाथ मिश्र और सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लागू कराएगा। इसी के सापेक्ष अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से जुड़े मुद्दों का समाधान कर उनकी आकांक्षाओं को नया आयाम देगा। गरीबी उन्मूलन और बेरोजगारी दूर करना राजद की प्राथमिकता होगी।

विश्वविद्यालयों में शोध में निवेश सुनिश्चित करें राज्यपाल और उपराज्यपाल : मोदी

नई दिल्ली, प्रेट्र : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को राज्यपालों से कहा कि विश्वविद्यालयों के चांसलर होने के नाते उन्हें उच्च शिक्षण संस्थानों में शोध कार्यों में पर्याप्त निवेश सुनिश्चित करना चाहिए, जिससे स्टार्ट-अप संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। यहां राज्यपालों और उपराज्यपालों के 50वें वार्षिक सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने उक्त टिप्पणी की। आदिवासी क्षेत्रों के विकास का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने तकनीक के समुचित उपयोग और खेल व युवा विकास के क्षेत्र में प्रगितिशील योजनाओं को अपनाने पर जोर दिया।

प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने राज्यपालों का छात्रों को जल संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करने का आह्वान किया। नई शिक्षा नीति और प्रभावकारी नवाचार के क्षेत्र में भी मोदी ने राज्यपालों की भूमिका का उल्लेख किया।

लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए काम कर रही सरकार : राज्यपालों के सम्मेलन के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा कि मोदी सरकार लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी। उन्होंने कहा कि सरकार का पूरा ध्यान जल, शिक्षा और कृषि क्षेत्र पर है। शाह ने कहा कि इस सम्मेलन का मुख्य ध्यान आदिवासियों के कल्याण और पानी, शिक्षा और कृषि से संबंधित मुद्दों पर था। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर राज्यपालों के सम्मेलन की कुछ तस्वीरें भी साझा की।

केंद्र-राज्यों के बीच राज्यपाल व उपराज्यपाल अहम कड़ी: इससे पहले, सम्मेलन के समापन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए राज्यपाल और उप राज्यपाल सबसे अहम कड़ी हैं। उन्हें इस आम धारणा को खत्म करने के लिए कोशिश करनी चाहिए कि राज्यपालों का पद औपनिवेशिक विरासत का भार है।

राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों एवं उपराज्यपालों के 50 वें सम्मेलन के समापन अवसर पर संबोधित करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उपराष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहे। एएनआइ

हापुड़ में दुल्हनों की विदाई के समय अंधाधुंध फायरिंग, एक की मौत

जागरण संवाददाता, हापुड़: उप्र के हापुड़ स्थित थाना धौलाना क्षेत्र के गांव नंगला उदयरामपुर में रविवार शाम शादी समारोह में उस समय भगदड़ मच गई, जब दो दुल्हनों की विदाई के समय हथियार बंद हमलावरों ने धावा बोल दिया और दूल्हों के सगे चाचा पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोली लगने से उनकी मौके पर मौत हो गई। जबकि वहां मौजूद सात लोग घायल हो गए। वारदात के बाद हमलावर हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए। एसपी सहित कई पुलिस अधिकारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटे हैं।

गांव नंगला उदयरामपुर निवासी विजय सिंह ने अपनी पुत्री आरती व ज्योति की शादी फरीदाबाद क्षेत्र के गांव अनंगपुर निवासी देवेंद्र के पुत्र सचिन और सागर के साथ तय की थी। रविवार सुबह बरात नंगला उदयरामपुर में पहुंचीं। शाम के समय दुल्हनों की विदाई की रस्म अदा की जा रही थी। इस दौरान हथियार बंद हमलावर मौके पर पहुंचे।

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हमलावरों ने दूल्हों के चाचा प्रॉपर्टी डीलर सुधीर पर फायरिंग कर दी। जिससे उनकी मौत हो गई। फायरिंग होता देखकर जान बचाने के लिए लोगों में भगदड़ मच गई। इस दौरान गोली लगने से कई लोग घायल हो गए।

सोन चिरैया के लिए बिजली के तारों को भूमिगत करने पर विचार करें : सरकार

नई दिल्ली, प्रेट्र : दुर्लभ और विलुप्तप्राय पक्षी सोन चिरैया (ग्रेट इंडियन बस्टर्ड) को बचाने के लिए केंद्र सरकार ने कंपनियों को उच्च क्षमता वाले बिजली के तारों को भूमिगत करने पर विचार करने को कहा है। इन तारों के संपर्क में आने से सोन चिरैया की मौत हो जाती है।

चिंताजनक है कि भारत में सोन चिरैया की आबादी अब 150 से भी कम रह गई है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) के निर्देश पर गठित एक समिति ने पक्षियों की रक्षा के उपायों के क्रियान्वयन पर समयबद्ध कार्ययोजना बनाने का फैसला किया है। समिति ने यह भी फैसला किया है कि सोन चिरैया के रहने वाले स्थानों को संरक्षण क्षेत्र घोषित किया जाएगा। वन महानिदेशक व पर्यावरण मंत्रालय के विशेष सचिव सिद्धांत दास ने बताया कि सोन चिरैया के संरक्षण पर काम शुरू हो गया है।

उल्लेखनीय है कि देश में जितनी संख्या में सोन चिरैया बचे हैं, उनमें 90 फीसद राजस्थान और गुजरात में पाए जाते हैं। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी इन्हें इक्का-दुक्का देखा जा सकता है। पाकिस्तान में तो इन पक्षियों की संख्या 15 के आसपास रह गई है।

आयुष्मान भारत के तहत इलाज में अफसरों की जेब सेहतमंद

जागरण संवाददाता, कानपुर

जरूरतमंद व गरीबों के लिए आयुष्मान भारत (प्रधानमंत्री जन आरोग्य) योजना में इलाज के नाम पर अफसरों की जेब सेहतमंद हो रही है। खरीद के नियमों को धता बताते हुए कानपुर स्थित लाला लाजपत राय अस्पताल (हैलट) में दस गुना अधिक कीमत पर इंजेक्शन खरीदकर उसका भुगतान भी करा लिया गया। जो इंजेक्शन हैलट में 135 रुपये में उपलब्ध है, उसे बाहर से 1456 रुपये में खरीदा गया। लाभार्थियों और चिकित्सकों की तरफ से दवा न मिलने की शिकायत पर हैलट के प्रमुख अधीक्षक (एसआइसी) ने भुगतान के बिलों की जांच की, तब इस खेल से पर्दाफाश हुआ। अब आयुष्मान योजना के तहत किए गए सभी भुगतान में दवाओं की खरीद के बिल की जांच होगी।

आयुष्मान योजना के लाभार्थी मरीज हों या उनका इलाज करने वाले चिकित्सक या जूनियर रेजीडेंट, लगातार दवा न मिलने की शिकायत एसआइसी से कर रहे थे। यह शिकायत उन दवाओं के लिए भी हुई, जो औषधि भंडार में सस्ते दरों पर उपलब्ध हैं। इस पर प्रमुख अधीक्षक के कान खड़े हुए। उन्होंने एक माह पूर्व आयुष्मान भारत के नोडल अफसर डॉ. एसके सिंह को पत्र लिखकर दवाओं की मूल्य सूची मांगी।

एसआइसी के मुताबिक, डॉ. एसके सिंह ने सूची मुहैया नहीं कराई, उल्टा नियमों का हवाला देकर हैलट से दवाएं लेने की बाध्यता न होने की बात कह पल्ला झाड़ने लगे।

> 'एक अस्पताल में दो व्यवस्था नहीं हो सकती। हैलट में सस्ती दवाएं उपलब्ध हैं तो बाहर से महंगी दवा खरीदने का औचित्य समझ से परे है। पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है।
> **– प्रो. आरके मौर्या, प्रमुख अधीक्षक, एलएलआर अस्पताल।**

> ''आयुष्मान में अलग खाता खोलना था, इसलिए दूसरा खाता खोला। बगैर सत्यापन के भुगतान तो रूटीन में है। यह सभी के संज्ञान में है।
> **डॉ. एसके सिंह, नोडल अफसर, आयुष्मान**

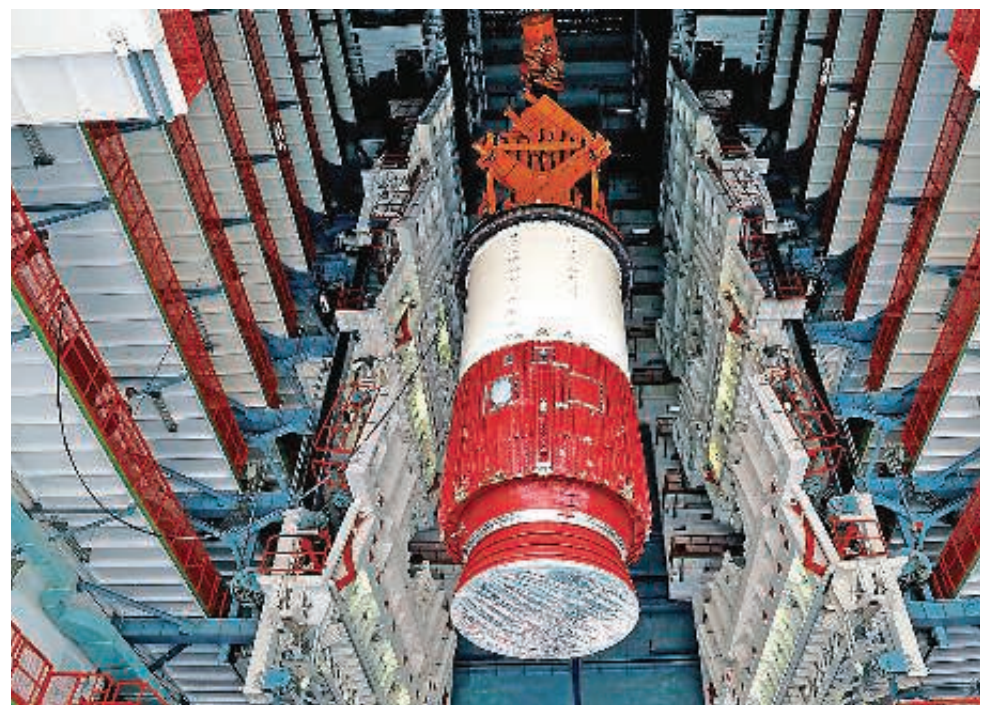

श्रीहरिकोटा में तैयारियां शुरू...

आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के श्रीहरिकोटा में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने पोलर सैटेलाइट लांच करने की तैयारियां शुरू कर दी है। रविवार को लांच व्हीकल पीएसएलवी–सी47 को लांचिंग स्टेशन तक ले जाया गया। सैटेलाइट 27 नवंबर को सुबह लांच होगा। प्रेट्र

एनटीपीसी के अंदर पहुंचा संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिक

जागरण संवाददाता, रायबरेली : एनटीपीसी की ऊंचाहार परियोजना में सुरक्षा को लेकर बड़ी चूक सामने आई है। कोयले की रैक के साथ एक संदिग्ध एनटीपीसी के अंदर पहुंच गया। संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिक बताया गया है। सुरक्षा बलों ने उसे पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। उससे पूछताछ की जा रही है।

आतंकी निशाने पर देश के बड़े औद्योगिक संस्थान हैं। इस बारे में खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के बाद ऊंचाहार एनटीपीसी संयंत्र की भी सुरक्षा कड़ी की गई है। समय-समय पर सुरक्षा को लेकर अधिकारी दिशा निर्देश भी दिया करते हैं। इसी दौरान रविवार को सुरक्षा व्यवस्था में सेंध लग गई। दोपहर करीब साढ़े तीन बजे झारखंड से कोयले की आपूर्ति लेकर आई मालगाड़ी के साथ एक संदिग्ध व्यक्ति संयंत्र क्षेत्र के अंदर घुस गया। मालगाड़ी जब संयंत्र क्षेत्र के कोल हैंडलिंग प्लांट के अंदर पहुंची तो रैक में उस व्यक्ति को देखकर लोग दंग रह गए। सीआइएसएफ जवानों ने उसे हिरासत में ले लिया। सूत्रों का कहना है कि इसके पास से पासपोर्ट और वीजा भी मिला है। जिसमें उसका नाम वाजेद अली निवासी बिलसबारी, बदलगांछी नाओगाओं बांग्लादेश लिखा है।

मील का पत्थर

एलबीएसएम कॉलेज के प्राचार्य ने शुरू की 'आशियाना योजना', कॉलेज परिसर के पुराने पेड़ों की टहनियों पर लगाए घोंसले

शुरू हुई पक्षियों को संरक्षित करने की योजना

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर

लगभग बीस साल पहले सुबह में लोगों की नींद चिड़ियों की चहचहाने की आवाज से खुलती थी। खासकर गौरैयों की आवाज सुनकर। आज गौरैयों की तादाद इतनी कम है कि उनकी आवाज सुनना और दर्शन पाना दुर्लभ है। अब उन्हें संरक्षित करने की मुहिम की शुरुआत झारखंड के जमशेदपुर स्थित लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल (एलबीएसएम) कॉलेज के प्राचार्य डॉ. अमर सिंह ने की है।

सिंह ने अपने द्वारा किए जा रहे प्रयास से कॉलेज के छात्रों को भी जोड़ा है। रविवार को कोल्हान विश्वविद्यालय की कुलपति शुक्ला महांती ने 'आशियाना योजना' की शुरुआत की। वैसे योजना की शुरुआत से पहले ही उन्होंने अपने पैसे से कॉलेज परिसर के पुराने पेड़ों की टहनियों पर वाटरप्रूफ प्लाईवुड से बने घोंसले लगवाए थे। अब इसे व्यापक रूप दिया जाएगा।

प्राचार्य डॉ. अमर सिंह ने बताया कि छोटे-छोटे प्रयास से हम जैव विविधता को संरक्षित कर सकते हैं। आज गौरैया जैसी पक्षी लुप्त होती जा रही है, यह सभी के लिए चिंतनीय है। उन्होंने कहा कि यह प्रारंभिक चरण है। साथ ही बताया कि यह घोंसला पूरी तरह वाटरप्रूफ प्लाईवुड से बना हुआ है। पेड़ में लगाने के लिए कांटी का इस्तेमाल नहीं किया गया। उसे तार से बांधा गया। उन्होंने उम्मीद जताई कम से कम गौरैया व बुलबुल इन घोसलों में अपना आशियान बनाएंगे।

हर घोंसले की देख-रेख की जिम्मेदारी एक छात्र को दी जाएगी। वह समय-समय पर रखरखाव की जानकारी योजना को क्रियान्वित करने वाली टीम को देंगे। साथ ही एक अंतराल पर समीक्षा भी की जाएगी। एलबीएसएम कोल्हान विश्वविद्यालय का पहला कॉलेज है, जहां जैव विविधता संरक्षण पर कार्यक्रम की शुरुआत की है।

जमशेदपुर के एलबीएसएम कॉलेज में आशियाना योजना के उद्घाटन के मौके पर रखे गए प्लाईवुड से बने घोंसले। इसका मकसद गोरैयों की तादाद बढ़ाना है। जागरण

छग सरकार का यूटर्न, कहा–आदिवासी महोत्सव के लिए पाक को नहीं दिया न्योता

नईदुनिया, रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार ने राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव के लिए पाकिस्तान को न्योता दिए जाने के मामले में यूटर्न ले लिया है। संस्कृति विभाग ने रविवार को एक लिखित स्पष्टीकरण जारी किया है। इसमें कहा गया है कि महोत्सव के लिए पाकिस्तान को कोई न्योता नहीं भेजा गया है। राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव का आयोजन 27 से 29 दिसंबर तक रायपुर में प्रस्तावित है। अपनी तरह के इस पहले आयोजन में देश के सभी राज्यों को आमंत्रित किया जा रहा है। इसके लिए राज्य के मंत्री अलग-अलग राज्यों में जाकर वहां के मुख्यमंत्रियों को निमंत्रण दे रहे हैं। साथ ही सार्क देशों को भी न्योता भेजा गया है। शनिवार को कैबिनेट की बैठक के बाद संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने बताया था कि विभागीय सचिव के जरिये सार्क देशों को उनके दूतावास के माध्यम से न्योता दिया गया है। नेपाल और बंगलादेश ने आयोजन में शामिल होने की सहमति भी दे दी है। उन्होंने सार्क देशों में शामिल पाकिस्तान को भी न्योता दिए जाने की बात कही थी।

साहब! मैं पढ़ना चाहती हूं मुझे मनचलों से बचा लो

जागरण संवाददाता, ऊधमसिंह नगर : मनचले युवकों द्वारा लगातार की जा रही छेड़छाड़ और अश्लीलता से घबराई छात्रा का पेपर छूट गया। इसके बाद उसने स्वजनों के साथ कोतवाली पहुंचकर पुलिस को तहरीर सौंपी। पीड़िता ने कोतवाल से कहा कि साहब मैं पढ़ना चाहती हूं, मुझे मनचलों से बचा लो। पुलिस ने आधा दर्जन आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

मानपुर रोड निवासी एक छात्रा काशीपुर स्थित एक कालेज में बीए प्रथम वर्ष की छात्रा है। छात्रा ने पुलिस से शिकायत की कि कॉलेज से घर जाते समय रामनगर रोड के ग्राम रम्पुरा के हरविंदर, शिंदर, नीटू और बंटी उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं। 13 नवंबर को भी चारों युवकों ने उसके साथ बदतमीजी की। इस वजह से इतना डर गई कि 16 नवंबर को पेपर देने नहीं गई, उस दिन उसका हिंदी का पेपर था। उसने बताया कि 17 नवंबर को उसके माता-पिता आरोपितों के गांव जाकर उनके परिवार वालों को समझाने गए तो उनके साथ गांव के दो लोगों ने मारपीट कर दी, हथियार का डर दिखाया। इतना ही नहीं, इसके बाद उल्टा, आरोपित उनकी शिकायत करने थाने पहुंच गए।

रविवार को कोतवाली पहुंची पीड़िता ने पुलिस ने कहा वह पढ़ना चाहती है। उसके माता-पिता उसे पढ़ा लिखाकर अफसर बनाना चाहते हैं, लेकिन मनचले कई दिनों से उसके पीछे पड़े हैं, उससे छेड़छाड़ करते हैं। आप मुझे इन मनचलों से बचा लो। पुलिस ने आरोपित हरविंदर, शिंदर, नीटू और बंटी, प्रेमो व गगन कौर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

17 हजार वक्फ बोर्ड की देश भर में फैली संपत्तियों पर कब्जा है। इनमें से 5,610 संपत्तियां पंजाब में है। इसके बाद मध्य प्रदेश का नंबर आता है जहां 3240 संपत्तियों पर कब्जा है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
सोमवार 25 नवंबर 2019

अपराध के खात्मे से ही सुशासन की नींव

बोले योगी ▶ दारोगा आमजन की उम्मीद पर खरा उतरने की चुनौती को लक्ष्य बनाएं

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अपराध का खात्मा ही सुशासन की नींव होती है। पुलिस को इसी बुनियाद पर काम करना चाहिए। ट्रेनिंग से निकले जवानों को आम आदमी की उम्मीद पर खरा उतरने की चुनौती स्वीकारनी होगी।

रविवार को डॉ. बीआर आंबेडकर पुलिस अकादमी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बतौर मुख्य अतिथि वर्ष 2018 के प्रशिक्षु 299 उपनिरीक्षकों की पासिंग आउट परेड की सलामी ली। समारोह में उन्होंने आंकड़ों के हवाले से यह साबित किया कि प्रदेश की कानून व्यवस्था में सकारात्मक सुधार आया है। योगी ने प्रयागराज के कुंभ, वाराणसी के अप्रवासी भारतीयों के सम्मेलन, लोकसभा चुनाव और अयोध्या प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद शांति व सौहार्द को पुलिस के मेहनत का नतीजा बताया।

उन्होंने कहा कि सरकार ने राज्य में पुलिस के संसाधन बढ़ाए हैं और बेहतर माहौल में प्रशिक्षण दिलाने के लिए खजाना खोला है। दो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर की क्षमता बढ़ी है। सात जिलों में पुलिस लाइन बनी है। 75 हजार जवानों की भर्ती हो चुकी है। चार हजार एसआइ और आपरेटर बने हैं। पचास हजार सिपाहियों की पादर्शिता से भर्ती का परिणाम आ गया है। प्रदेश में पुलिस प्रणाली को मिलने वाले फंड में वृद्धि की गई है। यह सब इसलिए कि राज्य की पुलिस प्रदेश में कानून के राज्य की स्थापना मजबूत कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके उपनिरीक्षकों के संकल्प से प्रदेश में सुशासन और स्थापित होगा। ऐसा काम करें कि वर्दी के प्रति लोगों का भरोसा बढ़े। सरकार की मंशा ऐसी संस्थाओं में लोगों का विश्वास पैदा करना है। कहा सरकार अपराध मुक्त वातावरण बनाने में सफल हो रही है। सीएम ने सुशासन के लक्ष्य हासिल करने का लक्ष्य दिया।

यूपी 100 का रेस्पांस टाइम आठ मिनट करेंगे : डीजीपी : समारोह में पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने कहा कि यूपी 100 का बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। 10 मिनट से घटाकर रेस्पांस टाइम आठ मिनट करने का लक्ष्य रखा है। इसको हम पूरा करेंगे। करीब 20 साल बाद प्रदेश में पुलिस की ट्रेनिंग व्यवस्था में असरदार सुधार हुआ है। बताया कि विधिक प्राविधानों के उपयोग और योगा का पाठ पढ़ने के बाद अपनी डयूटी सुधारने में पुलिस सफल हुई है। प्रदेश में सुरक्षा का वातावरण बना है। हत्या दस फीसद, लूट 30 फीसद, बल्बा 32 फीसद, रेप 28 फीसद, अपहरण तीस फीसद और डकैती में करीब तीस फीसद की कमी आई है। पॉक्सो एक्ट की दो प्रमुख कार्रवाई का जिक्र किया।

मुरादाबाद में पुलिस अकादमी में प्रशिक्षु दारोगाओं की पासिंग आउट परेड में सर्वांग सर्वोत्तम बिजनौर के हरजीत सिंह को तलवार भेंट करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जागरण

खास बातें

- सीएम बोले, पीड़ित को न्याय दिलाने का काम करें वर्दी।
- शपथ याद कर स्थापित मानदंड का पालन करें उप निरीक्षक।
- व्यवसायिक पुलिसिंग को लेकर सीएम ने दिए कई टास्क।
- रूल आफ-लॉ को सबसे अनिवार्य शर्त बताया।
- बेहतर प्रशिक्षण को बेहतर सेवा में बदलने की दी नसीहत।

उत्तर प्रदेश पुलिस को मिले 299 नए दारोगा

जासं, मुरादाबाद : डॉ. भीमराव आंबेडकर पुलिस अकादमी में रविवार को प्रशिक्षु दारोगा की पासिंग आउट परेड की सलामी सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ली। परेड के पूरा होते ही यूपी पुलिस को 299 नए दारोगा मिल गए। जोश, उत्साह व गौरव से भरे इस पल का गवाह प्रशिक्षु दारोगा के परिजन बने। इसके पूर्व डीजीपी ओपी सिंह ने पासिंग आउट परेड में शामिल दारोगा को व्यावसायिक जीवन में आने वाली चुनौतियों की जानकारी दी। कार्यक्रम के अंत में डीजी ट्रेनिंग सुजानवीर सिंह ने अतिथियों के प्रति आभार जताते कहा कि गुणवत्ता पूर्ण प्रशिक्षण ही हमारा प्रमुख उद्देश्य है।

रिहा किए जा सकते हैं कुछ और कश्मीरी नेता घर जाने की दी इजाजत

राज्य ब्यूरो, जम्मू : जम्मू-कश्मीर में सौ दिन से अधिक समय से हिरासत में चल रहे कुछ नेताओं को जल्द रिहा किया जा सकता है। इन नेताओं पर लगाए गए प्रतिबंधों में भी ढील दी जा रही है। कुछ राजनीतिक नेताओं को स्वास्थ्य कारणों से घाटी के बाहर जाने की इजाजत भी मिल सकती है। जम्मू-कश्मीर सरकार के कुछ अधिकारियों ने इसके संकेत भी दिए हैं, लेकिन केंद्र सरकार के साथ विचार-विमर्श के बाद ही इसपर अंतिम फैसला लिया जाएगा।

सूत्रों के अनुसार, राज्य प्रशासन ने गत शनिवार को चार से पांच नेताओं को उनके अनुरोध पर कुछ देर के लिए घर जाने की इजाजत भी दी थी। बता दें कि हाल ही में डल झील के किनारे बने सेंटूर होटल (सब जेल) से विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं को ठंड के कारण एमएलए हॉस्टल में स्थानांतरित किया गया था। इस हॉस्टल को भी सब जेल का दर्जा दिया गया है। ये नेता जम्मू-कश्मीर से पांच अगस्त को अनुच्छेद 370 हटने के बाद से ही हिरासत में हैं। इनमें तीन पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। डॉ. फारूक अब्दुल्ला को जन सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत हिरासत में लिया गया है, जबकि अन्य दो पूर्व मुख्यमंत्रियों उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को भी हिरासत में रखा गया है। इस समय कश्मीर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हिरासत में रखे गए कुछ नेताओं व उनके परिवार के सदस्यों ने इससे उनके स्वास्थ्य पर पड़ रहे असर की शिकायत की थी। महबूबा मुफ्ती को भी इसी कारण टूरिस्ट हट से सरकारी आवास में भेजा गया था। पीपुल्स कांफ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन, आइएएस से त्यागपत्र देकर नेता बने शाह फैसल भी इस समय हिरासत में हैं।

जम्मू-कश्मीर में आज से घर-घर पहुंच समस्याएं दूर करेंगे अधिकारी

राज्य ब्यूरो, जम्मू

- गांव की ओर अभियान के लिए तैयारियां पूरी, अधिकारी पहुंचे गांव
- जम्मू-कश्मीर के सात हजार गांवों में चलाया जाएगा अभियान

जम्मू-कश्मीर राज्य प्रशासन ने गांव की ओर अभियान को सफल बनाने के लिए तैयारियां पूरी कर ली है। जम्मू-कश्मीर की चार हजार से अधिक पंचायतों में सोमवार से उत्सव जैसा माहौल होगा। वरिष्ठ अधिकारी ग्रामीणों के दरवाजों पर जाकर उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए पंचायतों में डेरा डालेंगे। यह अभियान 25 से 30 नवंबर तक चलेगा।

इस दौरान वरिष्ठ अधिकारियों को पंचायतों में एक रात भी बितानी होगी। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद यह अभियान पहली बार चलाया जा रहा है। वहीं, इससे पहले भी एक बार इस तरह का अभियान चलाया जा चुका है। इसे सफल बनाने के लिए सोमवार को जम्मू-कश्मीर में जिला स्तर पर गतिविधियों का आयोजन किया गया। चार हजार से अधिक पंचायतों के करीब सात हजार गांवों में यह अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान आइएएस और आइएफएस अधिकारियों समेत सैकड़ों वरिष्ठ अधिकारी लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को मौके पर समाधान करेंगे। पंच, सरपंचों के संगठन की ओर से इस अभियान पर नाराजगी जताने के बावजूद इस अभियान को सफल बनाने के लिए सभी डिप्टी कमिश्नरों की अध्यक्षता में अधिकारियों को ट्रेनिंग दी गई। उन्हें उपपंचायतों के बारे में भी जानकारी दी गई, जहां उनकी नियुक्ति की गई है। उन्हें कहा गया कि वह इस काम को सफल बनाने के लिए हर मुमकिन प्रयास करें।

जम्मू की डिप्टी कमिश्नर सुषमा चौहान, ऊधमपुर के डिप्टी कमिश्नर पियूष सिंगला, कठुआ के डिप्टी कमिश्नर ओम प्रकाश भगत सहित कई अन्य ने जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर चर्चा की। इस अभियान के दौरान पहले चरण में हुए फैसलों पर चर्चा करने के अलावा ग्रामीणों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं का लाभ पहुंचाने और किसानों की आय दोगुना करने पर जोर दिया जाएगा।

मुख्य सचिव और डिवीजनल कमिश्नर भी करेंगे दौरा

इस अभियान में जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रहमण्यम, जम्मू के डिवीजनल कमिश्नर संजीव वर्मा और कश्मीर के डिवीजनल कमिश्नर बसीर खान भी ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा करेंगे। वहीं, रविवार को कई अधिकारी पंचायतों की ओर रवाना हो गए। उन्होंने पंचायतों में इस अभियान के लिए किए गए प्रबंधों का जायजा लिया।

श्रीनगर में चार दिन बाद खुले बाजार

राज्य ब्यूरो, जम्मू : कश्मीर में धमकी भरे पोस्टर लगने के चार दिन बाद रविवार को कई जगहों पर दुकानें खुली हुई थीं। श्रीनगर में भी संडे बाजार गुलजार नजर आया। कई लोग खरीदारी करते नजर आए। श्रीनगर शहर में सिविल लाइन और लाल चौक के आसपास क्षेत्रों में सुबह से ही दुकानें खुली हुई थीं। हालांकि श्रीनगर के डाउन-टाउन सहित अन्य पुराने शहर में दुकानें बंद रहीं। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद से स्थिति लगभग शांति बनी हुई थी। दुकानें सुबह से दोपहर तक खुलना शुरू हो गई थीं। स्कूलों में बच्चों की हाजिरी भी बढ़ने लगी थी। लेकिन अलगाववादियों को लगातार शांत हो रहे हालात रास नहीं आ रहे थे। उन्होंने बीते बुधवार को घाटी में कई जगह दुकानदारों को धमकाने के लिए पोस्टर लगा दिए। इसके बाद पुलिस ने कई जगहों पर छापे मारे और कुछ को हिरासत में लिया।

'टमाटर चाहिए तो गुलाम कश्मीर दो और माफी मांगो'

मनोज जानी, पेटलावद (झाबुआ, मप्र)

- मध्य प्रदेश के 150 से अधिक किसानों ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को ट्विटर और डाक विभाग के जरिये भेजे पैगाम

ईरान से आयात के बाद भी टमाटर की किल्लत झेल रहे पाकिस्तान को मध्य प्रदेश के किसानों ने नया प्रस्ताव भेजा है। झाबुआ जिले के पेटलावद के 150 से अधिक किसानों ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को ट्विटर और डाक विभाग के जरिए भेजे पैगाम में कहा है कि इमरान खान गुलाम कश्मीर दो और हमारे टमाटर ले लो। इतना ही नहीं, किसानों ने पाकिस्तान से 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमले के लिए माफी की भी मांग की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी ट्वीट किया है।

ट्विटर के जरिए भारतीय किसान यूनियन की झाबुआ जिला इकाई ने इमरान से कहा कि बाघा बार्डर से आपके देश में टमाटर जाते थे, लेकिन आतंकवादियों और आपकी सेना ने हमारे देश के निर्दोष लोगों पर हमले किए, आतंकवाद फैलाया, 26/11 व पुलवामा जैसे हमले करवाए। इसके बाद हमारे देश और हमने आपको टमाटर नहीं देने का फैसला लिया था। बीते दो दिनों की मीडिया रिपोर्ट में आपके देश में टमाटर को लेकर खराब हालत की जानकारी आई है। अगर पाकिस्तान भारत के दुश्मनों को हमारी सरकार को सौंप दे और अनधिकृत रूप से कब्जा किए गुलाम कश्मीर को शांतिपूर्वक सौंप दे तो भाकियू उत्पादक किसानों के साथ टमाटर भेजने पर विचार कर सकती है। किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष महेंद्र हामड़ ने कहा कि 18 सितंबर 2016 को हुए उरी आतंकवादी हमले के बाद से किसान नाराज थे और पाकिस्तान टमाटर भेजना बंद कर दिया थे। इससे पहले करीब डेढ़ दशक से पाकिस्तान टमाटर यहां से भेजे जाते थे।

क्यों खास है : पेटलावद का टमाटर चटख लाल रंग का होता है और खट्टे-मीठे स्वाद की वजह से पाकिस्तान में बहुत पसंद किया जाता है। एक टमाटर का वजन 50 से लेकर 150 ग्राम तक होता है।

पूर्व वित्त मंत्री को दूसरे दिन भी नहीं मिली श्रीनगर से बाहर जाने की इजाजत

राज्य ब्यूरो, जम्मू : पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा के नेतृत्व में कश्मीर आए सिविल सोसायटी के प्रतिनिधिमंडल को दूसरे दिन भी पुलिस ने श्रीनगर से आगे नहीं जाने दिया।

प्रतिनिधिमंडल में शामिल सुशोभा बार्वे का कहना है कि हम कश्मीर में जहां जाना चाहते हैं, वहां हमें जाने नहीं दिया जा रहा है। हमसे मिलने लोग ही हमारे पास आ रहे हैं। रविवार को भी पांच प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलने के लिए होटल में आए। हम दक्षिण कश्मीर के पुलवामा और बडगाम में जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने जाने नहीं दिया। इस ग्रुप में शामिल पूर्व सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्ला ने एक दिन पहले ही कहा था कि वह पुलवामा जाना चाहते थे, लेकिन एएसपी सिक्योरिटी ने उन्हें यह कहकर जाने से रोक दिया था कि वहां के हालात सही नहीं हैं।

गौरतलब है कि दिल्ली स्थित कनसंर्ड सिटीजंस ग्रुप के बैनर तले पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा, पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्ला, पूर्व एयर वाइस मार्शल कपिल काक आदि श्रीनगर पहुंचे थे।

नदी संसद करेगी काली नदी का कल्याण

रवि प्रकाश तिवारी, मेरठ

- सभी नौ जिलों में गठित होगी समिति, हर छह महीने में नदी संसद की बैठक में समीक्षा की योजना
- इससे मिलते-जुलते मॉडल पर ही राजस्थान की अरवरी नदी को पुनर्जीवित किया जा चुका है

उत्तर प्रदेश में काली नदी को जिंदा करने का जो प्रयास इन दिनों चल रहा है, उसमें प्रशासनिक और सामाजिक दोनों ही ओर से महती भागीदारी निभाई जा रही है। नदी की साफ-सफाई और उसकी राह को खाली कराने के बाद उसकी धार कल-कल कर बहती रहे, इसकी खातिर भविष्य में भी साझा प्रयास की जरूरत पड़ेगी। इसी को ध्यान में रखते हुए अब नदी संसद के गठन की योजना पर भी बात उठने लगी है। इससे मिलते-जुलते मॉडल पर ही राजस्थान की अरवरी नदी को पुनर्जीवित किया जा चुका है। नदी संसद के तौर पर राजस्थान के अलवर जिले की अरवरी एक बड़ी मिसाल है। काली के लिए भी कुछ उसी मार्ग पर चलने की तैयारी हो रही है।

काली नदी उप्र के मुजफ्फरनगर से निकलकर मेरठ, हापुड़, अलीगढ़ होते हुए कन्नौज में गंगा से मिलती है। यानी उद्गम से समागम तक रास्ते में नौ जिले काली से कभी उपकृत होते रहे हैं, जहां आज भी उसके निशान हैं। नदी को नवजीवन मिलने के बाद इसमें सालभर पानी रहे और औद्योगिक कचरे व सीवर का डंपिंग ग्राउंड न रहे, इस खातिर प्रत्येक जिले में एक समिति बनाने की योजना पर विचार चल रहा है।

कैसे हो नदी संसद का गठन : नदी संसद के लिए पहले जिलास्तरीय टीम का गठन होगा। इसमें नदी सफाई, नदी बचाओ, जल संरक्षण पर काम करने वाले लोगों को सक्रिय सदस्य के तौर पर चुना जाए। इसके साथ ही समाज के कुछ और प्रतिष्ठित लोगों को इस समिति का हिस्सा बनाया जाए। इस तरह प्रत्येक जिले में 20-21 लोगों की एक टीम हो जाएगी। नदी संसद के मॉडल में हर जिले में संयोजक और सह संयोजक भी होंगे। नदी संसद के लिए जिला स्तरीय टीम में सक्रिय सदस्य के तौर पर शामिल किए जाने के साथ ही समय-समय पर किए जाने वाले अधिवेशन में जिलाधिकारी से लेकर नदी विकास से जुड़े सरकारी महकमों के अफसरों को भी आमंत्रित किए जाने का प्रस्ताव सामने आया है। काली के उद्धार में जुटे नदी पुत्र रमन त्यागी कहते हैं जिला स्तरीय समिति के गठन की प्रक्रिया शुरू भी कर दी गई है।

अधिवेशन में तय किए जाएं निर्णय : जिला स्तरीय समिति को लेकर नदी संसद का गठन होगा और हर जिले के संयोजक और सह-संयोजक को लेकर कैबिनेट की तर्ज पर निर्णय लेने वाली संस्था का गठन किया जाएगा। अधिवेशन में हर जिले के प्रतिनिधि अपने-अपने क्षेत्र में नदी की स्थिति और समस्याओं के निराकरण की दिशा में किए गए प्रयासों पर चर्चा करेंगे। जहां कोई दिक्कत होगी, उसके समाधान का मार्ग भी खोजा जाएगा।

भूजल सेना की हो सकती है महती भूमिका : प्रदेश सरकार ने आम जनता को जल संचय के प्रति जागरूक करने और जल संरक्षण को बढ़ावा देने के मकसद से हर जिले में भूजल सेना का गठन किया हुआ है। नदी संसद को संचालित करने और इसे सफल बनाने में भूजल सेना जैसी संस्थाओं का भी अहम रोल हो सकता है। ये पहले से ही इस दिशा में काम कर रहे हैं, लिहाजा इनका साथ काली नदी को पुनर्जीवित करने की कोशिश को मुकाम तक पहुंचा सकता है।

44 साल बाद नैरोगेज पर छुक छुक लेकर दौड़ेगा नया इंजन

विनोद कुमार, पठानकोट

अब बूढ़े हो चुके इंजनों की पहाड़ों पर सांस नहीं फूलेगी। पठानकोट-जोगिंदरनगर नैरोगेज रेल सेक्शन पर 44 साल बाद छुक-छुक को लेकर नया इंजन नैरोगेज दौड़ेगा और हिमाचल की हसीन वादियों का दीदार करवाएगा। मुंबई की परेल वर्कशॉप में बने नए इंजन को पठानकोट के लिए रवाना कर दिया गया। इसी हफ्ते नया ताकतवर डीजल इंजन पहुंच जाएगा। इससे पहले पठानकोट लोको को वर्ष 1976 में नया इंजन मिला था।

इंजन नंबर 715 जेडडीएम-3 सुरक्षा के लिहाज से भी अहम है। मौजूदा समय में मौजूद चार इंजनों का कैबिन आगे की ओर ही है। जिससे इसे मोड़ने में बहुत समय लग जाता है। इसके अलावा ड्राइवर के आगे छह से सात मीटर लंबा बोनट होने के कारण ट्रैक साफ दिखाई नहीं देता था। नए इंजन में आगे और पीछे दोनों ओर कैबिन हैं। इसे मोड़ने की जरूरत नहीं है। यह ट्रेन के दोनों ओर जुड़ सकता है। नए इंजन के आगे बोनट नहीं है। ड्राइवर पांच मीटर की दूरी पर साफ देख सकता है।

बूढ़े हो चुके हैं चार इंजन : नैरोगेज पर दौड़ने वाले इंजन की उम्र 36 साल मानी जाती है। मौजूदा समय में दौड़ रहे इंजनों में से तीन अपनी उम्र पूरी कर चुके हैं जबकि चौथा फरवरी 2020 में उम्र पूरी कर लेगा। पठानकोट से जोगिंदरनगर के बीच एक दिन में 14 ट्रेन आवाजाही करती हैं। इसके लिए 12 इंजनों की जरूरत है। अगर कोई इंजन रास्ते में हांफ जाता है तो उसे लाने के लिए लोको इंजन भेजना पड़ता है। इस कारण ट्रेनों को संचालन प्रभावित होता है रेल सेक्शन को अब भी सात और नए रेल इंजन चाहिए।

नैरोगेज सेक्शन का नया डीजल इंजन शनिवार को पठानकोट पहुंचा। जागरण

महीने के दूसरे शनिवार को बंद रहेंगे उप्र के कोषागार

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : प्रदेश के सभी कोषागार और उप कोषागार अब महीने के दूसरे शनिवार को बंद रहेंगे। यह व्यवस्था दिसंबर से लागू होगी। प्रस्ताव को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंजूरी मिलने के बाद वित्त विभाग ने शासनादेश जारी कर दिया है।

अभी प्रदेश के सभी कोषागार और उप कोषागार महीने के दूसरे शनिवार और स्थानीय अवकाशों को खुलते हैं। वहीं बैंक और सरकारी दफ्तर दूसरे शनिवार और स्थानीय अवकाशों को बंद रहते हैं। दूसरे शनिवार और स्थानीय अवकाशों पर खुलने के कारण कोषागार और उप कोषागार कर्मियों को साल में 15 दिन का मानदेय मिलता था। दूसरे शनिवार को कोषागारों में बंदी का आदेश प्रभावी होने पर अब यह मानदेय नहीं मिलेगा।

वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि कोषागारों के कार्मिकों के संगठनों की ओर से यह मांग की जा रही थी कि चूंकि बैंक और दूसरे सरकारी दफ्तर दूसरे शनिवार को बंद रहते हैं, इसलिए कोषागारों में भी यह बंदी लागू की जाए। अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव कुमार मित्तल ने बताया कि इस बारे में शासनादेश जारी कर दिया गया है।

माघ मेले की तैयारी

उत्तर प्रदेश की पावन नगरी प्रयागराज में माघ मेले की तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं। तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए गंगा नदी पर पंटून पुल तैयार किया जा रहा है। रविवार की सुबह पुल पर निर्माण कार्य में जुटे श्रमिक। जनवरी से मध्य फरवरी तक आयोजित माघ मेले में लाखों श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाते हैं। यहां पांच पंटून पुल बनाए जा रहे हैं। एएफपी

पीएससी की परीक्षा के बाद होगी आरक्षण की गणना

नईदुनिया, रायपुर : छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (पीएससी) ने राज्य सेवा परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। पीएससी के चेयरमैन केआर पिस्दा ने बताया कि आरक्षण की जिम्मेदारी पीएससी की नहीं होती है। आरक्षण नियुक्तिकर्ता विभाग को तय करना है। ऐसे में आरक्षण के कारण परीक्षा को रोका नहीं जा सकता है। राज्य सरकार ने ओबीसी और एससी वर्ग का आरक्षण बढ़ाया है। आरक्षण के मामले को लेकर कोर्ट में मामला चल रहा है। ऐसे में आशंका जताई जा रही थी कि परीक्षा प्रभावित होगी। लेकिन पीएससी ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि आरक्षण के कारण परीक्षा को रोका नहीं जाएगा। पीएससी ने राज्य सेवा परीक्षा के लिए 199 पदों का विज्ञापन जारी किया है। बताया जा रहा है कि विज्ञापन में सिर्फ 15 विभाग की रिक्तियों को शामिल किया गया है। अन्य विभाग से रिक्तियां आने के बाद पदों की संख्या में इजाफा होगा। पीएससी के आला अधिकारियों ने बताया कि अभी जो भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है, वह पुराने आरक्षण नियमों के आधार पर जारी किया गया है। हाईकोर्ट से आरक्षण नियमों पर आदेश आने के बाद विभागों को आरक्षण रिवाइज करना होगा। परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद आरक्षण नियम को लागू करने की जिम्मेदारी विभाग की होगी।

बढ़ेगी ताकत

एयरोस्पेस इंजीनियरिंग विभाग ने बनाए मानवरहित दो हेलीकॉप्टर, मानव संसाधन मंत्री ने आंतरिक सुरक्षा के लिए बताया मददगार

सरहदों की निगहबानी करेगा आइआइटी का 'प्रहरी'

जागरण संवाददाता, कानपुर

दूर-दुर्गम क्षेत्रों में तैनात सेना के जवानों तक राशन और दवाइयां पहुंचाना अब मुश्किल नहीं होगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) कानपुर ने दो ऐसे मानवरहित हेलीकॉप्टर बनाए हैं जो किसी भी दुर्गम स्थान में उड़ान भरकर वहां पांच से दस किलो तक वजन की सामग्री पहुंचा सकते हैं। आइआइटी ने इन्हें 'प्रहरी' नाम दिया है। ये सरहद की निगहबानी भी कर सकेंगे। हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट कर इन हेलीकॉप्टरों को आंतरिक सुरक्षा के लिए मददगार बताया था। इसके अलावा भारतीय सेना ने भी इन्हें बेड़े में शामिल करने की इच्छा जताई है।

ये हेलीकॉप्टर एयरोस्पेस इंजीनियरिंग विभाग के डॉ. अभिषेक व डॉ. मंगल कोठारी के निर्देश में पीएचडी व रिसर्च स्कॉलर छात्रों ने बनाए हैं। डॉ. अभिषेक ने बताया कि एक मानव रहित हेलीकॉप्टर बड़ा और दूसरा छोटा है। दोनों में कैमरा, सेंसर, सर्विलांस सिस्टम हैं। बड़े में 6.0 हार्स पावर व छोटे में 3.2 हार्स पावर का इंजन लगाया गया है। ये पेट्रोल से उड़ान भरने में सक्षम हैं। एक में पांच लीटर और दूसरे में ढाई लीटर का टैंक है। बड़े हेलीकॉप्टर में दो रोटार हैं। इसे रिमोट के सहारे उड़ाकर किसी भी स्थिति-स्थान पर दस किलो वजन तक राशन, दवाइयां व अन्य सामान पहुंचाया जा सकता है। वहीं दूसरे में एक रोटार है जिसकी क्षमता आधी है। हालांकि इसका इस्तेमाल सर्विलांस के लिए भी किया जा सकता है। ये किसी भी क्षेत्र में उड़ने वाले संदिग्ध ड्रोन को कैप्चर भी कर सकते हैं। खास बात ये है कि सामान्य ड्रोन की अपेक्षा ये दोनों हेलीकॉप्टर छह गुना अधिक समय तक हवा में रह सकते हैं। आइआइटी की एयर स्ट्रिप के अलावा लद्दाख और पोखरण में इनका सफल परीक्षण किया जा चुका है। मानवरहित यान बनाने वाले छात्रों ने इसे अधिक संख्या में बनाने के लिए एंड्योर एयर सिस्टम नाम की स्टार्टअप कंपनी भी बनाई है।

आइआइटी छात्रों द्वारा बनाया गया मानवरहित यान प्रहरी। सौ : आइआइटी प्रोफेसर

आधा घंटा उड़ सकते थे ड्रोन

डॉ. अभिषेक ने बताया कि अभी तक बनने वाले ड्रोन व मानवरहित यान अधिकतम आधा घंटे तक उड़ सकते थे, क्योंकि ये बैटरी चालित थे। पहली बार पेट्रोल से चलने वाले यह दोनों मानव रहित यान तीन घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम हैं।

न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में भी पढ़ेंगे कानपुर आइआइटी के शोध छात्र

जासं, कानपुर : कानपुर आइआइटी के इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर इंजीनियरिंग के शोध छात्र-छात्राओं को न्यूयार्क यूनिवर्सिटी में भी पढ़ने का मौका मिलेगा। शोध पूरा होने पर डिग्री पर कानपुर आइआइटी और न्यूयार्क यूनिवर्सिटी की मुहर लगेगी। कानपुर आइआइटी ने न्यूयार्क यूनिवर्सिटी के टंडन स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के साथ इन दोनों ट्रेड में संयुक्त शोध कार्यक्रम का करार किया है। करार के तहत आइआइटी के छात्र अपने शोध का कुछ हिस्सा न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में पूरा कर सकेंगे। उन्हें छात्रवृत्ति भी मिलेगी। दोनों संस्थानों के शोध छात्रों को इस कार्यक्रम में भागीदारी के लिए आवेदन करना होगा। करार पर आइआइटी कानपुर के निदेशक प्रोफेसर अभय करंदीकर व टंडन स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग की डीन जेलेना कोवासिविक ने हस्ताक्षर किया है। करार के तहत टंडन स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के छात्र भी आइआइटी कानपुर में पढ़ सकेंगे।

पेयजल सुविधा के मामले में गांवों से बेहतर हैं शहर

नई दिल्ली, एएनआइ

- 58.2 फीसद ग्रामीण व 80.7 फीसद शहरी घरों में उपलब्ध है पेयजल सुविधा
- नेशनल सैंपल सर्वे (एनएसएस) में सामने आई हैं यह बातें

पेयजल सुविधा के मामले में शहरों की स्थिति गांवों से बेहतर है। जुलाई से दिसंबर 2018 के दौरान सिर्फ 58.2 फीसद ग्रामीण व 80.7 फीसद शहरी घरों में पीने का पानी उपलब्ध था। ये बातें नेशनल सैंपल सर्वे (एनएसएस) में सामने आई हैं।

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने 76वें दौर के एनएसएस के हिस्से के रूप में पेयजल, सफाई, स्वच्छता और आवासीय स्थिति पर सर्वेक्षण करवाया। 'भारत में पेयजल, सफाई, स्वच्छता व आवासीय स्थिति' शीर्षक रिपोर्ट में कहा गया है, 'ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति का मुख्य स्रोत हैंडपंप और शहरी क्षेत्र में पाइपलाइन है। 42.9 फीसद ग्रामीण घरों में लोग हैंडपंप का पानी पीते हैं, जबकि 40.9 फीसद शहरी घरों में पाइपलाइन का पानी पीने में इस्तेमाल होता है। ग्रामीण इलाके के 87.6 फीसद व शहरी क्षेत्र के 90.9 फीसद घरों में साल भर पर्याप्त पेयजल उपलब्ध होता है।'

सिर्फ 50 फीसद ग्रामीण व 75 फीसद शहरी घरों में उपलब्ध है स्नानघर

रिपोर्ट के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्र के 50.3 व शहरी क्षेत्र के 75 फीसद घरों में विशेष स्नानघर की सुविधा उपलब्ध है। इसमें बताया गया है कि गांवों के 71.3 व शहरों के 96.2 फीसद घरों में शौचालय की सुविधा है। ग्रामीण इलाके में 50.9 व शहरी क्षेत्र में 48.9 फीसद घरों में सेप्टिक टैंक वाला शौचालय उपलब्ध है।

305 परियोजनाओं को मंजूरी दी है केंद्र ने निर्मल गंगा मिशन के तहत। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत करीब 28613 करोड़ रुपये है। यह जानकारी जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दी है।

न्यूज गैलरी

जनसंघ के संस्थापक सदस्य रहे कैलाश जोशी का निधन

कैलाश जोशी। फाइल

भोपाल : जनसंघ के संस्थापक सदस्य रहे दिग्गज भाजपा नेता कैलाश जोशी (91) का रविवार सुबह निधन हो गया। करीब दो महीने पहले पत्नी के निधन के बाद अस्वस्थ चल रहे जोशी एक सप्ताह से अस्पताल में भर्ती थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री कमलनाथ सहित देश भर के नेताओं ने उनके निधन पर शोक प्रकट किया है। जोशी जनसंघ, जनता पार्टी एवं भाजपा में कई प्रमुख पदों पर रहे। वह आठ बार विधायक, दो बार लोकसभा और एक बार राज्यसभा सदस्य रहे। जोशी को मध्य प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री रहने का श्रेय भी प्राप्त है। आपातकाल के बाद 1977 में जनता पार्टी ने जब सत्ता संभाली, तब वह मुख्यमंत्री चुने गए थे, उनका कार्यकाल करीब सात महीने ही रहा। मार्च 1990 में पटवा सरकार में वह मंत्री भी रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक संदेश में कहा कि मध्यभारत अंचल में भाजपा और जनसंघ को मजबूत बनाने में उन्होंने कड़ा संघर्ष किया। (नईदुनिया)

उत्तराखंड में एक महीने में तीसरी बार आया भूकंप

चमोली : उत्तराखंड में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस बार भूकंप का केंद्र चमोली जिले का किलोंडी गांव रहा। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3 .4 मापी गई और इसकी गहराई दस किलोमीटर रही। चमोली के अलावा राज्य में किसी और जिले से भूकंप की सूचना नहीं है। एक माह में तीसरी बार प्रदेश में धरती डोली है। चमोली जिले में रविवार को दोपहर बाद करीब एक बजकर बीस मिनट पर भूकंप का झटका महसूस किया गया। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी केएन जोशी के अनुसार भूकंप का केंद्र गोपेश्वर के निकट किलोंडी गांव के पास था। गौरतलब है कि 28 अक्टूबर और 19 नवंबर को कुमाऊं के पिथौरागढ़ में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। (जासं)

पाकिस्तान से पहुंची डेढ़ किलो हेरोइन, तीन गिरफ्तार

अजनाला (अमृतसर) : पाकिस्तान से पहुंची हेरोइन की खेप में से चाटीविंड पुलिस ने डेढ़ किलो हेरोइन रविवार रात को बरामद कर ली। इसकी डिलीवरी करने जा रहे तीन तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपितों में एक दंपती भी शामिल है। आरोपित इस खेप को दिल्ली की किसी पार्टी को सप्लाई करने जा रहे थे। पुलिस ने आरोपितों के मोबाइल से कई लोगों के नंबर हासिल किए हैं। एसएसपी देहात विक्रम दुग्गल ने बताया कि पकड़े गए आरोपितों में रंजीत सिंह, हरजीत सिंह और उसकी पत्नी मंदीप कौर शामिल हैं। (जासं)

परनीत ने हेलीकॉप्टर में सुनी विधायकों की शिकायत

पहल ▶ पंजाब के सीएम की पत्नी ने अफसरशाही पर लगाम लगाने का दिया भरोसा, नाराज विधायकों ने साधी चुप्पी

पटियाला से सांसद के साथ हेलीकॉप्टर में नूरमहल आए सभी विधायक

जागरण संवाददाता, पटियाला

अफसरशाही के हावी होने और फोन टैपिंग से नाराज पटियाला जिले के विधायकों को मनाने की कमान पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी व सांसद परनीत कौर ने संभाल ली है। परनीत रविवार को नाराज विधायकों को अपने साथ हेलीकॉप्टर में लेकर गईं और उनसे बातचीत की। परनीत कौर के सामने अपनी बात रखने के बाद रविवार शाम को विधायक मीडिया से इस बारे में बात करने से बचते रहे।

परनीत कौर को रविवार को जालंधर के नूरमहल में एक धार्मिक कार्यक्रम में आना था। हेलीकॉप्टर में परनीत कौर से नाराज विधायकों की बातचीत करवाने के लिए कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत अपने साथ राजपुरा के विधायक हरदयाल कंबोज, घनौर के विधायक मदन लाल जलालपुर और समाना के विधायक काका राजिंदर सिंह को साथ लेकर पटियाला पहुंचे। सांसद, कैबिनेट मंत्री और तीनों विधायक हेलीकॉप्टर में पटियाला से नूरमहल के लिए रवाना हो गए। इस यात्रा के दौरान विधायकों ने परनीत कौर के साथ जिले के अधिकारियों की कार्यशैली और उनके रवैये पर बातचीत की। बताया जा रहा है कि नाराज विधायकों की बातचीत सुनने के बाद परनीत कौर ने उन्हें हालात पर नियंत्रण करने का भरोसा दिया है। वहीं, विधायकों ने भी फैसला परनीत पर छोड़ दिया है। गौरतलब है कि संसद के सत्र के लिए परनीत कौर दिल्ली में थीं। इस बीच पटियाला में विधायकों ने पुलिस प्रशासन पर मनमानी के आरोप लगाए थे। विधायक जलालपुर और कंबोज ने अपनी की सरकार पर सवाल खड़े कर दिए थे।

हेलीकॉप्टर में बैठे (बाएं से) राजपुरा के विधायक हरदयाल कंबोज, घनौर के विधायक मदन लाल जलालपुर व समाना के विधायक काका राजिंदर सिंह सांसद परनीत कौर के साथ बातचीत करते हुए। इनके साथ नाभा के विधायक कैबिनेट मंत्री साधू सिंह धर्मसोत भी थे। जागरण

▶ विधायकों ने अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर दिए थे

एसएसपी ने विधायक के फोन टैपिंग के आरोपों को नकारा

बेशक समाना के विधायक काका राजिंदर सिंह की तरफ से पुलिस पर उनका और उनके सचिव का फोन टैप करने का आरोप लगाने के बाद सीआइए समाना के इंचार्ज इंस्पेक्टर विजय कुमार का तबादला कर दिया गया, लेकिन एसएसपी मनदीप सिंह फोन टैपिंग की किसी भी घटना से इन्कार कर रहे हैं। फिलहाल फोन टैपिंग के लिए गृह मंत्रालय की मंजूरी जरूरी होती है। अपराधिक मामलों की जांच के लिए बिना मंजूरी फोन टैप किए जा सकते हैं। मंजूरी या बिना मंजूरी फोन टैप करने का रिकॉर्ड मोबाइल कंपनियों के पास रहता है। इस रिकॉर्ड की जानकारी अदालत के आदेश पर हासिल की जा सकती है।

इस कारण हुए विधायक अपनी ही सरकार से खफा

विधायक हरदयाल कंबोज (राजपुरा) : एसडीएम राजपुरा पर उनकी पंचायत से पांच लाख रुपये रिश्वत मांगने के आरोप लगाए थे। मामला उठने के बाद एसडीएम का तबादला कर दिया गया।

विधायक काका राजिंदर सिंह (समाना) : पुलिस पर उनका और उनके सचिव का फोन टैप करने का आरोप लगाया। विधायक के आरोप लगाने के बाद सीआइए समाना के इंचार्ज इंस्पेक्टर विजय कुमार का तबादला कर दिया गया।

मदन लाल जलालपुर (घनौर) : थाना प्रभारी पर कांग्रेस के सरपंच पर हमला करने वालों पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। इसके बाद थाना खेड़ी गंडियां के इंचार्ज को निलंबित कर दिया गया।

बीएचयू के मुस्लिम शिक्षक प्रकरण में प्रोफेसरों ने छेड़ा अभियान

जागरण संवाददाता, वाराणसी : बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी स्थित संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय में सहायक प्रोफेसर फिरोज खान की नियुक्ति के विरोध में अब प्रोफेसर भी मैदान में कूद गए हैं। रविवार को लगभग 50 प्रोफेसरों व संस्कृत विद्वानों ने राष्ट्रपति को पत्र भेजकर मामले में हस्तक्षेप की मांग की। दूसरी ओर संकाय में अवकाश के चलते रुइया छात्रावास में आंदोलनरत छात्रों ने अगली रणनीति बनाने के लिए मंथन किया।

संकाय में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर फिरोज खान की नियुक्ति को लेकर छात्र आंदोलन के बीच शनिवार को ही दो प्रोफेसर प्रो. रेवा प्रसाद द्विवेदी व कमलेश दत्त त्रिपाठी भी राष्ट्रपति को पत्र भेज चुके हैं। इसी क्रम में और कई प्रोफेसर व संस्कृत भाषा के विद्वान राष्ट्रपति को पत्र भेज रहे हैं। अभी तक इस प्रकरण में मौन रहे संस्कृत के विद्वान व बीएचयू के संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के एमेरेटस प्रोफेसर चितरंजन ज्योतिषी भी आहत हैं। अन्य प्रोफेसरों के साथ ही उन्होंने भी राष्ट्रपति को पत्र भेजकर प्रकरण के समाधान का अनुरोध किया है। वहीं, फिरोज प्रकरण को लेकर आरएसएस का विवि प्रशासन के पक्ष में बयान आने के बाद छात्र काफी नाराज हो गए थे और विश्व संवाद केंद्र का घेराव कर धरना दिया था। उसी सयम से आरएसएस पदाधिकारी दो खेमे में बंट गए।

भगवान राम की प्रतिमा की सुरक्षा के लिए गुजरात मॉडल पर विचार

रविप्रकाश श्रीवास्तव, अयोध्या

▶ सुरक्षा अध्ययन के लिए अहमदाबाद जा सकते हैं एसएसपी

▶ 251 मीटर ऊंची इस प्रतिमा के लिए 447.46 करोड़ की राशि की गई है मंजूर

रामनगरी में लगने वाली भगवान राम की प्रतिमा की सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता रणनीति बन रही है। 251 मीटर ऊंची इस प्रतिमा की बेहतर सुरक्षा के लिए गुजरात मॉडल पर विचार चल रहा है। गुजरात में सरदार पटेल की प्रतिमा की सुरक्षा को लेकर जो व्यवस्था की गई है। उसी तरह भगवान राम की प्रतिमा की हिफाजत देखने को मिल सकती है। इसके लिए एसएसपी आशीष तिवारी के साथ कुछ जिम्मेदार अधिकारी गुजरात जा सकते हैं।

गुजरात में स्थापित 182 मीटर ऊंची सरदार पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया में अपनी तरह की सबसे ऊंची प्रतिमा है। अयोध्या में लगने वाली भगवान की प्रतिमा इससे भी ऊंची होगी। सुरक्षा अध्ययन के लिए फिलहाल अधिकारियों को अनुमति नहीं मिली है, लेकिन इसे लेकर प्रक्रिया चल रही है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में भगवान राम की 251 मीटर ऊंची प्रतिमा लगाने की तैयारी तेजी से आगे बढ़ रही है। अयोध्या पर फैसला आने के बाद इसको लेकर शासन गंभीर हो गया है। योगी कैबिनेट ने प्रतिमा के लिए 447.46 करोड़ की राशि मंजूर कर दी है। प्रतिमा के लिए कुल 61 हेक्टेयर भूमि की दरकार है। परियोजना 2022 में पूर्ण किए जाने का लक्ष्य है।

प्रस्तावित विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा के बेसमेंट में भव्य सभागार होगा। मनोहारी संग्रहालय में भगवान राम के पूर्ववर्ती विष्णु के सभी 24 अवतारों की प्रतिमाएं एवं उनके बारे में जानकारी सहित रामजन्मभूमि की मुक्ति के लिए संघर्ष का इतिहास प्रदर्शित किया जाएगा। प्रस्तावित प्रतिमा के इर्द-गिर्द विश्रामघर, श्रीरामकुटी, डिजिटल म्यूजियम, लाइब्रेरी, पार्किंग, लैंड स्केपिंग भी विकसित करना प्रस्तावित है। इसे देखते हुए सुरक्षा व निगरानी के अभूतपूर्व इंतजाम की तैयारी चल रही है। एसएसपी का कहना है कि प्रतिमा की निगरानी के सबसे बेहतर व आधुनिक इंतजाम हों, इसे लेकर उच्चाधिकारियों से लगातार मार्गदर्शन प्राप्त किया जा रहा है।

राजसदन में भी सम्मानित हुए रामलला के अधिवक्ता

जासं, अयोध्या : सुप्रीम कोर्ट में रामलला विराजमान की पैरवी करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता के. परासरन रविवार को राजसदन के मेहमान बने। राजपरिवार के मुखिया बिमलेंद्रमोहन मिश्र, उनके अनुज शैलेंद्रमोहन मिश्र एवं उनके पुत्र यतींद्र मिश्र ने परासरन तथा उनके साथ आए रामलला की पैरवी करने वाले पीवी योगेश्वरन, केंद्र सरकार के पूर्व सॉलिसिटर जनरल मोहन परासरन, सतीश परासरन आदि का अभिनंदन किया। उन्हें उत्तरीय, स्मृति चिह्न आदि प्रदान किए। मिश्र ने परासरन और उनके सहयोगी अधिवक्ताओं के अवदान को अप्रतिम बताया। कहा, उन्होंने देश के लिए चुनौती बने सदियों पुराने विवाद का संवैधानिक दायरे में पटाक्षेप कर राममंदिर के साथ राष्ट्रमंदिर की भी संभावनाएं प्रशस्त की हैं। यदि राममंदिर के विषय को पूरी प्रामाणिकता से प्रस्तुत करने वाले अधिवक्ता न होते तो यह विवाद किस करवट बैठता इसकी कल्पना की जा सकती है। सदियों पुराने विवाद का गौरवमय समापन करने वाले अधिवक्ता हमारे लिए किसी नायक से कम नहीं हैं। दिल्ली से आए अधिवक्ताओं का दल शनिवार से ही रामनगरी के प्रवास पर है। शनिवार को इस दल ने विहिप नेताओं के साथ रामलला के रिसीवर मंडलायुक्त मनोज मिश्र को सुप्रीम फैसले की प्रति सौंपी।

अयोध्या पर पुनर्विचार याचिका से हिंदू और मुस्लिम एकता को होगा नुकसान : रिजवी

नई दिल्ली, प्रेट्र : राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (एनसीएम) के अध्यक्ष गयूरुल हसन रिजवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अयोध्या में राम मंदिर निर्माण पर आए फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करना मुस्लिमों के हित में नहीं होगा। इससे हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच एकता को नुकसान पहुंचेगा। अल्पसंख्यक आयोग के प्रमुख ने कहा कि पुनर्विचार याचिका दायर करने से हिंदुओं के बीच ऐसा संदेश जाएगा कि वे राम मंदिर के निर्माण के रास्ते में रोड़े अटका रहे हैं। उन्होंने मुस्लिम पक्ष से मस्जिद के लिए दी गई पांच एकड़ की वैकल्पिक भूमि को स्वीकार करने का भी अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि ऐसा करना न्यायपालिका का सम्मान होगा।

रविवार को एक साक्षात्कार में रिजवी ने कहा कि एनसीएम ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक बैठक की थी और उसके सभी सदस्यों ने एक सुर में कहा था कि फैसले को स्वीकार करना चाहिए। एनसीएम अध्यक्ष ने कहा कि मुस्लिमों को अयोध्या में मंदिर बनाने में मदद करनी चाहिए जबकि हिंदुओं को मस्जिद के निर्माण में मदद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह दोनों समुदायों के बीच सामाजिक सौहार्द को मजबूत करने में मील का पत्थर साबित होगा। रिजवी के अनुसार, पुनर्विचार याचिका दायर करने से हिंदुओं के बीच यह संदेश जाएगा कि मुस्लिम समुदाय अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की राह में रोड़े अटकाना चाहता है। उन्होंने कहा कि इससे हिंदू-मुस्लिम एकता को 'नुकसान' पहुंचेगा।

जमीयत जैसे संगठन वादे से मुकरे : उन्होंने कहा, 'पुनर्विचार याचिका दायर नहीं करनी चाहिए क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआइएमपीएलबी) और जमीयत उलेमा-ए-हिंद समेत सभी पक्षों ने वादा किया था कि सुप्रीम कोर्ट के गए फैसले का सम्मान किया जाएगा।' उन्होंने आरोप लगाया कि एआइएमपीएलबी और जमीयत जैसे मुस्लिम संगठन अपने वादे से मुकर रहे हैं।

आम मुस्लिम याचिका के पक्ष में नहीं

रिजवी ने पूछा, 'सिर्फ अभी नहीं बल्कि कई वर्षों से वे कह रहे हैं कि वे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार करेंगे तो फिर पुनर्विचार की क्या जरूरत है?' उन्होंने पूछा कि पुनर्विचार याचिका दायर करने का क्या औचित्य है जब वे भी कह रहे हैं कि याचिका '100 फीसद' खारिज कर दी जाएगी। एनसीएम प्रमुख ने कहा, 'इस देश का आम मुस्लिम पुनर्विचार याचिका के पक्ष में नहीं है क्योंकि वह नहीं चाहता कि जो मामले सुलझ गए हैं उन्हें फिर उठाया जाए और समुदाय ऐसी चीजों में फंसे।'

ओवैसी मुस्लिमों का इस्तेमाल कर रहे

रिजवी ने कहा कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन (एआइएमआइएम) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी समेत एआइएमपीएलबी के सिर्फ चार-पांच सदस्य ही पुनर्विचार याचिका के पक्ष में हैं। एनसीएम प्रमुख ने आरोप लगाया कि ओवैसी मुस्लिमों का इस्तेमाल करके राजनीति करते हैं और वह उन्हें ऐसे मुद्दों में उलझाए रखना चाहते हैं ताकि उन्हें वोट मिल सकें।

परीक्षा के लिए छात्रा को रुविवि भेजेगा जेल प्रशासन

जासं, शाहजहांपुर

चिन्मयानंद प्रकरण

▶ छात्रा का सोमवार को एलएलएम द्वितीय सेमेस्टर का बैक पेपर है

▶ परीक्षा देने को लेकर अब भी बना हुआ है संशय

पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद से ब्लैकमेलिंग के आरोप में जेल में बंद छात्रा को परीक्षा के लिए जेल प्रशासन सोमवार को एमजेपी रुहेलखंड विश्वविद्यालय भेजेगा। हालांकि, परीक्षा देने के संबंध में अभी संशय बना हुआ है। जेल प्रशासन का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर छात्रा को बरेली में विश्वविद्यालय ले जाया जाएगा। परीक्षा में बैठने देने पर निर्णय विश्वविद्यालय प्रशासन ही लेगा। छात्रा का सोमवार को एलएलएम द्वितीय सेमेस्टर का बैक पेपर है। जबकि 26 नवंबर से एलएलएम तृतीय सेमेस्टर की भी परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। जेल अधीक्षक राकेश राय ने बताया कि हमें कोर्ट का आदेश मिल गया है। छात्रा को बरेली भेजा जाएगा। उसे वहां परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाती है या नहीं, इस बारे में निर्णय विश्वविद्यालय प्रशासन लेगा। रुविवि की रजिस्ट्रार सुनीता पांडेय ने बताया कि कोर्ट की ओर से अभी कोई आदेश नहीं मिला है। यदि आदेश मिलता है तो बैठक के बाद उस पर निर्णय लिया जाएगा।

भाजपा नेता के बेटे को पुलिस ने रिसीव कराया समन : चिन्मयानंद से ब्लैकमेलिंग के आरोपित भाजपा नेता डीपीएस राठौर व भाजयुमो के पूर्व महामंत्री अजीत सिंह के नाम सीजेएम ने दो दिन पहले दोबारा समन जारी किया था। रविवार दोपहर पुलिस डीपीएस राठौर के सेठ इंक्लेव स्थित आवास पर पहुंची, जहां वह नहीं मिले। उनकी अनुपस्थिति में उनके बेटे को समन रिसीव कराकर पुलिस वापस हो गई। अब भाजपा नेता को तीन दिसंबर को ब्लैकमेलिंग के अन्य आरोपितों के साथ कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। उधर, दूसरे आरोपित भाजयुमो नेता अजीत सिंह को अभी समन रिसीव नहीं कराया जा सका है। आरसी मिशन थाना के प्रभारी निरीक्षक संजय सिंह ने बताया कि अजीत सिंह का समन हमें अभी नहीं मिला है।

एक दिन में 1431 श्रद्धालुओं ने करतारपुर साहिब के किए दर्शन

महिंदर सिंह अर्लीभन्न, डेरा बाबा नानक (गुरदासपुर)

▶ करतारपुर पैसेंजर टर्मिनल पर पहली बार दिखीं श्रद्धालुओं की कतारें

▶ अब तक कुल 6427 लोग कर चुके हैं करतारपुर साहिब की यात्रा

डेरा बाबा नानक में करतारपुर कॉरिडोर खुलने के 16वें दिन पहली बार रिकॉर्ड 1431 श्रद्धालु सीमा पार गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब के दर्शन के लिए गए। हालांकि सूची में 1785 श्रद्धालु शामिल थे, लेकिन 354 श्रद्धालु पैसेंजर टर्मिनल पर नहीं पहुंचे। दो हफ्ते बाद श्री करतारपुर साहिब के दर्शन करने जाने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा भी 6247 तक पहुंच गया है।

उद्घाटन के बाद पहली बार रविवार को करतारपुर पैसेंजर टर्मिनल पर श्रद्धालुओं की कतारें देखने को मिलीं। संगत की संख्या को देखते हुए पाकिस्तान की ओर से बसों का प्रबंध किया गया था। श्रद्धालुओं ने बताया कि गुरुद्वारा साहिब में पाकिस्तान गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से बहुत अच्छे प्रबंध किए गए हैं। सूजी व मूंगी का कड़ाह प्रसाद के अलावा मखाने, छुहारे और बादाम का प्रसाद भी संगत को बांटा गया।

भारत और पाकिस्तान के बीच हुए समझौते के मुताबिक कॉरिडोर से रोजाना पांच हजार तक श्रद्धालु जा सकते हैं, लेकिन श्रद्धालुओं की संख्या बेहद कम रही। इसे देखते हुए सिख संगठनों की तरफ से पासपोर्ट की अनिवार्यता खत्म करने और पाकिस्तान द्वारा लगाई गई 20 डालर की फीस खत्म करने की मांग उठ रही है। पंजाब सरकार ने शनिवार को डेरा बाबा नानक बस स्टैंड से कॉरिडोर के पैसेंजर टर्मिनल तक शटल बस सेवा शुरू कर दी है।

पाकिस्तान में गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब के दर्शन कर लौटे श्रद्धालु। जागरण

एक जैसे दो खाता संख्या मामले में बैंक ने सुधारी गलती

नईदुनिया, भिंड

मध्य प्रदेश के भिंड में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की आलमपुर शाखा के अधिकारियों ने दो ग्राहकों को एक ही खाता नंबर जारी करने की गलती में सुधार कर लिया है। एक ही खाता नंबर होने पर एक ग्राहक रकम जमा करता रहा और दूसरा ग्राहक रुपये निकालता रहा। यह क्रम करीब एक साल तक चलता रहा। बैंक ने अपनी ओर से अब उस ग्राहक के खाते में 81 हजार 60 रुपये जमा कराए हैं, जिसके पैसे दूसरे ग्राहक ने निकाल लिए थे। नए खाता नंबर के साथ नई पासबुक सोमवार को दी जाएगी। खाते से रकम निकालने वाले ग्राहक से बैंक प्रबंधन ने लिखित में आश्वासन लिया है कि वह दो माह में निकाली गई रकम वापस करेगा। ऐसा न करने पर उसके खिलाफ एफआइआर कराई जाएगी।

आलमपुर के रूरई गांव निवासी हुकुम सिंह कुशवाह हरियाणा में गोलगप्पे बेचने का काम करते हैं। उन्होंने आलमपुर की एसबीआइ शाखा में बचत खाता खुलवाया था। बैंक से उन्हें 12 नवंबर 2018 को पासबुक दी गई। इसमें ग्राहक संख्या 88613177424 थी और बचत खाता संख्या 20313782314 थी। हुकुम सिंह हरियाणा से इस खाते में समय-समय पर रुपये जमा कराते रहे। इधर इससे पहले रोनी गांव निवासी हुकुम सिंह बघेल को बैंक की ओर से यही ग्राहक संख्या और इसी खाता नंबर की पासबुक जारी की गई थी। बघेल ने खाता आधार नंबर से लिंक करा लिया था। हरियाणा से हुकुम सिंह कुशवाह रकम जमा कराते और यहां हुकुमसिंह बघेल उसे अपना समझ निकाल लेते। बीते दिनों मामला सामने आने के बाद कुशवाह ने बैंक प्रबंधन से शिकायत की थी। लापरवाही का पता लगते ही बैंक प्रबंधन के हाथ-पांव फूल गए थे। रुपये निकालने वाले बघेल ने मीडिया को बताया कि वे समझ रहे थे कि मोदी जी खाते में पैसा जमा करा रहे हैं, इसलिए उन्होंने कोई पूछताछ नहीं की और रकम निकालते रहे।

रविवार को बुलाया बैंक, रकम जमा की : हुकुम सिंह कुशवाह ने बताया कि रविवार को बैंक मैनेजर राजेश सोनकर ने उन्हें बुलाया। ग्वालियर से आए दो अधिकारी भी साथ थे। बैंक में उन्हें बताया गया कि उनको नया खाता नंबर दिया जा रहा है। इस खाते में बघेल द्वारा निकाले गए 81 हजार 60 रुपये जमा कराए गए। नए खाते की पासबुक सोमवार को दी जाएगी। कुशवाह का कहना है कि प्रबंधन ने हुकुम सिंह बघेल को भी बुलवाया था। बघेल का खाता नंबर भी बदला जा रहा है। जानकारों के मुताबिक बैंक में इस तरह के मामलों में भरपाई के लिए एक विशेष खाता होता है। फिलहाल उसी खाते से रुपये जमा कराए गए हैं।

चर्चा

अभाविप के राष्ट्रीय अधिवेशन में रोजगार परिदृश्य और संभावनाओं पर हुई चर्चा

मेक इन इंडिया से निर्यात वाला देश बन रहा भारत

जागरण संवाददाता, आगरा

मेक इन इंडिया से भारत वैश्विक बाजार में निर्यात करने वाला देश बनता जा रहा है। रेलवे और रक्षा के क्षेत्र में भारत उत्पादों को निर्यात करने लगा है। आने वाले समय में दुनियाभर में भारत से मोबाइल निर्यात किए जाएंगे। रविवार को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) के अंशकालिक निदेशक सतीश मराठे ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) के 65 वें राष्ट्रीय अधिवेशन में 'रोजगार परिदृश्य एवं संभावनाओं' पर आयोजित विमर्श में कहा कि स्वरोजगार और कौशल से भारत की अर्थव्यवस्था में उछाल आएगा।

आगरा कॉलेज मैदान पर सजाए गए गुरुनानक देव नगर में उन्होंने कहा कि चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए भारतीय बाजार और यहां के उद्योगपति तैयार नहीं हैं। यह चिंता का विषय है, विनिर्माण के क्षेत्र में निवेश नहीं हो रहा है। मगर, मेक इन इंडिया के सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। ट्रेड एंड टैरिफ पॉलिसी में किए जा रहे बदलाव से भी अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। 25 नवंबर तक चलने वाले अधिवेशन में 40 प्रांत के 1800 अभाविप पदाधिकारी शामिल हुए हैं। अभाविप के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. एस सुबय्या, राष्ट्रीय महामंत्री निधि त्रिपाठी आदि मौजूद रहीं। सतीश मराठे ने कहा कि महंगाई दर 2.5 फीसद से बढ़कर 4.10 तक पहुंच गई है। इसमें प्याज के कारण 0.75 फीसद महंगाई बढ़ी है। यह कुछ दिन में नियंत्रण में आ जाएगी।

औद्योगिक नीति के साथ बने रोजगार नीति भी : जेएनयू के अर्थशास्त्र विभाग के डॉ. संतोष मेहरोत्रा ने कहा कि 2008 की वैश्विक मंदी के बाद दुनिया के 100 देशों ने औद्योगिक नीति लागू की है, लेकिन भारत में यह नीति लागू नहीं हो सकी है। भारत में केवल औद्योगिक नीति से काम नहीं चलेगा। इसके साथ रोजगार नीति भी बनाने की जरूरत है। मगर, सरकार ने रोजगार नीति पर काम शुरू नहीं किया है। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं तलाशनी चाहिए। मार्डन सर्विस सेक्टर में रोजगार के अवसर खुल रहे हैं।

आगरा में अभाविप के राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित करते भारतीय रिजर्व बैंक के अंशकालिक निदेशक सतीश मराठे। मंचासीन हैं अभाविप के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. एस सुबय्या, डॉ. संतोष मेहरोत्रा व अन्य। जागरण

अमेरिकी विवि की रिसर्च बुक में शामिल हुईं 'टॉयलेट मैडम'

नईदुनिया, रायगढ़

▶ स्वच्छता अभियान को लेकर किए गए कार्यों के कारण मिली जगह

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ की टॉयलेट मैडम कही जाने वाली मोनिका को अमेरिकी विश्वविद्यालय ने अपनी रिसर्च बुक में जगह दी है। स्वच्छ भारत मिशन में उल्लेखनीय काम करने वाली मोनिका इजारदार को पेंसिलवेनिया की रिसर्च बुक में शामिल किया गया है और मोनिका को इस मिशन में ट्रेंड सेटर बताकर उनका साक्षात्कार प्रकाशित किया है। पेंसिलवेनिया की इस रिसर्च बुक में मोनिका के अलावा जशपुर की पूर्व कलेक्टर प्रियंका शुक्ला, स्वच्छ भारत मिशन के ब्रांड अम्बेसडर अमिताभ बच्चन, भारत के कैबिनेट सचिव पीके सिन्हा सहित कई लोगों का भी जिक्र किया गया है।

बता दें कि विश्वविद्यालय ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत भारत में किए जा रहे कामों पर एक शृंखला बनाई है। विश्वविद्यालय की क्रिस्टीना बच्चेरी ने भारत में स्वच्छ भारत मिशन के प्रेरकों द्वारा गांवों को खुले में शौच मुक्त करने के तरीकों और उसकी सफलता को लेकर अपनी रिपोर्ट तैयार की है। इसमें प्रेरकों के जरिए पूरे देश में आंदोलन की तरह लोगों में जागरूकता लाने कैसे काम किए गए और उसका क्या प्रभाव रहा इस पर रिसर्च बुक तैयार की गई है। इसमें मोनिका का भी एक संक्षिप्त साक्षात्कार प्रकाशित किया गया है। मालूम हो कि मोनिका इजारदार ने दुर्गम आदिवासी अंचलों में जाकर ओडीएफ के लिए काम किया था।

मोनिका इजारदार। नईदुनिया

सबरीमाला की यात्रा के लिए रेहाना को सुरक्षा नहीं देगी केरल पुलिस

कोच्चि, प्रेट्र : केरल पुलिस विवादास्पद कार्यकर्ता रेहाना फातिमा को सबरीमाला स्थित भगवान अय्यपा मंदिर में प्रवेश के लिए सुरक्षा नहीं प्रदान करेगी। केरल सरकार ने यह फैसला किया है कि जब तक उसे कोर्ट का आदेश नहीं मिल जाता, तब तक वह पारंपरिक रूप से प्रतिबंधित आयुवर्ग वाली महिलाओं को मंदिर में प्रवेश के लिए सुरक्षा नहीं प्रदान करेगी।

फातिमा ने पिछले साल अक्टूबर में 30 साल की उम्र में पुलिस सुरक्षा के बीच मंदिर में प्रवेश का प्रयास किया था, लेकिन भारी विरोध के कारण लौटना पड़ा था। इस साल भी फातिमा ने मंदिर में प्रवेश के लिए आवेदन किया है और पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार भगवान अय्यपा मंदिर में 10-50 वर्ष की महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल सभी उम्र की महिलाओं को भगवान अयप्पा मंदिर में प्रवेश की इजाजत दे दी थी, लेकिन हाल ही में उसने अपने निर्णय की समीक्षा के लिए मामले को बड़ी पीठ में भेजने का निर्णय लिया है।

Download UPSC IAS Material: www.iascgl.com

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
सोमवार 25 नवंबर 2019

दैनिक जागरण
पढ़ना मस्तिष्क के लिए वैसा ही है, जैसा शरीर के लिए व्यायाम

महाराष्ट्र सरकार का भविष्य

आनन-फानन बनी महाराष्ट्र की नई सरकार के खिलाफ उच्चतम न्यायालय पहुंचे दलों को तत्काल कोई राहत नहीं मिल सकी तो इसका एक मतलब यह भी है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस और उपमुख्यमंत्री अजीत पवार को बहुमत साबित करने की तैयारी के लिए कुछ और समय मिल गया। किसी के लिए भी कहना कठिन है कि उच्चतम न्यायालय आवश्यक दस्तावेजों को देखने के बाद क्या आदेश देता है, लेकिन माना यही जा रहा है कि वह फड़नवीस सरकार को बहुमत साबित करने के लिए निर्देशित कर सकता है। देखना है कि इस सूरत में वह फड़नवीस सरकार को कितने समय की मोहलत देता है? उच्चतम न्यायालय का फैसला जो भी हो, अभी यह जानने का कोई उपाय नहीं कि किसका पलड़ा भारी है? भले ही अजीत पवार के साथ आए विधायकों में से अधिकांश शरद पवार के पास लौट गए हों, लेकिन यह कहना कठिन है कि बहुमत परीक्षण की स्थिति में वे किसके हिसाब से चलेंगे-शरद पवार के हिसाब से या अजीत पवार के हिसाब से? इसे लेकर संशय इसलिए भी है, क्योंकि जहां शरद पवार खेमे के लोग कह रहे हैं कि करीब-करीब सभी विधायक उनके साथ हैं वहीं अजीत पवार कह रहे हैं कि उनकी सरकार बहुमत साबित करने में समर्थ रहेगी। वह यह भी दावा कर रहे हैं कि चाचा शरद पवार का आशीर्वाद उनके साथ है। पता नहीं ऐसा है या नहीं, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि फड़नवीस सरकार को सहारा देने में अजीत पवार के साथ निर्दलीय विधायकों की भी भूमिका महत्वपूर्ण होगी।

आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में जोड़-तोड़ की राजनीति चाहे जो शक्ल ले, जो लोग कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना की बेमेल सरकार बनते देखकर राहत की सांस ले रहे थे वे अजीत पवार संग भाजपा की सरकार को लेकर शिकायत दर्ज कराने के अधिकारी नहीं रह गए हैं। उन्हें यह समझना चाहिए कि भाजपा से शिवसेना की दगाबाजी के साथ ही महाराष्ट्र में जोड़-तोड़ से सरकार बनना सुनिश्चित हो गया था। यह सही है कि शिवसेना के नेतृत्व में बनने वाली सरकार में भी अजीत पवार उपमुख्यमंत्री बनते, लेकिन शायद उन्होंने यह पाया कि उस सरकार की तुलना में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ज्यादा स्थिर होगी। यह मानने के भी अच्छे-भले कारण हैं कि वह शरद पवार की छत्रछाया से बाहर आने का अवसर खोज रहे थे। उनकी राजनीतिक रणनीति और महत्वाकांक्षा का जो भी हश्र हो, शिवसेना के साथ कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेताओं को राजनीतिक नैतिकता का उपदेश देने का कोई अधिकार नहीं। सब जानते हैं कि इन दलों के नेता जो कर रहे थे वह घोर अवसरवाद ही था।

शिक्षकों का प्रदर्शन

उत्तराखंड में शिक्षकों की ग्रेडिंग उनके प्रदर्शन के आधार पर होगी। शासन ने इस संबंध में शिक्षा महकमे को कार्रवाई करने को कहा है। प्रदर्शन के लिए बोर्ड परीक्षा के स्थान पर मासिक परीक्षा को आधार बनाया जाएगा। यह अच्छा कदम है। इससे विद्यालयों में शैक्षिक माहौल बनाने में भी मदद मिलेगी। अभी तक माध्यमिक शिक्षकों के प्रदर्शन का आकलन हाईस्कूल और इंटर की बोर्ड परीक्षा के परिणामों से किया जाता रहा है। वहीं प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षकों का आकलन विद्यालयों में छात्रों के सतत एवं व्यापकमूल्यांकन के आधार पर करने पर जोर दिया गया। बावजूद यह पैटर्न कामयाब नहीं हो सका। इसके स्थान पर अब मासिक परीक्षा के प्रदर्शन से शिक्षकों का मूल्यांकन किए जाने से कक्षाओं में शिक्षकों की नियमित उपस्थिति और अच्छे परिणाम देने के लिए प्रतिस्पर्धा का भाव बढ़ेगा। शासन ने निजी विद्यालयों में मासिक परीक्षा की तर्ज पर ही सरकारी प्राथमिक से लेकर माध्यमिक विद्यालयों में इसे लागू किया है। अच्छी बात ये है कि मासिक परीक्षा के पैटर्न में बदलाव भी किया गया है। पहले केंद्रीयकृत तरीके से तैयार किए जा रहे प्रश्नपत्र और विद्यालयों तक पहुंचाने और फिर मासिक परीक्षा कराने के तरीके में कई तरह की खामियां सामने आ चुकी हैं। इस मुद्दे पर शासन स्तर पर भी मंथन हो चुका है। इसके बाद ही महकमे को मासिक परीक्षा के आधार पर ग्रेडिंग देने का फार्मूला तैयार करने को कहा गया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इससे बेहतर परिणाम आएगा। खासतौर पर विद्यालयों में पठन-पाठन पर जोर देने वाले और अध्यापन को सरल व सुगम बनाने के लिए आधुनिक तकनीक व नई पहल करने वाले शिक्षकों को इस कदम से स्वाभाविक रूप से प्रोत्साहन मिल सकेगा। इस योजना में सर्वश्रेष्ठ चिह्नित होने वाले शिक्षकों को मास्टर ट्रेनर बनाने पर भी विचार किया जाएगा, ताकि अच्छे शिक्षकों की कारगर शिक्षण विधि का लाभ अन्य शिक्षक भी उठा सकें। अभी तक सरकार और महकमा दोनों ही स्तर पर अच्छे शिक्षकों का मूल्यांकन और उन्हें प्रोत्साहित करने को लेकर उत्साह नहीं दिखाया गया है। शिक्षकों को उल्लेखनीय कार्यों के लिए पुरस्कृत करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य शिक्षक पुरस्कार से कुछ चुनिंदा शिक्षकों को सम्मानित कर इतिश्री की जाती रही है। मासिक परीक्षा के बहाने शिक्षण कार्य में यदि अपेक्षित सुधार होता है तो इसे सराहा जाना चाहिए। हालांकि देखना यह भी होगा कि यह प्रयोग जमीन पर उतरता भी है या सिर्फ रस्म अदायगी साबित होकर रह जाएगा।

लोक उत्सव बने संविधान दिवस

हृदयनारायण दीक्षित

26 नवंबर को संविधान दिवस का आयोजन राष्ट्रीय उत्सव के रूप में मनाया जाना चाहिए। संविधान मानने और जानने में ही भारतीय लोकतंत्र का भविष्य निहित है

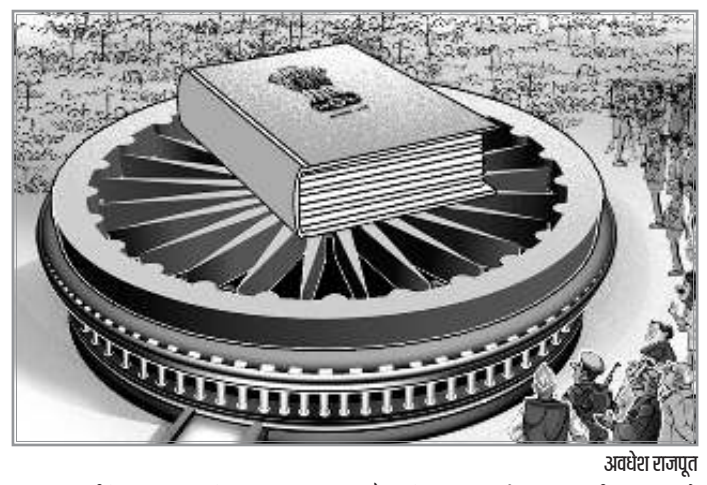

अवधेश राजपूत

संविधान भारत का राजधर्म है। संविधान का निर्माण 1946 में गठित संविधान सभा ने किया था। सभा ने विभिन्न विषयों पर 17 समितियां गठित की थीं। सभाध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद प्रक्रिया, संचालन सहित चार समितियों के सभापति थे। इसी तरह संघीय विधान सहित तीन समितियों के सभापति पं. नेहरू थे। सरदार पटेल मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक आदि मामलों की समिति के सभापति थे। प्रारूप समिति के सभापति डॉ. बीआर आंबेडकर का काम विशिष्ट था। डॉ. आंबेडकर ने ही संविधान पारण का प्रस्ताव रखा था। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार हुआ। इस प्रकार 26 नवंबर, 1949 की तिथि भारतीय गणतंत्र के लिए ऐतिहासिक महत्व की है। इस ओर सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही ध्यान गया। मुंबई में डॉ. आंबेडकर की प्रतिमा का शिलान्यास करते हुए मोदी ने 11 अक्टूबर, 2015 को एलान किया कि 26 नवंबर संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस अवसर पर मंगलवार को वह संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का भी इसी प्रयोजन के लिए 26 नवंबर को विशेष सत्र आयोजित होगा।

संविधान सर्वोच्च विधि है, लेकिन कई अर्थों में यह विश्व के अन्य संविधानों से भिन्न है। इसकी उद्देशिका विशिष्ट है। इसके अनुसार संविधान की सर्वोपरिता का मुख्य शक्ति स्रोत 'हम भारत के लोग' हैं। 'हम भारत के लोगों' ने संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए इस संविधान को अधिनियमित व अंगीकृत किया है। उद्देशिका में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय, समता व बंधुता के राष्ट्रीय स्वप्न हैं। संविधान निर्माताओं ने दुनिया के कई संविधानों से अनुभव लिए। आयरलैंड से राज्य के नीति निदेशक तत्वों की प्रेरणा ली। संसदीय प्रणाली ब्रिटिश परंपरा का अनुभव है। मूल अधिकार अमेरिकी संविधान के अनुभव हैं। वैसे प्राचीन भारत में लोकतंत्र व नीति निदेशक तत्वों जैसी धारणा पहले भी थी। यह बात संविधान सभा में डॉ. आंबेडकर ने ही कही थी। अन्य देशों से अलग भारत के संविधान में प्रशासनिक उपबंध भी हैं। नीति निदेशक तत्व खूबसूरत निर्देश हैं। संविधान में मूल कर्तव्य हैं। मूल अधिकारों का दायरा बड़ा है, वैसे ही मूल कर्तव्यों की व्यापकता भी है।

राजनीतिक तंत्र में मूल अधिकारों के प्रति सजगता जरूरत से ज्यादा है। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र का आधार है। यह हमारे संविधान का मूलरस है, लेकिन प्रायः इसका दुरुपयोग होता है। विधायी सदनों में असीम वाक् स्वातंत्र्य है, लेकिन संसदीय सदनों का शोर आहतकारी है। अधिकार भोग के साथ कर्तव्य पालन भी प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। संविधान (अनुच्छेद 51ए) में मूल कर्तव्यों की सूची है। पहला कर्तव्य है-'संविधान का पालन करें। उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगान का आदर करें।' मगर तमाम राजनीतिक सामंत संविधान का आदर नहीं करते। दूसरा कर्तव्य सांस्कृतिक है, 'स्वतंत्रता के राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों का पालन करें।' लेकिन यहां वंदे मातरम पर भी विवाद हैं। तीसरे कर्तव्य में देश की एकता, संप्रभुता व अखंडता की रक्षा है, लेकिन विश्वविद्यालयों में भी भारत के टुकड़े करने की धौंस है। सार्वजनिक संपदा की सुरक्षा भी मूल कर्तव्य है। यहां तमाम आंदोलनकारी बसों व दफ्तरों में आग लगाते हैं। पर्यावरण, संरक्षण वाले मूल कर्तव्य की घोर उपेक्षा है। सामासिक संस्कृति की परंपरा का संवर्धन भी एक कर्तव्य है। 'सामासिक संस्कृति' शब्द के भ्रम को सर्वोच्च न्यायालय ने दूर किया था 'कि सामासिक संस्कृति का आधार संस्कृत भाषा और साहित्य है। यही भिन्न जनों को एक सूत्र में बांधती है।' न्यायालय की इस व्याख्या की भी उपेक्षा है।

संविधान निर्जीव शब्द संचय नहीं होता। प्रत्येक संविधान का उद्देश्य और दर्शन भी होता है। भारत के संविधान का उद्देश्य 'हम भारत के लोग' की ऋद्धि, सिद्धि और समृद्धि है। संविधान सभा ने 22 जनवरी, 1947 को संविधान का उद्देश्य संकल्प पारित किया था। उसमें कहा गया था कि 'यह प्राचीन भूमि विश्व में अपना समुचित और गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त करेगी और विश्व शांति व मानव कल्याण के लिए पूरा सहयोग देगी।' यहां प्राचीन भूमि का अर्थ प्राचीन दर्शन व संस्कृति ही है। विश्व कल्याण के लिए भारत की तत्परता का संविधान में उल्लेख महत्वपूर्ण है। संविधान पूर्ण दस्तावेज है। उसमें संशोधन की जटिलता नहीं है। डॉ. आंबेडकर ने सभा में ठीक ही कहा था, 'जो लोग संविधान से असंतुष्ट हैं, उन्हें केवल दो-तिहाई बहुमत प्राप्त करना है। यदि वे निर्वाचित संसद में दो-तिहाई बहुमत भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो यह नहीं समझा जा सकता कि जनसाधारण असंतोष में उनके साथ है।'

संविधान स्वयं शक्ति संपन्न नहीं होता। डॉ. आंबेडकर ने 25 नवंबर, 1949 को संविधान सभा के अंतिम भाषण में ठीक कहा था, 'संविधान चाहे जितना अच्छा हो यदि उसे संचालित करने वाले लोग बुरे हैं तो वह निश्चित ही बुरा हो जाता है।' डॉ. प्रसाद ने कहा था, 'संविधान किसी बात के लिए उपबंध करे या न करे, देश का कल्याण उन व्यक्तियों पर निर्भर करेगा जो देश पर शासन करेंगे।' इसका दुरुपयोग भी हुआ है। राज्य विधानसभाओं को भंग करने वाले अनुच्छेद 356 का लगभग सवा सौ बार दुरुपयोग हुआ। 1975 में की गई आपातकाल की उद्घोषणा अनुच्छेद 353 का घोर उल्लंघन थी। न्यायालयों की शक्ति घटाई गई। न्यायायिक पुनरावलोकन को कमतर किया गया। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान की पवित्रता नष्ट की गई।

संविधान प्रवर्तन के 70 वर्ष पूरे हो रहे हैं। संविधान में अनेक संस्थाएं हैं। उसमें सभी समस्याओं के समाधान हैं। संविधान के प्रवाह में भारतीय लोकतंत्र ने विश्व प्रतिष्ठा अर्जित की है, लेकिन देश का बहुमत संविधान से सुपरिचित नहीं है। बहुमत राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री के संवैधानिक प्राधिकार से भी परिचित नहीं है। समान नागरिक संहिता का संवैधानिक नीति निर्देश भी अल्प ज्ञात है। विधायिका के कामकाज की छवि अच्छी नहीं है। संविधान के अस्थायी अनुच्छेद 370 से भी कम लोग परिचित थे। उसके निरसन के बाद ही इस उपबंध की जानकारी राष्ट्रव्यापी हुई। राजनीतिक दलों के तमाम लोग भी संविधान नहीं जानते। प्रधानमंत्री की पहल पर संविधान दिवस का आयोजन हो रहा है। इसे राष्ट्रीय उत्सव के रूप में व्यापक होना चाहिए। उच्च शिक्षा में संविधान का ज्ञान अनिवार्य करने की भी जरूरत है। डॉ. पट्टाभि सीतारमैया ने सभा में कहा था, 'आखिरकार संविधान का क्या अर्थ है? यह राजनीति का व्याकरण है। राजनीतिक नाविक के लिए कुतुबनुमा। वह प्राणशून्य है। हम उसे और उपयोगी बना सकते हैं।' संविधान मानने और जानने में ही भारतीय लोकतंत्र का भविष्य निहित है।

(लेखक उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं)

response@jagran.com

आदर्शों से दूर होती राजनीति

देश ने दो अक्टूबर, 2019 को महात्मा गांधी को उनकी 150वीं जयंती पर याद किया। अनेक कार्यक्रमों में विद्वान वक्ताओं विशेषकर नेताओं ने गांधी जी के सिद्धांतों और मूल्यों की समसामयिक आवश्यकता को निरुपित किया और जनता को उनके बताए मार्ग पर चलने की सलाह दी। महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनावों के बाद जनता को यह देखने का एक और अवसर मिला कि देश के राजनेता गांधी जी के सिद्धांतों का कितना पालन करते हैं! हरियाणा में दो धुर-विरोधी दल साथ आ गए, मगर मंत्रिपरिषद बनाने में सहमति 17 दिन बाद ही बनी। सामान्य जन यही मानते हैं कि गठबंधन सरकारों में यह देरी मलाईदार महकमों को लेकर ही होती है। ऐसे वक्त पर गांधी जी की चर्चा नहीं होती। हरियाणा के बाद राजनीति में स्थायी भाव बन चुके पदलोलुपता, स्वार्थपरकता और पुत्रमोह जैसे तत्व बेहिचक और बेशर्मी से महाराष्ट्र में फिर एक बार सामने आए हैं। इसके झंझावात में प्रजातंत्र के मूल्य और सिद्धांत पूरी तरह बिखर गए हैं। स्वच्छता अभियान में भारत जितना आगे बढ़ा, प्रजातांत्रिक मूल्यों के अनुपालन में वह उससे कई गुना अधिक नीचे आ गया। इन दो राज्यों में जो कुछ वहां के नेताओं ने देश और समाज के समक्ष रखा है, वह हर उस व्यक्ति को शर्मसार करता है जो प्रजातांत्रिक मूल्यों में आस्था रखता है। मुझे आश्चर्य होता है जब कोई दल अपने सौ-पचास निर्वाचित प्रतिनिधियों को किसी होटल में पहुंचाता है। वे सब बंधक की स्थिति स्वीकार कर लेते हैं। कोई विरोध नहीं करता है। वे अनुशासन का नाम लेते हैं, मगर आत्मसम्मान को तिलांजलि देने में हिचकते नहीं। पूरे देश में यह भी चर्चा का विषय बन चुका है कि परिवारवाद और पुत्र मोह के कारण कई महत्वपूर्ण राजनीतिक दल अपना अस्तित्व खोने के कगार पर पहुंच चुके हैं, मगर न वे स्वयं सीख रहे हैं न ही अन्य उनसे सबक ले रहे हैं।

सभी को सरकार में शामिल होना है। इसी कारण केंद्र में भी जोड़तोड़ की सरकारें बनीं और बिखरीं। राज्यों में आयाराम-गयाराम से प्रारंभ हुआ सिलसिला खूब फला-फूला। जिन पर मूल्यों को स्थापित करने और गांधी जी की विरासत संभालने की जिम्मेदारी थी, वे स्वयं इस खेल में भागीदार बन गए। जनता देखती रह गई। हालांकि पिछले चार-पांच दशकों में लोगों की राजनीति की समझ बढ़ी है। अपने अधिकारों का न मिलना और हर स्तर के चयनित प्रतिनिधि के विशेष अधिकारों और सुविधाओं का लगातार बढ़ते जाना उनको खटकने लगा है। चयनित युवा प्रतिनिधियों के समक्ष बड़ी चुनौती है। क्या वे अपने वरिष्ठों का अस्वीकार्य आचरण भी चुपचाप सहन करेंगे या अपने मतदाताओं की अपेक्षाओं को साकार करने में स्वार्थ रहित सेवा भाव का उदाहरण प्रस्तुत करेंगे? उनके सामने दो विकल्प हैं। वे भी गांधी जी को भुला दें। केवल दो अक्टूबर को प्रतिवर्ष उन्हें श्रद्धांजलि देने की रस्म पूरी करते रहें। या उनके साहित्य का श्रद्धापूर्वक अध्ययन करें। उसे आज के बदले संदर्भ में समझें और अपनी क्षमता के अनुरूप उसे आचार-विचार में शामिल करें। आज चरखे से सूत कातने का एक विकल्प होगा कंप्यूटर का वह कौशल सीखना जो अंतिम व्यक्ति के जीवन को सार्थक

जगमोहन सिंह राजपूत

हमारा राजनीतिक तंत्र ऐसे दलदल में फंस गया है जिसमें 'सत्ता से सेवा' का स्थान 'सत्ता से स्वार्थ' में बदल चुका है

और गरिमामय बनाने में उपयोग में आ सके। अन्य भी हो सकते हैं। देश में आज भी विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे अनेक लोग हैं जिनका सार्वजनिक जीवन खुली किताब है। राजनीति में यह संख्या बढ़नी चाहिए और उभरनी चाहिए।

गांधी जी के स्वराज्य की संकल्पना में केवल अंग्रेजों का भारत से आधिपत्य समाप्त करना मात्र ही लक्ष्य नहीं था। उन्होंने मानव जीवन के हर पहलू पर गहन मनन, चिंतन और विमर्श किया और बिना किसी हिचक के लिखा कि सत्य की खोज में मैंने बहुत से विचारों को छोड़ा है और नई बातें सीखी भी हैं। उनकी तरह हर व्यक्ति को जीवन के प्रत्येक मोड़ पर यही लगना चाहिए कि उसका अपना विकास रुका नहीं है, मगर अनुभव के साथ गति पकड़ रहा है। जनता में यह धारणा ठोस आधारों पर निर्मित हुई है कि हमारा राजनीतिक तंत्र चुनावों की राजनीति में इतना जकड़ गया है कि उसमें 'सत्ता से सेवा' का स्थान 'सत्ता से स्वार्थ' में परिवर्तित हो गया है। अपेक्षा तो यह थी कि शासन लोक सम्मति से चलेगा। प्रत्येक जनप्रतिनिधि प्रतिपल यह जानने के लिए प्रयत्नशील रहेगा कि उसके क्षेत्र के मतदाता क्या चाहते हैं। वह अपना अधिकतम समय अपने क्षेत्र में ही बिताएगा। उसके आचरण में अपने ही लोगों से निकटता लगातार बढ़ेगी न कि उसकी अनुपलब्धता बढ़ती जाएगी! वे यह समझेंगे कि स्वराज्य का अर्थ आत्म-अनुशासन और आत्मसंयम है। अंग्रेजी शब्द 'इंडिपेंडेंस' अक्सर सभी प्रकार की मर्यादाओं से मुक्त निरंकुश आजादी या स्वच्छंदता का अर्थ देता है, वह अर्थ स्वराज्य में नहीं है। भारत में स्वराज्य आने के बहुत पहले ही गांधी जी ने उसके मूल आधार और शक्ति को समझ लिया था। उन्होंने कहा था कि मेरा स्वराज्य तो हमारी सभ्यता की आत्मा को अक्षुण्ण रखना है। स्वराज्य की रक्षा केवल वहीं हो सकती है जहां देशवासियों की ज्यादा बड़ी संख्या ऐसे देशभक्तों की हो जिनके लिए अपने देश की भलाई का ज्यादा महत्व हो। उनकी अपेक्षा थी कि स्वराज्य हमें और हमारी सभ्यता को 'अधिक शुद्ध और मजबूत' बनाएगा। भारत की सभ्यता के मूल तत्व नीति पालन यानी सदाचरण को वे सर्वोच्च स्थान देते थे।

स्वराज्य में सर्वहारा, संबंध, समता, समन्वय, संवाद, सम्मान और सेवा अनिवार्य तत्व हैं। इन्हें ठुकराकर की जाने वाली राजनीति उसी प्रकार दूषित हो रही है जैसे स्वतंत्रता के बाद नदियां और वायु प्रदूषित होती गईं। यदि समय रहते आवश्यक उपाय किए जाते तो आज हवा और पानी जहरीले नहीं हो गए होते। नई पीढ़ी के भविष्य में जहर नहीं घुल रहा होता। सभी देख रहे हैं कि राजनीति में भी प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है, मगर जितना ध्यान उसे रोकने के लिए दिया जाना चाहिए, वह नहीं हो रहा है। क्या अभी भी उचित दिशा परिवर्तन संभव है? उत्तर है सच्चा स्वराज्य थोड़े लोगों द्वारा सत्ता प्राप्त कर लेने से नहीं, बल्कि जब उस सत्ता का दुरुपयोग होता हो तो सब लोगों द्वारा उसका प्रतिकार करने की क्षमता प्राप्त करके हासिल किया जाता है। देश को इस पर विचार करना ही होगा।

(लेखक शिक्षा और सामाजिक समन्वय के क्षेत्र में कार्यरत हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

भोग और त्याग

मनुष्य जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए भौतिक पदार्थों की परम आवश्यकता है। बिना इन पदार्थों के भोग के जीवन की कल्पना करना संभव नहीं है। भौतिक सामग्री का उपयोग हम किस भावना से कर रहे हैं, यह समझना बहुत जरूरी है। वेदों में भी मनुष्य जीवन को सम्यक रूप से चलाने के लिए भोग और त्याग का अद्भुत समन्वय स्थापित करते हुए कहा गया है कि संसार की समस्त वस्तुओं का प्रयोग त्याग भाव से करो। यानी त्याग और भोग साथ-साथ। त्यागी तो योगी होता है और भोगी संसारी। वास्तव में भोग और योग दोनों हमारे भीतर ही हैं। आवश्यकता है दोनों में संतुलन बैठाने की। हम त्याग भी करते हैं और भोग भी, लेकिन हम कितना त्याग करते हैं और कितना भोग यही बड़ा प्रश्न है। प्रत्येक वस्तु का उपभोग करते हुए हमारी भावना त्याग की होनी चाहिए। जितनी भौतिक सामग्री से हमारा जीवन सम्यक रूप से चले उतनी का ही भोग करो। यही आनंद का नैतिक सूत्र है। संसार में रहते हुए संपूर्ण भौतिक सामग्री का संग्रह करो, परंतु दूसरों के हितों को देखते हुए त्याग की भावना को आत्मसात करते हुए उसका प्रयोग करो।

हमारी परंपरा भी इसी सिद्धांत की अनुगामी रही है कि भोग उतना ही होना चाहिए जितना जीवन के लिए जरूरी होता है। केवल भोगों में आसक्त हो जाना राक्षस प्रवृत्ति है। भोग जब तक त्याग के दायरे में रहता है तब तक वह मनुष्य के लिए हितकर होता है। जब त्याग की भावना समाप्त हो जाती है, उसी समय मनुष्य की लालसा विशाल रूप ले लेती है, जिसका कोई अंत नहीं है। भोग की यही भावना संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए एवं स्वयं मनुष्य के आनंद में बाधक बनती है। अत्यधिक भोग भोगने की प्रवृत्ति मनुष्य के जीवन को अधोगति की ओर ले जाती है। इसके विपरीत त्याग की भावना मनुष्य को मानसिक आनंद एवं शांति की प्राप्ति कराती है। त्याग पूर्वक भोग करने वाला मनुष्य अपने जीवन से सदा संतुष्ट रहता है। भोग एवं त्याग का समन्वय ही संपूर्ण विश्व को शांति पथ की ओर अग्रसर करता है।

आचार्य दीपचंद भारद्वाज

कठपुतली कला का संरक्षण जरूरी

देवेंद्रराज सुथार

प्राचीन धरोहर कठपुतली कला का जादुई संसार सरकारी संरक्षण एवं प्रोत्साहन के अभाव में सिमटता जा रहा है

कठपुतली कला द्वारा महिला शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, परिवार नियोजन जैसे सम-सामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रमों ने लोगों की गलत धारणाओं को बदलकर उन्हें सही दिशा एवं मार्गदर्शन देने का काम किया है, लेकिन कद्रदानों की कमी और सरकारी संरक्षण के अभाव में यह कला अब दम तोड़ रही है। आज यह संकट के दौर से गुजर रही है। वस्तुतः कठपुतली कलाकार अपना पुश्तैनी धंधा छोड़कर अन्य कामकाज करने लगे हैं।

आमतौर पर इन कठपुतलियों का सिर लकड़ी या पेपरमेशी का होता है, उसी के हिसाब से उनका धड़ होता है। इनके हाथ-पैर लकड़ी के या कपड़े में रुई भरकर बनाए जाते हैं। इनके हर अंग से एक पतली तथा लंबी डोरी बंधी होती है, जिसका अंतिम सिरा पुतली चालक कलाकारों के हाथ की अंगुलियों से बंधा होता है। अपनी अंगुलियों के जादू से ही ये कलाकार इस डोर को हिलाकर कठपुतलियों को अपने इशारे पर नचाते हैं।

यह चिंताजनक है कि आज महानगरों में रहने वाले अधिकांश बच्चों एवं युवाओं को कठपुतली के खेल के बारे में जानकारी तक नहीं है। अभिभावकों के पास समय ही नहीं है कि वे बच्चों को अपने देश की सांस्कृतिक विरासत एवं लोककलाओं से परिचित करवाएं। मोबाइल और कंप्यूटर से चिपके बच्चे भी अब संस्कृति, रीति-रिवाजों एवं त्योहारों में कोई विशेष रुचि लेना पसंद नहीं करते हैं। उनकी नवीन चीजों को जानने एवं समझने की प्रवृत्ति का इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से हर समय चिपके रहने के कारण दिन प्रतिदिन ह्रास होता जा रहा है। सवाल है कि आज जब विदेशी पर्यटक हमारी लोककलाओं को देखने, जानने एवं समझने में विशेष रुचि दिखा रहे हैं तो हम आखिर क्यों अपनी कलाओं से मुंह मोड़ रहे हैं। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि इस लुप्त होती कला के प्रति सरकार संजीदा होकर शीघ्र संरक्षण के लिए प्रयास करे एवं उचित कदम उठाए। स्कूलों और महाविद्यालय में यह खेल दिखाकर युवा पीढ़ी का ध्यान इस कला की ओर खींचा जा सकता है। गांवों एवं कस्बों में धार्मिक आयोजनों एवं मेलों के अवसर पर इस कला का मंचन सरकारी स्तर पर करवाकर भी इस कला के प्रति मोह उत्पन्न किया जा सकता है।

हम जितना जल्दी हो समझें कि किसी भी राष्ट्र की लोककला एवं संस्कृति ही उसकी आत्मा होती है। लोककला से ही लोकधर्मिता का भाव उत्पन्न होता है। जीवन ऊर्जा का महासागर है। जब अंतःचेतना जागृत होती है तो ऊर्जा जीवन को कला के रूप में उभारती है। कला जीवन को सत्यम् शिवम् सुंदरम् से समन्वित करती है। इसके द्वारा ही बुद्धि आत्मा का सत्य स्वरूप झलकता है। रवींद्रनाथ टैगोर ने भी कहा है कला में मनुष्य अपने भावों की अभिव्यक्ति करता है। ये लोककलाएं लोक-शिक्षण, सामाजिक सरोकार, ऐतिहासिक घटना, प्रसंग और भाईचारे का संदेश देने के साथ ही लोगों में जागृति लाने का सशक्त माध्यम भी हैं। इसलिए इन्हें सहेजकर रखना बेहद जरूरी है।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

चुनावी चंदे का सवाल

चुनावी चंदे की बेहतर व्यवस्था शीर्षक से लिखे अपने लेख में संजय गुप्त ने भारतीय चुनावों में धन के इस्तेमाल, इनसे जुड़े चुनावी बांड तथा इस पर जारी वर्तमान विवाद की सम्यक समीक्षा की है। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने देश के राजनीतिक दलों के चुनावी चंदे को पारदर्शी बनाने के लिए 2017-18 के बजट के दौरान चुनावी बांड शुरू करने की घोषणा की थी। यह ठीक है कि चुनावी बांड खरीदने वालों के नाम गोपनीय रखे जाते हैं, लेकिन बैंक के पास उनकी पूरी जानकारी होती है। इसके अलावा बांड खरीदने वाले को उसका जिक्र अपनी बैलेंस शीट में भी करना होता है। राजनीतिक दलों को भी चुनाव आयोग को चुनावी बांड से मिले धन की जानकारी देनी होती है। अतः यह कहा जा सकता है कि चुनावी बांड से भले ही राजनीतिक भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से लगाम लगाया जाना संभव नहीं हुआ हो, लेकिन कौन सी पार्टी किस जगह से पैसा जुटाती है, इस बात का पता तो अवश्य ही चल जाएगा। चुनावी चंदे को और पारदर्शी बनाने के एक उपाय के रूप में चुनावी बांड से जुड़ी गोपनीयता को यदि खत्म कर दिया जाए तो नाम उजागर होने के भय से कई कॉरपोरेट्स चुनावी बांड खरीदने से पीछे हट सकते हैं। हालांकि उस स्थिति से निपटने के लिए प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं की अमेरिका की तरह संयुक्त चुनावी रैली, चुनाव प्रचार के लिए इंटरनेट के बेहतर उपयोग आदि पर विचार किया जा सकता है। बहरहाल चुनावी खर्च और उससे जुड़े भ्रष्टाचार जैसे विषयों पर एक सार्थक बहस की आवश्यकता है, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता।

चंदन कुमार, देवघर

वाजिब नहीं जेएनयू बंद करने की मांग

जेएनयू बंद होना चाहिए कि मांग करने वाले ना तो आज के बारे में जानते हैं, ना आने वाले कल के बारे में। यदि शरीर के किसी में अंग में बीमारी हो जाती है तो उस अंग का इलाज किया जाता है न कि पूरे शरीर को खत्म कर दिया जाता है। एक तरफ तो कहा जाता है कि शिक्षा से देश महान बनता है, पढ़े लिखे लोगों से देश का भविष्य बनता है, तो दूसरी तरफ शिक्षा देने वाले उपक्रमों को बंद करने की बात करना कहां का औचित्य है! अगर किसी राजनीतिक पार्टी में कोई घोटालेबाज, भ्रष्ट हो तो क्या हम यह कह दें कि पूरी पार्टी व सभी नेता खराब हैं! हर जगह ऐसे चंद लोग पाए जाते हैं, जो बुराई है उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए ना कि जूं के डर से घाघरे को फेंकने की बात होनी चाहिए। चाहे कोई भी हो सबको समान रूप से शिक्षा मिलनी चाहिए। शिक्षा सस्ती/मुफ्त हो ताकि गरीब से गरीब तक की पहुंच वहां तक हो। एक गरीब के बच्चे भी पढ़ लिखकर अपने घर का एवं देश का उज्ज्वल भविष्य बन सकें।

hemahariupadhyay@gmail.com

हो कड़ी कार्रवाई

आए दिन भारत के किसी ना किसी राज्य तथा महानगर में सीवर की सफाई करते हुए उसकी जहरीली गैस से मौत का सिलसिला जारी है। साल भर में कितनी घटनाएं हो जाती हैं। लगातार ऐसी घटना के कारण मरने वालों की संख्या बढ़ रही है। वैसे तो दिल्ली सरकार द्वारा इस बात का दावा किया जा रहा था कि अब किसी भी सीवर कर्मचारी की मौत नहीं होगी और उसको सीवर की सफाई के लिए आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे, लेकिन यदि ऐसा है तो एक बार फिर घटना कैसे हुई? इस मामले में जिम्मेदार ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।

विजय कुमार धनिया, नई दिल्ली

मतदाताओं का अपमान

राजनीति में कब दुश्मन दोस्त बन जाए यह कहा नहीं जा सकता। महाराष्ट्र में भाजपा और एनसीपी ने मिलकर सरकार तो बना ली, पर चुनाव लड़ते समय भाजपा को शिव सैनिकों ने और शिवसेना को भाजपा वालों ने भी वोट दिया था। जनता जब अपना बहुमूल्य वोट किसी राजनीतिक दल को देती है तो बहुत ही सूजबूझ के साथ देती है। ऐसे में सत्ता की कुर्सी के लालच में राजनीतिक पार्टियां अपनी मर्जी से आपस मे गठबंधन तो कर लेती हैं, पर साथ-साथ वो उन मतदाता के मतों का दुरुपयोग भी करती हैं, जिन्होंने साथ आई हुई पार्टी की विचारधारा के खिलाफ वोट किया है। यह खेल उन सत्ताधारी नुमाइंदों को भारी पड़ सकता है।

satyamraiw|6304@gmail.com

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा

90 करोड़ मतदाताओं के साथ भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जहां विविध स्तरों पर चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग को एक स्वायत्त संगठन के तौर पर मान्यता मिली है।

आजकल

शेषन के बाद सुस्त पड़े चुनाव सुधार

अनंत मित्तल
वरिष्ठ पत्रकार

भारत में चुनाव सुधारों के लिहाज से किंवदंती बने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन ने चुनाव आयोग के संवैधानिक महत्व को देश के नेताओं, राजनीतिक दलों और मतदाताओं को बखूबी समझाया। शेषन ने अपने संवैधानिक पद के बूते चुनाव व्यवस्था को चलताऊ रवैये से निजात दिलाकर जवाबदेह प्रणाली में विकसित किया। हालांकि उनके बाद यह मुहिम कुछ कमजोर पड़ी। इसका एक बड़ा सुबूत यह है कि चुनावी चंदे के 'इलेक्टोरल बांड' पर अभी भी हमें ठोस चुनाव सुधार का इंतजार है

देश के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे टीएन शेषन का हाल ही में निधन हो गया है। भारत में टीएन शेषन के चुनाव आयुक्त बनने से पहले बहुत कम ही लोगों को चुनाव आयोग की शक्तियों के बारे में विस्तार से जानकारी थी। शेषन ने चुनाव सुधार पर व्यापक जोर दिया, लेकिन बहुत सी खामियां अब भी इसमें हैं, जिन्हें दूर करने की जरूरत है। विधि आयोग और सुप्रीम कोर्ट वर्तमान चुनाव प्रणाली एवं प्रक्रिया में आमूल-चूल सुधार सुझा रहे हैं, मगर संसद उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। वर्ष 2019 का आम चुनाव गवाह है कि चुनाव आयोग यदि सख्ती न करे तो मतदाताओं को भरमाने के लिए राजनेताओं के बोल बिगड़ने में देर नहीं लगती, फिर चाहे वे सत्तारूढ़ हों अथवा विपक्षी। इसी आम चुनाव में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के कामकाज में दखल नहीं देने का स्पष्ट रुख दिखाकर उसकी स्वायत्त संवैधानिक हैसियत भी देश को समझा दी। कुछ विपक्षी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट से याचना की थी कि वह चुनाव आयोग को कतिपय चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामलों में कार्रवाई का निर्देश दे। सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के बयानों के विरुद्ध विपक्ष द्वारा की गई शिकायतों को मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा द्वारा ठुकराने पर दायर की गई थी।

निर्वाचन प्रक्रिया में सख्ती : लगभग 90 करोड़ मतदाताओं वाले इस देश को टीएन शेषन ने निर्वाचन प्रक्रिया संबंधी प्रावधान सख्ती से लागू करके पहली बार यह अहसास कराया था कि चुनाव लोकतंत्र की आत्मा है और उसकी शुचिता सर्वोपरि है। उन्होंने जता दिया कि चुनाव आयोग द्वारा चुनाव को भरसक निष्पक्ष संचालित कराने पर ही असली जन प्रतिनिधित्वकारी सरकार बन सकती है। बाद में मुख्य चुनाव आयुक्त जेएम लिंगदोह ने भी बहुत सख्ती से सारे प्रावधान लागू किए। लिंगदोह ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव की भी आचार संहिता बना दी। लिंगदोह ने भी अपने मुख्य चुनाव आयुक्त काल में हुए तमाम चुनावों में भ्रष्ट तौर-तरीकों पर अधिकतम अंकुश लगाया।

टीएन शेषन ने जन समर्थन के मद में चूर नेताओं में सबसे अधिक सख्ती बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद पर की। उन्होंने होम गार्ड की सुरक्षा में बिहार का विधानसभा चुनाव कराने का लालू प्रसाद का दबाव सख्ती से दरकिनार करके पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की निगरानी में मतदान कराया। बिहार में वर्ष 1995 का विधानसभा चुनाव पूरे तीन महीने और कई चरणों में संपन्न हुआ। बिहार के तत्कालीन चुनावी इतिहास में वह चुनाव अपेक्षाकृत बहुत कम हिंसा व चुनावी धांधली के साथ संपन्न हुआ माना जाता है।

टी एन शेषन

मतदाता पहचान पत्र की मुहिम

फर्जी मतदान रोकने के लिए मतदाता पहचान पत्र बनाने का काम टीएन शेषन ने ही शुरू करवाया था। वोट डालते वक्त इस पहचान पत्र को दिखाना भी उन्होंने अनिवार्य करवाया था। चुनाव आचार संहिता का उन्होंने सख्ती से पालन कराया। फर्जी मतदान पर रोक लगने से लोकतंत्र मजबूत हुआ। पर्यवेक्षक तैनात करके पार्टियों और प्रत्याशियों की मनमानी पर रोक लगाई। मतदान प्रक्रिया को केंद्रीय बलों की निगरानी में संपन्न कराने की परिपाटी शेषन ने ही डाली जिससे राज्य मशीनरी का दुरुपयोग कम हुआ और नेताओं की धौंस-पट्टी पर लगाम लगी।

कलेक्टर के रूप में करियर की शुरुआत

तिरुनेल्लई नारायण अय्यर शेषन ने अपना करियर तो जिला कलेक्टर और फिर ग्रामीण विकास सचिव जैसे सरकारी ओहदे से आरंभ किया, पर वर्ष 1989 में कैबिनेट सचिव जैसे नौकरशाही के सर्वोच्च पद तक पहुंचे। शेषन ने केआर नारायणन के खिलाफ राष्ट्रपति पद का चुनाव भी लड़ा। टीएन शेषन योजना आयोग के सदस्य भी रहे। देश का दसवां मुख्य चुनाव आयुक्त बनकर उन्होंने चुनाव प्रक्रिया का कायाकल्प कर दिया। उनके कार्यकाल में उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता के अनुसार चुनाव खर्च की निगरानी बढ़ी और कम पैसे वाले प्रत्याशियों को भी बराबरी का मौका मिला। बिना अनुमति लाउडस्पीकरों का प्रयोग भी उनके कार्यकाल में रोका गया तथा देर रात प्रचार वाहनों पर उन्होंने पाबंदी लगाई।

चुनाव प्रक्रिया में सुधार की वर्तमान मुहिम

मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा के अनुसार, चुनाव सुधार संबंधी आठ बिंदुओं का सुझाव सरकार को दिया गया है। इसमें जन प्रतिनिधि कानून के तहत मतदाताओं को वर्ष में दो बार वोटर आइ कार्ड बनाने का मौका देने और गलत खबर तथा झूठे हलफनामे पर दो साल की सजा का प्रावधान करने की सिफारिश की गई है। पत्र के अनुसार, पारदर्शी और साफ-सुथरा चुनाव कराने के लिए जरूरी है कि चुनाव लड़ने का सबको समान अवसर दिया जाए। इसकी सिफारिश हालांकि शेषन ने भी की थी। उन्होंने जात-पांत की दुहाई देकर वोट जुटाने को भी अपने चुनावी अमले से सख्ती से रुकवाया मगर हमारे चुनाव आज भी जातीय समीकरणों तथा धार्मिक ध्रुवीकरण का शिकार हैं। चुनाव प्रक्रिया पैसे, शराब, उपहारों, ताकत और रसूख की मोहताज है। इसीलिए संसद में करोड़पतियों का बोलबाला है भले वे पक्ष में हों अथवा विपक्ष में। अत्यधिक खर्चीले चुनावों ने गरीबों के नुमाइंदों के लिए पंचायत से लेकर विधानसभा और संसद तक सभी विधायी संस्थाओं के दरवाजे बंद कर दिए हैं।

नेताओं को कराया चुनाव आयोग की हैसियत का अहसास : टीएन शेषन ने अपने कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल गुलशेर अहमद और बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव सहित तमाम नेताओं को चुनाव आयोग की हैसियत का अहसास कराया। उन्होंने केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती के लिए चरणबद्ध मतदान की परंपरा डाली जिसका आज राजनीतिक दलों को प्रचार के दौरान खूब फायदा मिल रहा है। शेषन के चुनाव आयोग संभालने से पहले देश में चुनावी सभाओं की न तो कोई समय सीमा तय थी और न ही प्रचार वाहनों और जुलूसों द्वारा शोर पर कोई लगाम। प्रचार सामग्री को चुनाव के दौरान विभिन्न प्रत्याशियों के समर्थक कहीं भी लगाने, टांगने अथवा चिपकाने को स्वतंत्र थे। शेषन ने चुनाव प्रचार की समय सीमा रात के 10 बजे मुकर्रर की और प्रचार सामग्री को घरों अथवा सरकारी दफ्तरों की दीवारों पर चिपकाने पर रोक लगा दी। उन्होंने चुनाव प्रचार में खर्च की सीमा की निगरानी भी कड़ाई से कराई तथा मतदान की पूर्व संध्या में मतदाताओं को प्रभावित करने के शराब अथवा पैसे बांटने जैसे हथकंडों को नेस्तनाबूद किया। उन्होंने चुनाव आयोग के पर्यवेक्षकों को मैदानी वस्तुस्थिति के सटीक आंकलन तथा रिपोर्टिंग के लिए प्रोत्साहित किया।

चुनाव आयोग ने मतदाताओं को उनके मत का महत्व बताने संबंधी जागरुकता अभियान भी चलाया। उन्होंने चुनाव आयोग को मतदाताओं की राय के रक्षक के रूप में पेश करके स्थानीय प्रशासन की मदद से उनके वोट लूटने पर रोक लगाई। तब से चले अभियानों की बदौलत ही आज अनेक राज्यों में लोग 70-80 फीसद तक मतदान कर रहे हैं। उन्होंने 1990 से 1996 के दौरान चुनाव प्रणाली को मजबूत और जनोन्मुख बनाया। उनके काल में यह कहा जाता था कि नेता या तो भगवान से डरते हैं या फिर शेषन से।

चुनाव का गंभीरता से प्रबंधन : मुख्य चुनाव आयुक्त बनने पर टीएन शेषन ने दो अगस्त 1993 को अपने एक आदेश द्वारा चुनाव आयोग की स्वायत्त संवैधानिक हैसियत का अहसास सरेआम करवा दिया। उसी के जरिये उन्होंने नेताओं और नौकरशाही को जता दिया कि चुनाव प्रबंधन गंभीर कार्यपालिक कार्य है और उसमें कोताही सभी वर्गों को भारी पड़ेगी। उन्होंने साफ चुनौती दी कि सरकार जब तक चुनाव आयोग के संवैधानिक अधिकारों, शक्तियों को नहीं मानती, तब तक आयोग देश में कोई भी चुनाव आयोजित नहीं करेगा। हालांकि पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने इसे लोकतंत्र की तालाबंदी और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने उन्हें पागल बता दिया, मगर वे टस से मस नहीं हुए। इसलिए पश्चिम बंगाल में राज्यसभा चुनाव को बीच में ही रोकना पड़ा। अंततः सरकार द्वारा चुनाव आयोग से सहयोग करने पर ही चुनाव संपन्न हुआ।

कांग्रेस की जिद के बावजूद 1993 के त्रिपुरा विधानसभा चुनाव भी शेषन ने फरवरी महीने में नहीं होने दिए थे। उन्होंने असम के पायेदार कांग्रेस नेता और केंद्रीय मंत्री संतोष मोहन देब के साथ चुनाव प्रचार में घूमने वाले पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई होने तक चुनाव स्थगित करने की घोषणा की। अंततः सरकार को पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई करनी पड़ी और अप्रैल में चुनाव आयोग ने मतदान कराया।

मार्च 1991 में ही शेषन ने बयान जारी कर दिया था, 'भूल जाइए कि संसद में गलत तौर-तरीकों का इस्तेमाल करके आप पहुंच जाएंगे, ऐसा करने की किसी को अनुमति नहीं होगी।' वर्ष 1994 में उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव से उनके दो मंत्रियों सीताराम केसरी एवं कल्पनाथ राय को हटाने का अनुरोध किया। चुनाव आयोग के अनुसार उन दोनों ने मतदाताओं को लुभाने और चुनाव पूर्व आचार संहिता तोड़ने जैसी अवैधानिक हरकत की थी। चुनाव प्रबंधन के कायाकल्प के लिए शेषन को 1996 में रेमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चुनाव आयोग की स्वायत्तता तथा संवैधानिक हैसियत का अहसास कराने के लिए शेषन सुप्रीम कोर्ट में भी पीछे नहीं हटे।

देश में सभी दलों के नेता उनसे इतने खफा हुए कि उन पर संसद में महाभियोग चलाकर उन्हें अपदस्थ करने की कोशिशें भी हुईं। इसके बावजूद वे अडिग रहे जिसकी तारीफ सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में फर्जी वोटों पर रोक संबंधी याचिका पर सुनवाई के दौरान भी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शेषन के कार्यकाल में चुनाव आयोग द्वारा अर्जित साख का सिक्का आज तक चल रहा है और अगला चुनाव भी उसी लीक पर आयोजित होना चाहिए। ताज्जुब ये है कि शेषन की सख्ती को चुनाव आयोग आज भी याद तो कर रहा है, मगर राजनीतिक जमात उसके प्रबंधन से खुश नहीं है। अब चुनाव आयोग ये सुझाव दे रहा है कि दो सीटों से चुनाव जीतने पर खाली होने वाली सीट पर उपचुनाव का खर्च उस प्रत्याशी से वसूला जाए जो जीतने पर एक सीट से इस्तीफा देगा। आयोग ने कानून मंत्रालय से आग्रह किया है कि यदि दो सीटों से चुनाव लड़ने पर रोक लगाना ठीक नहीं है, तो चुनाव सुधार के तहत कम से कम एक सीट के चुनाव का खर्च तो उसे छोड़ने वाले से वसूला जाए। इसके लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कानून मंत्री को पत्र लिखा है। उसमें चुनाव सुधारों के प्रस्ताव पर अमल करने का अनुरोध है। आठ बिंदुओं वाले सुधार प्रस्ताव में मतदान से 48 घंटे पहले के 'प्रचार थमने' की अवधि में प्रिंट मीडिया को भी शामिल करने और चुनावी चंदे में राजनीतिक दलों को छूट देने का मामला है।

खरी-खरी

निठल्ले दद्दा और कट चाय

राजेंद्र नागर 'निरंतर'

'अरे छोटे, कहां जा रहे हो? आओ कट-कट हो जाए।' आवाज कानों में पड़ते ही मैंने देखा कि मोहल्ले के 'बड़े भिया' चाय की दुकान पर बैठे थे। मैं जानता था कि अगर रुक गया तो ये अपनी कविता पिलाकर ही मानेगा। उन्होंने हाथ खींचकर पास बैठा लिया।

'ला रे छोरे, छोटे भई के लिए चाय ला,' उन्होंने श्रोता फंसाने का फंदा फेंका।

मुझे भयाक्रांत देख बिना भूमिका बनाए सीधे बोले- 'यार क्या बताऊं तेरेको, कल रात को भोत जोर से प्रसव वेदना की तरह कविता वेदना हुई। एकदम ताजी वाली कविता तुम्हें सुनाना चाहता हूं।'

मुझे लगा मैं बोल दूं कि रात में जिस क्षण आपको कविता वेदना हुई, ठीक उसी क्षण से मैं बहरा हो गया हूं। मगर चाय आती देख लगा कि जब तक सुड़कूंगा, तब तक झेल लूं। वे शुरू भये...

तुम नहीं, गम नहीं, शराब नहीं,
ऐसी लकड़ी की बेंच का जवाब नहीं।

कहते हुए उन्होंने बड़े प्यार से उस बेंच को माशूका समझते हुए सहला दिया, जिस पर उनकी तशरीफ टिकी थी।

हमने तुरंत कहा- 'वाह दद्दा, क्या लिखे हैं। यह कविता तो आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिलवा देगी।'

वे ताड़ गए कि हम उनके मजे ले रहे हैं। पर उन्होंने भी बेशर्मी और थेथरई में ही तो पीएचडी की थी, सो बोले- 'देख छोटे, हमको पता है कि तुम हमको वही समझ रहे हो, जो नेता जनता को समझती है। समझ लो! पर कविता तो तुम्हें सुननी ही पड़ेगी!

लेकिन तब तक मैं अपनी चाय सुड़क चुका था इसलिए बोला- दद्दा, चाय तो पी ही ली। बाकी कविता फिर कभी।

'ऐ छोरे, कांदा डालके दो पोहे ला! दद्दा ने तुरंत दो पोहे का ऑर्डर मारा। दरअसल वे कविताई के शरद पवार थे। अपने हाथ आई कोई चीज कैसे छोड़ सकते थे।

वे फिर शुरू भये...

देश में आजकल ये क्या हो रिया है!
तू सई बताना बोर तो नी हो रिया है?

उनकी ये कालजयी पंक्ति सुनकर लगा कि दद्दा की अदा भी बड़ी अजीब है, पहले घाव देते हैं, फिर उसमें नाखून चुभोकर पूछते हैं- दर्द तो नी हो रिया!

तेरा चांद सा चेहरा, तेरे सफेद दांत,
मेरेको लगता है, पागल कर देंगे आज।

इसलिए अपने बचने का चांस न देख अपन बेचारगी में कविता सुनते रहे। दद्दा भी भोत निठल्ले थे, सो पोहे खतम होने के बाद फिर चाय बुलाई और कविता सुनाते रहे।

ट्वीट-ट्वीट

त्रिशंकु विधानसभाएं कारोबार और रोजगार के नए साधन मुहैया करा सकती हैं। अंडमान निकोबार में विधायकों के लिए नए रिजॉर्ट बनें जहां परिंदा पर न मार सके। बीमा कंपनियां मोटा प्रीमियम लेकर विधायकों के दलबदल का इंश्योरेंस कर सकें। कुछ चार्टर विमान सिर्फ विधायकों को लाने-ले जाने के लिए हों।

अखिलेश शर्मा@akhileshsharma1

होटल संचालकों ने कभी इस बारे में नहीं सोचा होगा कि उनकी बिक्री के टारगेट महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन के चलते पूरे होंगे। नोट-दरअसल मैं यह मानकर चल रहा हूं कि पार्टियों ने मुफ्त में अपने विधायकों को होटलों में नहीं रखा होगा।

विक्रम साठये@vikramsathaye

आखिर महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी अपने 105 विधायकों को होटल में क्यों नहीं छिपा रही है? क्या वे स्वभाव से वफादार किस्म के हैं? या फिर कोई उन पर डोरे ही नहीं डालना चाहता?

मिन्हाज मर्चेंट@MinhazMerchant

बैंकों में धोखाधड़ी का जोर पकड़ता खतरनाक रुझान

वीना सुखीजा

बीते सप्ताह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद को एक सवाल के जवाब में बताया कि मौजूदा वित्तीय वर्ष के पहले छह महीनों यानी अप्रैल से सितंबर के बीच सरकारी बैंकों में 95,760 करोड़ रुपये कीमत के 5,743 धोखाधड़ी के मामले सामने आए हैं। वित्त मंत्री द्वारा उपलब्ध कराया गया यह आंकड़ा इसलिए चिंताजनक है, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पेश एक रिपोर्ट के मुताबिक 2018- 2019 के वित्तीय वर्ष में सरकारी बैंकों समेत सभी बैंकों में धोखाधड़ी के कुल 6,801 मामले सामने आए थे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बैंको में धोखाधड़ी के मामले कितनी तेज रफ्तार से बढ़ रहे हैं। सिर्फ संख्या के मामले में ही नहीं, बल्कि घोटाले की रकम में भी बहुत ज्यादा का इजाफा हो रहा है। पिछले वर्ष के बैंक घोटालों की साझी रकम जहां 71,543 करोड़ रुपये थी, वहीं चालू वित्त वर्ष के महज छह महीनों में हुए घोटालों की रकम ही 95,760 करोड़ रुपये है।

यही नहीं दो साल पहले यानी वित्त वर्ष 2017-18 में धोखाधड़ी के कुल 5,916 मामले हुए थे और उनमें 41,167 करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ था। धोखाधड़ी के ये लगातार बढ़ते मामले और उसकी शिकार धनराशि का बढ़ता ग्राफ बताता है कि देश के बैंकों के सिर पर किस तरह आर्थिक स्थायित्व के डगमगाने का खतरा मंडरा रहा है। यह जितनी बड़ी चिंता का विषय बैंकों और उनकी नियामक संस्था आरबीआइ के लिए है, उससे कई गुना ज्यादा बैंकों के साथ लेन-देन करने वाले आम लोगों को डराने वाला विषय है, क्योंकि इन घोटालों के चलते सरकारी बैंकों से आम लोगों का भरोसा टूट रहा है। आखिर दोषी कौन है? निश्चित रूप से कोई भी इसकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहेगा, लेकिन इस डरावनी स्थिति के लिए बैंकों के ऑडिटर्स, क्रेडिट रेटिंग संस्थाएं और खुद आरबीआइ भी इसके लिए जिम्मेदार है।

हैरानी की बात यह कि 90 फीसद धोखाधड़ी के ये मामले सरकारी बैंकों में हो रहे हैं। पिछले पांच वर्षों में ऐसे मामलों में 400 प्रतिशत की बढ़ोतरी बता रही है कि धोखेबाज निश्चिंत हैं। विभिन्न शोधों से यह बात उभरकर सामने आयी है। धोखाधड़ी के ये मामले आंतरिक सिस्टम की कमजोरियों का नतीजा हैं। धोखाधड़ी के व्यापक अध्ययन से पता चलता है कि हालांकि रिजर्व बैंक के पास इस तरह की धोखाधड़ी से बचने को लेकर प्रारंभिक चेतावनी संकेत प्रणाली मौजूद है, लेकिन बैंक कभी भी इसका फायदा नहीं उठाते हैं और शायद आरबीआइ उनके विरुद्ध उस हद तक सख्त नहीं होती, जिस हद तक होना चाहिए।

प्रतीकात्मक

सरकारी बैंकों में ही इस तरह के ज्यादातर मामले इसलिए होते हैं, क्योंकि इन बैंकों में हर स्तर पर तैनात लोग अपनी जिम्मेदारियों के प्रति लापरवाह हैं। खराब कार्य प्रणाली और अप्रभावी इंटरनल ऑडिट की वजह से धोखाधड़ी संभव होती है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, बेंगलुरू के एक शोध अध्ययन के मुताबिक इस तरह की धोखाधड़ी और नॉन परफॉर्मिंग एसेट के बीच एक सीधा संबंध होता है। शोध के मुताबिक जहां भी कर्ज की राशि एक करोड़ रुपये से अधिक थी, उसे नहीं चुकाने के मामलों में बैंकों द्वारा दिखाई जा सकने वाली सक्रियता में कमी पाई गई। इसका मतलब यह है कि बैंक छोटे ग्राहकों पर तो सख्ती दिखाता है, लेकिन बड़े कर्जदाताओं के साथ उसका रवैया अजीब तरह की नरमी से भरा होता है।

यह स्थिति वास्तव में यह कॉरपोरेट कंपनियों और बैंक के लोन विभाग के उच्चाधिकारी के बीच की मिलीभगत का संकेत है। आइआइएम बॉम्बे ने भी अपने एक शोध में पाया है कि सिंडिकेट बैंक और इंडियन बैंक धोखाधड़ी मामलों की प्रारंभिक जांच से ही पता चलता है कि न केवल कर्मचारी, बल्कि बैंक प्रबंधन के वरिष्ठ अधिकारी भी इसमें शामिल थे। सवाल है आखिर इसकी कमजोर कड़ी क्या है?

धोखाधड़ी के कई का मामलों में तो मुकदमे की नौबत आने तक संबंधित अधिकारी या कर्मचारी रिटायर भी हो जाता है। वैसे धोखाधड़ी के इस पूरे खेल में बैंकों से जुड़े तीसरे पक्ष मसलन वकील या चार्टर्ड एकाउंटेंट भी शामिल होते हैं। वास्तव में ये गठजोड़ का मजबूत हिस्सा होते हैं। यही वजह है कि आम तौर पर बैंक ऑडिटर्स धोखाधड़ी के शुरुआती संकेतों पर ध्यान नहीं देते हैं।

बहरहाल बैंकों में धोखाधड़ी रोकने के लिए वित्त मंत्री के मुताबिक सरकार ने व्यापक उपाय किए हैं। इसके लिए बीते दो वित्त वर्षों के दौरान निष्क्रिय कंपनियों के 3,38,000 बैंक खातों को बंद किया गया और आर्थिक अपराधियों की संपत्तियों को जब्त करने के प्रावधान को बैंकिंग कानून से जोड़ा गया है। ये अच्छे कदम हैं, फिर भी धोखेबाजों को रोक पाने के लिए ये अपर्याप्त हैं। धोखाधड़ी को हतोत्साहित करने के लिए ये उपाय इसलिए भी कम हैं, क्योंकि बैंक वित्तीय अपराध के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को दोषी ठहराने में बहुत सफल नहीं रहे हैं। इसके पीछे कुछ हद तक फॉरेंसिंग एकाउंटिंग की बारीकियों की जानकारी के साथ-साथ धोखाधड़ी कानून की अच्छी समझ वाले विशेषज्ञ वित्तीय जांच अधिकारियों की कमी भी है।

आरबीआइ ने धोखाधड़ी से जुड़ी सूचनाओं के आदान-प्रदान में भी सरकारी बैंकों के बीच समन्वय की कमी देखी है। अगर सरकार धोखाधड़ी के खतरे को रोकना चाहती है तो वित्तीय धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए अखिल भारतीय सेवाओं की तरह एक इंटीग्रेटेड जांच ढांचा बनाए। यह वित्तीय और कानूनी जानकारी वाले अधिकारियों से लैस हो, इन्हें वित्तीय अनियमितताओं की एक निश्चित समय में सफलतापूर्वक जांच पूरी करने में सक्षम बनाने के लिए उच्चस्तरीय प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए। - इमेज रिफ्लेक्शन सेंटर

जागरण जनमत — कल का परिणाम

क्या पूर्व प्रधानमंत्रियों के परिवार को एसपीजी सुरक्षा न दिए जाने का फैसला सही है?

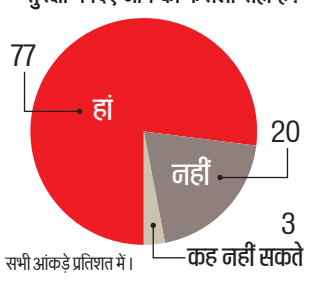

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या महाराष्ट्र में भाजपा का सरकार बनाने का दांव सही है?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर **POLL** लिखें, स्पेस देकर **Y, N** या **C** लिखकर 57272 पर भेजें
Y -हां, **N**-नहीं, **C**-कह नहीं सकते

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

गया भतीजा छोड़कर हैं पवार हैरान,
छत्रप की धूमिल हुई बनी-बनाई शान।
बनी-बनाई शान उड़े हाथों के तोते,
हंसते बने न आज बने ना उनसे रोते।
दिया गलत का साथ भोगिए आप नतीजा,
फूट गया परिवार भाग कर गया भतीजा।

- ओमप्रकाश तिवारी

मुद्दा

पर्यटन में नवाचार से अछूता रहा लद्दाख

मुकुल श्रीवास्तव
प्रोफेसर, लखनऊ विश्वविद्यालय

लद्दाख के बारे में देश के अन्य क्षेत्रों के लोग बहुत कम जानते हैं। हालांकि यह इलाका कई मामलों में बेहद समृद्ध है जिसमें व्यापक सुधार के जरिये इसे और समृद्ध किया जा सकता है। पर्यटन में नवाचार के जरिये यहां पर्यटकों की संख्या बढ़ाई जा सकती है

पिछले दिनों लद्दाख लिटरेचर फेस्टिवल का हिस्सा बनते हुए इसे नजदीक से जानने का मौका मिला। यह लिटरेचर फेस्टिवल लद्दाख के संभागीय आयुक्त सौगत बिस्वास के दिमाग की उपज थी जिससे देश के अन्य भागों के निवासी लद्दाख को जम्मू कश्मीर के चश्मे से देखने की बजाय लद्दाख के स्वतंत्र नजरिये से देखें। जब लद्दाख पहुंचा तो वह जम्मू कश्मीर राज्य का एक हिस्सा भर था, लेकिन मेरे लौटने से पहले वह देश का एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया। सच कहा जाए तो इस लिटरेचर फेस्टिवल के बहाने ही लद्दाख की समर्थ साहित्यिक सांस्कृतिक परंपरा की विरासत को समझ पाया। बात चाहे पर्यटन की हो या जम्मू कश्मीर की समस्याओं या साहित्य की, मेरे जैसे बहुत से लोगों के लिए जम्मू कश्मीर का मतलब सिर्फ कश्मीर घाटी और श्रीनगर के आस-पास के इलाके ही रहे हैं।

लेह लद्दाख लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 1,73,266 वर्ग किमी के कुल क्षेत्रफल के साथ भारत में सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है। लेह की चौड़ी सड़कों और संकरी गलियों में एक हफ्ते तक घूमने के दौरान कोई भी स्थानीय निवासी ऐसा नहीं मिला जो सरकार के इस फैसले से नाराज हो। कश्मीर घाटी में रहने वाले लोगों के मुकाबले लेह लद्दाख के लोगों का जीवन ज्यादा मुश्किल भरा है, पर वे लोग अपनी मांगों को मनवाने के लिए न तो हिंसक हुए और न ही उग्रवाद का सहारा लिया। लद्दाख वासियों के लिए केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) की मांग एक पुराने नारे की शक्ल में रही है। कश्मीरी संस्कृति से लद्दाख के लोगों का कोई सीधा रिश्ता नहीं रहा, जम्मू कश्मीर राज्य की 60 फीसद जमीन लद्दाख में है, पर प्रशासन कश्मीर केंद्रित ही रहा।

दसवीं से उन्नीसवीं सदी तक लद्दाख एक स्वतंत्र राज्य था, जहां लगभग 32 राजाओं का इतिहास रहा है, लेकिन 1834 में डोगरा सेनापति जोरावर सिंह ने लद्दाख पर कब्जा कर लिया और यह जम्मू- कश्मीर के अधीन चला गया। लेकिन लद्दाख अपनी स्वतंत्र पहचान को लेकर हमेशा मुखर रहा। केंद्र शासित प्रदेश की मांग दशकों पुरानी है। वर्ष 1989 में इस मांग को कुछ सफलता मिली, जब यहां बौद्धों के धार्मिक संगठन लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन (एलबीए) के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन हुआ। वर्ष 1993 में केंद्र और प्रदेश सरकार लद्दाख को स्वायत्त हिल काउंसिल का दर्जा देने को तैयार हो गईं। इस काउंसिल के पास ग्राम पंचायतों के साथ मिलकर आर्थिक विकास, सेहत, शिक्षा, जमीन के उपयोग, कर और स्थानीय शासन से जुड़े फैसले लेने का अधिकार है, जबकि कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, संचार और उच्च शिक्षा से जुड़े फैसले जम्मू-कश्मीर सरकार के लिए ही सुरक्षित रखे गए।

प्रतीकात्मक

किसी भी राज्य के मानव संसाधन की गुणवत्ता का आकलन वहां शैक्षिक संस्थानों की उपलब्धता से लगाया जा सकता है। लेह लद्दाख में आज तक एक विश्वविद्यालय नहीं बना था। इसी वर्ष फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख क्षेत्र में पहले विश्वविद्यालय 'यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख' की आधारशिला रखी जिससे लेह, करगिल, नुब्रा, जंस्कर, द्रास और खलतसी के डिग्री कॉलेज संबद्ध हैं। जम्मू क्षेत्र में आइआइटी, एक आइआइएमसी के अलावा कुल चार विश्वविद्यालय हैं, वहीं कश्मीर घाटी में तीन विश्वविद्यालय और एक राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान है।

लद्दाख में दो जिले हैं- लेह और कारगिल। यह इलाका सामरिक दृष्टि से भी बहुत संवेदनशील है, क्योंकि इसी इलाके में एक तरफ चीन है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान। इसके बावजूद पिछले कुछ वर्षों में यहां पर्यटकों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। लेकिन यहां साल के छह महीने जीवन आसान नहीं है। लगभग छह महीनों के लिए लद्दाख दुनिया से एक तरह से कट जाता है और कुछ जगहों पर लोग माइनस 32 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी रहते हैं।

अधिकांश लोगों के रोजगार का एकमात्र साधन पर्यटन ही है, पर अपनी भौगौलिक विषमताओं के कारण पर्यटकों का बड़ा हिस्सा जम्मू कश्मीर तक ही सीमित रह जाता है। तथ्य यह भी है कि लद्दाख के ठंडे पर्यावरण में भारत के किसी भी जगह से ज्यादा धूप मिलती है। लद्दाख में आसमान साफ रहता है, जिससे वहां सौर ऊर्जा के लिए अनुकूल वातावरण है। वहां मानसून के दौरान बहुत कम बारिश होती है। सौर ऊर्जा को बिजली में बदलने की क्षमता यहां देश के किसी भी अन्य क्षेत्र से ज्यादा है।

लद्दाख में इस समय नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन (एनएचपीसी) की दो पनबिजली परियोजनाएं चल रही हैं। इनमें चुटक परियोजना 44 मेगावॉट क्षमता की है जबकि निमो बाजगो परियोजना में 45 मेगावॉट क्षमता की इंस्टाल्ड कैपेसिटी है। वहीं जम्मू-कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (जेकेएसपीडीसी) की नौ पनबिजली परियोजनाएं चल रही हैं। इनसे 15 मेगावॉट बिजली बनाने की क्षमता है।

सौर और पन बिजली के क्षेत्र में जो संभावनाएं हैं उनका दोहन लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बन जाने से अधिक होगा और इससे रोजगार सृजित होगा और वहां के निवासियों का जीवन स्तर बेहतर होगा। एकमात्र पर्यटन व्यवसाय होने के बावजूद पर्यटन में चल रहे नवाचार से लद्दाख का इलाका अछूता रहा है। होम स्टे की संख्या अभी बहुत कम है और होटल महंगे हैं। लद्दाख के वन्य जीवन के बारे में भी लोगों को बहुत कम पता है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान यहां का सबस

87.60 फीसद परिवारों को ग्रामीण क्षेत्रों में और 90.90 फीसद परिवारों को शहरी क्षेत्रों में साल भर पर्याप्त पेयजल उपलब्ध होता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के पेयजल, साफ सफाई, स्वच्छता और आवास की स्थिति पर राष्ट्रीय सर्वेक्षण की 76वें दौर की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
सोमवार 25 नवंबर 2019

डाटागीरी

देश में दिव्यांग बच्चों को कम ही नसीब होती है शिक्षा

सामान्य बच्चों की तुलना में भारत में दिव्यांग बच्चे शिक्षा से अधिक महरूम रह जाते हैं। यूनेस्को की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि पांच वर्ष तक की आयु के केवल 27 फीसद दिव्यांग ही शिक्षा हासिल करते हैं। वहीं, इससे अधिक आयुवर्ग की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है।

नेशनल न्यूज, नई दिल्ली

यूं तो दिव्यांग बच्चों को आत्मनिर्भर बनाकर मुख्यधारा में जोड़ने के लिए देश में कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। देश में सामान्य बच्चों की तुलना में दिव्यांग बच्चे शिक्षा से अधिक वंचित हैं। कुछ समय पहले यूनेस्को द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। इसमें बताया गया है कि भारत में सामान्य बच्चों की तुलना में दिव्यांग बच्चे कम अनुपात में शिक्षा हासिल कर पाते हैं। भारत में दिव्यांग बच्चों की संख्या 78,64,636 है। यह संख्या देश में कुल बच्चों की 1.70 फीसद है। देश के कुल बच्चों में दिव्यांग लड़के 1.81 फीसद, जबकि 1.58 फीसद लड़कियां हैं। रिपोर्ट में सामने आया है कि पांच साल की आयु के 3,68,697 दिव्यांग बच्चों में केवल 27 फीसद शिक्षा हासिल कर रहे हैं। 72 फीसद बच्चे ऐसे हैं, जिन्होंने कभी किसी शिक्षण संस्थान की चौखट भी नहीं देखी है। वहीं, इनमें एक फीसद बच्चे ऐसे हैं, जिन्होंने कुछ समय तक शिक्षा हासिल की, लेकिन किन्हीं कारणों से उन्हें इसे बीच में ही छोड़ना पड़ा। रिपोर्ट में पांच से 19 आयुवर्ग के दिव्यांग बच्चों के आंकड़े भी एकत्र किए गए हैं। इसमें बताया गया है कि इस आयुवर्ग के 61 फीसद दिव्यांग बच्चे शिक्षा हासिल कर रहे हैं, जबकि यह देश में कुल बच्चों के शिक्षा प्राप्त करने की दर (71 फीसद) से कम है। इस आयुवर्ग में 27 फीसद छात्र ऐसे हैं, जो कभी भी किसी भी शैक्षणिक संस्थान में नहीं गए। वहीं, इस आयुवर्ग में देश में कुल बच्चों में 17 फीसद बच्चे ऐसे हैं, जो शिक्षा से दूर हैं।

राज्यों के हिसाब से स्थिति : 5 से 19 आयुवर्ग के दिव्यांग बच्चों के शिक्षा प्राप्त करने की दर सबसे अधिक गोवा और केरल में है। वहीं, ओडिशा और बंगाल ऐसे राज्य हैं, जहां दिव्यांग बच्चों द्वारा शिक्षा को बीच में छोड़ने की दर देश के कुल औसत से अधिक है। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नगालैंड में एक तिहाई दिव्यांग बच्चों ने कभी कोई शिक्षा हासिल नहीं की।

पांच वर्ष तक के दिव्यांग

27 फीसद ने शैक्षिक संस्थान में दाखिला लिया
71.5 फीसद ने कभी कोई शैक्षिक संस्थान नहीं गए
1.5 फीसद ने कुछ शिक्षा हासिल की, लेकिन फिर अधूरी छोड़ दी

स्थिति	कुल	लड़के	लड़कियां
शैक्षिक संस्थान में दाखिला लिया	99,259	54,521	44,738
कुछ शिक्षा हासिल की	5,472	3,030	2,442
कभी स्कूल नहीं गए	2,63,966	1,46,319	1,17,647
पांच वर्ष तक के कुल दिव्यांग	3,68,697	2,03,870	1,64,697

पांच से 19 आयुवर्ग के दिव्यांग

शिक्षा हासिल की			
स्थिति	कुल	लड़के	लड़कियां
दिव्यांग बच्चे	61.18	61.75	60.45
कुल छात्र	70.97	72.26	69.55
शिक्षा अधूरी छोड़ी			
स्थिति	कुल	लड़के	लड़कियां
दिव्यांग बच्चे	12.14	12.34	11.89
कुल छात्र	11.82	11.70	11.96
बिल्कुल शिक्षा हासिल नहीं की			
स्थिति	कुल	लड़के	लड़कियां
दिव्यांग बच्चे	26.68	25.92	27.66
कुल बच्चे	17.21	16.04	18.49

(सभी आंकड़े फीसद में)

मप्र में 'आदर्श ग्राम' चयन में रुचि नहीं ले रहे सांसद, छह माह में महज एक ने चुना गांव

बेरुखी ▶ पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को मिला सिर्फ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का प्रस्ताव

प्रदेश की 29 संसदीय सीटों में से 28 सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी जीते हैं

नईदुनिया, भोपाल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल 'सांसद आदर्श ग्राम' योजना में मध्य प्रदेश के सांसदों की रुचि नहीं दिखाई दे रही है। यही कारण है कि छह माह के कार्यकाल में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद राकेश सिंह को छोड़कर प्रदेश के शेष सांसद अपने संसदीय क्षेत्र में एक भी ऐसा गांव तलाश नहीं कर पाए हैं, जिसे तमाम सुविधाएं पहुंचाकर आदर्श बनाया जा सके। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रत्येक सांसद को पांच गांव की जिम्मेदारी लेने को कहा है, लेकिन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने भी अब तक एक ही गांव चुना है। इसका प्रस्ताव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तक पहुंच गया है।

प्रधानमंत्री मोदी ने पहले कार्यकाल में देशभर के सांसदों से अपने संसदीय क्षेत्र में एक गांव चुनने और उन्हें तकनीकी, सांस्कृतिक रूप से आदर्श बनाने के निर्देश दिए थे। इस बार प्रधानमंत्री ने प्रत्येक सांसद को पांच गांव गोद लेकर अपने कार्यकाल में उन्हें आदर्श ग्राम में बदलने को कहा है। यह निर्देश मई 2019 में दिए गए थे, लेकिन प्रदेश में इन निर्देशों का असर देखने को नहीं मिल रहा है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तक अभी एक सांसद का प्रस्ताव पहुंचा है। सूत्र बताते हैं कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने जबलपुर के ग्राम घाना को आदर्श ग्राम बनाने के लिए चुना है। इसके अलावा किसी भी सांसद ने अभी तक विभाग को कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है, जबकि मध्य प्रदेश की 29 संसदीय सीटों में से 28 सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी जीते हैं। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पहले कार्यकाल में 11 अक्टूबर, 2014 को सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की थी।

पीएम मोदी ने अपने पहले कार्यकाल में सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की थी। प्रतीकात्मक

योजना में तीन बातों पर जोर : योजना में गांव में बुनियादी सुविधाओं के साथ खेती, पशुपालन, कुटीर उद्योग, रोजगार आदि पर ध्यान दिया जाना है। इसमें तीन बातों पर जोर दिया गया है। गांव के लिए जो भी योजना बनाई जाए, वह मांग पर आधारित हो, समाज द्वारा प्रेरित हो और उसमें जनता की भागीदारी हो। योजना का मुख्य उद्देश्य सांसदों की देखरेख में चुनी गईं ग्राम पंचायतों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना है। इस योजना के तहत ग्रामों के विकास के लिए इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास योजना और मनरेगा से फंडिंग की जाती है।

पिछले कार्यकाल में भी नहीं हुआ काम : योजना से सांसदों की बेरुखी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले साल जिन सांसदों ने गांव गोद लिए थे। वे भी पूरी तरह से विकास कार्य नहीं करा सके, जबकि उन्हें दो साल में गांव को पूरी तरह से तस्वीर बदलना थी।

सिर्फ नाम देने से कोई गांव आदर्श नहीं हो जाता है। योजना के लिए केंद्र सरकार ने न तो कोई वित्तीय प्रावधान किया है और न ही सांसद अपनी निधि से अलग से राशि इन गांवों के लिए दे रहे हैं। पिछले समय में भी जो गांव आदर्श गांव के तौर पर चुने गए थे, उनमें भी कोई विशेष काम नहीं हुए हैं। राज्य सरकार अपने स्तर से प्रदेश के सभी गांवों के विकास के लिए रोड मेप तैयार कर रही है। वित्तीय उपलब्धता के हिसाब से प्राथमिकता तय कर विकास कार्य कराए जाएंगे।

- कमलेश्वर पटेल, मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

लखीमपुर-दुधवा-पीलीभीत में 2358 कैमरे करेंगे बाघों की गणना

जागरण संवाददाता, लखीमपुर : दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत टाइगर रिजर्व और कतर्निया घाट वन्यजीव विहार में फिर बाघ गणना की कवायद शुरू कर दी गई है। इसके लिए 2358 कैमरे ट्रैप लगाने की योजना है। सबसे पहले दिसंबर में पीलीभीत टाइगर रिजर्व में 338 साइटों पर 676 कैमरे लगाकर इसकी शुरुआत की जाएगी। इसके बाद दिसंबर से जनवरी के बीच किशनपुर सेंक्च्युरी, बफरजोन के मैलानी-भीरा रेंज, पलिया, संपूर्णानगर, महेशपुर और गोला की 222 साइटों पर 444 कैमरे लगाए जाएंगे। इसके बाद फरवरी व मार्च में दुधवा नेशनल पार्क के 366 साइटों पर 672 तथा मार्च व अप्रैल में कतर्निया घाट वन्यजीव विहार के 283 साइटों के लिए 566 कैमरे लगाए जाएंगे। कैमरों के जरिये बाघ, तेंदुआ, हाथी, भालू, हिरन, बारहसिंघा सहित तमाम प्रजातियों की गणना एक दिसंबर से शुरू होगी। ये कैमरे डब्ल्यूडब्ल्यूएफ (वर्ल्ड वाइडलाइफ फंड) की ओर से लगवाए जाएंगे।

कई तरीकों से होगी गिनती : 27 व 28 नवंबर को एक साथ सभी स्थानों पर मांसाहारी वन्यजीवों की गणना उनके पग चिह्न सहित कई अन्य तरीकों से की जाएगी। 29 व 30 नवंबर को सभी जगह पर शाकाहारी वन्यजीवों की गणना कराई जाएगी। इसके लिए सभी रेंज अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है।

वन्यजीवों की गणना के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कैमरे अलग-अलग तारीखों में लगाए जाने हैं। गणना के लिए दुधवा व पीलीभीत के बीच तालमेल बनाया गया है।

- डॉ. अनिल पटेल, उपनिदेशक

उच्च हिमालय में पर्वतारोहण और ट्रैकिंग के लिए बढ़ रहे सैलानियों के कदम

शैलेंद्र गोदियाल, उत्तरकाशी

पर्वतारोहण एवं ट्रैकिंग के लिए प्रसिद्ध गंगोत्री नेशनल पार्क क्षेत्र में गोमुख-तपोवन ट्रैक की सैर का इस बार नया रिकॉर्ड बना है। अब तक यहां लगभग 19 हजार पर्यटक पहुंच चुके हैं, जो कि बीते दस सालों में सर्वाधिक संख्या है। इसमें विदेशियों की तादाद भी अच्छी-खासी है। यही वजह रही कि इस बार पार्क के राजस्व में भी अच्छा-खासा इजाफा हुआ। पार्क के गेट अभी 30 नवंबर को बंद किए जाने हैं।

उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट इस वर्ष एक अप्रैल को खोले गए थे। गंगोत्री-गोमुख-तपोवन ट्रैक भी पार्क क्षेत्र में ही आता है, जिस पर इस बार पर्यटकों व पर्वतारोहियों की सबसे अधिक चहल-पहल रही। आंकड़ों पर गौर करें तो 31 अक्टूबर तक पार्क की सैर को 18773 पर्यटक एवं पर्वतारोही पहुंच चुके थे। सुखद यह कि इस बार बरसात के दौरान भी गोमुख ट्रैक सुचारू रहा, जिससे पर्यटकों और पर्वतारोहियों को किसी तरह की परेशानी नहीं हुई।

कई चोटियों के आरोहण को गए पर्वतारोही दल : इस सीजन में विदेशी पर्यटकों के कई ग्रुप पार्क की सैर को पहुंचे, जिससे गंगोत्री-गोमुख-तपोवन ट्रैक गुलजार रहा है। यही नहीं सतोपंथ, शिवलिंग, भागीरथी प्रथम, भागीरथी द्वितीय, सुदर्शन, गंगोत्री ग्रुप, जोगिन, माउंट मुम्बा, त्रिमुखी आदि चोटियों के आरोहण को भी कई दल गए। इसके अलावा इनर लाइन क्षेत्र में आने वाले भैरव घाटी से नेलांग तक भी काफी पर्यटकों ने सैर की। हिमालय माउंटेनियरिंग एंड ट्रेकिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष जयेंद्र पंवार ने बताया कि यह सीजन पर्यटन और तीर्थाटन के लिए काफी अच्छा रहा। कई पर्वतारोही दल हिमाचल से केदारनाथ के लिए भी गए।

प्रतीकात्मक

- गंगोत्री नेशनल पार्क की सैर करने वाले पर्यटकों का इस बार बना नया रिकॉर्ड, राजस्व भी बढ़ा
- बीते दस वर्षों में पर्यटकों की यह सर्वाधिक संख्या, 30 नवंबर तक खुला रहेगा पार्क

वर्ष वार गंगोत्री नेशनल पार्क में पहुंचे पर्यटक

वर्ष	पर्यटक	राजस्व
2019	18773	40.84
2018	17108	36.34
2017	16881	38.30
2016	12643	31.41
2015	14098	31.86
2014	7487	19.46
2013	5430	15.40
2012	16386	29.09
2011	15367	29.15
2010	12626	18.04

(नोट : राजस्व का आंकड़ा लाख रुपये में।)

ईको टूरिज्म के अनुरूप यह वर्ष उच्च हिमालय में ट्रैकिंग करने वालों के लिए काफी मुफीद रहा है। बीते दस वर्षों में इस बार सबसे अधिक पर्यटकों ने गंगोत्री नेशनल पार्क की सैर की। उम्मीद है कि 30 नवंबर तक इस आंकड़े में और इजाफा होगा।

- नंद बल्लभ शर्मा, उप निदेशक, गंगोत्री नेशनल पार्क, उत्तरकाशी

सिमरन की 'स्विंग' पर पाबंदियां 'क्लीन बोल्ड'

जहीर हसन, बागपत

- उत्तर प्रदेश की बेटी ने रोक के बावजूद हासिल किया मुकाम
- हरियाणा की महिला क्रिकेट टीम में कर रहीं बेहतरीन प्रदर्शन

हजार बर्क गिरे लाख आंधियां उठें... वो फूल खिलके रहेंगे जो खिलने वाले हैं। साहिर लुधियानवी का यह शेर क्रिकेटर सिमरन चौधरी के हौसले की नुमाइंदगी करता है। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के गांव असारा में उस वक्त क्रिकेट का यह ख्वाब पला था, जब समाज के कथित ठेकेदारों ने लड़कियों के घर से निकलने, जींस पहनने, मोबाइल रखने पर पाबंदियां लगा रखी थीं। इससे बेपरवाह सिमरन ने लक्ष्य को सामने रख अभ्यास जारी रखा। हौसले की गेंदबाजी से पाबंदियों की गिल्ली तो उड़ी ही, तालिबानी सोच भी 'क्लीन बोल्ड' हो गई। हरियाणा की महिला टीम में शामिल सिमरन का यह प्रयास यकीनन काबिल-ए-तारीफ है।

वर्ष 2012 में यह तालिबानी फरमान जारी होने के बाद आसारा गांव सुर्खियों में आया था। ऐसे में उस समय 15 साल की सिमरन चौधरी को अपना ख्वाब दरकता सा जरूर नजर आया, लेकिन हौसला नहीं खोया। वह रोजाना प्रैक्टिस करने 40 किमी दूर बागपत आने लगीं। एक भाई और सात बहनों में सबसे छोटी सिमरन के पिता जमील ने गरीबी के चलते बिटिया को घर बैठा लिया। वह कई दिन प्रैक्टिस को नहीं आई तो सरूरपुर कलां गांव निवासी कोच डॉ. मुन्ना उनके पिता जमील से मिले। उन्होंने सिमरन को अपने परिवार में रखकर तराशना शुरू किया। मेहनत रंग लाई और वर्ष 2014 में सिमरन हरियाणा की अंडर-19 महिला क्रिकेट टीम में बतौर गेंदबाज शामिल हो गईं।

राष्ट्रीय टीम में शामिल होने का सपना : कोच डॉ. मुन्ना कहते हैं कि सिमरन का लक्ष्य राष्ट्रीय महिला क्रिकेट टीम में पहुंचने का है। मुन्ना ने कहा कि उत्तर प्रदेश में प्रोत्साहन नहीं मिलने के कारण वह हरियाणा से खेलने लगीं।

अभ्यास करतीं सिमरन चौधरी। सौजन्य : परिजन

तेज गेंदबाज हैं सिमरन

सिमरन की मां बशीरन बेटी की उपलब्धि पर गदगद हैं। कहती हैं, कोच डॉ. मुन्ना के लिए दिल से दुआ निकलती है। 23 वर्षीय सिमरन हरियाणा के सोनीपत में कक्षा 11 की पढ़ाई भी कर रही हैं।

बढ़ते गए कदम

2014-15 में वह हरियाणा की तरफ से जम्मू में खेलीं। 2015-16 में मुंबई के खिलाफ 10 ओवर में नौ रन देकर पांच विकेट झटके। अब वह अहमदाबाद में महिला अंडर-23 क्रिकेट मैच में हाथ आजमा रही हैं।

फोटो न्यूज

दुनिया की पहली लकड़ी की इमारत का मिला दर्जा

नेशनल डेस्क, नई दिल्ली : दुनिया में ऐसी बहुत सी इमारतें हैं, जो अपनी विशेष बनावट और शानदार निर्माण शैली के कारण लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। यह तस्वीर चीन के गुइझोई प्रांत के यिंगशान शहर में बनी एक लकड़ी की इमारत की है। 99.90 मीटर ऊंची इस इमारत को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। खास बात यह है कि इसे एक नहीं, बल्कि दुनिया की पहली लकड़ी की इमारत, सबसे ऊंची और आर्किटेक्चर के हिसाब से तीन कैटेगरी में रिकॉर्ड बुक में जगह मिली है। इस इमारत को पर्यटकों के लिए खोला गया गया है। दुनियाभर से पर्यटक इसे देखने के लिए आ रहे हैं।

फोटो साभार-शिन्हुआ

लकड़ी की इमारत के नाम तीन गिनीज रिकॉर्ड्स दर्ज

यह है खासियत

किसी इमारत को बनाने में सीमेंट, पत्थर, रेत आदि तमाम चीजों को इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसको बनाने में पिलरों को छोड़ कर पूरी तरह से सिर्फ लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है। लकड़ी का प्रयोग करते हुए इतनी ऊंची इमारत का निर्माण करना अपने आप में एक अनोखा काम है। 24 मंजिला इस इमारत में 150 से ज्यादा कमरे हैं। पूरी तरह से ईकोफ्रेंड्ली इस इमारत का निर्माण आर्किटेक्ट सुइ हैंग की डिजाइन के आधार पर किया गया है। फिलहाल इसके सभी कमरे खाली हैं।

हिमालय पर मिलने वाली कीड़ा जड़ी को लैब में तैयार कर रहे हरियाणा के यशपाल

जागरण संवाददाता, हिसार

परंपरागत किसानी छोड़ आधुनिक खेती करने वालों के लिए मॉडर्न किसान यशपाल सिहाग रोल मॉडल साबित हो सकते हैं। कभी शिक्षा व टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देशभर में झंडा गाड़ने वाले यशपाल ने समुद्रतल से 11500 फुट से अधिक ऊंचाई पर हिमालयी क्षेत्र में मिलने वाली कीड़ा जड़ी (यारसागुंबा) को हरियाणा के हिसार में अपनी लैब में पैदा करके किसानों के लिए नई उम्मीद जगाई है। करीब दो वर्ष पहले सिवानी बोलान निवासी यशपाल ने वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से हिसार-तोशाम रोड पर दस बाई दस के तीन कमरों में लैब बना कर कीड़ा जड़ी का व्यावसायिक उत्पादन आरंभ किया। आज वह इससे प्रति वर्ष 25 से 30 लाख रुपये कमा रहे हैं।

कीड़ा जड़ी के उपयोग : सामान्य तौर पर समझें तो कीड़ा जड़ी एक तरह का जंगली मशरूम है, जो एक खास कीड़े की इल्लियों यानी कैटरपिलर्स को मारकर उस पर पनपता है। इस जड़ी का वैज्ञानिक नाम है कॉर्डिसेप्स साइनेसिस। कीड़ा जड़ी को अलग-अलग रूप व स्वरूपों में उपयोग किया जाता है। मुख्यतौर पर रक्त शर्करा को नियंत्रित करने, श्वसन प्रणाली को बेहतर बनाने, किडनी व लीवर संबंधित रोगों से बचाने में, शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने, पुरुष और महिलाओं में प्रजनन क्षमता व शुक्राणुओं की संख्या बढ़ाने में उपयोगी है। इसके अलावा प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत करने, फेफड़े और गुर्दे को तंदरुस्त रखने में इससे मदद मिलती है। साथ ही यह रक्त और अस्थि मज्जा के निर्माण में भी सहायक है। इसके अलावा इसका प्रयोग जीवन रक्षक दवाओं में भी किया जाता है।

हिसार में कीड़ा जड़ी को लैब में तैयार करते यशपाल सिहाग। सौजन्य यशपाल

15 साल की मेहनत से गुरमुखी में बताई राम महिमा

सुरेश कामरा, पटियाला

- साहित्यकार हर्ष कुमार हर्ष ने देवनागरी से गुरमुखी लिपि में लिख दी श्रीरामचरितमानस
- 1990 में इस ग्रंथ का लिप्यंतरण करना शुरू किया, जो 2005 में पूरा हुआ

भगवान श्री राम के आदर्श, कर्तव्य परायणता व राम राज्य की महिमा को जन-जन तक पहुंचाने के लिए पटियाला के वरिष्ठ साहित्यकार हर्ष कुमार हर्ष ने सार्थक पहल की है। उन्होंने महर्षि तुलसी दास जी के देवनागरी लिपि में लिखे श्रीरामचरितमानस का गुरमुखी लिपि में लिप्यंतरण किया है। यानी इसकी भाषा तो अवधी ही है, लेकिन लिपि देवनागरी की बजाय गुरमुखी कर दी गई है। इसके लिए सालों तक शोध किया और करीब 15 साल की कड़ी मेहनत के बाद इस कार्य को पूर्ण किया।

हर्ष बताते हैं कि 1990 में इस ग्रंथ का लिप्यंतरण करना शुरू किया, जो 2005 में पूरा हुआ। जालंधर के अमित पॉकेट बुक्स प्रकाशक ने 930 पन्नों के उनके ग्रंथ के भाग एक की 20 हजार कॉपियां प्रकाशित कीं। कुछ समय पहले भाग दो भी प्रकाशित हुआ है। उन्होंने बताया कि ग्रंथ की खूबसूरती है कि तुलसी दास जी की तरफ से देवनागरी लिपि में लिखे ग्रंथ की भाषा अवधी है। उन्होंने भी अपने गुरमुखी लिप्यंतरण किए ग्रंथ की भाषा अवधी ही रखी है। कठिन शब्दों का अर्थ हर पेज के फुटनोट में दिया है।

हस्तलिखित पुस्तकें टटोलीं, फिर मिला शत्रुघ्न के परिवार का इतिहास : हर्ष कुमार बताते हैं कि ग्रंथ में जिन नामों का वर्णन है, उनके पूरे परिवार की भी जानकारी दी है। श्री राम जी के भाई लक्ष्मण व भरत के परिवार की जानकारी तो कई पुस्तकों व ग्रंथों से मिल गई, लेकिन शत्रुघ्न के परिवार की जानकारी नहीं मिल रही थी। पहले तो परिवार की जानकारी ग्रंथ में शामिल करने का विचार छोड़ दिया, लेकिन मन नहीं माना तो कई दिन तक सेंट्रल स्टेट लाइब्रेरी में पड़ी हस्तलिखित पुस्तकों को टटोला तो जानकारी मिल गई। ये कुछ दिन इन 15 सालों के सफर के पीड़ादायक व सुकून देने वाले दोनों तरह के पल थे।

देवनागरी से गुरमुखी में श्रीरामचरितमानस लिखने वाले हर्ष कुमार हर्ष। जागरण

इन ग्रंथों की ली सहायता

पटियाला की सेंट्रल स्टेट लाइब्रेरी में रखीं हस्तलिखित पुस्तकें टटोलने को अलावा महर्षि वाल्मिकी जी की रामायण, हिंदू मिथिहास कोष, सीता निष्कासन, पंजाब कोष भाग 1-2, गुरु शब्द रत्नाकर के अलावा दर्जनों ग्रंथ पढ़े।

ऐसे आया विचार

पवित्र ग्रंथ को गुरमुखी में लिप्यंतरण करने के विचार पर हर्ष कहते हैं कि प्रभु श्री राम को हर धर्म के लोग मानते व पूजते हैं। इसी कारण उनके मन में विचार आया कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो गुरमुखी जानते हैं और श्री राम जी के बारे में जानना चाहते हैं, ऐसे में उनको इससे वंचित क्यों रखा जाए। इससे न केवल अन्य धर्मों में भाईचारा बढ़ेगा, बल्कि गुरमुखी लिपि पढ़ने वाले लोग भी इस ग्रंथ को जान सकेंगे।

1000 करोड़ रुपये का कोष बनाएगा आइआइटी, शोध एवं अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए पूर्व छात्रों की मदद से अगले वर्ष तक।

'ग्रीन कुंभ' की थीम पर होगा हरिद्वार कुंभ

- गंगा की शुद्धता और पर्यावरण की रक्षा पर रहेगा फोकस
- सोलर पावर आधारित एलईडी लाइट्स से रोशन होगा मेला क्षेत्र

हरिद्वार कुंभ में सौर ऊर्जा से इस तरह होगी ईको-फ्रेंडली आतिशबाजी। जागरण

अनूप कुमार, हरिद्वार

हरिद्वार कुंभ-2021 को भव्य, शानदार, यादगार और अनूठा बनाने के लिए कुंभ मेला अधिष्ठान बड़े पैमाने पर तैयारी कर रहा है। विशेष यह कि इस बार हरिद्वार यह आयोजन 'ग्रीन कुंभ' की थीम पर होगा। इसमें गंगा की शुद्धता और पर्यावरण की रक्षा पर विशेष फोकस रहेगा। इसके तहत विद्युत ऊर्जा का कम से कम (लगभग शून्य) और सौर ऊर्जा का अधिकाधिक इस्तेमाल करने की योजना है। कुंभ के इतिहास में पहली बार ग्रीन कुंभ की थीम पर कुंभ मेला शुभारंभ समारोह का आयोजन होगा। इस दौरान बड़े पैमाने पर ईकोफ्रेंडली आतिशबाजी और लेजर शो कराने की तैयारी है। इसके साथ ही पूरा हरकी पौड़ी क्षेत्र और मुख्य कुंभ नगर सोलर पावर आधारित एलईडी लाइट्स से रोशन रहेगा।

कुंभ मेला स्थल और नहर पटरी मार्ग को खूबसूरत बनाने के लिए हजारों की संख्या में लगाए जाने वाले 'हैरिटेज पोल' भी सौर ऊर्जा आधारित होंगे। पूरे मेला क्षेत्र को ग्रीन क्षेत्र घोषित कर यहां सभी डीजल-पेट्रोल वाहनों पर रोक लगाने की योजना है। सिर्फ बैट्री और सौर ऊर्जा से चलने वाले वाहनों को ही मेला क्षेत्र में चलाए जाने की अनुमति होगी। इसके लिए बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा से चार्ज होने वाले रिक्शा, टेंपो और बसों को चलाने की योजना बनाई गई है। पूरे मेला क्षेत्र को भव्य रूप प्रदान करने के लिए इसे आकर्षक रंगों से सजाने की भी योजना है। इसमें भी सौर ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे शाम ढलते ही कुंभ मेला क्षेत्र की इमारतें सौर ऊर्जा से संचालित विविध रंगों वाली लेजर लाइट्स से दमकने लगेंगी।

खर्च कम करने को प्रभावशाली प्रेजेंटेशन : कुंभ मेला अधिकारी दीपक रावत बताते हैं कि 'ग्रीन कुंभ' के लिए खर्च सीमा काफी कम करने की योजना भी बनाई जा रही है। मेला अधिष्ठान इसे लेकर अपनी तैयारी लगभग पूरी कर चुका है। अब शासन स्तर से इसकी मंजूरी के लिए प्रभावशाली प्रेजेंटेशन तैयार किया जा रहा है।

जागरण विशेष की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/jagran-special

जागरण विशेष

मेला क्षेत्र को सुगंधित बनाने की तैयारी

कुंभ मेला अधिष्ठान की पूरे कुंभ मेला क्षेत्र में 24 घंटे सुगंधित वातावरण बनाए रखने की भी खास तैयारी है। मेला अधिष्ठान पूरे कुंभ मेला क्षेत्र में अभियान चलाकर इस तरह के सुगंधित फूलों के पौधे लगाने जा रहा है, जो दिन-रात खुशबू बिखरते हैं।

जनवरी से पूरी तरह प्रदूषणमुक्त हो जाएगा गंगा का पानी

उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की हालिया रिपोर्ट के अनुसार गोमुख से लेकर ऋषिकेश तक गंगा के पानी की गुणवत्ता उत्तम श्रेणी की है। हां, ऋषिकेश से लेकर हरिद्वार तक जरूर दिक्कत है। हरिद्वार में गंगा के पानी के कुछ नमूनों में कुछेक स्थानों पर फीकल कॉलीफार्म (मल-मूत्र) पाया गया है। हालांकि, अब दोनों शहरों में गंगा में गिर रहे गंदे नालों की टैपिंग और कुछ एसटीपी (सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट) के तैयार होने से स्थिति में सुधार हुआ है। आगामी जनवरी तक यह समस्या पूरी तरह से हल हो जाएगी क्योंकि तब तक नमामि गंगे के तहत निर्माणाधीन एसटीपी भी तैयार हो जाएंगे। अपर सचिव एवं कार्यक्रम निदेशक नमामि गंगे उदयराज सिंह बताते हैं कि नमामि गंगे के तहत सभी नालों की टैपिंग का काम पूरा कर लिया गया है। ऐसे में इन शहरों से निकलने वाला सीवर और गंदे नाले गंगा में नहीं गिरेंगे।

12 हजार महिलाओं को स्वावलंबी बना चुकी हैं सुमन

दिखाई राह ▸ झारखंड में तीन दशक से कौशल विकास प्रशिक्षण के माध्यम से कर रहीं महिलाओं का उत्थान

तौहीद रब्बानी, पलामू

झारखंड के गढ़वा की रहने वालीं समाज सेविका सुमन अखौरी तीन दशक से ग्रामीण और आदिवासी इलाकों की महिलाओं को कौशल विकास के माध्यम से सशक्त बनाने में जुटी हैं। जागृति महिला मंडल नामक संस्था के बैनर तले अब तक वह गढ़वा व पलामू क्षेत्र की 12 हजार से अधिक महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई से लेकर हस्तशिल्प के अन्य प्रशिक्षण देकर स्वावलंबन की राह दिखा चुकी हैं।

नारी सशक्तीकरण

युवतियों और महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का सुमन का जुनून कुछ ऐसा है कि इसके लिए वह डालटनगंज के जीएलए कॉलेज में लेक्चरर पद की नौकरी भी छोड़ चुकी हैं। अभी तक वह पलामू व गढ़वा में पांच हजार से अधिक स्वयं सहायता समूह का गठन कर चुकी हैं। इन समूहों से सात हजार से ज्यादा महिलाएं जुड़ी हुई हैं। बकौल सुमन अभी तक वह 12 हजार से अधिक महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण दे चुकी हैं। कई महिलाएं प्रशिक्षण लेकर खुद का ट्रेनिंग सेंटर भी चलाने लगी हैं। अब वे दूसरी महिलाओं को प्रशिक्षण दे रहीं हैं। 61 साल की सुमन अखौरी जहां पूरे प्रमंडल में सुमन दीदी के नाम से मशहूर हैं, वहीं हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में उन्हें संत ईश्वर सेवा सम्मान से नवाजा गया है। सुमन बताती हैं कि शुरू से ही उन्हें गरीब, लाचार व बेबस महिलाओं की तकलीफ देखकर पीड़ा होती थी। उनके लिए कुछ करने को मन करता था। इसी सोच के तहत आखिरकार उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की ठानी। सामाजिक कार्य करते हुए उन्होंने 1988 में जागृति महिला मंडल नामक संस्था का गठन किया। नौकरी करते हुए सेवा कार्य में दिक्कत हो रही थी। इसे देखते हुए 1996 में नौकरी से त्यागपत्र देकर पूरी तरह से समाजसेवा में जुट गईं।

सुमन का कहना है कि यह सम्मान मिलना उनके लिए ही नहीं, पूरे झारखंड के लिए गौरव की बात है। उनका मानना है कि लड़कियों और महिलाओं का आत्मनिर्भर होना जरूरी है। इससे समाज में उनकी स्थिति मजबूत होगी। महिलाओं को भाग्य भरोसे नहीं रहना चाहिए। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए। झारखंड के पलामू जिला के पांकी प्रखंड के डंडार कलां गांव में जन्मी सुमन पलामू जिले के मुख्यालय मेदिनीनगर मुख्य बाजार में रहकर संस्था का कार्य करती हैं।

पलामू में प्रशिक्षण पाकर हुनरमंद बनी एक महिला को प्रमाण पत्र देती सुमन अखौरी। जागरण

किस क्षेत्र में दिया जाता है प्रशिक्षण

जागृति महिला मंडल के माध्यम से सिलाई, कढ़ाई, पापड़ बनाने, लाह का खिलौना बनाने, लाख की चूड़ी बनाने सहित अन्य कार्यों का प्रशिक्षण महिलाओं को दिया जाता है।

कई संस्थाएं कर चुकी हैं पुरस्कृत

सुमन अखोरी को पूर्व में भी कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। नाबार्ड संस्था ने 2010 में सम्मानित किया था। सहकार भारती संस्था ने भी सम्मानित किया है। महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा करने पर 2012 में रांची में हुए दैनिक जागरण के सम्मान समारोह में सुमन को झारखंड के तत्कालीन राज्यपाल सैयद अहमद ने सम्मानित किया था। इन्हें दो माह पूर्व महिला सशक्तीकरण को लेकर मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी सम्मानित किया था।

सरोकार की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/positive-news

प्रदूषण से पक्षियों की मृत्यु दर में 40 फीसद का इजाफा

चिंताजनक ▸ आइवीआरआइ के वैज्ञानिकों के अध्ययन में सामने आई स्थिति

हिमांशु मिश्र, बरेली

वर्तमान में प्रदूषण वैश्विक स्तर पर बड़ी चुनौती बना हुआ है। दुनियाभर के वैज्ञानिक इससे निपटने के रास्ते तलाश रहे हैं, लेकिन कोई भी उचित समाधान दिखाई नहीं दे रहा है। इससे इंसान ही नहीं बेजुबान पशु-पक्षी पर प्रभावित हो रहे हैं। आलम यह है कि पिछले तीन सालों में प्रदूषण के बढ़े स्तर से देशभर में पक्षियों के मृत्यु दर में करीब 40 फीसद का इजाफा हुआ है। कई पक्षियों की प्रजातियां लुप्त होने के कगार पर पहुंच गई हैं। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (आइवीआरआइ) के वैज्ञानिकों के अध्ययन में यह चिंताजनक बात सामने आई है।

पक्षी विशेषज्ञ और आइवीआरआइ के पूर्व संयुक्त निदेशक डॉ. रिशेंद्र वर्मा के मुताबिक, छोटे पक्षियों के फेफड़े इंसानों की तुलना में काफी छोटे होते हैं। इंसानों की अपेक्षा पक्षियों में एक सेकंड में चार गुना तेजी से श्वसन प्रक्रिया होती है, जिससे प्रदूषण की स्थिति में इन पक्षियों में कैंसर और कई तरह की गंभीर बीमारियों का खतरा 90 फीसद तक बढ़ गया है। पक्षियों का मृत्यु दर प्रदूषण के संपर्क में आने से 40 फीसद तक बढ़ गया है क्योंकि पक्षी 24 घंटे प्रदूषण के संपर्क में रहते हैं। डॉ. वर्मा बताते हैं कि पक्षियों के पौष्टिक आहार कहे जाने वाले कैटरपिलर, कीड़े-मकोड़ों की तादाद भी इसके चलते कम होती जा रही है।

ऐसे किया अध्ययन : डॉ. वर्मा ने बताया कि देश के विभिन्न बड़े शहरों में जाकर वहां पक्षियों के हालात पर अध्ययन किया। इस दौरान उनमें होने वाली बीमारियों, प्रदूषण के स्तर आदि की जानकारी जुटाई।

गौरैया, हंस सहित कई प्रजातियां हुई कम : डॉ. वर्मा बताते हैं कि पिछले एक साल में अकेले दिल्ली में प्रदूषण की भयावह स्थिति के कारण गौरैया, हंस, चील, किंगफिशर सहित पक्षियों की कई प्रजातियां कम हो गई हैं।

प्रदूषण के कारण कई गंभीर बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं पक्षी। प्रतीकात्मक

ये पड़ रहे प्रभाव

- प्रजनन क्षमता हो रही कम
- पक्षियों की दैनिक दिनचर्या हुई खराब
- 80 फीसद पक्षी शहरों से कर रहे पलायन
- कैंसर समेत अन्य गंभीर बीमारियां ले रहीं चपेट में
- पौष्टिक आहार की हो रही कमी
- हर साल देश में मर रहे हैं करीब पांच लाख पक्षी

हरियाणा के तैराकों ने बनाया नेशनल रिकॉर्ड

बहादुरगढ़ में मैराथन तैराकी में हिस्सा लेते खिलाड़ी। जागरण

- बिना रुके 10 घंटे 32 मिनट में 210 किलोमीटर मैराथन तैराकी की
- 2017 में 125 और 2018 में 200 किमी मैराथन तैराकी का बनाया था रिकॉर्ड

जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़

हरियाणा के सब जूनियर और जूनियर तैराकों ने एक नया नेशनल रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है। रविवार को राष्ट्रीय स्तर के तैराकों ने बिना रुके, बिना थके 210 किलोमीटर तैरने का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। 10 घंटे 32 मिनट में 72 तैराकों ने मिलकर ये रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले हरियाणा स्वीमिंग एसोसिएशन के तैराकों ने 200 किलोमीटर तैरने का नेशनल रिकॉर्ड बनाया था। 210 किलोमीटर मैराथन स्वीमिंग का रिकॉर्ड बनाकर हरियाणा ने अपना ही पिछला नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है। साल 2017 में 125 किलोमीटर तैरने के रिकार्ड के साथ इस रिकॉर्ड अभियान की शुरुआत हुई थी।

रविवार को बहादुरगढ़ के एचएल सिटी के स्वीमिंग पुल पर सुबह 8:30 बजे रिकॉर्ड बनाने के लिए तैराकी शुरू हुई थी। सबसे पहले सब जूनियर तैराकों ने रिकॉर्ड बनाने के लिए तैराकी की शुरुआत की और उसके बाद दूसरे तैराक भी इसमें शामिल होते चले गए। अर्जुन अवार्डी पहलवान धर्मेंद्र और भारतीय तैराकी संघ के सहसचिव अनिल खत्री ने सिटी बजाकर तैराकी की शुरुआत करवाई। शैलजा जून ने तैराकों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि हरियाणा में तैराकी का क्रेज बढ़ रहा है। तैराकी ऐसा खेल है जिससे न केवल शरीर तंदरुस्त होता है बल्कि मानसिक दृढ़ता भी हासिल होती है। 24 नवंबर को हरियाणा तैराकी संघ के अध्यक्ष सांसद धर्मबीर सिंह का जन्मदिन भी है। इसीलिए हरियाणा तैराकी संघ ने नया रिकॉर्ड बनाने का काम किया है। भारतीय तैराकी संघ के सह सचिव अनिल खत्री ने बताया कि स्पोर्ट्स के जरिये ही युवाओं को नई दिशा दी जा सकती है। जो युवा खेलों से जुड़ जाता है वो कभी नशे और दूसरी बुराइयों की तरफ नहीं जाता है।

मुरादाबाद में महफूज है पुलिस का ब्लैक बॉक्स

श्रीशचंद्र मिश्र 'राजन', मुरादाबाद

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के थानों और पुलिस चौकियों में खजाने व मालखाने को डाकू सुल्ताना से महफूज रखने के लिए 1887 में अंग्रेजी हुकूमत ने एक अनोखी तरकीब निकाली थी। इंग्लैंड की एक कंपनी की मदद से ऐसी तिजोरी का निर्माण कराया गया, जिसको तोड़ना तो दूर, जलाया भी नहीं जा सकता था। यह तिजोरी (ब्लैक बॉक्स) आज भी मुरादाबाद की शहर कोतवाली में महफूज है। पुलिस इसे अपना ब्लैक बॉक्स कहती है।

अंग्रेजों के शासनकाल में डाकू सुल्ताना एलानिया लूट करता था। सुल्ताना ने 1887 में नांगल थाने की बिजनौर पुलिस चौकी में लूटपाट की थी। सरकारी खजाने की लूट के बाद चौकी में आगजनी की घटना ने अंग्रेजी हुकूमत को हिलाकर रख दिया था। इसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के थानों व पुलिस चौकियों को डाकू सुल्ताना से महफूज रखना अंग्रेजों के लिए बड़ी चुनौती बन गई। इस पर इंग्लैंड की एक कंपनी की मदद से तिजोरी तैयार कराई गई। इसको समुद्री जहाज की मदद से इंग्लैंड से भारत लाया गया था। इसका वजन 200 किलोग्राम से भी अधिक है। बता दें कि ब्लैक बॉक्स प्लेन में होता है। प्लेन नष्ट होने पर ब्लैक बॉक्स ही सुरक्षित रहता है।

22 अक्टूबर को चर्चा में आई तिजोरी : मुरादाबाद जिले के नोडल अधिकारी एडीजी कमल सक्सेना और आइजी रमित शर्मा 22 अक्टूबर को शहर कोतवाली का निरीक्षण करने पहुंचे थे। दोनों पुलिस अधिकारियों की नजर मालखाने की एक पुरानी तिजोरी पर पड़ी। तब पता चला कि तिजोरी का वजूद बहुत पुराना है। अंग्रेजी हुकूमत ने डाकुओं के कोप से बचने के लिए तिजोरी का सहारा लिया।

तोड़ना तो दूर, जलाना या नष्ट करना भी संभव नहीं : तिजोरी को तोड़ना ही नहीं, बल्कि उसे जलाकर नष्ट करने में डकैत सफल नहीं हो सके थे। कोतवाली प्रभारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि आग में 24 घंटे बाद भी उसमें रखा सामान पूरी तरह से महफूज रहता है। तिजोरी दीवार में चिनवाई गई है। साल की लकड़ी से बने दरवाजों की सांकल व सिटकनी भी इंग्लैंड की बनी है।

आज भी रखे जाते हैं महत्वपूर्ण कागजात और बरामद माल : तिजोरी का उपयोग पुलिस आज भी कर रही है। तिजोरी का इस्तेमाल थाने के महत्वपूर्ण अभिलेख और साक्ष्य सुरक्षित रखने में हो रहा है।

उप्र की पीतलनगरी मुरादाबाद की शहर कोतवाली में दीवार में लगी तिजोरी व उस पर लगी प्लेट। जागरण

झारखंड की रीत 'चलना नृत्य और बोलना गीत'

झारखंड के घर-घर में मांदर ढोल-नगाड़े का प्रचलन है। यहां की लोकप्रिय कहावत है 'चलना ही नृत्य और बोलना हो गीत'। ऐसे में कोई भी गीत-संगीत का कार्यक्रम बिना वाद्य यंत्रों के अधूरा ही रहता है। इन वाद्य यंत्रों का निर्माण एक कला है और सिद्धहस्त कलाकार अपने बरसों के अनुभव से इन्हें तैयार करते हैं। रांची स्थित डॉ. रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान में इन दिनों लोक वाद्य यंत्र निर्माण की कार्यशाला चल रही है। इसमें कलाकार वाद्य यंत्रों का निर्माण करते हैं। रविवार को कार्यशाला में ढोल तैयार करता एक कलाकार और ढोल बजाकर आवाज परखती महिला। यह कार्यशाला वर्ष में एक बार दो सप्ताह के लिए होती है। जगदीश यादव

शीतकालीन गद्दी पर विराजमान हुए बाबा मध्यमेश्वर

संवाद सहयोगी, रुद्रप्रयाग : पंचकेदारों में शामिल द्वितीय केदार भगवान मध्यमेश्वर की उत्सव डोली विभिन्न पड़ावों पर प्रवास के बाद रविवार को अपने शीतकालीन गद्दीस्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में विराजमान हो गई। अब अगले छह माह बाबा मध्यमेश्वर यहां अपने भक्तों को दर्शन देंगे। मध्यमेश्वर के कपाट बीते 21 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद हुए थे। इसके बाद बाबा की उत्सव डोली गौंडार व रांसी होते हुए शनिवार को गिरिया पहुंची थी। यहां रविवार सुबह पुजारी ने डोली की विशेष पूजा-अर्चना कर बाबा को भोग लगाया। फिर जैसे ही डोली अपने अंतिम पड़ाव के लिए रवाना हुई, बाबा के जयकारों से पूरा क्षेत्र शिवमय हो गया। फाफंज, मंगोली, ब्राह्मणखोली, डंगवाड़ी आदि स्थानों पर ग्रामीणों ने मांगल गीतों के बीच पुष्प, अक्षत व पंचगव्य से डोली का भव्य स्वागत किया। केदारनाथ धाम के रावल भीमा शंकर लिंग ने पुजारियों के साथ मंगोलीचारी में डोली की आगवानी की। दोपहर बाद करीब पौने तीन बजे ऊखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर परिसर पहुंचने पर भक्तों ने पुष्प वर्षा के साथ डोली का स्वागत किया। यहां मंदिर की परिक्रमा करने के बाद विधि-विधान पूर्वक बाबा की भोगमूर्ति को मंदिर के गर्भगृह में विराजमान किया गया।

तैयारी

सोनप्रयाग, भीमबली व रामबाड़ा में बहुमंजिला घोड़ा पार्किंग बनाने का प्रस्ताव, सोनप्रयाग, गौरीकुंड, लिनचोली व केदारनाथ में अस्थाई पशु चिकित्सा केंद्र होंगे स्थापित

घोड़ा-खच्चर भी कर सकेंगे केदारनाथ पैदल मार्ग पर आराम

बृजेश भट्ट, रुद्रप्रयाग

यात्राकाल के दौरान केदारनाथ पैदल मार्ग पर बड़ी संख्या में घोड़ा-खच्चर काल-कवलित हो जाते हैं। इसकी वजह बनती है पैदल मार्ग की थकान और आराम के लिए घोड़ा पड़ाव न होना। इसी के मद्देनजर पशुपालन विभाग ने पैदल मार्ग पर घोड़ा-खच्चर पार्किंग और चार अस्थाई पशु चिकित्सालय स्थापित करने की कवायद शुरू कर दी है, ताकि बीच-बीच में घोड़ा-खच्चर को आराम मिल सके।

केदारनाथ यात्रा में घोड़ा-खच्चर की भूमिका सबसे अहम होती है। आधे से अधिक यात्री इनके जरिये ही बाबा के दर्शन को पहुंचते हैं। इस वर्ष भी पांच लाख से अधिक यात्री घोड़ा-खच्चर से ही केदारनाथ पहुंचे। इसके लिए सात हजार से अधिक घोड़ा-खच्चरों का पंजीकरण किया गया था। स्थानीय लोगों के अनुसार इनमें से 300 से अधिक घोड़ा-खच्चर की विभिन्न बीमारियों से मौत हो गई, लेकिन प्रशासन के पास 100 के आसपास का ही आंकड़ा है। हालांकि, इस आंकड़े को भी बहुत बड़ा मानते हुए पशुपालन विभाग की टीम पिछले दिनों वैष्णो देवी की यात्रा का अध्ययन करने गई थी। यहां लौटकर टीम ने अपने सुझाव प्रशासन को दिए। टीम का तर्क है कि केदारनाथ जाने वाले घोड़ा-खच्चर एक दिन में औसतन 45 किमी का सफर करते हैं, जिससे वो थककर चूर हो जाते हैं। पैदल मार्ग में उनके आराम के लिए कोई स्थान उपलब्ध नहीं है, जिससे कई बीमारियां उन्हें घेर लेती हैं, जो आखिरकार उनकी मौत की वजह बनती हैं।

इन्हीं तमाम बिंदुओं को केंद्र में रखकर विभाग ने अब घोड़ा-खच्चर संचालन को रोडमैप तैयार किया है। इसके तहत सोनप्रयाग, भीमबली व रामबाड़ा में बहुमंजिला घोड़ा पार्किंग बनाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा घोड़ा-खच्चरों के संचालन का तौर-तरीका बदलने के साथ ही सोनप्रयाग, गौरीकुंड, लिनचोली व केदारनाथ में अस्थाई पशुचिकित्सा शिविर भी बनाए जाने हैं, ताकि समय रहते घोड़ा-खच्चर को उपचार मिल सके। इससे उनकी मौत का आंकड़ा काफी कम हो जाएगा। पशुपालन विभाग के सुझावों पर डीएम मंगेश घिल्डियाल ने जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिशासी अभियंता को पार्किंग के लिए स्थान तलाशने के निर्देश दिए हैं।

अलग हो रास्ता : पशुपालन विभाग ने घोड़ा-खच्चर के लिए अलग से रास्ता बनाने का सुझाव भी दिया है। सामान ढोने वाले घोड़ा-खच्चर भी रात के वक्त ही पैदल मार्ग पर जाएं। इससे पैदल यात्रियों को दिक्कत नहीं होगी। विदित हो कि पैदल मार्ग पर घोड़ा-खच्चरों की आपसी टक्कर में अक्सर पैदल यात्री चोटिल हो जाते हैं।

यात्रा सीजन में केदारनाथ पैदल मार्ग पर घोड़े-खच्चरों की अहम भूमिका रहती है। आधे से अधिक यात्री इनके जरिये ही केदारनाथ पहुंचते हैं। फाइल फोटो

> वैष्णो देवी यात्रा का तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद केदारनाथ यात्रा को बेहतर बनाने के लिए सुझाव दिए गए हैं। इस संबंध में डीएम ने भी आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
> – रमेश नितवाल, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, रुद्रप्रयाग

मुस्लिम योग साधना शिविर के समापन पर दिखी योग की ताकत

शिविर के समापन पर गले से कार खीचता योग साधक। जागरण

- वैदिक आश्रम गुरुकुल महाविद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ शिविर संपन्न
- साधकों ने प्रस्तुत किए हैरतअंगेज कार्यक्रम

जागरण संवाददाता, कोटद्वार

उत्तराखंड के भाबर क्षेत्र के अंतर्गत वैदिक आश्रम गुरुकुल महाविद्यालय में चल रहा मुस्लिम योग साधना शिविर रविवार को रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ संपन्न हो गया। समापन पर योगी राज विश्वपाल जयंत (आधुनिक भीम) और उनके शिष्य देवेंद्र फौजी ने योग के बल पर हैरतअंगेज कारनामे प्रस्तुत किए। महाविद्यालय परिसर में आयोजित समापन समारोह में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. रूप किशोर ने कहा कि भारतीय संस्कृति का जन्म गुरुकुल से ही हुआ है और वह आज भी गुरुकुल संस्कृति का संरक्षण व संवर्द्धन कर रहे हैं। कण्वाश्रम की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने आमजन को योग के प्रति प्रेरित किया। इस दौरान गुरुकुल के संस्थापक योगीराज विश्वपाल जयंत ने योग के बल पर बाजुओं की ताकत से विपरीत दिशाओं में जा रही दो कारों को रोककर दर्शकों को दांतों तले अंगुली दबाने को मजबूर कर दिया। जबकि, उनके शिष्य देवेंद्र फौजी ने आंख, दांत व गले से सरिया मोड़ने के साथ ही चेन से भारी कार खींचने का हैरतअंगेज कारनामा दिखाया। उन्होंने करीब एक टन के वजनी पत्थर छाती पर रखकर भी तुड़वाया।

अतिरिक्त ब्लॉक में कोयला उत्पादन शुरू करे सीआइएल

नई दिल्ली : कोयला मंत्रालय ने सरकारी कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड (सीआइएल) से कहा है कि वह अपने अतिरिक्त कोल ब्लॉक में जल्दी उत्पादन शुरू करे अथवा इन्हें सरकार को वापस लौटा दे। सीआइएल को 110 अतिरिक्त कोल ब्लॉक दिए गए थे। मंत्रालय ने हाल में कंपनी से इस बारे में जानकारी मांगी थी। इसके जवाब में कंपनी ने बताया था कि 50 ब्लॉक के बारे में जानकारी जुटाई जा चुकी है और 41 ब्लॉक की छानबीन जारी है। इसके अलावा 19 अन्य ब्लॉक के बारे में जानकारी जुटाई जानी है। (प्रेट्र)

एस्सार स्टील के मामले में सुप्रीम कोर्ट का आइबीसी पर फैसला ऐतिहासिक है। आइबीसी समय के साथ ज्यादा परिपक्व और तर्कसंगत हो रहा है।

— एमएस साहू, चेयरमैन, आइबीबीआइ

चुनौती ▶ रेलवे को आधुनिकीकरण के लिए चाहिए 700 मेगाहट्र्ज का 15 मेगाहट्र्ज स्पेक्ट्रम, विभाग ने दिखाई कमी

रेलवे की सबसे महंगे स्पेक्ट्रम की मांग अधर में

दूरसंचार विभाग ने कहा – इतना दिया तो 5-जी सेवाओं के संचालन में होगी मुश्किल

संजय सिंह, नई दिल्ली

5-जी सेवाओं के लिए अत्यावश्यक और सबसे महंगे स्पेक्ट्रम के मुफ्त आवंटन की रेलवे की मांग से दूरसंचार विभाग पशोपेश में है। विभाग का कहना है कि यदि रेलवे की मांग मानी गई तो इससे देश में मोबाइल सेवाओं का आधुनिकीकरण प्रभावित होगा। जबकि रेलवे का तर्क है कि उक्त स्पेक्ट्रम के बगैर रेलवे के कायाकल्प का प्रधानमंत्री का सपना पूरा नहीं होगा।

रेलवे ने दूरसंचार विभाग से 700 मेगाहट्र्ज बैंड के 15 मेगाहट्र्ज स्पेक्ट्रम की मांग की है। इस मांग के पीछे रेलवे का तर्क है कि उसके 66 हजार रूट किलोमीटर के ट्रैक और 8,000 से ज्यादा स्टेशनों के विशाल नेटवर्क पर रोजाना 21 हजार यात्री एवं माल गाड़ियां चलती हैं। इनमें हर रोज करीब 2.2 करोड़ लोग सफर करते हैं। कुल मिलाकर भारतीय रेल हर साल आठ अरब यात्रियों और एक अरब टन माल को गंतव्य तक पहुंचाती है।

सिस्टम अपग्रेड करने के लिए रेलवे ने स्पेक्ट्रम मांगे थे। प्रतीकात्मक

फिलहाल रेलवे को अपने जीएसएम-आर आधारित नेटवर्क के संचालन के लिए 900 मेगाहट्र्ज बैंड का 1.6 मेगाहट्र्ज (पेयर्ड) स्पेक्ट्रम मिला हुआ है। परंतु इससे अब आगे काम नहीं चलने वाला है। अभी ट्रेन से ट्रेन तथा ट्रेन से ट्रैकसाइड के बीच रेडियो कम्यूनिकेशन के लिए रेलवे 2-जी स्तर के जीएसएम-आर मोबाइल सिस्टम का इस्तेमाल करती है। अभी तक 2,500 रूट किलोमीटर पर इस सिस्टम को लगाया जा चुका है। बाकी नेटवर्क पर 5-वाट और 25-वाट के वीएचएफ सेट्स का प्रयोग किया जाता है। ये दोनो सिस्टम मुख्यतया वॉयस-आधारित हैं। इनमें डाटा हैंडलिंग की कोई क्षमता नहीं है।

रेल मंत्रालय के अनुसार नवंबर, 2017 में प्रधानमंत्री के साथ हुए चिंतन शिविर में रेलवे नेटवर्क के साथ अल्ट्रा-हाईस्पीड वायरलेस कॉरिडोर्स के विकास का प्रस्ताव किया गया था। उस समय से ही रेलवे ने अपने आपरेशंस, यात्री सुरक्षा, संरक्षा, संतुष्टि तथा वित्तीय हालत में सुधार की दिशा में अनेक कदम उठाए हैं। शिविर का एक बड़ा निर्णय रेलवे की सिग्नलिंग एवं ट्रेन कंट्रोल प्रणाली को यूरोपीय ट्रेन कंट्रोल सिस्टम की तर्ज पर आधुनिक एवं मोबाइल कम्यूनिकेशन आधारित बनाने का था। इसके लिए 700 मेगाहट्र्ज बैंड के 15 मेगाहट्र्ज स्पेक्ट्रम की आवश्यकता है। रेलवे का कहना है कि चूंकि इस स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल लाभ के बजाय जनता की भलाई के लिए किया जाना है, लिहाजा इसका मुफ्त आवंटन किया जाना चाहिए।

रेलवे की इस मांग पर दूरसंचार विभाग ने आपत्ति जताई और कहा कि रेलवे का काम 600 से 450-470 मेगाहट्र्ज बैंड के स्पेक्ट्रम से भी चल सकता है। परंतु पर्याप्त 700 मेगाहट्र्ज स्पेक्ट्रम के बिना 5-जी सेवाएं नहीं चल सकतीं। उसने दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) से इस मसले पर राय मांगी। ट्राई ने रेलवे की मांग को उचित ठहराते हुए कम से कम 10 मेगाहट्र्ज स्पेक्ट्रम मुफ्त देने का सुझाव दिया। परंतु दूरसंचार विभाग अब भी खुद को रेलवे की मांग पूरी करने की स्थिति में नहीं पा रहा।

विभाग का कहना है उसके पास कुल मिलाकर 700 मेगाहट्र्ज बैंड में 35 मेगाहट्र्ज स्पेक्ट्रम ही उपलब्ध है। यदि 15 मेगाहट्र्ज स्पेक्ट्रम रेलवे को दे दिया गया तो सिर्फ 20 मेगाहट्र्ज स्पेक्ट्रम बचेगा जो भविष्य की 5जी सेवाओं के संचालन के लिए नाकाफी है। इन सेवाओं की शुरुआत अगले वर्ष से प्रस्तावित है, जिसके लिए इसी वर्ष दिसंबर तक स्पेक्ट्रम की नीलामी होनी है।

कई टेलीकॉम कंपनियां 700 बैंड स्पेक्ट्रम की खरीद के लिए तैयार बैठी हैं। यदि नीलामी के लिए केवल 20 मेगाहट्र्ज स्पेक्ट्रम उपलब्ध हुआ तो इससे उसकी कीमत बहुत अधिक बढ़ जाएगी। टेलीकॉम कंपनियां स्पेक्ट्रम की ऊंची कीमत को लेकर पहले से ही शिकायत कर रही हैं। स्पेक्ट्रम महंगा होने से उसकी बिक्री मुश्किल होगी जिसका असर अंततः पूरे देश में मोबाइल सेवाओं के आधुनिकीकरण और डाटा की स्पीड पर पड़ेगा। इन तर्कों के बाद रेलवे 10 मेगाहट्र्ज तक स्पेक्ट्रम लेने को राजी हो गया है। लेकिन डीओटी इस पर भी राजी नहीं है। दोनो विभागों के अड़ियल रुख को देखते हुए अधिकारी अब इस विवाद के समाधान के लिए पीएमओ से हस्तक्षेप की उम्मीद कर रहे हैं।

चावल का रिजर्व प्राइस घटाने की तैयारी में सरकार

प्रतीकात्मक

- एफसीआइ के पास चावल का बहुत अधिक हो चुका है बफर स्टॉक
- प्रति क्विंटल 500 रुपये कटौती पर हो रहा विचार
- वर्तमान में 2,785 रुपये प्रति क्विंटल है मूल्य

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्र सरकार चावल के रिर्जव प्राइस में कटौती पर विचार कर रही है। चावल का बफर स्टॉक बहुत ज्यादा होने के कारण खुले बाजार में इसकी बिक्री बढ़ाने की कोशिश के तहत दाम में 500 रुपये प्रति क्विंटल तक की कमी की जा सकती है। हालांकि गेंहू के रिजर्व प्राइस में किसी तरह की कटौती करने की योजना नहीं है।

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ओपन मार्केट सेल स्कीम (ओएमएसएस) के तहत बिक्री को गति देने के लिए चावल के रिजर्व प्राइस में कटौती की जाएगी। इसके तहत चावल का मूल्य 2,785 रुपये से घटाकर 2,250 रुपये प्रति क्विंटल किया जा सकता है। गौरतलब है कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एफसीआइ) के बफर स्टॉक की बिक्री ओएमएसएस के तहत की जाती है, जिसका संचालन खाद्य मंत्रालय करता है।

एफसीआइ देशभर से अनाज की खरीदारी और वितरण के लिए केंद्र की नोडल एजेंसी के तौर पर काम करता है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वर्तमान में एफसीआइ के पास करीब 2.31 करोड़ टन चावल और 3.73 करोड़ टन गेहूं का भंडार है। नवंबर तक इसके पास कुल मिलाकर करीब छह करोड़ टन अनाज मौजूद था। इससे पहले एफसीआइ ने चालू वित्त वर्ष में एक करोड़ टन गेहूं थोक खरीदारों को बेचने का फैसला किया था। इसका आधार मूल्य 2,080 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया है। पिछले वित्त वर्ष में करीब 70 लाख टन गेहूं बेचा गया था।

न्यूज गैलरी

सेल को आर्सेलरमित्तल के जवाब का इंतजार

नई दिल्ली : सेल और आर्सेलरमित्तल के संयुक्त स्टील प्लांट को लेकर संशय बरकरार है। सरकारी स्टील कंपनी सेल ने कहा है कि अत्याधुनिक ऑटोमोटिव स्टील (गाड़ियों को बनाने में प्रयोग की जाने वाली स्टील) प्लांट की स्थापना के मामले में उसे अभी तक आर्सेलरमित्तल के जवाब का इंतजार है। सेल के बोर्ड ने इस प्लांट की स्थापना की मंजूरी दो वर्ष पहले ही दे दी थी। सेल के चेयरमैन एके चौधरी ने कहा कि अभी तक आर्सेलरमित्तल की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। (प्रेट्र)

खान मार्केट दुनिया का 20वां सबसे महंगा बाजार

नई दिल्ली : नई दिल्ली का खान मार्केट दुनिया के सबसे महंगे बाजारों की सूची में एक स्थान सुधार के साथ 20वें स्थान पर आ गया है। मेन स्ट्रीट एक्रॉस द वर्ल्ड-2019 के नाम से तैयार इस सूची में दुनिया के सबसे महंगे बाजारों को जगह दी गई है। सूची के मुताबिक खान मार्केट में जमीन का किराया 243 डॉलर (करीब 17 हजार रुपये) प्रति वर्गफुट सालाना है। खान मार्केट पिछले वर्ष की सूची में 21वें स्थान पर था। इस सूची में पहला स्थान हांगकांग के काजवे बे को दिया गया है। (प्रेट्र)

गौतम थापर का प्रमोटर का दर्जा खत्म हो

नई दिल्ली : गौतम थापर को चेयरमैन पद से हटाने के बाद संकटग्रस्त सीजी पावर अब उनका प्रमोटर का दर्जा भी खत्म करना चाहती है। सीजी पावर की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक उनका जुड़े रहना कंपनी के लिए अच्छा नहीं है। इससे पहले अगस्त में आंतरिक जांच के दौरान कई तरह की वित्तीय अनियमितताएं सामने आई थीं। थापर सहित कंपनी के कई शीर्ष अधिकारियों पर फंड में हेरफेर करने के आरोप लगे थे। इसके बाद थापर को कंपनी बोर्ड से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। आशीष कुमार गुहा को कंपनी का नया चेयरमैन चुना गया था। (प्रेट्र)

पंकज ओसवाल की याचिका सुनी जाने योग्य : एनक्लैट

नई दिल्ली : एनक्लैट ने कहा है कि एनसीएलटी में पंकज ओसवाल द्वारा दाखिल याचिका कंपनी एक्ट के तहत सुनी जाने योग्य है। इस उत्तराधिकार की लड़ाई में पंकज ओसवाल की माता, ओसवाल एग्रोमिल्स लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनी ओसवाल ग्रीनटेक लिमिटेड एनक्लैट पहुंच गए थे। इसमें कहा गया था कि पंकज के पास याचिका दाखिल करने के लिए ग्रुप में जरूरी 10 परसेंट हिस्सा नहीं है। (प्रेट्र)

इंटरनेट कंपनियां एजीआर फैसले पर ले रहीं राय

नई दिल्ली, प्रेट्र : इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (एजीआर) मामले पर कानूनी राय ले रही हैं। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (आइएसपीएआइ) ने कहा है कि वह अपने सदस्यों पर सुप्रीम कोर्ट के एजीआर पर फैसले लागू होने या नहीं होने के बारे में कानूनी राय ले रहा है। एसोसिएशन का कहना है कि दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने बेवजह उसके सदस्यों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला लाद दिया है। संगठन का कहना है कि उसके कई सदस्य स्टार्ट-अप जैसे हैं जो छोटे शहरों और कस्बों में अपना कारोबार चला रहे हैं।

आइएसपीएआइ के प्रेसिडेंट राजेश छड़िया ने कहा कि हमने प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को इस बारे में अवगत कराया है। हमें वहां से जल्द कोई जवाब मिलने की उम्मीद है। इस बीच, हमें दूरसंचार विभाग से भी एक पत्र मिला है और हम उस पर कानूनी राय ले रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि डॉट ने इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनियों को बेवजह इस मामले में घसीट लिया है। इस महीने की शुरुआत में डीओटी ने एजीआर की जद में आई सभी कंपनियों को एक पत्र लिखा था। इसमें उन्हें कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में वे तीन महीनों के भीतर सरकार को अपनी देनदारी का भुगतान करें।

डीओटी ने 13 नवंबर के अपने आदेश में कहा कि यह सभी लाइसेंसधारकों की जिम्मेदारी है कि वे लाइसेंस करार में वर्णित प्रारूप के तहत देनदारी का मूल्यांकन और उसका भुगतान कर दें। डीओटी का यह पत्र कंपनियों को मिलने के बाद आइएसपीएआइ ने पीएमओ को चिट्ठी लिखी थी। संगठन का मानना था कि इस मामले में जो कंपनियां पक्षकार नहीं थीं, उनसे इस तरह की मांग करना उचित नहीं है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय पहले एजीआर पर अपने फैसले में सरकार द्वारा एजीआर की गणना के तरीके को उचित ठहराया था। उसके बाद भारती एयरटेल और वोडाफोन समेत दर्जनों टेलीकॉम कंपनियों (जिनमें से अधिकांश बंद भी हो चुकी हैं) पर सरकार को करीब 1.47 लाख करोड़ रुपये की देनदारी बन गई है। इस फैसले के बाद वोडाफोन आइडिया ने दूसरी तिमाही के नतीजे में करीब 51,000 करोड़ रुपये का कर्ज दिखाया, जो किसी एक तिमाही में किसी भी भारतीय कंपनी का सबसे बड़ा घाटा है।

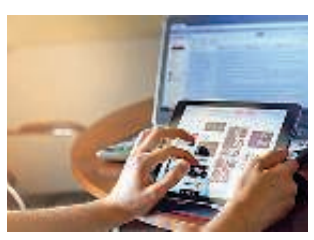

प्रतीकात्मक

- कंपनियों के संगठन ने कहा – हमें इस फैसले में बेवजह घसीटा जा रहा है
- दिया तर्क – जो कंपनियां पक्षकार नहीं, उन पर फैसला थोपना उचित नहीं

सुरक्षा ने दिया 7,857 करोड़ रुपये मूल्य की भूमि का प्रस्ताव

नई दिल्ली, प्रेट्र : मुंबई स्थित सुरक्षा रियल्टी ने जेपी इन्फ्रा के वित्तीय कर्जदाताओं को 7,857 करोड़ रुपये मूल्य की भूमि का प्रस्ताव दिया है। इसके अलावा कंपनी जेपी इन्फ्रा में एकमुश्त 25 करोड़ रुपये लगाने को भी तैयार है। जेपी इन्फ्रा की इन्सॉल्वेंसी प्रक्रिया के दौरान कर्जदाताओं के 9,782.60 करोड़ रुपये के दावे स्वीकार किए गए थे। इसमें से सुरक्षा रियल्टी भू-संपत्ति समेत कुल 7,882 करोड़ रुपये के भुगतान को तैयार है।

दूसरी तरफ, सुरक्षा रियल्टी की स्पर्धी एनबीसीसी इंडिया ने कर्जदाताओं को 9,782.60 करोड़ रुपये के पूर्ण भुगतान का वादा किया है। इसके तहत वह 5,001 करोड़ रुपये की भू-संपत्ति, यमुना एक्सप्रेसवे तथा अनबिके फ्लैट्स से हासिल लाभ का आधा हिस्सा देने को तैयार है। गौरतलब है कि नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनक्लैट) ने जेपी इन्फ्रा के कर्जदाताओं की समिति (सीओसी) से कहा था कि वह एनबीसीसी और सुरक्षा की संशोधित बोलियों पर विचार करे। एनबीसीसी ने इससे पहले कई वजहों के चलते इस बोली से हटने की इच्छा जताई थी।

अनिल अंबानी का इस्तीफा नामंजूर

नई दिल्ली, प्रेट्र : रिलायंस कम्यूनिकेशंस (आरकॉम) ने रविवार को कहा कि उसके कर्जदाताओं ने चेयरमैन अनिल अंबानी समेत चार अन्य निदेशकों का इस्तीफा नामंजूर कर दिया है। इन्हें कंपनी की चल रही कॉरपोरेट इन्सॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रक्रिया में सहयोग करने को कहा गया है। अंबानी समेत कंपनी के चार निदेशकों रायना करनी, छाया वीरानी, मंजरी कक्कड़ और सुरेश रंगाचार ने इस महीने की शुरुआत में इस्तीफा दे दिया था।

आरकॉम ने बीएसई को दी जानकारी में कहा कि उसके कर्जदाताओं की समिति (सीओसी) की 20 नवंबर को बैठक हुई थी। उस बैठक में कर्जदाताओं की एकमत से राय थी कि इस्तीफे स्वीकार नहीं किए जाने चाहिए। आरकॉम ने दी गई जानकारी में कहा, 'कंपनी के निदेशकों को सूचित किया जाता है कि उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है। उन्हें निदेशक के रूप में कंपनी में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते रहने और कॉरपोरेट इन्सॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रक्रिया में रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल को पूरा सहयोग करने की सलाह दी जाती है।'

एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (एजीआर) पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद आरकॉम की सरकार को देनदारी काफी बढ़ गई है। इसके चलते चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर, 2019) में कंपनी का कंसोलिडेटेड घाटा 30,142 करोड़ रुपये पर जा पहुंचा है। यह किसी भी भारतीय कॉरपोरेट कंपनी द्वारा किसी एक तिमाही का दूसरा सबसे बड़ा घाटा है। इससे पहले वोडाफोन आइडिया को भी चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में एजीआर के चलते ही लगभग 51,000 करोड़ रुपये का घाटा झेलना पड़ा, जो किसी एक तिमाही में किसी भी भारतीय कंपनी को घाटे का रिकॉर्ड है।

अनिल अंबानी। फाइल फोटो

- सीओसी ने 20 नवंबर की बैठक में पांचों का इस्तीफा नामंजूर कर दिया
- इन सबसे इन्सॉल्वेंसी प्रक्रिया में पूरा सहयोग करने को कहा गया है

बुरी हालत में कंपनी

आरकॉम ने एजीआर के लिए दूसरी तिमाही में 28,314 करोड़ रुपये की प्रोविजनिंग की, जिसके चलते उसका घाटा 30,000 करोड़ रुपये के ऊपर चला गया। कंपनी को लाइसेंस फीस के मद में 23,327 करोड़ रुपये और स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज के मद में सरकार को 4,987 करोड़ रुपये का भुगतान करना है। स्वीडन की कंपनी एरिक्सन के आवेदन पर इन्सॉल्वेंसी प्रक्रिया से गुजर रही है।

ये संपत्तियां हैं बिक्री पर

आरकॉम ने अपनी संपत्तियों को बिक्री पर रखा है। इनमें 122 मेगाहट्र्ज के स्पेक्ट्रम भी हैं, जिनकी इन्सॉल्वेंसी प्रक्रिया से पहले करीब 14,000 करोड़ रुपये कीमत लगाई जा रही थी। कंपनी के पास करीब 7,000 करोड़ रुपये मूल्य का टेलीकॉम टावर बिजनेस भी है। इसके अलावा कंपनी के ऑप्टिकल फाइबर बिजनेस का मूल्य करीब 3,000 करोड़ रुपये है।

आइबीसी में सुधार करेगी सरकार

- संकटग्रस्त संपत्ति खरीदने वालों का किया जाएगा बचाव
- संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान हो सकता है सुधार

संकटग्रस्त संपत्तियों में कई वजह से कम खरीदार रुचि लेते हैं। प्रतीकात्मक

नई दिल्ली, प्रेट्र : सरकार संकटग्रस्त संपत्ति खरीदने वालों के बचाव के लिए इन्सॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड (आइबीसी) में सुधार पर विचार कर रही है। इस सुधार के जरिये संकटग्रस्त कंपनी के पूर्व प्रमोटर्स द्वारा किए गए अपराध से संपत्ति के नए खरीदार को सुरक्षा प्रदान की जाएगी। बताया जा रहा है कि इस सुधार के बाद संकटग्रस्त संपत्तियों की रिजॉल्यूशन प्रक्रिया आसान हो जाएगी, क्योंकि कानूनी पचड़े से बचाव के चलते इस तरह की संपत्तियों में खरीदारों की रुचि बढ़ेगी।

सूत्रों के मुताबिक संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान आइबीसी में सुधार किए जाने की उम्मीद है। इससे पहले इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं, जहां नए खरीदारों को पूर्व प्रमोटर्स द्वारा की गई गड़बड़ियों की वजह से परेशान होना पड़ा है। हालांकि भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड (बीपीएसएल) जैसे मामलों में किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी।

गौरतलब है कि पिछले महीने ईडी ने बीपीएसएल की ओडिशा स्थित करीब चार हजार करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच कर दी थी। इस संकटग्रस्त कंपनी के रिजॉल्यूशन के लिए जेएसडब्ल्यू स्टील की योजना को मंजूरी दी गई थी। लेकिन वह रिजॉल्यूशन प्रक्रिया में देर कर रही थी और उस पर फंड में हेरफेर करने का आरोप भी लग रहा था। इसके चलते एनक्लैट ने ईडी और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय से बीपीएसएल की संपत्ति अटैच करने को कहा था।

एस्सार स्टील मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ऐतिहासिक : साहू

नई दिल्ली, प्रेट्र : इन्सॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया (आइबीबीआइ) के चेयरमैन एमएस साहू ने एस्सार स्टील मामले में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि दिवालिया प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय ऐतिहासिक है। इस फैसले के बाद रिजॉल्यूशन प्रक्रिया बीच में रोकने वालों को नसीहत मिल गई है। आइबीबीआइ प्रमुख ने कहा कि लागू होने के तीन वर्ष के दौरान आइबीसी लगातार समृद्ध हुआ है। इन्सॉल्वेंसी से जुड़े प्रत्येक निर्णय के बाद इसकी जड़ें मजबूत हुई हैं। इसी महीने की 15 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने एस्सार स्टील मामले में अपना फैसला सुनाया था। कोर्ट ने आर्सेलरमित्तल को संकटग्रस्त एस्सार स्टील के अधिग्रहण की मंजूरी दे दी थी। कानूनी चुनौती के चलते यह मामला लंबे समय से लटका हुआ था।

ऑडिटरों के लिए नियम और होंगे सख्त

- ऑडिटिंग के दौरान दिखी हर संदिग्ध गतिविधि की जानकारी सरकार तक पहुंचानी पड़ेगी
- इसका मकसद कंपनियों के कामकाज में पारदर्शिता का स्तर बढ़ाना

नितिन प्रधान, नई दिल्ली : ऑडिटर को ऑडिटिंग के स्तर पर कंपनियों के कामकाज में दिखने वाली हर गड़बड़ी की जानकारी अब सरकार तक पहुंचानी पड़ेगी। सरकार चाहती है कि ऑडिटर की खुद की संतुष्टि पर अधिक भरोसा नहीं करते हुए रिपोर्ट अपने पास भी रखी जाए, ताकि वक्त पर उसका इस्तेमाल हो सके।

कंपनी के वित्तीय लेखाजोखा का ऑडिट करने वाली ऑडिट कंपनियां फिलहाल तीन स्तर पर काम करती हैं। इसके तहत ऑडिटिंग के वक्त कंपनी के कामकाज में किसी भी संदिग्ध गतिविधि के संज्ञान में आने पर कंपनियों को उसकी जांच करने को कहा जाता है। कंपनी को 45 दिनों के भीतर जांच पूरी करके ऑडिटर को देनी होती है।

जांच में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं पए जाने पर ऑडिटर अपने काम को आगे बढ़ाता है। लेकिन यदि इस जांच में कोई गड़बड़ी पकड़ी जाती है तो ऑडिटर के लिए इसकी जानकारी रेगुलेटर और कॉरपोरेट अफेयर मंत्रालय (एमसीए) के माध्यम से सरकार तक पहुंचानी जरूरी होती है।

बीते कुछ वर्षों में बैंक घोटालों और कुछ कंपनियों के मामले में ऑडिटरों की भूमिका को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। कुछ ऑडिट कंपनियों पर कार्रवाई भी हुई है। इस पूरे परिदृश्य में अब सरकार ऑडिट कंपनियों की भूमिका को और सख्त व पारदर्शी बनाने पर विचार कर रही है। सूत्र बताते हैं कि इसी क्रम में ऑडिट कंपनियों के लिए शुरुआती जांच की रिपोर्ट सही आने पर भी उसकी जानकारी सरकार को देना अनिवार्य बनाया जा सकता है। एमसीए में इस पर विचार चल रहा है और सूत्रों का कहना है कि जल्द ही इसका एलान भी हो सकता है।

निगाहें

इस सप्ताह जारी होने हैं दूसरी तिमाही के जीडीपी आंकड़े, कुल मिलाकर बाजारों के सीमित दायरे में रहने की संभावना

जीडीपी आंकड़ों और ग्लोबल संकेतों का बाजार पर दिखेगा असर

नई दिल्ली, प्रेट्र : इस सप्ताह प्रमुख भारतीय शेयर बाजारों की नजर अमेरिका-चीन में चल रही ट्रेड वार्ता, विदेशी पूंजी प्रवाह और जीडीपी आंकड़ों को लेकर लगाए जा रहे कयासों पर रहेगी। इसके अलावा महाराष्ट्र का राजनीतिक घटनाक्रम भी निवेशकों को प्रभावित करेगा। कुल मिलाकर बाजार के सीमित दायरे में रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। सैमको सिक्युरिटीज एंड स्टॉकनोट के सीईओ जिमीत मोदी के मुताबिक इस दौरान शेयर बाजारों के सुस्त रहने की संभावना है। इस सप्ताह सरकार की ओर से कोई सकारात्मक नीतिगत खबर आने की उम्मीद नहीं है। इसके अलावा विनिवेश और ग्लोबल घटनाक्रम की वजह से भी बाजार नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकते हैं।

जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के रिसर्च प्रमुख विनोद नायर के मुताबिक इस सप्ताह जारी होने वाले दूसरी तिमाही के जीडीपी आंकड़े शेयर बाजारों को प्रभावित करेंगे। हालांकि आंकड़े शुक्रवार को कारोबारी सत्र के बाद जारी होंगे। लेकिन इनको लेकर लगाए जा रहे कयासों का असर दिखाई देने की बात कही जा रही है। कई रेटिंग एजेंसियों और इकोनॉमिक संस्थाओं ने विकास दर कम रहने की आशंका जताई है। इससे पहले चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में यह पांच परसेंट रही थी। पिछले सप्ताह के कारोबार में सेंसेक्स 2.72 अंक और निफ्टी 18.95 अंक की बढ़त दर्ज करने में सफल रहे थे।

प्रतीकात्मक

सात कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 76 हजार करोड़ रुपये गिरा

नई दिल्ली, प्रेट्र : पिछले सप्ताह सेंसेक्स और निफ्टी साप्ताहिक बढ़त के बावजूद 10 सबसे बड़ी कंपनियों में से सात के बाजार पूंजीकरण में 76,164.3 करोड़ रुपये की गिरावट दर्ज की गई। इस दौरान टीसीएस को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। शीर्ष 10 कंपनियों में से सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी और एसबीआइ के एम-कैप में इजाफा हुआ। आंकड़ों के मुताबिक पिछले सप्ताह टीसीएस के एम-कैप में 39,118.6 करोड़ रुपये की गिरावट आई है। इस दौरान यह घटकर 7,76,950.02 करोड़ रुपये रह गया। इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक के एम-कैप में 10,410.2 करोड़, इन्फोसिस में 7,174.59 करोड़, एचयूएल में 7,154.7 करोड़, एचडीएफसी बैंक में 7,033.72 करोड़ रुपये की गिरावट दर्ज की गई। दूसरी ओर रिलायंस इंडस्ट्रीज का एम-कैप 48,874.91 करोड़ रुपये के इजाफे के साथ 9,80,287.54 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया।

इस महीने मेहरबान रहे एफपीआइ

नई दिल्ली, प्रेट्र : इस महीने में अब तक विदेशी निवेशक भारतीय शेयर बाजारों पर मेहरबान रहे हैं। डिपॉजिटरी आंकड़ों के मुताबिक चालू महीने में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआइ) ने घरेलू शेयर बाजारों में करीब 17,722 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश किया है। इस दौरान उन्होंने 17,547.55 करोड़ रुपये इक्विटीज में और 175.27 करोड़ रुपये डेट सेग्मेंट में डाले हैं। इस तरह विदेशी निवेशकों ने 1-22 नवंबर के बीच कुल 17,722.82 करोड़ रुपये भारतीय बाजारों में लगाए हैं। सकारात्मक ग्लोबल संकेतों और घरेलू स्तर पर बेहतर कारोबारी स्थितियों के चलते एफपीआइ पिछले दो महीनों से शुद्ध निवेशक बने हुए हैं। इन निवेशकों ने अक्टूबर में कुल 16,464.6 करोड़ और सितंबर में 6,557.8 करोड़ रुपये भारतीय शेयर बाजारों में निवेश किए।

सोने के आयात में नौ परसेंट की गिरावट

नई दिल्ली, प्रेट्र : इस वर्ष अप्रैल-अक्टूबर की अवधि के दौरान भारत के सोना आयात में नौ परसेंट की गिरावट आई है। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक समीक्षाधीन अवधि में सोने के आयात में करीब 1,763 करोड़ डॉलर (करीब 1.25 लाख करोड़ रुपये) की गिरावट दर्ज की गई है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान यह आंकड़ा करीब 1,940 करोड़ डॉलर मूल्य का रहा था। सोने के आयात में गिरावट के चलते देश के व्यापार घाटे में सुधार हुआ है। इस वर्ष अप्रैल-अक्टूबर की अवधि के दौरान देश का व्यापार घाटा करीब 9,472 करोड़ डॉलर रहा। पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान व्यापार घाटा करीब 11,615 करोड़ डॉलर रहा था।

236 करोड़ रुपये (3.3 करोड़ डॉलर) का यूरो जैकपाट जीता है हंगरी के एक नागरिक ने। यह हंगरी के किसी नागरिक द्वारा लॉटरी में जीती गई अब तक की सबसे बड़ी इनामी राशि है। 2012 से शुरू यूरो जैकपॉट यूरोप के 18 देशों में खेली जाने वाली लॉटरी है।

न्यूज गैलरी

पाकिस्तान में छह वर्षों के दौरान 33 पत्रकारों की हत्या

इस्लामाबाद : जम्मू-कश्मीर में कथित रूप से मानवाधिकार उल्लंघन की दुहाई देने वाला पाकिस्तान खुद पत्रकारिता के लिए सुरक्षित जगह नहीं है। फ्रीडम नेटवर्क के अनुसार, पिछले छह वर्षों में यहां 33 पत्रकारों की काम के दौरान हत्या हो चुकी है। इस तथ्य की दूसरे संगठनों ने भी पुष्टि की है। पाकिस्तान प्रेस फाउंडेशन के अनुसार, 2002 से 2019 के बीच 48 पत्रकारों की मौत हुई, जिनमें 24 पत्रकार काम करते हुए मारे गए। 171 पत्रकारों पर बड़े तो 77 पत्रकारों पर छोटे-मोटे हमले हुए। इतना ही नहीं 18 पत्रकार गिरफ्तार हुए, 26 को हिरासत में लिया गया और 36 पर विभिन्न मामलों में मुकदमे दर्ज किए गए। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के मुताबिक, विश्व पत्रकारिता सूचकांक में पाकिस्तान 142वें नंबर पर है। (एएनआइ)

पूर्वी कांगो में हुए विमान हादसे में 24 की मौत

गोमा : रविवार को कांगो के गोमा शहर में हुए एक विमान हादसे में 24 लोगों की मौत हो गई। विमान स्थानीय कंपनी बिजी बी का था और बेनी जाने के लिए टेक ऑफ करने के कुछ ही देर बाद यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 19 सीटों वाले डार्नियर विमान में कुल 17 यात्री और दो चालक दल के सदस्य थे। मलबे से 24 शव मिले हैं, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि इसकी चपेट में आकर कुछ अन्य लोग भी मरे हैं। (रायटर)

हवाई हमले में तीन तालिबानी आतंकी मारे गए

काबुल : हेरात और फरह प्रांत में अफगान सुरक्षा बलों पर किए गए हवाई हमले में तीन तालिबानी आतंकी मारे गए हैं। यह हमले रविवार सुबह नौ से दस बजे के बीच किए गए। जिन आंतकियों को लक्ष्य करके हमला किया गया था वह मुख्य सड़क के किनारे बारूदी सुरंग बिछा रहे थे। हमले में इनके विस्फोटक से भरे वाहन को भी नष्ट कर दिया गया। (आइएएनएस)

हमले में आठ अफगान सुरक्षाबलों की मौत

काबुल : काजरान प्रांत के दाइकुनी जिले में रविवार को उग्रवादियों द्वारा सुरक्षा चौकी पर किए गए हमले में आठ सुरक्षा बलों की मौत हो गई। प्रांतीय सरकार के प्रवक्ता साकिनी एहसानी ने घटना की पुष्टि की है। अभी तक किसी भी आतंकी समूह ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। (एएनआइ)

न्यूजीलैंड में आया 5.9 तीव्रता का भूकंप

वेलिंगटन : न्यूजीलैंड में शनिवार को 5.9 तीव्रता का भूकंप आया। फिलहाल इससे हताहत होने वालों की संख्या का पता नहीं चला है। इसी तरह अलास्का के एंड्रियन द्वीप पर भी रविवार सुबह 6.3 तीव्रता का भूकंप आया। फिलहाल यहां पर सुनामी या किसी प्रकार की एडवाइजरी जारी नहीं की गई है। (एएनआइ)

रोमानिया में दूसरे राउंड के लिए मतदान शुरू

बुखारेस्ट : रोमानिया में रविवार को राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे दौर के लिए मतदान शुरू हो गया। यूरोपीय संघ के समर्थक क्लाउस इओहनीस की वापसी होने की उम्मीद है। 10 नवंबर को हुए पहले दौरे के मतदान में इओहनीस को 38 फीसद वोट मिले थे। जबकि पूर्व प्रधानमंत्री को विओरिका डांसिला को 22 फीसद वोट मिले थे। बता दें कि पिछले महीने विश्वासमत साबित नहीं कर पाने के चलते डांसिला की सरकार गिर गई थी। (एएफपी)

मिस्र ने पशुओं की ममी के बारे में जानकारी सार्वजनिक की

सक्कारा : मिस्र के पुरातत्व मंत्रालय ने हाल ही में मिले पशुओं की ममी के बारे में जानकारी सार्वजनिक की है। मंत्रालय ने कहा है कि इनमें दो शेर शावकों के साथ ही कई घड़ियाल, पक्षियों और बिल्लियों की ममी हैं। बीते शनिवार को एक प्रदर्शनी के दौरान इस आशय की घोषणा की गई। पुरातत्वविदों को बिल्ली की ममी मिलती रही है, लेकिन शेर की ममी दुर्लभ है। मंत्रालय ने कहा है कि पशुओं की सभी ममी ईसवी पूर्व 664-332 की हैं। मंत्रालय ने पिछले सप्ताह घोषणा की थी कि वह वास्तव में शेर की ममी है सुनिश्चित करने के लिए स्कैन कराने में जुटा है। (एपी)

फ्रांस में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात

दक्षिण-पूर्वी फ्रांस में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। रोतेब्रुन-सुर-आर्गेस शहर में आई बाढ़ में डूबी भगवान बुद्ध की प्रतिमा। लगातार बारिश होने से हवाई एवं रेल व परिवहन सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। सैकड़ों घर बाढ़ में बह गए और अनेक लोग लापता हैं। एएफपी

ट्रंप के महाभियोग मामले में कुछ और लोगों की हो सकती है पेशी

वाशिंगटन, रायटर : अमेरिका में प्रतिनिधि सभा की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग मामले की जांच कर रही संसदीय समिति ने अभी तक हुई सुनवाई की रिपोर्ट तैयार करनी शुरू कर दी है। समिति के प्रमुख एडम स्किफ ने कहा है कि मामले में कुछ और लोगों की पेशी होगी, इसके बाद महाभियोग प्रस्ताव की रूपरेखा तैयार होगी।

बाद में यह प्रस्ताव सदन में विचारार्थ रखा जाएगा। सदन की स्वीकृति के बाद महाभियोग प्रस्ताव पर बहस और उस पर मतदान हो सकता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर महाभियोग की तलवार 25 जुलाई को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से उनकी टेलीफोन वार्ता के कारण लटकी है। इस वार्ता में ट्रंप ने अपने संभावित चुनावी प्रतिद्वंद्वी व डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता पूर्व उप राष्ट्रपति जो बिडेन के खिलाफ जांच शुरू कराने की कोशिश की थी। 2015 में अमेरिकी सैन्य सहायता में गड़बड़ी को लेकर तत्कालीन उप राष्ट्रपति बिडेन पर अंगुली उठी थी। माना जा रहा है कि ट्रंप ने 2020 के चुनाव की चुनौती कमजोर करने के लिए यूक्रेन में ताना-बाना बुनने की कोशिश की।

सोशल मीडिया पर ईरानी अफसरों के अकाउंट ब्लॉक किए जाएं

- ईरानी जनता के लिए इंटरनेट रोके जाने पर अमेरिका ने कहा
- कहा कि ईरान किसी बड़े हमले की तैयारी भी कर रहा है
- पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में 200 प्रतिशत की वृद्धि पर हो रहा प्रदर्शन

वाशिंगटन, एएफपी : अमेरिका ने फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर से कहा है कि वे अपने प्लेटफॉर्म पर सक्रिय ईरानी नेताओं और अधिकारियों के अकाउंट तत्काल प्रभाव से ब्लॉक कर दें। ईरान में सरकार की नीतियों से भड़की जनता के लिए वहां की सरकार ने इंटरनेट संपर्क खत्म कर दिया है। अमेरिका ने इसके जवाब में सरकार से जुड़े लोगों को सोशल मीडिया पर ब्लॉक करने के लिए कहा है। अमेरिका ने कहा है कि ईरान किसी बड़े हमले की तैयारी भी कर रहा है।

ईरान मामलों के विशेष अमेरिकी दूत ब्रायन हुक ने कहा है कि ईरान में इस समय घोर पाखंडियों की सरकार है। इसने जनता के लिए इंटरनेट को बंद कर दिया है जबकि इसके खुद के मंत्री और अधिकारी सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए विलंब न करते हुए सभी सोशल मीडिया कंपनियां ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई, राष्ट्रपति हसन रुहानी और विदेश मंत्री जवाद जरीफ के सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक करें। ...और इसे तब सक्रिय किया जाए जब ईरान सरकार आमजनों के लिए इंटरनेट चालू कर दे। ईरान में पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में की गई 200 प्रतिशत की वृद्धि के विरोध में 15 नवंबर से जनता सड़कों पर है। विरोध प्रदर्शनों को काबू में करने के लिए सरकार ने इंटरनेट पर रोक लगा दी है। सरकार ने इन विरोध प्रदर्शनों में पांच लोगों के मरने की पुष्टि की है लेकिन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मरने वालों की तादाद 100 से ज्यादा बताई है। अमेरिका के कड़े प्रतिबंधों के चलते ईरान की अर्थव्यवस्था बुरे दौर से गुजर रही है और महंगाई आसमान पर पहुंच गई है। आवश्यक वस्तुओं के लिए लोग तरस रहे हैं। सुरक्षा बलों की सख्ती विरोध जताने वालों को सड़कों से हटा पाने में नाकाम है।

ब्रिटिश पीएम जॉनसन के चुनाव घोषणापत्र में ब्रेक्जिट पर जोर

रणनीति ▶ 12 दिसंबर को होने वाले चुनाव में हरहाल में बहुमत चाहते हैं

सत्तारूढ़ कंजरवेटिव पार्टी ने मितव्ययिता जैसे मुद्दों पर आगे बढ़ने का संकल्प भी दोहराया

लंदन, एएफपी : ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने रविवार को कंजरवेटिव पार्टी का चुनाव घोषणापत्र जारी किया। इसमें उन्होंने आम चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए ब्रेक्जिट और मितव्ययिता जैसे मुद्दों पर आगे बढ़ने का संकल्प दोहराया है। जॉनसन ने जुलाई में अल्पमत सरकार का कामकाज संभाला था, लेकिन संसद के माध्यम से ब्रिटेन को यूरोपीय संघ से अलग करने के समझौते (ब्रेक्जिट) को गति देने में असमर्थ रहे थे। ऐसे में वह 12 दिसंबर को होने वाले चुनाव में हरहाल में बहुमत चाहते हैं।

ब्रेक्जिट पर चल रहे गतिरोध को खत्म करने के लिए जॉनसन साढ़े चार साल में तीसरे आम चुनाव को एकमात्र विकल्प के रूप में देखते हैं। इसी मुद्दे पर 2016 में जनमत संग्रह भी हुआ था, जिसमें 52 फीसद मतदाताओं ने ब्रेक्जिट के पक्ष में मतदान किया था। ब्रेक्जिट समझौते की तिथि को तीन महीने आगे बढ़ाकर 31 अक्टूबर से 31 जनवरी करने के बाद विपक्षी दलों ने जॉनसन के जल्द आम चुनाव कराने के निर्णय का समर्थन किया है। जॉनसन ने शनिवार को कहा, 'मैं अपना घोषणापत्र मतदाताओं के साथ साझा करने के लिए उत्सुक हूं। हमारे पास जनमत संग्रह का सम्मान करने वाली स्पष्ट योजना है। हम इस पर आगे बढ़ेंगे और प्रत्येक व्यक्ति और उसके परिवार को लाभ पहुंचाने में अपना ध्यान केंद्रित करेंगे।'

चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों के मुताबिक कंजरवेटिव पार्टी को 42 और मुख्य विपक्षी दल लेबर पार्टी को 29 फीसद वोट मिलने की संभावना जताई जा रही है। ब्रेक्जिट विरोधी लिबरल डेमोक्रेट्स को 15, ब्रेक्सिट पार्टी को छह और ग्रींस को तीन फीसद मत मिलने की उम्मीद है।

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन रविवार को लंदन में सत्तारूढ़ कंजरवेटिव पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र जारी करने ट्रेन से पहुंचे थे। रायटर

सत्ता संभालने के बाद लोकप्रियता में हुई वृद्धि

कंजरवेटिव पार्टी का मानना है कि चार महीने पहले टेरीजा मे के पद छोड़ने और जॉनसन के सत्ता संभालने के बाद उसकी लोकप्रियता में वृद्धि हुई है। कंजरवेटिव पार्टी इस बात को भी अपने पक्ष में मानकर चल रही है कि निगेल फराज के नेतृत्व वाली ब्रेक्जिट पार्टी ने 300 से अधिक सीटों से अपने उम्मीदवार हटा लिए हैं। पूर्व में फराज पर ब्रेक्जिट समर्थक वोटों को बांटने का आरोप लगता रहा है। ब्रिटिश संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कामंस में 650 सीटें हैं।

इमरान की पार्टी को मिले विदेशी चंदे की जांच कराने की मांग

- पीटीआइ के असंतुष्ट संस्थापक सदस्य ने चुनाव आयोग से किया अनुरोध
- बाबर ने नवंबर, 2014 में विदेशी चंदे के खिलाफ भी एक मामला दायर किया था

इस्लामाबाद, आइएएनएस : पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआइ) पार्टी के असंतुष्ट संस्थापक सदस्य अकबर एस बाबर ने चुनाव आयोग से विदेशी चंदा मामले की जांच का अनुरोध किया है। इस मांग से तीन दिन पहले ही चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी के खिलाफ पांच साल पुराने विदेशी चंदा मामले की सुनवाई रोजाना करने का फैसला किया था।

बाबर ने नवंबर, 2014 में पार्टी को मिले विदेशी चंदे के खिलाफ एक मामला दायर किया था। इसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि 21 करोड़ रुपये की रकम पार्टी को दो विदेशी कंपनियों से हुंडी के जरिये मिली और बाद में इसे पश्चिम एशिया से पाकिस्तान स्थित खातों में भेजा गया था।

एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार के मुताबिक शनिवार को पाकिस्तान चुनाव आयोग को दिए अपने छह पन्नों के आवेदन में बाबर ने पीटीआइ पर स्क्रूटनी कमेटी के काम में बाधा डालने का आरोप लगाया है। उन्होंने चुनाव आयोग से अनुरोध किया कि वह पार्टी के बैंक खातों के रिकॉर्ड अपने कब्जे में ले। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी स्क्रूटनी कमेटी को प्रमाणिक रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं करा रही। उन्होंने कहा, इस मामले में चुनाव आयोग सात बार सुनवाई कर चुका है और इस संबंध में 16 दिशा-निर्देश जारी कर चुका है, लेकिन खान की पार्टी लगातार उन्हें नजरअंदाज कर रही है।

इमरान को अयोग्य ठहराने के लिए याचिका: न्यायपालिका के खिलाफ टिप्पणी के कारण प्रधानमंत्री इमरान खान को अयोग्य ठहराने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता ताहिर मकसूद ने खान के खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला चलाने की मांग की है। ताहिर ने कहा, प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के जजों की आलोचना की है, जो कोर्ट की अवमानना है। न्यायपालिका विरोधी टिप्पणी के लिए 2013 में भी सुप्रीम कोर्ट ने खान को अवमानना नोटिस जारी किया था।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का फाइल फोटो।

सीपीईसी के भारी कर्ज तले दब जाएगा पाकिस्तान : अमेरिका

इस्लामाबाद, आइएएनएस : अमेरिका ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा है कि चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (सीपीईसी) से सिर्फ चीन को फायदा होगा। इसके विपरीत पाकिस्तान भारी कर्ज के बोझ तले दब जाएगा।

डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, वाशिंगटन के विल्सन सेंटर में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए अमेरिका की थिंकटैंक व दक्षिण एशिया मामलों की अतिरिक्त मंत्री एलिस वेल्स ने कहा कि कई बिलियन डॉलर की यह परियोजना पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव डालेगी। उन्होंने कहा कि सीपीईसी पाकिस्तान की मदद नहीं है। यह तो एक वित्तीय स्वरूप है जो चीनी कंपनियों को अनिवार्य मुनाफा प्रदान करेगा और उसका बहुत ही थोड़ा पाकिस्तान को भी मिल जाएगा।

वेल्स ने कहा, 'सीपीईसी की सबसे खर्चीली परियोजना कराची से पेशावर तक रेलवे लाइन का उच्चीकरण है। इस परियोजना की जब घोषणा की गई थी तब लागत 8.2 बिलियन डॉलर (करीब 588 अरब रुपये) आंकी गई थी। हालांकि, अक्टूबर 2018 में पाकिस्तानी रेल मंत्री ने कहा था कि सौदेबाजी से इस परियोजना की लागत दो अरब डॉलर (करीब 143 अरब रुपये) कम करा ली गई है।' उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक गरीब देश है और वह इतना कर्ज बर्दाश्त नहीं कर सकता। साथ ही हालिया मीडिया रिपोर्ट में यह भी कहा जा रहा है कि यह परियोजना अब नौ अरब डॉलर की हो चुकी है। पाकिस्तान को समझना होगा कि चीन कर्ज दे रहा है न कि अमेरिका की तरह अनुदान।

इराक में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की कार्रवाई में पांच मरे

बसरा में प्रदर्शन के दौरान लोगों ने टायरों में आग लगा दी। प्रेट्र

बगदाद, रायटर : इराक के नसीरिया शहर में सुरक्षा बलों की कार्रवाई में पांच प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। शनिवार देर रात शहर के प्रमुख पुलों से सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले दागने के साथ ही गोलियां भी चलाईं। इसमें 50 से ज्यादा प्रदर्शनकारी घायल भी हुए हैं।

इराक के दक्षिणी हिस्से में नसीरिया के अलावा बसरा शहर में भी विरोध प्रदर्शन उग्र रूप ले चुका है। देश में गत एक अक्टूबर से सरकार के खिलाफ शुरू हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान करीब 330 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदर्शनकारी गरीबी और घोर भ्रष्टाचार को लेकर वर्तमान सरकार को हटाने की मांग कर रहे हैं। नसीरिया में सुरक्षा बलों की कार्रवाई के बाद शिया समुदाय के पवित्र शहर कर्बला में रविवार सुबह उग्र प्रदर्शन हुए। भड़के लोगों को तितर-बितर करने के लिए सुरक्षा बलों ने बल प्रयोग किया, जिसमें 24 लोग घायल हो गए।

यौन हिंसा के खिलाफ फ्रांस में सड़कों पर उतरे हजारों लोग, किया प्रदर्शन

पेरिस, आइएएनएस : महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा के विरोध में शनिवार को फ्रांस में हजारों लोगों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से इन अपराधों से निपटने के लिए तत्काल कदम उठाने और इस संबंध में समाज के विभिन्न वर्गों को शिक्षित करने के लिए बजट निर्धारित करने की मांग की। फ्रांस में इस साल अब तक पुरुष साथियों द्वारा महिलाओं की हत्या के 137 मामले सामने आ चुके हैं। 2017 में यह आंकड़ा 109 और 2018 में 121 था। सरकारी अनुमान के अनुसार, राजधानी पेरिस में हुए प्रदर्शन में 49 हजार लोग शमिल हुए। वहीं इस प्रदर्शन का आयोजन करने वाले संगठन नाउ टाउट्स के अनुसार, इसमें एक लाख लोगों ने शिरकत की। देशभर में हुए इन प्रदर्शनों में बड़ी संख्या में छात्रों और बुजुर्गों ने भी हिस्सा लिया। इस प्रदर्शन का आयोजन करने वाली संस्था के संस्थापक कैरोलिन डी हास ने कहा, यह प्रदर्शन यौन हिंसा के खिलाफ समाज में अभूतपूर्व विरोध को प्रतिबिंबित करता है।

फ्रांस के मार्सिले शहर में रविवार को महिलाओं के खिलाफ हिंसा के विरोध में लोगों ने बैनर-पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। रायटर

तीन बच्चों के साथ जर्मनी लौटी आइएस की महिला सदस्य

फ्रैंकफर्ट, एएफपी : आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट (आइएस) की एक महिला सदस्य तीन बच्चों के साथ अपने मूल देश जर्मनी लौट आई है। जर्मनी की पुलिस के अनुसार, 30 साल की लॉरा एच आइएस की पहली वयस्क महिला सदस्य है जो आधिकारिक माध्यम से सीरिया से जर्मनी लौटी है। उसका दावा है कि आइएस की विचारधारा से अब उसका कोई लेना-देना नहीं है। जर्मनी के हेसे प्रांत की रहने वाली लॉरा शनिवार को इराक के इरबिल शहर से विमान के जरिये फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पहुंची। स्थानीय मीडिया के अनुसार, लॉरा को लौटने के तुरंत बाद गिरफ्तार नहीं किया गया, लेकिन उसकी आतंकी संगठन की संदिग्ध सदस्यता जांच का विषय है। वह बच्चों की उचित देखभाल करने में असफल रही। उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया है और देश छोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उसके बच्चों को नजदीकी रिश्तेदार को सौंप दिया गया है। लॉरा अपने बच्चों और सोमालिया में जन्मे अमेरिकी नागरिक पति के साथ 2016 में सीरिया चली गई थी, जहां वह आइएस से जुड़ी। पति की मौत और कुर्दिश सेना द्वारा पकड़े जाने के बाद उसे अल-होल जेल शिविर में रखा गया था।

थमा प्रदर्शन

कैरी लैम ने शांति और स्थिरता पर जताया संतोष, विश्लेषक ज्यादा मतदान को लोगों की ओर से लोकतंत्र के लिए मजबूत इच्छा का प्रदर्शन बता रहे हैं

हांगकांग में निकाय के लिए रिकॉर्ड मतदान

हांगकांग, रायटर : पुलिस की चाक-चौबंद व्यवस्था के बीच हांगकांग में स्थानीय निकाय के लिए रविवार को रिकॉर्ड मतदान हुआ। शाम 7.30 बजे तक 63 प्रतिशत वोट पड़ चुके थे जबकि मतदान के लिए तीन घंटे का समय बचा था। मतदान खत्म होते ही मतगणना का कार्य शुरू हो जाएगा, रात में ही पहला परिणाम आ सकता है। शांतिपूर्ण मतदान को कैरी लैम प्रशासन की सफलता बताया जा रहा है तो कुछ विश्लेषक ज्यादा मतदान को लोगों की ओर से लोकतंत्र के लिए मजबूत इच्छा का प्रदर्शन बता रहे हैं।

अपना वोट डालने के बाद हांगकांग की मुख्य प्रशासक कैरी लैम ने कहा कि उनकी सरकार निकायों की सिफारिशों को गंभीरता से लेती है। वे शासन में प्रभावी भूमिका अदा करती हैं। इसलिए लोगों में उनके प्रति विश्वास की भावना है। बढ़-चढ़कर मतदान लोगों की इसी भावना को प्रतिबिंबित करता है। लैम ने उम्मीद जताई कि हांगकांग में रविवार जैसी शांति और स्थिरता आने वाले दिनों में भी कायम रहेगी और लोग छह महीने से चली आ रही अशांति से हुए कष्टों को भूलने की कोशिश करेंगे। कोई नहीं चाहता हांगकांग अव्यवस्था वाली पुरानी स्थितियों में लौटे। वहीं 19 वर्षीय छात्र माइकेल एनजी ने कहा, ज्यादा मतदान से लोकतंत्र की हमारी इच्छा मजबूत होकर निकायों में पहुंचेगी। लोकतंत्र की मांग वाले आंदोलन में शामिल रहे माइकेल ने पहली बार मतदान किया था। कुल 18 जिला स्तरीय निकायों की 452 सीटों के लिए मतदान हुआ।

हांगकांग में चीन के साथ प्रत्यर्पण संधि के प्रस्ताव के विरोध में शुरू हुआ आंदोलन धीरे-धीरे लोकतंत्र और आजादी की मांग वाले आंदोलन में तब्दील हो गया। यह आंदोलन करीब छह महीने चला जिसमें भारी हिंसा हुई। इस हिंसा के चलते हांगकांग की छवि को नुकसान हुआ, साथ ही हजारों करोड़ की सार्वजनिक संपत्ति और कारोबार का नुकसान हुआ। 2012 में चीन की सत्ता संभालने वाले चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के लिए यह दौर सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरा। अब जबकि हफ्ते भर से हालात काबू में हैं, तब लोगों ने चैन की सांस ली है।

पिछले कई माह से प्रदर्शनों और हिंसा से जूझ रहे हांगकांग में रविवार को स्थानीय निकाय चुनाव में मतदान के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। एक मतदान केंद्र पर लगी कतारें। रायटर

ट्रंप की इच्छा के खिलाफ सील कमांडो की बर्खास्तगी पर आगे बढ़ी नौसेना

वाशिंगटन, एएफपी : अमेरिकी नौसेना ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इच्छा के खिलाफ जाकर अपने खास दस्ते सील कमांडो के एक सदस्य की बर्खास्तगी की कार्यवाही को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। इराक से जुड़े चर्चित मामले में युद्ध अपराध के आरोपी रहे 40 वर्षीय एडवर्ड गैलाघर को एक अन्य मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद नौसेना ने पदावनत कर दिया था। लेकिन ट्रंप ने नौसेना के इस फैसले को पलट दिया था। ट्रंप ने इसके साथ ही एलान किया था कि युद्ध में लड़ने वाले लोगों को नौसेना से बाहर नहीं किया जाएगा।

राष्ट्रपति के इस एलान के खिलाफ जाते हुए नौसेना ने इस सप्ताह गैलाघर और उसकी यूनिट के तीन अन्य सदस्यों की बर्खास्तगी को लेकर रिव्यू बोर्ड के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। गैलाघर पर 2017 में इराक में इस्लामिक स्टेट (आइएस) के एक घायल कैदी की चाकू मारकर हत्या करने के अलावा अन्य लोगों की हत्या की कोशिश करने और न्याय में बाधा डालने का आरोप था।

हिरोशिमा में परमाणु हमले के पीड़ितों से मिले पोप फ्रांसिस

- परमाणु हमले की भयावहता देखने वाले लोगों ने पोप से की भेंट
- विश्व समुदाय से इस त्रासदी से सबक लेने पर जोर दिया

पीस मेमोरियल पार्क में पुष्पांजलि अर्पित करते पोप फ्रांसिस। रायटर

हिरोशिमा, एएफपी : पोप फ्रांसिस ने जापान में अपने चार दिवसीय दौरे की शुरुआत रविवार को हिरोशिमा से की। 1945 में परमाणु हमले की भयावहता देखने वाले लोगों ने रविवार को यहां एक कार्यक्रम में पोप से भेंटकर अपनी दर्द भरी दास्तां सुनाई। उस त्रासदी को देखने वाले लोगों से तबाही का मंजर सुनने के बाद पोप परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर जमकर बरसे। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में अमेरिका ने अगस्त, 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु बम गिराए थे। इनमें लाखों लोगों की मौत हो गई थी। परमाणु विस्फोट से उपजे घातक विकिरण से बड़ी आबादी गंभीर बीमारियों की चपेट में आ गई थी। इस त्रासदी का दंश झेलने वाली बुजुर्ग पीड़िता योशिको काजिमोटो ने पोप को बताया कि परमाणु हमले के बाद उन्होंने सड़कों पर अधजले लोगों को दर्द से रेंगते देखा था। काजिमोटो के पूरे परिवार के उजड़ने की दास्तां सुनने के बाद पोप ने विश्व समुदाय से इस त्रासदी से सबक लेने पर जोर दिया।

उमेश यादव • एएफपी

अब अपनी सरजमीं पर भी घातक साबित हो रहे हैं भारतीय तेज गेंदबाज

अभिषेक त्रिपाठी • कोलकाता

भारतीय धरती पर किसी तेज गेंदबाज को मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज बनते हुए देखना वाकई में सुखद है। यह सिर्फ गुलाबी गेंद की वजह से नहीं हुआ है, बल्कि पिछले कुछ वर्षों में भारतीय तेज गेंदबाजों का विदेश ही नहीं देश की पिचों में प्रदर्शन शानदार रहा है। यह बात भारतीय कप्तान विराट कोहली, मुख्य कोच रवि शास्त्री और गेंदबाजी कोच भरत अरुण के अलावा दुनिया भर के दिग्गज मान रहे हैं। पिछले दो साल में ही तीन बार ऐसा हुआ, जिसमें भारतीय तेज गेंदबाजों ने किसी टेस्ट मैच में 19 या उससे ज्यादा विकेट चटकाए हैं। इतना ही नहीं, कोलकाता में हुए सीरीज के दूसरे टेस्ट में भारतीय तेज गेंदबाजों की गति को बांग्लादेश टीम सही से भांप भी नहीं पाई और टेस्ट के दौरान उसके चार बल्लेबाज चोटिल भी हुए। साथ ही टेस्ट इतिहास में जो अब तक पांच कंकशन सब्सीट्यूट हुए हैं उनमें से चार भारतीय तेज गेंदबाजों के खिलाफ हुए हैं।

कोहली की कप्तानी में भारतीय तेज गेंदबाजों का भारत में प्रदर्शन

गेंदबाज	टेस्ट	ओवर	रन	विकेट	पारी में सर्वश्रेष्ठ	मैच में सर्वश्रेष्ठ	औसत	5 विकेट	10 विकेट
उमेश यादव	23	602.2	1867	78	6/88	10/133	23.93	2	1
मुहम्मद शमी	14	389.3	1125	51	5/35	7/58	22.05	1	0
इशांत शर्मा	15	370.3	1001	36	5/22	9/78	27.8	1	0
भुवनेश्वर	5	130.3	367	18	5/48	8/96	20.38	1	0
वरुण आरोन	2	20	72	2	1/03	1/21	36.00	0	0

कोहली की कप्तानी में भारतीय स्पिनरों का भारत में प्रदर्शन

आर अश्विन	28	1283	3500	159	7/59	13/140	22.01	12	4
रवींद्र जडेजा	28	1207.1	2771	130	7/48	10/154	21.31	6	1
कुलदीप	3	94	340	14	5/57	6/119	24.28	1	0
अमित मिश्रा	4	118.5	396	12	3/51	4/60	33.00	0	0
जयंत यादव	4	104.3	367	11	3/30	4/68	33.36	0	0
शाहबाज नदीम	1	17.2	40	04	2/18	4/40	10.00	0	0

महेंद्र सिंह धौनी की कप्तानी में ही नहीं, विराट कोहली के कप्तान बनने के शुरुआती दौर में भी भारत में पिचें इस तरह से बनाई जाती थीं कि हमारे स्पिनर रविचंद्रन अश्विन, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, जयंत यादव विपक्षी टीम को धराशायी कर दें, लेकिन अब हमारे तेज गेंदबाज ऐसा कर रहे हैं। इसके पीछे सिर्फ गुलाबी गेंद और परिस्थितियां नहीं हैं, बल्कि तेज गेंदबाजों की कड़ी मेहनत है।

कोलकाता के ईडन गार्डेंस में इशांत शर्मा की अगुआई में भारत के तेज गेंदबाजों ने 19 के 19 विकेट झटके। ऑलराउंडर महमूदुल्लाह रिटायर्ड आउट नहीं होते तो शायद यह आंकड़ा 20 भी पहुंच जाता। इंदौर में पहले टेस्ट में भी 14 विकेट लिए थे। भारतीय स्पिनरों को वहां पांच विकेट मिले और एक रन आउट हुआ। यह मैच भी तीन दिन में खत्म हुआ था। यह वही होलकर स्टेडियम था जहां 2016 में भारतीय स्पिनरों (अश्विन और जडेजा) ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 17 विकेट लिए थे। उस मैच में तेज गेंदबाज उमेश यादव ही एकमात्र विकेट ले पाए थे और दो रन आउट हुए थे। इससे आपको पता चलेगा कि पिछले दो-तीन साल में भारतीय तेज गेंदबाजों की क्वालिटी कितनी सुधरी है। बहुत वर्षों बाद कोलकाता में देखने को मिला कि बल्लेबाज गेंदबाजों से डर रहे हों। बल्लेबाज अपना सिर बचाने की कोशिश कर रहे हों। ऐसा डर कभी वेस्टइंडीज के आक्रमण के सामने दिखाई देता था। खास बात यह है कि ऐसा तब हो रहा है जब भारत के दो मुख्य तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और भुवनेश्वर कुमार चोटिल होने के कारण टीम से बाहर थे। उमेश यादव, इशांत शर्मा और मुहम्मद शमी ने उनकी अनुपस्थिति में दिखाया कि इस गठजोड़ के पास तेजी, स्विंग, आक्रामकता और बाउंसर का जो पैक है वो किसी बल्लेबाज व टीम को परेशान करने के लिए काफी है। निश्चित तौर पर अगले साल न्यूजीलैंड में होने वाले दो टेस्ट में इसका असर देखने को मिलेगा।

01 जनवरी 2018 के बाद कोहली की कप्तानी में भारतीय तेज गेंदबाजों का घर में प्रदर्शन

गेंदबाज	टेस्ट	ओवर	रन	विकेट	पारी में सर्वश्रेष्ठ	मैच में सर्वश्रेष्ठ	औसत	5 विकेट	10 विकेट
उमेश यादव	7	154.3	527	38	6/88	10/133	13.86	2	1
मुहम्मद शमी	6	134.2	361	24	5/35	7/58	15.04	1	0
इशांत शर्मा	5	98.0	299	18	5/22	9/78	16.61	1	0

01 जनवरी 2018 के बाद कोहली की कप्तानी में भारतीय स्पिनरों का घर में प्रदर्शन

आर अश्विन	8	256.2	723	34	7/145	8/189	21.26	1	0
रवींद्र जडेजा	8	232.0	642	26	4/17	6/35	24.69	0	0
कुलदीप	2	66.0	249	10	5/57	6/119	24.90	1	0
नदीम	1	17.2	40	04	2/18	4/40	10.00	0	0

नोट : इसमें उन्हीं गेंदबाजों को शामिल किया गया है, जिन्होंने कम से कम एक विकेट लिया है।

19 विकेट तेज गेंदबाजों ने इस मैच में लेकर भारत को जीत दिलाई। भारत में ऐसा पहली बार हुआ है जब भारतीय टीम ने बिना स्पिनरों के विकेट झटके ही तेज गेंदबाजों के दम पर विपक्षी टीम को ऑलआउट कर मैच जीता हो

इशांत शर्मा • एपी

अगर आप यह सोचेंगे कि तेज गेंदबाज नहीं कर पाएंगे तो आप नकारात्मक सोच रहे हैं। जिस तरह से तेज गेंदबाज गेंदबाजी कर रहे हैं उससे वह कहीं, किसी भी पिच पर विकेट ले सकते हैं। वह घर में खेलें या बाहर उन्हें विश्वास है कि वह विकेट ले सकते हैं।
विराट कोहली, भारतीय कप्तान

03 बार अब पारी में पांच या ज्यादा विकेट ले चुके हैं उमेश यादव। उन्होंने दूसरी बार भारत में पांच विकेट झटके। इन दोनों मैचों में भारत को जीत मिली। उन्होंने एक बार पर्थ में पांच विकेट लिए थे। उस टेस्ट में भारत हारा था

भारतीय गेंदबाजी आक्रमण को देखकर अच्छा लगा। मुझे लगता है कि पिछले 15 महीनें विदेशी धरती पर गेंदबाजी करते हुए उनको पता चल गया है कि कैसे एक-दूसरे का सहयोग किया जाता है। जब आप दबाव बनाते हो तब यह सब चीजें होती हैं। उन्हें पता है कि वे इस समय विश्व के सर्वश्रेष्ठ आक्रमण हैं।
रवि शास्त्री, भारत के मुख्य कोच

भारतीय तेज गेंदबाज समूह में शिकार करते हैं। वे एक-दूसरे पर गर्व करते हैं। इस समूह के पीछे यही रहस्य है। उन्होंने अपना प्रोसेस सेट कर रखा है। वह अपने बेसिक्स पर ध्यान देते हैं और यही उन्हें सफलता दिलाती है। हमारा एक अनुभवी आक्रमण है। इस आक्रमण की खूबसूरत बात यह है कि वह परिस्थितियों के हिसाब से जल्द ही खुद को ढाल लेते हैं। गेंदबाज आपस में काफी बात करते हैं। न्यूजीलैंड दौरा निश्चित तौर पर बड़ी चुनौती होगा। हम इसके लिए तैयार हैं।
भरत अरुण, गेंदबाजी कोच

03 बार ऐसा हुआ है जब भारतीय तेज गेंदबाजों ने एक टेस्ट में मिलकर 19 या उससे ज्यादा विकेट लिए हैं। भारतीय तेज गेंदबाजों ने इससे पहले 2018 में ट्रेंट ब्रिज में इंग्लैंड के खिलाफ 19 विकेट और 2017-18 में जोहानिसबर्ग में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 20 विकेट लिए थे

भारत में देश के तेज गेंदबाजों का एक टेस्ट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन

विकेट	बनाम	स्थान	वर्ष
19	बांग्लादेश	कोलकाता	2019-20
17	श्रीलंका	कोलकाता	2017-18
16	इंग्लैंड	चेन्नई	1933-34
16	पाकिस्तान	दिल्ली	1979-80
16	पाकिस्तान	कोलकाता	1998-99

02 बार ऐसा हुआ है जब भारतीय स्पिनर को घरेलू सरजमीं पर विकेट नहीं मिला (जिस टेस्ट में कम से कम एक गेंद फेंकी गई हो)। 2017-18 में श्रीलंका के खिलाफ ईडन में ही ऐसा हुआ था

शमी ने मुझसे कहा कि जेब में जो भी हो मुझे दे दो। हम एक-दूसरे की सफलता के मजे ऐसे ही लेते हैं। जहां तक इस मैच की बात है तो मैं सिर्फ सही जगह पर गेंद पटक रहा था और अपनी योजना पर टिका था। हमने पिछले मैच में लेग कटिंग गेंद (बायें हाथ के बल्लेबाज को राउंड द विकेट फेंकना) का इजाद किया। हमने इस बारे में गेंदबाजी और बल्लेबाजी कोच से बात की। उन्हें लगता था कि इससे सिर्फ अनायास ही सफलता मिलती है, लेकिन मैं जानबूझकर वह गेंद फेंक रहा था और इस मैच में भी मैंने वैसे ही किया। जब हमने शुरू किया था तो स्विंग नहीं मिल रही थी, लेकिन शनिवार की रात को यह स्विंग हुई।
इशांत शर्मा, मैन ऑफ द सीरीज

पुरानी वेस्टइंडीज से हमारी तुलना करना जल्दबाजी : कोहली

भारतीय टीम टेस्ट में बेस्ट

- भारत ने बांग्लादेश को हराकर जीता अपना पहला डे-नाइट टेस्ट मैच
- इशांत ने मैच में झटके नौ विकेट व उमेश को मिलीं आठ सफलताएं

विशेष संवाददाता, कोलकाता: विराट कोहली ने बांग्लादेश से गुलाबी गेंद से टेस्ट जीतने के बाद कहा कि उनकी कप्तानी वाली भारतीय टीम की तुलना पिछली सदी के आठवें दशक वाली वेस्टइंडीज के साथ करना जल्दबाजी होगी।

कप्तान के रूप में कोहली की यह 33वीं जीत है। वेस्टइंडीज की टीम भी 1971 से 1980 तक अपनी सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में थी और अब भारत भी उसी फॉर्म में है। कोहली ने मैच के बाद कहा कि मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि इस समय हम अपने खेल में शीर्ष पर हैं। आप केवल सात मैचों के बाद ही टीम के दबदबे का आकलन नहीं कर सकते। आप वेस्टइंडीज की टीम की बात कर रहे हैं, जिन्होंने 15 वर्षों तक अपना दबदबा कायम रखा। उन्होंने हंसते हुए कहा कि आप मुझसे यह सवाल संन्यास के समय पूछ सकते हैं। हां, आप सात साल बाद यह सवाल यह पूछ सकते हैं, ना कि सात मैचों के बाद। कोहली ने कहा कि अब सोच बदल गई है और वे अब विश्व में किसी भी टीम को हरा सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि अभी समय (तुलना के लिए) बाकी है। लेकिन जिस तरह से हम खेल रहे हैं, उससे काफी उत्साहित हैं। अब हम न्यूजीलैंड में खेलेंगे और हमारे दिमाग में अब अगली सीरीज जीत है। देखते हैं कि विदेश में क्या होता है। कप्तान ने कहा कि हम टेस्ट क्रिकेट खेलने का इंतजार करते हैं। यही सोच बदली है। हमें पता है कि अगर हम अच्छा खेलते हैं तो हम दुनिया में कहीं भी जीत सकते हैं। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में खेलने में मजा तभी आएगा जब एक सीरीज घर में हो और फिर एक सीरीज बाहर। इससे विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में संतुलन बना रहेगा।

गांगुली ने कहा, कोलकाता ही नहीं, पूरे देश में होने चाहिए डे-नाइट टेस्ट: ईडन गार्डेंस में पहले डे-नाइट की अपार सफलता के बाद बीसीसीआइ अध्यक्ष सौरव गांगुली ने वादा किया कि देश के सभी हिस्सों में डे-नाइट टेस्ट आयोजित कराए जाएंगे।

ईडन गार्डेंस तीन दिन के दौरान पूरी तरह से दर्शकों से खचाखच भरा रहा और इससे टेस्ट क्रिकेट के पुराने दिनों की यादें ताजा हो गईं। गांगुली ने कहा कि मैं संतुष्ट और खुश हूं। हम यह टेस्ट क्रिकेट के लिए करना चाहते थे। यह बेहद जरूरी है क्योंकि लोग टेस्ट क्रिकेट देखने नहीं पहुंच रहे थे। हमने इसके लिए अच्छा प्रमोशन किया। यह जानते हुए भी कि टेस्ट पांच दिन से पहले खत्म हो जाएगा लोगों ने पांचों दिन की टिकट खरीदी।

अभिषेक त्रिपाठी • कोलकाता

चाहे विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका हो या टेस्ट रैंकिंग, लगातार चार बार पारी के अंतर से जीतना हो या तेज गेंदबाजों का प्रदर्शन भारतीय टीम सबसे आगे है। भारतीय टीम ने बांग्लादेश को ईडन गार्डेंस स्टेडियम में अपने पहले डे-नाइट टेस्ट में तीसरे दिन के शुरुआती घंटे में ही पारी और 46 रन से हराकर यह साबित कर दिया कि लाल गेंद का टेस्ट हो या गुलाबी गेंद का, विराट की टीम बेस्ट है। इस मैच के साथ ही भारतीय टीम के टेस्ट मैचों के घरेलू सत्र का शानदार अंत हुआ।

भारतीय टीम ने इस सत्र में भारत में पांच टेस्ट खेले, जिसमें सभी जीते, जबकि लगातार चार मैच उसने पारी के अंतर से जीते, जो आज तक किसी भी टीम ने नहीं किया है। भारतीय टीम ने इस दौरान दक्षिण अफ्रीका को 3-0 से और बांग्लादेश को 2-0 से हराया। इस पूरे टेस्ट सत्र में कभी भी ऐसा नहीं लगा कि भारतीय टीम किसी मैच को हारने की स्थिति में है। भारतीय टीम अगले साल न्यूजीलैंड में विश्व चैंपियनशिप के तहत दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगी। जहां तक सीमित ओवरों के क्रिकेट की बात है तो उसे अब वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन-तीन मैचों की वनडे व टी-20 सीरीज खेलनी है।

उमेश और इशांत का कहर: तेज गेंदबाजों इशांत शर्मा (9/78) और उमेश यादव (8/82) की शानदार गेंदबाजी के दम पर दुनिया की नंबर-1 टेस्ट टीम भारत ने मेहमान बल्लेबाजों का दम निकाल दिया। इशांत ने पहली पारी में तो उमेश ने दूसरी पारी में पांच विकेट लिए। इशांत को मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। इशांत और उमेश दोनों ने इस सीरीज में 12-12 विकेट लिए, लेकिन इशांत का औसत सबसे अच्छा रहा। इसके साथ भारत ने दो मैचों की सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली। उसने इंदौर में खेले गए पहले टेस्ट मैच में भी बांग्लादेश को एक पारी और 130 रनों से हराया था।

तीसरे दिन सिर्फ 52 गेंद का मैच: भारत ने शुक्रवार को टॉस हारने के बाद पहले गेंदबाजी करते हुए बांग्लादेश को 106 रनों पर आउट किया और फिर कप्तान विराट कोहली के शानदार शतक की बदौलत अपनी पहली पारी नौ विकेट पर 347 रनों पर घोषित कर दी थी। भारत के लिए पहली पारी में इशांत शर्मा ने पांच विकेट लिए। इसके बाद भारतीय टीम ने दूसरे दिन शनिवार को खेल खत्म होने तक 152 रनों पर बांग्लादेश के छह बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखा दी थी। बाकी की औपचारिकता रविवार को पूरी हुई। बांग्लादेश टीम अपनी दूसरी पारी में नौ विकेट पर 195 रन बना सकी। दूसरे दिन रिटायर्ड हर्ट हुए महमूदुल्लाह बल्लेबाजी करने नहीं उतरे। बांग्लादेश की ओर से रहीम ने सबसे अधिक 74 रन बनाए। रहीम ने शनिवार को अपने स्कोर 59 रनों से आगे खेलते हुए कई आकर्षक शॉट लगाए, लेकिन अंततः वह उमेश का शिकार हुए। रहीम ने 96 गेंदों का सामना कर 13 चौके लगाए। अल अमीन हुसैन ने भी 21 रनों की आकर्षक पारी खेली। इस पारी में भारत की ओर से उमेश यादव ने सबसे अधिक पांच विकेट लिए। इशांत शर्मा को चार विकेट मिले। इस तरह इशांत ने इस मैच में कुल नौ और उमेश ने आठ विकेट अपने नाम किए। भारत ने तीसरे दिन सिर्फ 52 गेंद फेंककर यह मैच अपने नाम किया।

स्कोर बोर्ड

टॉस : बांग्लादेश (वल्लेबाजी) मैन ऑफ द मैच/ सीरीज : इशांत शर्मा

बांग्लादेश, पहली पारी : 106 (30.3 ओवर), भारत, पहली पारी : 347/9 घोषित (89.4 ओवर), परिणाम : भारत पारी और 46 रन से जीता

बांग्लादेश (दूसरी पारी) 195 (41.1 ओवर) (152/6 से आगे)

	रन	गेंद	चौके	छक्के
मुश्फिकुर रहीम का. जडेजा बो. यादव	74	96	13	00
इबादत हुसैन का. कोहली बो. यादव	00	04	00	00
अल अमीन हुसैन का. साहा बो. यादव	21	20	05	00
अबू जाएद नाबाद	02	02	00	00

अतिरिक्त : (बा-8, लेबा-9, वा-5) 22, कुल : 41.1 ओवर में 195 रन पर सभी आउट, विकेट पतन : 1-152 (इबादत, 34.1), 8-184 (रहीम, 39.3), 9-195 (अल अमीन, 41.1)

गेंदबाजी : इशांत 13-2-56-4, उमेश यादव 14.1-1-53-5, मुहम्मद शमी 8-0-42-0, रविचंद्रन अश्विन 5-0-19-0, रवींद्र जडेजा 1-0-8-0

लगातार चार टेस्ट पारी के अंतर से जीतने वाली पहली टीम

दक्षिण अफ्रीका, पुणे (10 से 13 अक्टूबर, 2019) भारत पारी और 137 रनों से जीता
दक्षिण अफ्रीका, रांची (19 से 22 अक्टूबर, 2019) भारत पारी और 202 रनों से जीता
बांग्लादेश, इंदौर (14 से 16 नवंबर 2019) भारत पारी और 130 रनों से जीता
बांग्लादेश, कोलकाता (22 से 24 नवंबर 2019) भारत पारी और 46 रनों से जीता

विश्व टेस्ट चैंपियनशिप तालिका

क्रम	टीम	मैच	जीते	हारे	ड्रॉ	अंक
01	भारत	7	7	0	0	360
02	ऑस्ट्रेलिया	6	3	2	1	116
03	न्यूजीलैंड	2	1	1	0	60
04	श्रीलंका	2	1	1	0	60
05	इंग्लैंड	5	2	2	1	56
06	पाकिस्तान	1	0	1	0	00
07	वेस्टइंडीज	2	0	2	0	00
08	बांग्लादेश	2	0	2	0	00
09	द. अफ्रीका	3	0	3	0	00

33 वीं जीत विराट कोहली ने कप्तान के तौर पर हासिल की। विराट ने सर्वाधिक टेस्ट जीतने वाले कप्तान के मामले में एलन बॉर्डर को पछाड़ा। ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर के नाम 32 टेस्ट जीत हैं। दक्षिण अफ्रीका के ग्रीम स्मिथ (53 टेस्ट जीत) इस मामले में शीर्ष पर हैं। ऑस्ट्रेलिया के रिकी पोंटिंग 48, स्टीव वॉ 41 और वेस्टइंडीज के कप्तान क्लाइव लॉयड 36 टेस्ट जीत चुके हैं

मैच के दौरान शॉट खेलते मुश्फिकुर रहीम। प्रेट्र

भारत-बांग्लादेश सीरीज में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन

बल्लेबाज	देश	मैच	पारी	रन	उच्चतम	औसत	100	50
मयंक अग्रवाल	भारत	02	02	257	243	128.50	01	00
मुश्फिकुर रहीम	बांग्लादेश	02	04	181	74	45.25	00	02
अजिंक्य रहाणे	भारत	02	02	137	86	68.50	00	02
विराट कोहली	भारत	02	02	136	136	68.00	01	00
चेतेश्वर पुजारा	भारत	02	02	109	55	54.50	00	02

गेंदबाज	देश	मैच	पारी	ओवर	विकेट	पारी में सर्वश्रेष्ठ	मैच में सर्वश्रेष्ठ	औसत	5 विकेट
इशांत शर्मा	भारत	2	4	48	12	5/22	9/78	10.75	1
उमेश यादव	भारत	2	4	49.4	12	5/53	8/82	15.00	01
मुहम्मद शमी	भारत	2	4	47.3	9	4/31	7/58	15.11	00
अबू जाएद	बांग्लादेश	2	2	46.0	6	4/108	4/108	30.83	00
आर अश्विन	भारत	2	3	35.2	5	3/42	5/85	20.80	00

धौनी से आगे निकले विराट

कोलकाता : भारत ने इसके साथ ही विराट की कप्तानी में लगातार सातवां टेस्ट जीता। यह लगातार सबसे अधिक मैच जीतने का भारतीय रिकॉर्ड है। इससे पहले भारत ने महेंद्र सिंह धौनी की कप्तानी में 2013 में लगातार छह टेस्ट मैच जीते थे। विराट पारी के अंतर से सबसे अधिक टेस्ट मैच जीतने वाले भारतीय कप्तान हैं। उनकी कप्तानी में भारत ने अब तक 11 मैच पारी के अंतर से जीते हैं, जबकि धौनी की कप्तानी में भारत ने नौ मैचों में पारी के अंतर से जीत हासिल की थी। अजहर की कप्तानी में आठ बार और गांगुली की कप्तानी में सात बार टीम इंडिया ने यह कारनामा किया था।

10 देश भारत, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, वेस्टइंडीज, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, श्रीलंका, जिंबाब्वे डे-नाइट टेस्ट खेल चुके हैं। जिंबाब्वे का टेस्ट दर्जा फिलहाल आइसीसी ने छीन लिया है

05 लगातार टेस्ट सीरीज (घर-बाहर मिलाकर) भारत ने जीती हैं

12 डे-नाइट टेस्ट मैच खेले गए हैं अभी तक। इसमें से 10 मैच मेजबान टीमों ने जीते हैं। 2017 में दुबई में पाकिस्तान अपनी घरेलू सीरीज में श्रीलंका से और 2018 में ब्रिजटाउन में वेस्टइंडीज की टीम श्रीलंका से हारी थी

ईडन गार्डेंस स्टेडियम में विजेता ट्रॉफी के साथ भारतीय टीम के सदस्य • ट्विटर

स्पोर्ट्स कंपनी के साथ जुड़े फेडरर

न्यूयॉर्क टाइम्स से

वाशिंगटन : 20 बार के ग्रैंडस्लैम चैंपियन स्विट्जरलैंड के टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर एक नामी स्पोर्ट्स कंपनी 'ओन' के साथ जुड़ गए हैं। 38 साल के फेडरर ने न्यूयॉर्क टाइम्स के माध्यम से इसकी घोषणा की और कहा कि वह अब एक निवेशक, डिजाइनर और लोगों के लिए इस कंपनी के नए चेहरे होंगे।

स्विट्जरलैंड की इस कंपनी को तीन दोस्तों ने मिलकर तैयार की है जिन्होंने साल 2010 में इस कंपनी को लांच किया था। इस कंपनी ने कई एथलीटों को अपने साथ जोड़ा हुआ है और उस सूची में फेडरर भी शामिल हो गए हैं। फेडरर ने ओन कंपनी के जूतों के साथ तस्वीरें इंस्टाग्राम पर साझा की। फेडरर ने कहा, 'इस कंपनी के जूतों को नजरअंदाज का करना आसान नहीं है क्योंकि हर कोई जैसे लोग, मेरे दोस्त और मेरी पत्नी इनका इस्तेमाल करती हैं।' फेडरर ने अपने अभ्यास सत्र के दौरान इन जूतों को पहना और कंपनी के करार से पहले ही वह जयूरिख में कंपनी के कार्यालय में जाकर जूतों के डिजाइन पर अपनी सलाह भी दी। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी खबर के अनुसार, फेडरर द्वारा बताए गए जूतों के डिजाइन अगले साल के लिए रखे गए हैं। इसके अलावा वह अन्य जिम्मेदारियों के अलावा सार्वजनिक रूप से कंपनी का प्रतिनिधित्व करेंगे। फेडरर फेशन की दुनिया में अजनबी हैं। फेडरर ने इस महीने लंदन में कहा था कि उनके पास अलग-अलग तरह के 250 जूतें हैं।

यासिर ने स्मिथ को आउट कर किया इशारा

ब्रिसबेन: ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के पहले टेस्ट मैच में केवल चार रन बनाकर आउट हो गए। गाबा में इस टेस्ट मैच में चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे स्मिथ को पहली पारी में यासिर शाह ने बोल्ड किया और वह 10 गेंदों पर एक ही चौका लगा पाए।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी के बाद स्मिथ शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं, लेकिन इस टेस्ट की पहली पारी में वह कुछ खास नहीं कर सके। लेग स्पिनर यासिर ने जब उन्हें बोल्ड किया तो ड्रेसिंग रूम की तरफ सात का इशारा किया। ऐसा इसलिए क्योंकि 33 वर्षीय शाह ने टेस्ट क्रिकेट में स्मिथ को सातवीं बार आउट किया।

'दादा परंपरा' पर विराट और गावस्कर हुए आमने-सामने

अभिषेक त्रिपाठी • कोलकाता

इसमें कोई शक नहीं कि इस समय भारतीय टेस्ट टीम शानदार प्रदर्शन कर रही है और उसने इस साल ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में पहली बार टेस्ट सीरीज में मात दी थी। घर में तो हमेशा ही भारत का प्रदर्शन शानदार रहा है, लेकिन टीम इंडिया के इतिहास को पेश करने में भारतीय कप्तान विराट कोहली और पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर आमने-सामने आ गए।

गुलाबी टेस्ट में बांग्लादेश को हराने के बाद पुरस्कार वितरण समारोह में कोहली ने कहा कि यह परंपरा दादा (सौरव गांगुली) ने शुरू की थी, जिसे हम आगे बढ़ा रहे हैं। दरअसल, संजय मांजरेकर ने विराट से यहां भारतीय तेज गेंदबाजों द्वारा करारे बाउंसर्स को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारा एक मंत्र है कि हमें खुद को मैदान में स्थापित करना है। हम सभी जानते हैं कि टेस्ट क्रिकेट मानसिक लड़ाई है। मेरा मतलब है कि पहले कोई भी बल्लेबाजों को चोटिल करना नहीं चाहता था। यह सिर्फ इतना ही होता था कि हम बल्लेबाजों के जेहन में घुस जाएं और उन्हें आउट करें और ऐसा ही हुआ, लेकिन अब हमने खड़ा होना सीख लिया है। यह सब कुछ दादा (सौरव गांगुली) के जमाने में शुरू हुआ था, जिसे हम अब आगे बढ़ा रहे हैं। अब हमारा गेंदबाजी आक्रमण बेखौफ है और उन्हें अपने ऊपर भरपूर विश्वास है। वह किसी भी बल्लेबाज के सामने खेलने को तैयार हैं। हमने बीते तीन से चार साल में जो भी मेहनत की है अब हम उसका फल काट रहे हैं। जब एक टीम तैयार हो रही होती है, तब बहुत कुछ कहने की जरूरत होती है। अब हमारे खिलाड़ी जानते हैं कि उन्हें क्या करना है। इस सम्मान समारोह से 30 गज दूर खड़े सुनील गावस्कर इसको सुन रहे थे। सम्मान समारोह के बाद जब गावस्कर से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि दादा इस समय बीसीसीआइ अध्यक्ष हैं तो मैं समझ सकता हूं कि उनकी तारीफ की ही जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि यह सब 2000 (गांगुली बांग्लादेश के खिलाफ कप्तान बने) के बाद शुरू हुआ। 1970-71 में भारतीय टीम वेस्टइंडीज जाकर वहां पांच मैचों की सीरीज में 1-0 से जीतकर आई थी। 1971 में इंग्लैंड को उसके घर में तीन मैचों की सीरीज में 1-0 से हराया था। 1975-76 में न्यूजीलैंड में जाकर 1-1 से ड्रॉ खेला था। विराट को शायद यह पता नहीं होगा। विराट उस समय पैदा भी नहीं हुए थे। 1980-81 में ऑस्ट्रेलिया में तीन मैचों की सीरीज 1-1 से ड्रॉ खेली। 1986 में इंग्लैंड को उसके घर में तीन मैचों की सीरीज में 2-0 से हराया। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ 2000 के बाद ही शुरू हुआ। पिछली सदी के आठवें और नौवें दशक में भी भारतीय टीम ने आक्रामता के साथ अच्छा खेल दिखाया था।

मतभेद

- विराट ने कहा कि दादा ने शुरू की थी आक्रामकता की परंपरा
- गावस्कर बोले, पिछली सदी में जब हम जीते तो विराट पैदा नहीं हुए थे

सुनील गावस्कर • फाइल फोटो, प्रेट्र

कोलकाता के ईडन गार्डेंस स्टेडियम में दिग्गजों के बीच सम्मानित होकर बहुत गर्व महसूस कर रही हूं।
– मिताली राज, कप्तान भारतीय महिला क्रिकेट टीम

पीबीएल के पांचवें सत्र में नहीं खेलेंगी साइना

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारत की स्टार शटलर साइना नेहवाल ने अगले अंतरराष्ट्रीय सत्र के लिए खुद को तैयार करने के लिए रविवार को आगामी प्रीमियर बैडमिंटन लीग (पीबीएल) से हटने का फैसला किया। पिछले पीबीएल सत्र में नॉर्थ ईस्टर्न वॉरियर्स के लिए खेलने वालीं 29 साल की साइना 20 जनवरी से 9 फरवरी के बीच खेले जाने वाले पांचवें चरण में खेलती हुई दिखाई नहीं देंगी।

चेल्सी को हराकर सिटी खिताबी दौड़ में बरकरार

गोल करने के बाद जश्न मनाते सिटी के खिलाड़ी रियाद महारेज। एएफपी

लंदन, एएफपी : गत चैंपियन मैनचेस्टर सिटी ने इंग्लिश प्रीमियर लीग (ईपीएल) में चेल्सी को 2-1 से हराकर मौजूदा सत्र में शीर्ष पर चल रहे लिवरपूल फुटबॉल क्लब के साथ खिताबी दौड़ में खुद को बरकरार रखा।

एतिहाद में शनिवार को खेले गए मुकाबले में चेल्सी ने एंगोलो कांटे (21वें मिनट) के गोल से शुरुआती बढ़त हासिल की, लेकिन जल्दी ही सिटी ने मुकाबले में वापसी की। पहले केविन डि ब्रूने (29वें मिनट) ने सिटी को बराबरी दिलाई और फिर रियाद महारेज (37वें मिनट) ने बॉक्स के अंदर से शानदार गोल करके सिटी को बढ़त दिलाई, जो अंत में निर्णायक साबित हुई।

अगर इंजुरी टाइम में रहीम स्टर्लिंग द्वारा किए गए गोल को वीडियो असिस्टेंट रेफरी (वार) की मदद से अयोग्य करार नहीं दिया गया होता तो मैनेजर पेप गॉर्डियोला की टीम की जीत का अंतर बड़ा हो सकता था। इस मुकाबले में सिटी ने 46.74 प्रतिशत गेंद पर कब्जा जमाया, लेकिन इस मामले में यह गॉर्डियोला के मैनेजर करियर के कुल 381 मुकाबलों में सबसे कम रहा।

उधर, लिवरपूल ने क्रिस्टल पैलेस को 2-1 से हराकर अपने शीर्ष क्रम को और मजबूत किया। वहीं, शनिवार को टॉटनहम के मैनेजर के तौर पर पहली बार उतरे जोस मौरिन्हो के मार्गदर्शन में उनकी टीम ने वेस्टहम को 3-2 से हराया। साथ ही लीसेस्टर सिटी ने ब्रिज्टन को 2-0 से शिकस्त देकर तालिका में दूसरा स्थान हासिल किया। अंक तालिका में लिवरपूल 37 अंकों के साथ पहले और लीसेस्टर 29 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। वहीं, चेल्सी को हराने के बाद सिटी 28 अंकों के साथ तीसरे पायदान पर पहुंच गई।

फुटबॉल डायरी

- ईपीएल में सिटी ने चेल्सी को 2-1 से हराया
- तालिका में शीर्ष पर काबिज लिवरपूल भी जीता

फ्लामेंगो ने जीता खिताब

लिमा, रायटर : ब्राजील के क्लब फ्लामेंगो ने गत चैंपियन रीवर प्लेट को 2-1 से हराकर पिछले 38 वर्षों में पहली बार कोपा लिबर्टाडोरेस का खिताब जीता। फ्लामेंगो की ओर से दोनों गोल गेब्रियल बारबोसा ने किए, जिन्हें मुकाबले के अंतिम लम्हों में रेड कार्ड दिखाया गया। शनिवार को फाइनल मुकाबले में खेल के 14वें मिनट में ही राफेल बोरे ने रीवर प्लेट को शुरुआती बढ़त दिलाई, लेकिन निर्धारित समय से एक मिनट पहले और इंजुरी टाइम में बारबोसा ने गोल करके फ्लामेंगो को खिताबी जीत दिलाई।

रामोस की गलती के बाद रीयल की शानदार वापसी

मैड्रिड, रायटर : स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में रीयल मैड्रिड ने अपने स्टार खिलाड़ी सर्जियो रामोस की गलती के बाद शानदार वापसी करते हुए रीयल सोसिएदाद को 3-1 से हरा दिया। इस जीत के साथ रीयल अंक तालिका में शीर्ष पर काबिज बार्सिलोना के 28 अंकों की की बराबरी कर ली। हालांकि गोल अंतर की वजह से बार्सिलोना शीर्ष पर है।

मुकाबले के दूसरे ही मिनट में रामोस द्वारा गलत बैक पास पर विलियन जोस ने गोल करके सोसिएदाद को बढ़त दिलाई। हालांकि, करीम बेंजमा (37वें मिनट), फेडरिको वाल्वर्डे (47वें मिनट) और लुका मॉड्रिक (74वें मिनट) ने गोल करके रीयल को जीत दिलाई। इस मुकाबले में स्थानापन्न के तौर पर उतरे गेरेथ बेल का स्वागत समर्थकों ने बैनर के साथ किया जिस पर लिखा था, वेल्स, गोल्फ, मैड्रिड। इससे पहले शनिवार को बार्सिलोना ने लेगानेस को 2-1 से हराया।

भारत की महिला एवं पुरुष टीमें ओलंपिक में पूल-ए में शामिल

नई दिल्ली, आइएएनएस : जापान की राजधानी टोक्यो में अगले साल होने वाले ओलंपिक गेम्स के लिए भारत की पुरुष और महिला हॉकी टीमों को पूल-ए में शामिल किया गया है। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ (एफआइएच) ने इसकी जानकारी दी।

पूल-ए में भारतीय महिला हॉकी टीम के अलावा मौजूदा चैंपियन ग्रेट ब्रिटेन और दुनिया की नंबर एक टीम नीदरलैंड्स को भी रखा गया है। इसके अलावा पूल-ए में जर्मनी, आयरलैंड और दक्षिण अफ्रीका भी शामिल हैं। महिला टीम के अलावा भारतीय पुरुष टीम को भी पूल-ए में ही रखा गया है। दुनिया की पांचवें नंबर की भारतीय पुरुष हॉकी टीम के साथ इस ग्रुप में अर्जेंटीना और दुनिया की नंबर एक टीम ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा स्पेन, न्यूजीलैंड और मेजबान जापान की टीमें भी इसी पूल में है।

संगीता फौगाट संग सात फेरे लेंगे पहलवान बजरंग पूनिया

जागरण संवाददाता, सोनीपत

पहलवान बजरंग पूनिया और महावीर फौगाट की बेटी संगीता फौगाट का रिश्ता तय हो गया है। सोनीपत के मॉडल टाउन स्थित बजरंग के घर पर पारंपरिक रीति-रिवाज से टीका (रोका) की रस्में निभाई गईं। परिजनों ने बताया कि टोक्यो ओलंपिक के बाद दोनों शादी के बंधन में बंधेंगे। संगीता फौगाट 'दंगल' के रीयल हीरो महावीर फौगाट की बेटी और स्टार महिला पहलवान गीता-बबीता की छोटी बहन हैं। रविवार को दोनों का रिश्ता एक रुपये से हुआ और शादी भी बिना दहेज के होगी। बजरंग के पिता बलवान सिंह ने कहा कि टोक्यो ओलंपिक के बाद ही शादी की जाएगी, क्योंकि वह बजरंग से देश के लिए मेडल चाहते हैं।

पहलवान बजरंग पूनिया और संगीता फौगाट में काफी समय से दोस्ती है। इस कारण दोनों के परिवार के लोगों ने उनकी शादी करने का फैसला लिया। टीका रस्म के कार्यक्रम में जहां बजरंग के परिवार के लोग मौजूद रहे वहीं रिश्ता लेकर संगीता फौगाट के पिता महावीर फौगाट, उनकी मां, बहनें गीता फौगाट और रितु, छोटा भाई दुष्यंत, चचेरा भाई हरेंद्र, चाचा और रिश्तेदार आए थे। बजरंग ने टीका रस्म के समय पैंट और टी-शर्ट पहने हुए थे। टीके के बाद महावीर फौगाट, उनकी पत्नी और बजरंग के माता-पिता, भाई-भाभी व उनके विदेशी कोच ने भी आशीर्वाद दिया। वहीं, गीता फौगाट और उनके पति पवन ने भी बजरंग को आशीर्वाद दिया। गीता ने भी शुगन के तौर पर बजरंग को रुपये दिए। पूनिया परिवार के करीबी रामकरण धनखड़, दीवान व अन्य लोग मौजूद रहे।

बबीता की शादी की तैयारी में भी जुटा फौगाट परिवार

संगीता की बड़ी बहन और 'दंगल गर्ल' बबीता फौगाट की एक दिसंबर को शादी होनी है, इसलिए संगीता का पूरा परिवार बबीता की शादी की तैयारियों में जुटा है। बजरंग पूनिया के भाई हरेंद्र ने बताया कि टीके का कार्यक्रम अचानक रख दिया गया था। वहीं महावीर फौगाट का कहना है कि एक पहलवान को दूसरा पहलवान ही अच्छी तरह से समझ सकता है। वो चाहते है कि उनकी चौथी बेटी रितु भी अपने लिए जीवन साथी के रूप में पहलवान का ही चयन करे। उनकी बड़ी बेटी गीता की पहलवान पवन से शादी हुई है और 1 दिसंबर को बबीता भी पहलवान विवेक से शादी कर रही हैं। महावीर का बेटा दुष्यंत भी पहलवान है, उन्होंने हाल में स्कूली खेलों में मेडल जीता है। महावीर का कहना है कि बेटे द्वारा महिला पहलवान चुने जाने पर भी उन्हें कोई हर्ज नहीं होगा।

वाटलिंग के दोहरे शतक से इंग्लैंड मुश्किल में

टेस्ट सीरीज ▶ मेजबान टीम ने नौ विकेट पर 615 रन बनाकर की पारी घोषित

कीवी विकेटकीपर बल्लेबाज बीजे ने खेली 205 रनों की पारी

माउंट माउंगानुई (न्यूजीलैंड), एएफपी : बीजे वाटलिंग के शानदार दोहरे शतक के बाद मिशेल सेंटनर के तीन विकेट की बदौलत न्यूजीलैंड ने पहले टेस्ट में रविवार को यहां चौथे दिन इंग्लैंड को तीन विकेट पर 55 रन बनाकर मुश्किल में डाल दिया। न्यूजीलैंड ने पहली पारी नौ विकेट पर 615 रन पर घोषित की थी। अगर इंग्लैंड को अंतिम दिन न्यूजीलैंड को फिर से बल्लेबाजी के लिए उतारना है तो उसे 207 रन बनाने होंगे।

इंग्लैंड के लिए चौथे दिन स्टंप से पहले के दो घंटे का समय काफी मुश्किल रहा, जिसमें उसने दोनों सलामी बल्लेबाज डॉम सिबले (12) और रोरी बर्न्स (31) के विकेट गंवा दिए। इसके बाद नाइट वॉचमैन जैक लीच (00) भी दिन की अंतिम गेंद पर पवेलियन लौट गए। तीनों विकेट सेंटनर के नाम रहे। सेंटनर के लिए यह दिन यादगार रहा, जिसमें उन्होंने पहले वाटलिंग के साथ रिकॉर्ड साझेदारी निभाने के अलावा अपना पहला टेस्ट शतक जड़ा और फिर तीन विकेट हासिल किए।

इंग्लैंड की टीम का पलड़ा तब भारी था जब न्यूजीलैंड की टीम पहली पारी में 197 रन पर पांच विकेट गंवा चुकी थी और उसके शीर्ष खिलाड़ी आउट हो चुके थे, जिसमें करिश्माई केन विलियमसन भी शामिल थे। लेकिन, वाटलिंग ने पहले कोलिन डि ग्रैंडहोम (65) के साथ 116 रन की साझेदारी निभाई और फिर सेंटनर के साथ रिकॉर्ड बुक में नाम लिखवाकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। वाटलिंग और सेंटनर दोनों ने टेस्ट में अपना सर्वश्रेष्ठ स्कोर खड़ा किया। वाटलिंग ने 205 रन बनाकर 2015 में श्रीलंका के खिलाफ नाबाद 142 रन की पिछली सर्वश्रेष्ठ पारी को पीछे छोड़ा। सेंटनर ने भी 126 रन बनाकर 2017 में बांग्लादेश के खिलाफ 73 रन के सर्वश्रेष्ठ स्कोर से बेहतर प्रदर्शन किया। इन दोनों ने सातवें विकेट के लिए 261 रन की रिकॉर्ड साझेदारी की।

यह न्यूजीलैंड के लिए पिछले 225 रन के रिकॉर्ड से बेहतर थी जो 2004 में क्रिस केर्न्स और जैकब ओरम के बीच दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ईडन पार्क में बनी थी। जोफ्रा आर्चर के वाटलिंग का विकेट झटकने के बाद न्यूजीलैंड ने नौ विकेट पर 615 रन के स्कोर पर पारी घोषित कर दी। यह इंग्लैंड के खिलाफ उसका सबसे बड़ा स्कोर भी है, इससे पहले 1973 में लार्ड्स पर नौ विकेट पर 551 रन पर पारी घोषित करना उसका सर्वश्रेष्ठ स्कोर था। वाटलिंग ने अपने दोहरे शतक के लिए 473 गेंद का सामना करते हुए 24 चौके और एक छक्का जमाया। उन्होंने 11 से ज्यादा घंटे तक शानदार बल्लेबाजी की।

दोहरा शतक लगाने के बाद जश्न मनाते बीजे वाटलिंग। एएफपी

टेस्ट में दोहरा शतक लगाने वाले पहले कीवी विकेटकीपर बने वाटलिंग

न्यूजीलैंड के बीजे वाटलिंग रविवार को इस टीम के पहले विकेटकीपर बने जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक जड़ा। 34 वर्षीय वाटलिंग ने 205 रन की शानदार पारी खेली। न्यूजीलैंड क्रिकेट (ब्लैककैप्स) ने ट्विटर पर इस उपलब्धि का जिक्र किया। वाटलिंग इसके साथ ही टेस्ट क्रिकेट में न्यूजीलैंड की ओर से सर्वश्रेष्ठ स्कोर करने वाले विकेटकीपर भी बन गए।

गिल चूके, चेतन ने जीता आइएनआरसी का चौथा दौर

बेंगलुरू, आइएएनएस : टीम एमआरएफ के चेतन शिवराम और बिक्कू बाबू ने अधिकांश दिग्गजों के पुल आउट का फायदा उठाते हुए रविवार को यहां आयोजित याच क्लब एफएमएससीआइ इंडियन नेशनल रैली चैंपियनशिप का चौथा दौर अपने नाम कर लिया। इन दोनों चालकों ने अपने सह-चालकों के साथ रेड्स टीम के लिए पहला और दूसरा स्थान हासिल किया। पांचवें और चौथे स्थान से शुरुआत करते हुए चेतन और बिक्कू ने अपनी गाड़ी को तमाम मुश्किलों से बचाए रखते हुए के-1000 रैली में पहला और दूसरा स्थान हासिल किया।

गत चैंपियन और ओवरनाइट लीडर गौरव गिल उन बड़े चालकों में शामिल हैं, जो रेस से हटने पर मजबूर हुए। पहले दिन की मुश्किलों को झेलने के बाद गौरव की कार दूसरे दिन स्टार्ट भी नहीं हुई। इससे एमआरएफ के चालकों को आगे निकलने और खिताब पर कब्जा करने का मौका मिल गया। अक्षरा के चेतन शिवराम ने इसी अंदाज में राउंड-2 भी जीता था। वह इस जीत के साथ ओवरऑल आइएनआरसी चैंपियनशिप लीडर बन गए हैं। वह तथा उनके साथी चालक दिलीप शरण ने अपनी श्रेणी में (आइएनआरसी-3) में जीत हासिल की। इन दोनों ने 1.47.37.300 घंटे का ओवरऑल समय निकाला। चेतन और दिलीप का यह समय दूसरे स्थान पर आए।

विविध

गुजरात की फोरेंसिक टीम ने गाजियाबाद लैब में भेजे सैंपल

प्रवीण विक्रम सिंह, ग्रेटर नोएडा

होमगार्ड वेतन घोटाला

▶ गाजियाबाद लैब से सटीक रिपोर्ट नहीं मिलने पर गुजरात लैब भेजा जाएगा

फर्जी मस्टर रोल तैयार कर उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर में होमगार्डों के वेतन में करोड़ों के घपले के बाद कार्यालय में आग लगाने की घटना की जांच कर रही गुजरात की फोरेंसिक टीम ने सैंपल गाजियाबाद लैब भेजे हैं। यदि गाजियाबाद लैब से सैंपल की सटीक रिपोर्ट नहीं मिल पाएगी तब इन्हें जांच के लिए गुजरात लैब भेजा जाएगा। इसके अलावा फोरेंसिक टीम ने आग लगने वाले जिला कमांडेंट होमगार्ड कार्यालय के घटनास्थल का मैप तैयार किया है। इससे यह पता लगाने का प्रयास किया गया है कि आग लगाने वाला अंदर कब और कैसे घुसा। आग पेट्रोल डालकर लगाई गई है या नहीं। सूत्रों ने दावा किया है कि गुजरात की फोरेंसिक टीम ने कई जले हुए मस्टर रोल को तकनीक का प्रयोग कर पढ़ लिया है। कार्यालय में हुए अग्निकांड की जांच कर रही फोरेंसिक टीम जल्द ही अपनी रिपोर्ट फैक्स के माध्यम से गौतमबुद्ध नगर पुलिस को सौंपेगी। वहीं रिमांड पर लिए गए घोटाले के आरोपितों से पुलिस की पूछताछ जारी है। आरोपितों ने पूछताछ में नाम तो बताए हैं, लेकिन फर्जी मुहर अभी तक बरामद नहीं करवाई है। पुलिस का दावा है कि बरामदगी का प्रयास किया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि एसएसपी वैभव कृष्ण से जुलाई में फर्जीवाड़ा कर होमगार्डों के ड्यूटी का फर्जी मस्टररोल तैयार कर भुगतान की शिकायत की गई थी। एसएसपी के निर्देश पर एसपी सिटी विनीत जायसवाल ने प्राथमिक जांच की थी। केवल मई व जून में शहर की सात कोतवाली की हुई जांच में ही बड़े स्तर पर ड्यूटी के मस्टररोल में गड़बड़ियां मिली थीं। प्रारंभिक जांच में ही फर्जी भुगतान पकड़ा गया था। फर्जी मस्टररोल तैयार कर हुए भुगतान में करीब 50 फीसद से अधिक फर्जी ड्यूटी पकड़ी गई थी, जबकि कोतवाली में काम करने वाले होमगार्ड के फर्जी मस्टर रोल बनाने में फर्जी मुहरों का इस्तेमाल किया गया था।

आरोपितों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य एकत्र होने के बाद बीते दिनों पुलिस ने तत्कालीन जिला कमांडेंट (अब मंडलीय कमांडेंट अलीगढ़) रामनारायण चौरसिया, सहायक जिला कमांडेंट सतीश चंद और अवैतनिक प्लाटून कमांडर सत्यवीर यादव, शैलेंद्र कुमार व मोंटू कुमार को गिरफ्तार किया था। घोटाले के दौरान वर्ष 2017 से 2019 तक राम नारायण जिले में तैनात था। आरोपितों की गिरफ्तारी से कुछ घंटे पहले ही गौतमबुद्ध नगर जिला कमांडेंट कार्यालय में आग लगा दी गई थी। एसआइटी की अब तक की जांच में पता चला है कि आग साजिशन लगाई गई है।

दरभंगा में ही बनेगा एम्स, हवाई अड्डे की भी औपचारिकताएं पूरी : नड्डा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि एम्स दरभंगा में ही बनेगा। इसके लिए उन्होंने पिछले माह पटना के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात की है। उन्होंने कहा कि मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए मैंने दरभंगा में एम्स दिया था और यह वहीं बनेगा।

नई दिल्ली में आंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र में अखिल भारतीय मिथिला संघ के तहत आयोजित मिथिला विभूति स्मृति पर्व समारोह-2019 को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वहां एम्स के साथ ही हवाई अड्डे का कार्य तीव्र गति पर है। उसकी सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं। उन्होंने नई दिल्ली से सहरसा और नई दिल्ली से जयनगर तक दुरंतो रेल को सभी दिन चलाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि इसके लिए वह रेल मंत्री पीयूष गोयल से जल्द मिलेंगे।

नड्डा ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक सबके विचार और नेतृत्व में एक बात समान है कि वे सबको साथ लेकर, जोड़कर चलते हैं। अटल जी की सरकार ने मैथिली को भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने का कार्य किया। मोदी सरकार ने मखाना के लिए अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की बात कही। मिथिला क्षेत्रीय नहीं भारतीय भाषा है। यह भाषा भारत की संस्कृति को प्रदर्शित करती है। इसलिए इसको विकसित करना हमारी जिम्मेदारी है। भारतीय मिथिल संघ द्वारा विश्व मैथिली सम्मेलन करने के विचार से सहमति जताते हुए उन्होंने कहा कि इससे मानवता का भला होगा। उन्होंने कहा कि मिथिला की संस्कृति को अधिक से अधिक लोग जानें, इसके लिए प्रयास किए जाने चाहिए। मुझे इस बात की भी खुशी है कि मधुबनी पेंटिंग को अब वैश्विक स्तर पर पहचान मिल चुकी है।

इस मौके पर भाजपा नेता हुकुमदेव नारायण यादव ने कहा कि वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने पत्र लिखा था कि केवल बालीवुड या बड़े-बड़े लोगों को पद्मविभूषण या पद्मभूषण जैसे सम्मान नहीं मिलने चाहिए। गरीबों में भी क्षमता और प्रतिभा है। इसके बाद केंद्र सरकार ने अब वेबसाइट बना दी है, जिससे गांव-देहात और पिछड़े इलाकों में कार्य करने वाले लोगों को भी यह सम्मान मिलता है।

डॉ. भीमराव आंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र में आयोजित समारोह में हुकुमदेव नारायण यादव को सम्मानित करते भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा। साथ में दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी, राज्यसभा सदस्य प्रभात झा व अखिल भारतीय मिथिला संघ के अध्यक्ष विजय चंद्र झा। जागरण

मुगलई हलीम की तरह जायका देगी पहाड़ी मॉश की दाल

सूरजकुंड मेला

अनिल बेताब, फरीदाबाद

34वें सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय क्राफ्ट मेले में हिमाचल के फूडकोर्ट में आप हिमाचली व्यंजनों का जायका भी ले सकेंगे। यहां मुगलई हलीम की तरह आपको फूडकोर्ट में पहाड़ी मॉश की दाल का स्वाद मिलेगा। जिस तरह पौष्टिकता से परिपूर्ण दालें जैसे मूंग, चना, उड़द की दाल, चावल, गेहूं, जौ तथा मसाले मिलाकर मुगलई हलीम बनाया जाता है, वैसे ही मॉश दाल को मुगलई हलीम की तरह पकाया जाता है। हलीम की तरह मॉश दाल भी कई घंटे पकती रहती है। कई जगह रात भर पकती है। इस दाल में तली हुई अदरक, लहसुन, प्याज और मसाले मिलाए जाते हैं।

रविवार को हिमाचल पर्यटन विभाग के अधिकारी सूरजकुंड पहुंचे थे। इन्होंने हरियाणा पर्यटन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक भी की। इसमें हिमाचल के सांस्कृतिक केंद्रों के साथ फूडकोर्ट पर भी चर्चा की गई। अधिकारियों के अनुसार हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध खाद्य पदार्थ सिद (खसखस, मटन और मिठाई के साथ भरवां) का भी फूडकोर्ट में सेवन किया जा सकता है। साथ ही हिमाचल का तुदुकिभथ, जो हिमाचल का परंपरागत पुलाव का एक प्रकार है, भी यहां खाने को मिलेगा। दाल, प्याज, अदरक, आलू, लहसुन और दही के साथ ही इसमें इलायची, लाल मिर्च पाउडर तथा दालचीनी का मिश्रण मिलाया जाता है। आम तौर पर मॉश दाल के साथ ही इसे परोसा जाता है।

हरियाणा के अपना घर के पास ही बनेगा हिमाचल का घर

जासं, फरीदाबाद : सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय क्राफ्ट मेले में हिमाचल के सांस्कृतिक दर्शन कराने के लिए मेला परिसर में पांच अस्थायी द्वार बनाए जाएंगे। वर्ष 1996 से बने महेश्वर देवता मंदिर द्वार को नया रूप दिया जाएगा। हिमाचल की प्राकृतिक सुंदरता पर केंद्रित हुए मेले के मुख्य द्वारों के आसपास के क्षेत्रों को संवारा जाएगा। महेश्वर देवता मंदिर द्वार के सामने हिमाचल का एक मुख्य द्वार बनाया जाएगा। मुख्य चौपाल के पिछले हिस्से के इसी क्षेत्र में हिमाचल के शिल्पियों को हट्स दी जाएंगी। इस बात की जानकारी हिमाचल पर्यटन विभाग के अतिरिक्त निदेशक मनोज शर्मा, संयुक्त आयुक्त टीएस नेगी तथा सुदर्शन शर्मा ने सूरजकुंड मेला परिसर का दौरा करने के बाद दी। उन्होंने सूरजकुंड मेले के नोडल अधिकारी राजेश जून, धर्मवीर, होटल राजहंस के महाप्रबंधक हरविंद्र सिंह तथा जगदीश चंद्र के साथ बैठक भी की। राजेश जून ने उन्हें सूरजकुंड मेले की तैयारियों की जानकारी दी, तो साथ ही मुख्य चौपालों के बारे में भी बताया।

हिमाचल के कई व्यंजन विश्व प्रसिद्ध हैं। सूरजकुंड मेले में देश-विदेश के पर्यटन इन व्यंजनों का जायका ले सकेंगे। फूडकोर्ट में बनाए जाने वाले व्यंजनों की सूची उच्च अधिकारी ही फाइनल करेंगे।
– मनोज शर्मा, अतिरिक्त निदेशक, हिमाचल पर्यटन विभाग

जेल के बारे में धारणा बदलेगी 'ब्लैक वारंट'

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

▶ 35 वर्षों तक तिहाड़ जेल में अपनी सेवाएं दे चुके हैं इस पुस्तक के सह लेखक सुनील गुप्ता

कोई भी इंसान जेल जाना भले ही न चाहता हो, लेकिन उसके बारे में जानने की इच्छा कमोबेश सभी रखते हैं। आमतौर पर जेल के बारे में नकारात्मक छवि लोगों के मन में रहती है। 35 वर्षों तक तिहाड़ जेल में अपनी सेवाएं दे चुके सुनील गुप्ता बताते हैं कि जेल को समझने के उद्देश्य से ब्लैक वारंट पुस्तक में उन्होंने कई ऐसी बातों का जिक्र किया है जिनके बारे में लोग जानना पसंद करेंगे। सुनील इस पुस्तक के सह लेखक हैं।

सुनील बताते हैं कि 35 वर्षों के कार्यकाल में वह कई पदों पर रहे। सहायक अधीक्षक, लॉ आफिसर समेत कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे। काफी अनुभव अर्जित किए। इन अनुभवों को ही इस पुस्तक में लिखने की कोशिश की। आमतौर पर फांसी के बारे में लोगों को तमाम तरह की जिज्ञासा रहती है। उन्होंने अपने कार्यकाल में एक-दो नहीं, बल्कि आठ कैदियों को फांसी के फंदे पर झूलते देखा है। इनमें रंगा व बिल्ला, मकबूल भट्ट, करतार सिंह, उजागर सिंह, सतवंत सिंह, केहर सिंह व अफजल शामिल थे। फांसी से जुड़ा दृश्य उनकी आंखों के सामने कई कई दिनों तक घूमता रहता था। वहां की यादों से उबरने में कई-कई दिन लगते थे। जब वह घर जाते थे तो वह वह दृश्य उनका पीछा नहीं छोड़ता था। उन दृश्यों से पीछा छुड़ाने के लिए वह कभी टीवी देखते तो कभी गाना सुनते थे। सुनील बताते हैं कि इसके अलावा भी जेल से जुड़े कई प्रसंग हैं, जिनका जिक्र उन्होंने इस पुस्तक में किया है।

जनता पार्टी के गठन के बारे में वह पहले सोचते थे कि आखिर इसका गठन तिहाड़ जेल में कैसे हुआ होगा। तिहाड़ में नौकरी की शुरुआत के बाद उन्हें इस प्रश्न का उत्तर जानने की बड़ी इच्छा थी। धीरे-धीरे यहां काम करते-करते उन्हें इस प्रश्न का उत्तर मिलता गया। आपातकाल के समय तिहाड़ में देश के अधिकांश बड़े नेता इसलिए बंद किए गए थे, क्योंकि यहां सुरक्षा चाकचौबंद थी। देश में भले ही नेताओं को आपस में मिलने में तब दिक्कत होती थी, लेकिन जेल में सभी आपस में मिल सकते थे। एक-दूसरे से बातें कर सकते थे। सुनील गुप्ता बताते हैं कि इस पुस्तक में निर्भया कांड के आरोपितों के बारे में भी कई बातों का जिक्र है।

दहेज के लिए पत्नी को बेचा, गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, कटिहार

▶ किसी तरह भागकर मायके पहुंची पीड़िता, कोर्ट के आदेश पर हुआ मामला दर्ज

बिहार के कटिहार में एक महिला को दहेज की रकम के लिए पति व ससुराल वालों द्वारा कानपुर की देह मंडी में बेचने का मामला सामने आया है। पीड़िता किसी तरह भागकर संदलपुर स्थित मायके पहुंची। वहां शनिवार को पति व ससुराल वालों के विरुद्ध कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की।

जानकारी के अनुसार पीड़ित महिला की शादी सात वर्ष पूर्व बिहार के ही अररिया जिले के एक गांव में हुई थी। शादी में उसके पिता ने अपने सामर्थ्य के मुताबिक दहेज दिया था। शादी के तीन साल बाद तक पति व ससुराल वाले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करते रहे। प्रताड़ना से तंग आकर वह मायके लौट आई थी। इस संबंध में पंचायत होने के बाद पति व ससुर उसे लेकर ससुराल चले गए। उसने आरोप लगाया कि चार साल पहले पति व ससुराल वालों ने उसे नशे की दवा खिला दी। इसके बाद बेहोशी की हालत में उसे उत्तर प्रदेश के कानपुर में देह मंडी के दलालों को बेच दिया गया।

पीड़िता के पिता ने अपनी बेटी के ससुराल से रहस्यमय स्थिति में लापता होने को लेकर अपहरण की आशंका जताते हुए मामला दर्ज कराया था। चार वर्ष तक उसके जिस्म का सौदा होता रहा। किसी तरह वह भागकर अपने मायके पहुंची। इसके बाद पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने आरोपित पति को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। पुलिस की मौजूदगी में पीड़िता का बयान दर्ज कराया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

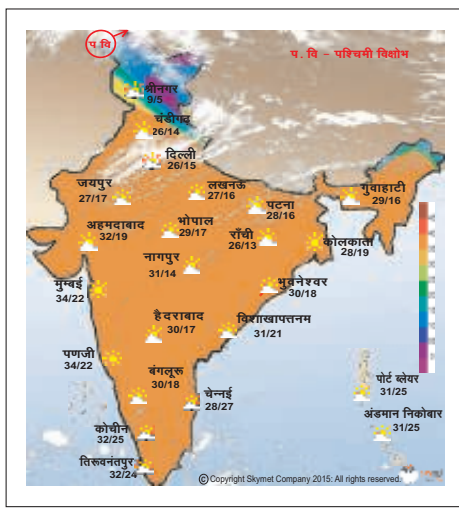

भारत के मुख्य शहरों का तापमान:

शहर		शहर	
मुम्बई	34/23/आंबा	अहमदाबाद	33/18/आंबा
कोलकाता	28/19/स्ता	बड़ोदा	33/19/स्ता
चेन्नई	31/25/व	नागपुर	31/15/व
हैदराबाद	30/17/स्ता	इन्दौर	29/18/स्ता
बंगलूरू	29/18/आंबा	राँची	29/19/व
त्रिवेन्द्रम	32/25/आंबा	पटना	32/21/स्ता
गुवाहाटी	27/18/आंबा	जमशेदपुर	30/20/व
गंगटोक	09/-3/आंबा	पुणे	30/19/आंबा

मौसम विशेष

जम्मू-कश्मीर व हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर वर्षा व बर्फबारी के आसार हैं। सुबह ठिठुरनभरी रहेगी। बादलों के साथ दिन शीतल और सुहावना रहेगा। दिल्ली सहित मैदानी भागों में कुछ स्थानों पर गरज के साथ बौछारें संभव है। सुबह में कुहासा रहेगा। घने बादल छाये रहेंगे।

कोरिंगा चक्रवात ने मचाई तबाही

1839 में आज ही बंगाल की खाड़ी में आया चक्रवात आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले के तटीय गांव कोरिंगा से टकराया था, इसलिए इसका नाम 'कोरिंगा' रख दिया गया। इस चक्रवात से समुद्र में उठी 40 फीट से ज्यादा ऊंची लहरों ने लगभग तीन लाख लोगों की जान ले ली थी।

अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का पेटेंट करवाया

1867 में आज ही स्वीडिश आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का पेटेंट करवाया था। नोबेल के नाम अलग-अलग 355 पेटेंट थे, जिसमें डानयनामाइट बहुत प्रसिद्ध है। अल्फ्रेड नोबेल ने ही 1895 में नोबेल पुरस्कार की स्थापना की थी।

अंतरराष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस मनाने की शुरुआत हुई

दुनिया भर में महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा को रोकने के लिए वर्ष 1999 से हर वर्ष 25 नवंबर को पूरे विश्व में अंतरराष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र संघ ने की थी। यह दिवस डोमिनिक तानाशाह राफेल ट्रूजिलो द्वारा सामाजिक कार्यकर्ता मीराबल बहनों की हत्या के विरोध में मनाया जाता है। 1960 में तीनों बहनों की हत्या कर दी गई थी।

संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा मानवाधिकार का उल्लंघन है और इसके पीछे की वजह महिलाओं के साथ भेदभाव है। 70 फीसद महिलाएं अपने संपूर्ण जीवन काल में कभी न कभी हिंसा का शिकार होती हैं।

इधर-उधर की

स्मार्टफोन से दूर रखने को निकाली अनोखी तरकीब

जकार्ता, एजेंसी : इंडोनेशिया में बांडुंग शहर के स्थानीय प्रशासन ने बच्चों को स्मार्टफोन और टीवी से दूर रखने के लिए पायलट प्रोग्राम शुरू किया है। इसके तहत बच्चों को मुर्गियों के बच्चे, सब्जी-फलों के पौधे और उनके बीज बांटे जा रहे हैं, ताकि बच्चे स्मार्टफोन छोड़कर उनकी देखभाल में व्यस्त रहें। स्थानीय प्रशासन ने बताया कि शहर 10 प्राथमिक स्कूल और दो जूनियर हाई स्कूल में 2000 चूजे और करीब 1500 मिर्च के पौधे उपलब्ध कराए हैं। इंडोनेशिया में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले लोग हर दिन आठ घंटे फोन पर बिताते हैं। जबकि वैश्विक औसत करीब दो घंटे का है। इतना ही नहीं आज के बच्चे भी इंटरनेट और स्मार्टफोन की लत का शिकार होते जा रहे हैं। इस पहल को लेकर अभिभावकों भी बहुत खुश हैं।

शोध अनुसंधान

डायबिटीज से बचाने में कारगर हो सकता है एवोकैडो

एवोकैडो के सेवन का एक बड़ा फायदा सामने आया है। शोधकर्ताओं का कहना है कि एवोकैडो का सेवन डायबिटीज की परेशानी से बचाने में कारगर है। एवोकैडो में एक तत्व होता है जो शरीर में डायबिटीज का कारण बनने वाली प्रक्रिया को रोकने में सक्षम है। इसकी अच्छी बात यह भी है कि यह तत्व किडनी, लिवर या मांसपेशियों को बिना नुकसान पहुंचाए खून में आसानी से अवशोषित हो जाता है। वैज्ञानिकों ने बताया कि जब कोशिकाओं का पावरहाउस कहा जाने वाला माइटोकांड्रिया फैटी एसिड्स को पूरी तरह जलाने में सक्षम नहीं रह जाता है, तब शरीर में इंसुलिन रजिस्टेंस पैदा हो जाती है। इससे खून में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे डायबिटीज कहा जाता है। एवोकैडो में पाया जाने वाला एक फैट मॉलीक्यूल इस प्रक्रिया को रोककर इंसुलिन रजिस्टेंस कम करता है। इससे व्यक्ति का वजन कम रखने में भी सहायता मिलती है। - एएनआइ

कम सोने वाले लोगों में हृदय रोग का खतरा अधिक

एक अध्ययन के अनुसार दावा किया गया है कि कम सोने वाले लोगों में हृदय रोग का खतरा ज्यादा होता है। कहा गया है कि यह स्थिति अधिकतर निम्न आर्थिक वर्ग वाले लोगों को होती है। स्वीट्जरलैंड के शोधकर्ताओं के अनुसार आर्थिक रूप से वंचित लोग कई कारणों से कम नींद लेते हैं। वे कई शिफ्ट में काम करते हैं, शोर भरे वातावरण में भी रहते हैं और उन पर आर्थिक तनाव ज्यादा होता है। 'कार्डियोवस्कुलर डिसीज' जर्नल में इस अध्ययन को प्रकाशित किया गया है। शोधकर्ताओं ने कहा कि समाज के हर स्तर पर संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता है। ताकि लोगों को अधिक नींद मिल सके। इसके साथ ही नींद में व्यवधान डालने वाले शोर से भी दूर रहने का प्रयास करना होगा। यह अध्ययन चार यूरोपीय देशों के 1,11,205 प्रतिभागियों के आठ समूहों पर किया गया है। शोधकर्ताओं ने बताया कि छह से 8.5 घंटे की नींद को सामान्य नींद कहा जाता है। छोटी नींद छह घंटे की होती है और लंबी नींद 8.5 की होती है। -प्रेट्र

सस्ते फ्यूल सेल के लिए बनाया नया उत्प्रेरक

मिली सफलता ▶ भारत, ब्रिटेन और चीन के वैज्ञानिकों ने मिलकर किया विकसित

जिरकोनियम से बनाया गया है उत्प्रेरक

नई दिल्ली, आइएसडब्ल्यू : फ्यूल सेल में उपयोग होने वाले महंगे प्लैटिनम कैटेलिस्ट (उत्प्रेरक) के किफायती और टिकाऊ विकल्प खोजने की वैज्ञानिकों की कोशिशों को एक नई सफलता मिली है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) मद्रास और ब्रिटेन तथा चीन के वैज्ञानिकों ने जिरकोनियम नाइट्राइड नैनोपार्टिकल्स विकसित किए हैं जो फ्यूल सेल में उपयोग होने वाले प्लैटिनम उत्प्रेरक का किफायती विकल्प हो सकता है।

फ्यूल सेल में उपयोग होने वाले प्लैटिनम उत्प्रेरक की लागत सेल के कुल मूल्य की करीब 20 प्रतिशत होती है। प्लैटिनम एक दुर्लभ धातु है जिसकी प्रति ग्राम कीमत करीब तीन हजार रुपये तक होती है। दूसरी ओर, पृथ्वी पर जिरकोनियम भरपूर मात्रा में मौजूद है और यह प्लैटिनम की तुलना में 700 गुना तक सस्ता भी है। शोधकर्ताओं का कहना है कि इन नैनोपार्टिकल्स का वास्तविक रूप में उपयोग किए जाने पर निकट भविष्य में बाजार में सस्ते और बेहतर फ्यूल सेल देखने को मिल सकते हैं।

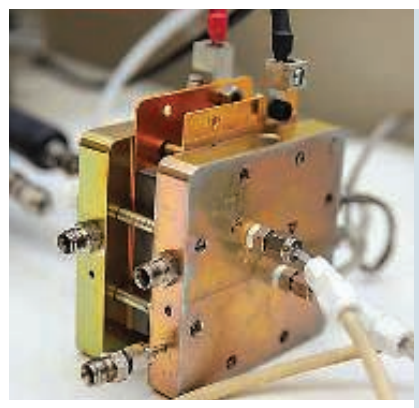
प्रतीकात्मक

आएंगे नए बदलाव

तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया में फ्यूल सेल और मेटल-एयर बैटरियां भविष्य में ऊर्जा के क्षेत्र में नए बदलावों को जन्म दे सकती हैं। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री और ऑफ-ग्रिड ऊर्जा उत्पादन में भी इनकी भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो सकती है। प्लैटिनम की उच्च लागत इन बैटरियों के उपयोग में अब तक सबसे बड़ी बाधा रही है। बेहतर क्षमता के किफायती और टिकाऊ उत्प्रेरक इस बाधा को दूर करने में मददगार हो सकते हैं।

आइआइटी मद्रास के शोधकर्ता तीजू थॉमस के अलावा इस अध्ययन में चीन के निनग्बो इंस्टीट्यूट ऑफ मैटेरियल्स टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग के याओ युआन, हैंग्जिआ सेन एवं समीरा अदीमी, शंघाई इंस्टीट्यूट ऑफ सिरेमिक्स के जियाचेंग वांग तथा रुग्आंग मा, ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग केजे पॉल एटफील्ड और चीन की यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज एकेडेमी ऑफ साइंसेज के वैज्ञानिक मिन्घुई यांग शामिल थे। यह अध्ययन शोध पत्रिका नेचर मैटेरियल्स में हाल में प्रकाशित किया गया है।

ऑक्सीजन रिडक्शन रिएक्शन (ओआरआर) फ्यूल सेल और मेटल-एयर बैटरियों में होने वाली एक प्रमुख रसायनिक अभिक्रिया है, जिसके उत्प्रेरक के रूप में प्लैटिनम का उपयोग होता है। प्लैटिनम आधारित सामग्री का उपयोग माइक्रो-इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स, कैंसर की दवाओं, ऑटोमोटिव कैटेलिटिक कन्वर्टर और इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी कन्वर्जन उपकरणों में भी होता है, लेकिन अत्यधिक महंगा, दुर्लभ और विषाक्तता के प्रति संवेदनशील होने के कारण प्लैटिनम का बड़े पैमाने पर उपयोग एक बड़ी बाधा है।

क्या होता है फ्यूल सेल: फ्यूल सेल एक ऐसा उपकरण है जो आणविक बंधों में संचित रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकता है। सामान्य तौर पर उपयोग होने वाले हाइड्रोजन फ्यूल सेल में हाइड्रोजन अणुओं को धनात्मक रूप से आवेशित हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन में विभाजित करने के लिए प्लैटिनम को उत्प्रेरक के रूप में उपयोग किया जाता है। जबकि इलेक्ट्रॉन प्रत्यक्ष विद्युत उत्पादन करने के लिए प्रवाहित होते हैं और धनात्मक हाइड्रोजन आयन ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऊर्जा के सबसे स्वच्छ रूपों में से एक के उत्पादन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आपूर्ति एक अन्य इलेक्ट्रोड के माध्यम से होती है। शोधकर्ताओं का कहना है कि जिरकोनियम नाइट्राइड प्लैटिनम आधारित कार्यों को तो कुशलता से पूरा करता ही है, बल्कि कई मायनों में इसे प्लैटिनम उत्प्रेरकों के मुकाबले अधिक बेहतर पाया गया है।

इस कारण अलग-अलग आकार की होती हैं पौधों की पत्तियां

प्रतीकात्मक

लंदन, प्रेट्र : विभिन्न प्रजातियों के पौधों की विभिन्न आकार की पत्तियां क्यों होती हैं? शोधकर्ताओं ने अब इसका पता लगाया है। अक्सर देखा जाता है कि पौधों की पत्तियां उनके हालातों के अनुरूप होती हैं। पत्तियां ही पौधे में भोजन पहुंचाती हैं इसलिए उनकी आकार भी विशेष महत्व रखता है।

शोधकर्ताओं ने बताया कि जीन परिवर्तन की एक बेहद साधारण प्रक्रिया होती है, जिसकी वजह से विभिन्न प्रजातियों में अलग-अलग आकार की पत्तियां पनपती हैं।

ब्रिटेन में जॉन इनेस सेंटर के शोधकर्ताओं ने जलीय मांसाहारी पादपों यूट्रिकुलेरिया गिब्बा या ब्लैडरवोर्टस का अध्ययन किया। इनकी पत्तियां कप के आकार की होती हैं और एक ढक्कन लगा होता है जो बंद होकर अंदर आए कीटों को बाहर जाने से रोकता है। शोधकर्ता जानना चाहते थे कि क्या वे विशेष वजहें हैं, जिनकी वजह से पौधे में एसी पत्तियां विकसित हुईं।

साइंस जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में बताया कि पत्ती की कोपल में जीन में बदलाव होने की वजह से पौधे उसे विभिन्न रूप दे पाने में सक्षम हो पाते हैं। इस अध्ययन के सह लेखक एनरिको कोएन ने बताया कि पादप मांसाहारी पौधों की पत्तियों की जटिल आकृति की शुरुआत सामान्य पत्ती की तरह ही होती है, फिर जीन में साधारण सा बदलाव होने पर वह एक विशेष आकृति ग्रहण कर लेती है। अपने अध्ययन में शोधकर्ताओं ने आणविक आनुवंशिक विश्लेषण का उपयोग किया। उन्होंने यह पता लगाया कि अगर कोपल में इस जीन के परिवर्तन को रोक दिया जाए तो पत्ती का आकार कुछ और ही हो जाता है। शोधकर्ताओं का कहना है कि यह खोज किसानों के लिए बेहद फायदेमंद हो सकती है। इसकी मदद से फसलों में जीन में मनमुताबिक हेरफेर करके ऐसी पत्तियां विकसित की जा सकतीं हैं जो ज्यादा से ज्यादा प्रकाश को ग्रहण कर सकें और प्रकाशसंश्लेषण से ज्यादा भोजन बनाएं। इसका परिणाम यह होगा कि फसलों में अनाज उत्पादन बेहतर हो जाएगा।

कान में पानी जाए तो सिर को मत झटकिये

न्यूयॉर्क, आइएएनएस : अक्सर यह देखा जाता है कान में पानी घुस जाने पर लोग उसको निकालने के सिर झटकते हैं, लेकिन यह हरकत जानलेवा भी हो सकती है। शोधकर्ताओं ने पाया है कि एसा करने से कान के कैनाल में फंसा पानी संक्रमण और यहां तक की ब्रेन डैमेज का भी कारण बन सकता है।

अमेरिका की कार्नेल यूनिवर्सिटी और वर्जीनिया टेक के शोधकर्ताओं ने बताया है कि छोटे बच्चों में सिर झटकना और भी ज्यादा हानिकारक हो सकता है। इससे ब्रेन डैमेज हो सकता है। भारतीय मूल के शोधकर्ता अनुज बसकोटा ने बताया कि 3डी प्रिटेंड कान की कैनाल के माध्यम से यह पता लगाया गया है कि कान में फंसे पानी को निकालने के लिए गुरुत्वाकर्षण बल से 10 गुना ज्यादा त्वरण की आवश्यकता होती है। इतना ज्यादा त्वरण बच्चों के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचा सकता है। साथ ही वयस्कों में कान के बड़े व्यास के कारण यह त्वरण कम है। शोधकर्ताओं ने यह भी बताया कि कैनाल में पानी की समग्र मात्रा और स्थिति इसे हटाने के लिए आवश्यक त्वरण को बदल भी सकती हैं।

यह तरीका हो सकता है कारगर: शोधकर्ताओं ने बताया कि एक समाधान है, जिसमें बिना सिर हिलाए कान में घुसे पानी को निकाला जा सकता है। कई प्रयोगों और सैद्धांतिक मॉडलों से पता चलता है कि पानी के पृष्ठतनाव की वजह से ही यह कान की कैनाल में फंस जाता है। इसलिए पानी की तुलना में कम पृष्ठ तनाव वाले लिक्विड जैसे- सिरका, अल्कोहल की कुछ बूंदे कान में डालने पर पानी निकल जाएगा। सिरका और अल्कोहल कान में पानी के पृष्ठ तनाव बल को कम कर देता है और इससे फंसा पानी निकल आता है।

▶ छोटे बच्चों में हो सकता ब्रेन डैमेज का खतरा

प्रतीकात्मक

शुगर-फ्री च्यूइंग गम से दांतों को फायदा

लंदन, प्रेट्र : शुगर-फ्री च्यूइंग गम चबाना दांतों में कैविटी की समस्या कम कर सकता है। किंग्स कॉलेज लंदन के शोधकर्ताओं ने पिछले 50 साल में हुए 12 अलग-अलग अध्ययन से मिले नतीजों के विश्लेषण के आधार पर यह निष्कर्ष दिया है। विज्ञान पत्रिका डेंटल रिसर्च के अनुसार, शुगर-फ्री च्यूइंग गम चबाने से दांतों के क्षय होने की गति धीमी हो जाती है। च्यूइंग गम चबाने की यह प्रक्रिया मुंह की सेहत से जुड़ी अन्य प्रक्रियाओं जैसे ब्रश करने आदि की तुलना में कैविटी के खिलाफ ज्यादा प्रभावी साबित हो सकती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि चबाने के दौरान मुंह की गतिविधि और इस दौरान बनने वाली लार दांतों की कैविटी के खिलाफ प्राकृतिक कवच की तरह काम करती है। इसके अलावा शुगर-फ्री च्यूइंग गम से जाइलीटोल और सोर्बिटोल जैसे एंटीबैक्टीरिया भी मुंह में पहुंचते हैं। इससे भी लाभ होता है। हालांकि, वैज्ञानिकों ने इन नतीजों को पुष्ट करने के लिए व्यापक शोध की जरूरत पर बल दिया है।

मलेशिया में सुमात्राई प्रजाति के अंतिम गैंडे की मौत

कुआलालंपुर, एपी : गैंडे में सबसे छोटे कद के सुमात्राई नस्ल का अब एक भी गैंडा मलेशिया में नहीं बचा है। शनिवार को बोर्नियो द्वीप स्थित मलेशिया के सबा प्रांत में ईमान नाम के अंतिम मादा गैंडे की मौत हो गई। 25 साल की ईमान कैंसर से पीड़ित थी। मलेशिया के अंतिम नर गैंडे की मौत छह महीने पहले ही हो चुकी है।

सबा प्रांत की उप मुख्यमंत्री व पर्यावरण मंत्री क्रिस्टिना ल्यू ने ईमान की मौत पर दुख जताते हुए कहा कि इस प्रजाति को विलुप्त होने से बचाने की कोशिश अभी भी जारी है। ईमान के अंडाणुओं को इसी प्रजाति के नर गैंडे के शुक्राणुओं के साथ कृत्रिम तरीके से निषेचन के लिए इंडोनेशिया भेजा जाएगा। दो सींग वाले सुमात्राई गैंडे एक समय भारत समेत पूरे एशिया में पाए जाते थे। विलुप्ती की कगार पर पहुंचे इस प्रजाति के अब कुछ ही गैंडे इंडोनेशिया में रह गए हैं। जंगलों के उजड़ने व अवैध शिकार के कारण गैंडों की संख्या तेजी से घटी है।

कार्बन नैनोट्यूब्स के उत्पादन में इस्तेमाल हो सकते हैं पुराने अखबार

ह्यूस्टन, प्रेट्र : पुराने अखबारों के जरिये सस्ते और बड़े पैमाने पर कॉर्बन नैनोट्यूब्स का उत्पादन किया जा सकता है। एक ताजा अध्ययन में यह बात सामने आई है। अध्ययनकर्ताओं ने बताया है कि पुराने अखबारों को कार्बन नैनोट्यूब्स बनाने के लिए पदार्थ के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह छोटे अणुओं के निर्माण का कम लागत और ईको-फ्रेंडली तरीका है। अध्ययनकर्ताओं में भारतीय मूल के वरुण शेनॉय गांगुली भी शामिल हैं।

अमेरिका की राइस यूनिवर्सिटी के वरुण शेनॉय गांगुली ने कहा कि कॉर्बन नैनोट्यूब्स अविश्वसनीय भौतिक संपत्ति है जो बड़ी संख्या में व्यावसायिक उत्पादों में काम में आता है। इनमें टचस्क्रीन डिस्प्ले में कंडक्टिव फिल्म्स, फ्लैक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स, ऊर्जा उत्पादन करने वाले फैब्रिक्स और 5जी नेटवर्क के एंटीना प्रमुख हैं। यह अध्ययन जर्नल ऑफ कॉर्बन रिसर्च में प्रकाशित हुआ है। इसमें पता चला है कि अखबार का लंबा पृष्ठ रासायनिक ढंग से कार्बन नैनोट्यूब के कृत्रिम निर्माण की आदर्श स्थिति उपलब्ध कराता है। हालांकि, अध्ययनकर्ताओं का कहना है कि सभी अखबार समान रूप से अच्छे नहीं होते हैं। वे ही अखबार अच्छे हैं जो कि चीनी मिट्टी या केओलिन के होते हैं यह आकार के परिणाम देते हैं और कार्बन नैनोट्यूब की वृद्धि करते हैं। गांगुली ने कहा कि कई चीजों जैसे पाउडर, कैल्शियम कार्बोनेट और टाइटेनियम डायोक्साइड पेपर की आकृति में काम आ सकते हैं, जो अपने स्तर पर अवशोषण और क्षय के स्तर को भरने में मदद करते हैं।

राइस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एंड्रयू बैरन ने कहा कि इस नई रिसर्च से हमने एक निरंतर प्रवाह प्रणाली को पाया है जो आश्चर्यजनक रूप से लागत कम करती है।

नमक की खदान में अस्थमा रोगियों को मिलता है लाभ

यह तस्वीर तुर्की के कंकरी शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर पांच हजार साल पुरानी नमक की खदान की है, जो जमीन से करीब 150 मीटर नीचे है। यह खदान हित्ती काल की बताई जाती है। कहते हैं कि इस खदान का वातावरण अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और फेफड़ों के रोगियों के लिए लाभदायक है। स्वास्थ्य लाभ के लिए यहां हजारों लोग आते हैं। खास बात यह है कि इस खदान से अभी भी नमक निकाला जाता है। इसमें पशुओं के शव भी मिले हैं, जो करीब 300 साल पुराने बताए जाते हैं। नमक निकालने में प्रयुक्त गाड़ी भी खदान में मिली है। एएफपी

स्क्रीन शॉट

कभी एडल्ट कॉमेडी नहीं बनाऊंगा : विपुल अमृतलाल शाह

सात सवाल

निर्माता-निर्देशक विपुल शाह ने अपने करियर का आगाज गुजराती थियेटर से किया था। बतौर निर्माता 'सिंह इज किंग', 'फोर्स' सीरीज, 'हॉलीडे : ए सोल्जर इज नेवर ऑफ ड्यूटी' जैसी फिल्में बना चुके विपुल अब 'कमांडो 3' लेकर आ रहे हैं। विद्युत जामवाल अभिनीत यह 'कमांडो' सीरीज की तीसरी फिल्म है। उसके अलावा वह पत्नी शेफाली शाह को लेकर वेब सीरीज बनाने की तैयारी में हैं। उनसे बातचीत :

हॉलीवुड के मुकाबले हमारी इंडस्ट्री में सीक्वल फिल्मों की शुरुआत में देरी हुई है?

- मैं इसे ऐसे देखता हूं कि अगर एक अच्छी फिल्म की कहानी में आगे बढ़ने की गुंजाइश होगी, तभी उसकी सीक्वल बन सकती हैं। 'कमांडो' ऐसी ही फिल्म थी। 'कमांडो 3' अगर दर्शकों को पसंद आएगी तो हम 'कमांडो 4' भी बनाएंगे।

आपके लिए सफलता का मंत्र क्या रहा है?

- जो कहानी मेरे दिल को छूती है, उसे पूरी ईमानदारी से बनाता हूं। फिल्मों को हिट कराने का फॉर्मूला किसी के पास नहीं है। हमारा काम ईमानदारी से पूरी कोशिश करना है। कभी सफलता मिलती है, कभी नहीं मिलती। दोनों का सम्मान करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। सफल होने पर घमंड नहीं करना चाहिए औ विफल होने पर डिप्रेस नहीं होना चाहिए। मेहनत करते रहना चाहिए। यही मैं फॉलो करता हूं।

विदेश में अपने सिनेमा को ले जाने के लिए किन खास चीजों का ध्यान रखना जरूरी है?

- हॉलीवुड का बजट हमारे पास नहीं होता है। भारतीय सिनेमा की स्ट्रेंथ इमोशन और कहानियां हैं। हमें उस पर ही जोर देना चाहिए और वैसी ही फिल्में बनानी चाहिए। भारतीय फिल्में पसंद करने वाले दर्शक बड़ी संख्या में पूरी दुनिया में हैं। हमारा बिजनेस विदेश में बढ़ रहा है। अपनी ताकत को लेकर आगे चलना चाहिए।

शेफाली शाह (पत्नी) को लेकर आपने वेब सीरीज या फिल्म नहीं बनानी चाही?

- मैं एक वेब सीरीज उन्हें केंद्रीय भूमिका में रखकर बना रहा हूं। उस पर काम चल रहा है। जब फिल्म में कोई ऐसा किरदार होता है तो मैं उनको ऑफर करता हूं। वह मेरी पत्नी हैं, इसलिए उनके पास कोई भी किरदार लेकर नहीं जाता। मैं उन्हें बतौर कलाकार वही इज्जत देता हूं, जो इंडस्ट्री देती है।

क्या शेफाली शाह कभी आपके प्रोजेक्ट्स करने से इन्कार भी करती हैं?

- हां, बिल्कुल करती हैं और करना भी चाहिए। उनकी अपनी इंडिपेंडेंट प्रतिभा और करियर है। उन्हें मेरे कहने पर कोई फिल्म नहीं करनी चाहिए। कलाकार के तौर पर जो उन्हें पसंद आए, वही करना चाहिए। इतनी आजादी हम एक-दूसरे को देते हैं और इज्जत करते हैं।

आजकल वेब और सिनेमा के लिए फिल्में बन रही हैं। टीवी के लिए ट्रेंड शुरू हुआ था, लेकिन बंद हो गया। वेब और सिनेमा के दर्शक अलग हैं... ?

- मैं मनाता हूं कि कहानी को वेब और सिनेमा के मुताबिक अलग नहीं करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि पूरा परिवार साथ बैठकर फिल्म देखे, तो उसका एक दायरा होता है। उसी दायरे में फिल्म बनानी होती है। फिल्म पारिवारिक मनोरंजन का जरिया है। चाहे वेब के लिए हो या थियेटर, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं पारिवारिक मनोरंजक फिल्में बनाऊं, जिसे पूरा परिवार एक साथ बैठकर देख सके। मैं कभी एडल्ट कॉमेडी फिल्में नहीं बनाऊंगा। मैं वैसी फिल्में न तो देखना पसंद करता हूं, न बनाना पसंद करता हूं।

गुजराती नाटकों और उपन्यासों पर आप भी काफी कुछ बनाते आए हैं। हमारे पास कहानियों का खजाना है, फिर भी रीमेक की ओर जा रहे हैं?

- हमारे पास बहुत सारा सांस्कृतिक खजाना है, जिसे लोगों ने छुआ नहीं है। दुर्भाग्य की बात है कि आज ज्यादातर लोग साहित्य नहीं पढ़ते। बहुत बड़ी कहानियां हैं, जो साहित्य में छुपी हुई हैं। अगर लोग पढ़ने की आदत डालें तो साहित्य की कहानियों से फिल्में बनेंगी।

स्मिता श्रीवास्तव

अपने सरनेम को करियर में बाधा मानते थे अनिल

अपने नाम के पीछे कपूर टाइटल भले ही नवोदित कलाकारों को किसी वरदान से कम नहीं लगता होगा, लेकिन अनिल कपूर इसे अपनी सफलता में बाधा मानते थे। अनिल के पिता प्रोड्यूसर सुरिंदर कपूर थे। वे दिग्गज अभिनेता पृथ्वीराज कपूर के दूर के रिश्तेदार थे। अनिल कपूर ने 1980 में तेलुगु फिल्म से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी। 1983 में अनिल को 'वो सात दिन' में मुख्य भूमिका का ऑफर मिला था। अनिल कहते हैं, 'जब मैंने करियर शुरू किया था, तब मुझे अपना सरनेम एक बाधा लगता था। तय किया कि वह करूंगा, जिसे किसी कपूर नहीं किया है। मैंने पहले गंभीर सिनेमा में जगह बनाई।'

पुरानी फिल्म से तुलना होना अच्छी बात : आशुतोष गोवारिकर

निर्देशक आशुतोष गोवारिकर की फिल्म 'पानीपत' की तुलना 'बाजीराव मस्तानी' से हो रही है। इस पर उनका कहना है कि संजय लीला भंसाली की फिल्म 'बाजीराव मस्तानी' काफी अच्छी फिल्म थी, इसलिए उससे 'पानीपत' की तुलना से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। 'पानीपत' की लड़ाई 1761 में मराठाओं और अफगानी सेना के बीच हुई थी। सदाशिव राव भाऊ मराठा सेना का नेतृत्व कर रहे थे। फिल्म में सदाशिव राव की भूमिका अर्जुन कपूर निभा रहे हैं, जबकि संजय दत्त अफगानी सेनापति अहमद शाह अब्दाली के किरदार में नजर आएंगे। आशुतोष कहते हैं, 'तुलना हमेशा होती है। जब मैं 'जोधा अकबर' बना रहा था, तब मेरी फिल्म की तुलना 'मुगल-ए-आजम' से हो रही थी। क्योंकि फिल्म मुगलकालीन थी और अकबर का किरदार था। जब 'बाजीराव मस्तानी' आई, तब इसकी तुलना 'जोधा अकबर' से की गई और जब 'पद्मावत' का ट्रेलर आया, तब 'बाहुबली' से इसकी तुलना की गई। पिछली फिल्मों से तुलना करना अच्छी बात है। मेरी फिल्म में सदाशिव राव भाऊ, बाजीराव से एक पीढ़ी आगे है। यह उससे 20 साल बाद की कहानी है।

अध्ययन

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के वैज्ञानिकों ने बताया कि सेटेलाइट के रियल टाइम डाटा से बाढ़ जैसी आपदा के दौरान प्रभावी रणनीति बनाई जा सकती है और लाखों लोगों को प्रभावित होने से बचाया जा सकता है

बाढ़ जैसी आपदा में बचाएंगे नासा के सेटेलाइट

ह्यूस्टन, प्रेट्र : अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने कहा है कि सेटेलाइट से रियल टाइम प्राप्त डाटा हमें कई तरह की प्राकृतिक आपदाओं में होने वाले नुकसान से बचा सकता है। इससे आपदा से बचने की समय से रणनीति बनाई जा सकती है और लाखों लोगों को प्रभावित होने से बचाया जा सकता है।

'इंवायरमेंटल साइंस' नामक शोध पत्रिका में प्रकाशित इस अध्ययन में आपदा की स्थिति में सेटेलाइट से रियल टाइम से मिले डाटा की अहमियत को बताया गया है।

नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर के शोधकर्ताओं ने दक्षिण-पूर्व एशिया में आई बाढ़ों का अध्ययन करते हुए बताया कि बाढ़ के बाद सबसे अहम बात एंबुलेंस और अन्य आपातकालीन सेवाओं के रिस्पांस टाइम की होती है। अगर से समय से काम करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा प्रभावित लोगों को बचाया जा सकता है, लेकिन देखा यह जाता है कि कई बार ये आपातकालीन सेवाएं, खुद सड़कों में फंस जाती हैं। इनके समय से न पहुंचने पर स्थिति बिगड़ जाती है। शोधकर्ताओं ने कहा कि अगर अगर एंबुलेंस ड्राइवर और अन्य आपातकालीन सुविधाओं को तुरंत ही यह सूचना मिल जाए की आगे कौन सी सड़क बाढ़ की वजह से बह गई है या कौन सी जाम है तो काफी हद तक नुकसान के साथ ही समय को भी बचाया जा सकता है। शोधकर्ताओं ने बताया कि अगर आपातकालीन सेवाओं के पास उपग्रह आधारित डिजिटल नक्शा होता जो दिखाता हो की कौन सी सड़क में क्या हलचल हो रही है तो कितना समय बचाया जा सकता था।

शोधकर्ताओं ने दक्षिण-पूर्व एशिया स्थित थाइलैंड की मेकांग नदी में 2011 में आई बाढ़ का अध्ययन किया। इस बाढ़ में लाखों एकड़ की फसल बर्बाद हो गई थी। लाखों लोग विस्थापित हुए और सैकड़ों लोग मारे गए। इस दिशा में काम करते हुए शोधकर्ताओं ने एक ऐसी एल्गोरिद्म बनाई है जो थाईलैंड के बैंकाक में मेकांग नदी बेसिन क्षेत्र में आपदा के दौरान आपातकालीन सेवाओं के लिए सबसे सही मार्ग बताती है, लेकिन शोधकर्ताओं का कहना है कि अभी इसमें सेटेलाइट का रियल टाइम डाटा नहीं शामिल है।

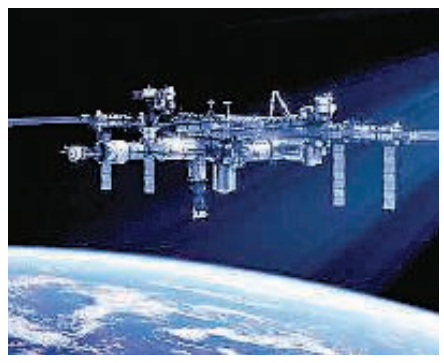
'इंवायरमेंटल साइंस' में प्रकाशित हुआ अध्ययन। प्रतीकात्मक

इस तरह बनाई एल्गोरिद्म

शोधकर्ताओं ने नासा के मॉडरेट रेजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रोरेडियोमीटर (एमओडीआइएस) का उपयोग करके बाढ़ के पानी की गहराई का अनुमान लगाया और नासा-यूएसजीएस लैंडसैट सेटेलाइट का उपयोग करके बाढ़ के फैलाव का पता लगाया। इसके अलावा उन्होंने नासा के सेडैक सेंटर के डाटा और ओपन स्ट्रीट मैप का भी उपयोग किया। इस दौरान उन्होंने मेकांग के बेसिन में एसे रूट तय किए जो बाढ़ के समय में कम प्रभावित होते हैं। जहां से बिना फंसे आसानी से निकला जा सकता है।